

भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन



अगस्त 2021

खंड 75 अंक 8

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
अजित आर. जोशी
देबा प्रसाद रथ
राजीव रंजन
सितीकांत पट्टनाईक
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर
तुषार बर्मन दास
पुलस्त्या बंदोपाध्याय

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2021

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<https://bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य 1

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22

मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य , 2021-22
मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) का संकल्प
4-6 अगस्त, 2021 7

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य 11

भाषण

वित्तीय समावेशन - अतीत, वर्तमान और भविष्य
श्री शक्तिकांत दास 13

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (करेंसी) - क्या यह पैसे (मनी) का भविष्य है
टी रबी शंकर 19

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 25

भारत में खाद्य मूल्य वर्धन पर कोविड-19 का प्रभाव 63

टीएलटीआरओ और संरचनात्मक चलनिधि:
एनबीएफसी के लिए एक अनुकूल स्थिति? 77

लघु वित्त बैंकों का प्रदर्शन - एक प्रारंभिक समीक्षा 93

वर्तमान सांख्यिकी 105

हाल के प्रकाशन 151

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य*

शक्तिकांत दास

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4, 5 और 6 अगस्त 2021 को हुई। उभरती घरेलू और वैश्विक समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों एवं संभावनाओं के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीति रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। एमपीसी ने 5 - 1 के बहुमत से यह भी निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखा जाए। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है। परिवर्तनीय रेपो दर भी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

आज, हम जून 2021 में एमपीसी की बैठक के समय की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में हैं। महामारी की दूसरी लहर थोड़ी कम हो रही, संरोधन को आसान किया गया है और हम धीरे-धीरे सुधार की ओर वापस आ रहे हैं, वैक्सीन निर्माण और प्रशासन लगातार बढ़ रहा है। फिर भी समय की मांग है कि हम अपनी कमर कस कर रखें और खासकर देश के कुछ हिस्सों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तीसरी लहर की किसी भी संभावना के प्रति सतर्क रहें।

सरकार के साथ हमारे कार्यों का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली को स्वस्थ और स्थिर रखते हुए तनाव को कम करना और विकास को प्राथमिकता देना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर¹ के दो उद्धरणों को एक साथ पढ़कर हमारे दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है “लेकिन मुझे पता है, किसी तरह, कि केवल जब पर्याप्त अंधेरा हो, तो ही आप सितारों को देख सकते हैं। चलते रहो। कुछ भी आपको धीमा न होने दें। आगे बढ़ो”

* गवर्नर का वक्तव्य : 6 अगस्त 2021

¹ स्रोत: मेम्फिस, टेनेसी में बिशप चार्ल्स मेसन मंदिर (3 अप्रैल 1968) और वाशिंगटन, डीसी यूएसए में स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना तीर्थयात्रा (कॉल टू कॉन्शियस, 1957) में दिए गए भाषण।

मैं एमपीसी के निर्णय के पीछे के तर्क को प्रस्तुत करके शुरू करता हूँ। एमपीसी ने मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सहिष्णुता बैंड से ऊपर होने वाले दो हालिया मुद्रास्फीति प्रिंटों के तहत अपनी बैठक की। इसने इस बात पर ध्यान दिया कि आर्थिक गतिविधि जून में एमपीसी की अपेक्षाओं की तर्ज पर व्यापक रूप से विकसित हुई है और अर्थव्यवस्था दूसरी लहर के झटके से उबर रही है। कुछ समय के अंतराल के बाद मानसून फिर से शुरू हो गया है और खरीफ की बुवाई रफ्तार पकड़ रही है। कुछ उच्च आवृत्ति संकेतक भी जून-जुलाई के दौरान फिर से ऊपर दिख रहे हैं। हमारी उम्मीद यह है कि टीकाकरण के प्रगतिशील उन्नयन, निरंतर बृहद नीतिगत समर्थन, निर्यात की अधिकता, कोविड संबंधित प्रोटोकॉल के लिए बेहतर अनुकूलन और सौम्य मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों के साथ गतिविधि में तेजी आने की संभावना है।

उपरोक्त मूल्य मुद्रास्फीति मई में तेजी से बढ़ी, जो प्रतिकूल आपूर्ति झटके, उच्च लॉजिस्टिक लागत, उच्च वैश्विक पण्य कीमतों और घरेलू ईंधन करों के संयोजन को दर्शाती है। जून में, हेडलाइन मुद्रास्फीति ऊपरी सहनशीलता के स्तर से ऊपर रही, लेकिन कीमतों की गति में सौम्यता आई। इसके अलावा, कोर मुद्रास्फीति मई में अपने चरम से सौम्य हुई। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है; ओपेक प्लस करार के परिणामस्वरूप कीमतों में कोई भी कमी मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में योगदान दे सकती है।

संतुलन पर, समग्र मांग की संभावनाओं में सुधार हो रहा है, लेकिन अंतर्निहित स्थितियां अभी भी कमजोर हैं। कुल आपूर्ति भी महामारी-पूर्व के स्तर से नीचे है। जबकि आपूर्ति बाधाओं को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में आपूर्ति-मांग संतुलन को बहाल करने के लिए और सुधार करने की आवश्यकता है। हाल के मुद्रास्फीति दबाव चिंता पैदा कर रहे हैं; लेकिन वर्तमान आकलन यह है कि ये दबाव अस्थायी हैं और बड़े पैमाने पर प्रतिकूल आपूर्ति पक्ष कारकों से प्रेरित हैं। हम महामारी से उत्पन्न एक असाधारण स्थिति के बीच में हैं। महामारी के दौरान मौद्रिक नीति का संचालन अनुकूल वित्तीय स्थितियों को बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है जो संवृद्धि का पोषण

और कायाकल्प करते हैं। इसलिए, इस स्तर पर, सभी पक्षों से निरंतर नीतिगत समर्थन - राजकोषीय, मौद्रिक और क्षेत्रीय - की आवश्यकता है ताकि नवीन और संकोची बहाली को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे ही मजबूत और सतत विकास की संभावनाएं सुनिश्चित होती हैं, एमपीसी मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने के अपने जनादेश के प्रति सचेत रहती है। तदनुसार, एमपीसी ने मौजूदा रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने और अपनी सभी बारीकियों के साथ निभावकारी रुख को जारी रखने का निर्णय लिया।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

घरेलू संवृद्धि

वायरस की दूसरी लहर के कम होने और अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने के साथ घरेलू आर्थिक गतिविधियां सामान्य होने लगी हैं। उच्च-आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि (i) खपत (निजी और सरकारी दोनों), (ii) निवेश और (iii) बाह्य मांग, सभी कर्षण प्राप्त करने के मार्ग पर हैं। मुझे इन तीनों पहलुओं में से प्रत्येक के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। प्रतिबंधों में ढील और टीकाकरण के बढ़ते कवरेज से यात्रा, पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों सहित वस्तुओं और सेवाओं पर निजी खर्च को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे कुल मांग में व्यापक सुधार होगा। कृषि और ग्रामीण मांग की मजबूत संभावनाएं निजी खपत का समर्थन करना जारी रखेगा। विनिर्माण और गैर-संपर्क गहन सेवाओं में सुधार, रुकी हुई मांग का आरंभ और टीकाकरण की गति के साथ शहरी मांग में तेजी आने की संभावना है। यह कई उच्च आवृत्ति संकेतकों जैसे, ऑटोमोबाइल का पंजीकरण, बिजली की खपत, गैर-तेल गैर-सोने का आयात, उपभोक्ता टिकाऊ बिक्री और शहरी श्रमिकों को काम पर रखना, में गति को प्रोत्साहित करके पुष्टि करता है। रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जुलाई दौर के नतीजे बताते हैं कि एक साल आगे मनोभाव ऐतिहासिक निचले स्तर से आशावादी क्षेत्र में लौट आई है। सूचीबद्ध फर्मों के शुरुआती नतीजे बताते हैं कि कॉर्पोरेट्स सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों के नेतृत्व में बिक्री, वेतन वृद्धि और लाभप्रदता में अपनी स्वस्थ वृद्धि को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। यह उपभोक्ताओं की कुल प्रयोज्य आय का भी समर्थन करेगा।

हालांकि निवेश की मांग अभी भी कमजोर है, क्षमता उपयोग में सुधार, इस्पात की बढ़ती खपत, पूंजीगत वस्तुओं के उच्च आयात, अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थिति और केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेजों से लंबे समय से प्रतीक्षित पुनरुद्धार के आरंभ होने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षणों में मतदान करने वाली फर्मों को 2021-22 की दूसरी तिमाही में उत्पादन मात्रा और नए ऑर्डर में विस्तार की उम्मीद है जो कि 2021-22 की चौथी तिमाही तक बनी रहेगी, जो निवेश के लिए अच्छा संकेत है। कारोबारों द्वारा महामारी के दौरान अपनाए गए नवाचार और कार्य मॉडल, महामारी के कम होने के बाद भी दक्षता और उत्पादकता लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे। इससे निवेश, रोजगार और संवृद्धि का एक सुचक्र शुरू करने में मदद मिलेगी।

2021-22 की पहली तिमाही के दौरान बाह्य मांग में उछाल आया और यह बढ़ते निर्यात, समग्र मांग को महत्वपूर्ण समर्थन देने में परिलक्षित हुआ। मजबूत बाह्य मांग भारत के लिए एक अवसर है और आगे नीतिगत समर्थन से इसे भुनाने में मदद मिलनी चाहिए। तथापि, वैश्विक पण्य कीमतों और वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव की घटनाएं, संक्रमण की नई लहरों के प्रति सुभेद्यता के साथ-साथ, आर्थिक गतिविधियों के लिए नकारात्मक जोखिम हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 2021-22 में 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जिसमें 2021-22 की पहली तिमाही में 21.4 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 6.1 प्रतिशत शामिल हैं। 2022-23 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर 17.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति

मई में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति तेजी से बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गई, जो प्रतिकूल आपूर्ति झटकों, क्षेत्र-विशिष्ट मांग-आपूर्ति बेमेल और बढ़ती वैश्विक पण्य कीमतों से स्पिलओवर पर सभी प्रमुख समूहों में वैविध्यपूर्ण बढ़ोत्तरी द्वारा संचालित थी। जून में यह 6.3 फीसदी पर रहा; हालांकि, कोर मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के पुनरुद्धार और खरीफ की बुवाई में तेजी, पर्याप्त खाद्य स्टॉक के बफर होने से आने वाले महीनों में अनाज की कीमतों के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य संकेतक सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप के कारण जुलाई में खाद्य तेलों और दालों की कीमतों में कुछ सौम्यता दिखाते हैं। मकान किराया जैसी प्रमुख सेवाओं में मुद्रास्फीति ऐतिहासिक औसत से नीचे बनी हुई है, जो कमजोर मांग की स्थिति को दर्शाती है। मुद्रास्फीति पर आयातित लागत दबावों के प्रभाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हैं। औद्योगिक कच्चे माल की ऊंची कीमतों का संयोजन, पेट्रोल और डीजल की उच्च पंप कीमतें उनके दूसरे दौर के प्रभावों के साथ, और लॉजिस्टिक लागत, विनिर्माण और सेवाओं के लिए लागत की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, हालांकि कमजोर मांग की स्थिति उत्पादन मूल्य और मुख्य मुद्रास्फीति की पास-थ्रू को प्रभावित कर रही है।

महामारी की शुरुआत से पहले, हेडलाइन मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की उम्मीदें 4 प्रतिशत पर अच्छी तरह से टिकी हुई थीं, जिससे मिले लाभ को समेकित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति दर में स्थिरता मौद्रिक नीति ढांचे की विश्वसनीयता को बढ़ावा देती है और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर करने के लिए शुभ संकेत देती है। यह बदले में, निवेशकों के लिए अनिश्चितता को कम करता है, अवधि और जोखिम प्रीमियम को कम करता है, बाहरी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है और इस प्रकार, संवृद्धि को बढ़ावा देता है। महामारी की शुरुआत के बाद से, एमपीसी ने महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए संवृद्धि के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी है। उपलब्ध डेटा मुद्रास्फीति प्रक्रिया को चलाने वाले बहिर्जात और बड़े पैमाने पर अस्थायी आपूर्ति झटकों की ओर इशारा करता है, जो एमपीसी के निर्णय को मान्य करता है। आपूर्ति पक्ष के चालक क्षणभंगुर हो सकते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए मांग दबाव निष्क्रिय बना रहता है। इस स्तर पर एक पूर्वकृत मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया नवीन और संकोची बहाली को मार सकती है जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पैर जमाने की कोशिश कर रही है।

मुद्रास्फीति 2021-22 की दूसरी तिमाही तक ऊपरी सहिष्णुता बैंड के करीब रह सकती है, लेकिन खरीफ फसल की

आवक और आपूर्ति पक्ष के उपायों के प्रभावी होने के कारण इन दबावों को 2021-22 की तीसरी तिमाही में कम होना चाहिए। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2021-22 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति अब 5.7 प्रतिशत पर अनुमानित है: 2021-22 की दूसरी तिमाही में 5.9 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 5.3 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत, जिसमें जोखिम व्यापक रूप से संतुलित हैं। 2022-23 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

जून-जुलाई के दौरान, कई देशों में उच्च मुद्रास्फीति संख्या और कुछ उन्नत देशों में विषम आर्थिक सुधार के साथ प्रारंभिक नीति सामान्यीकरण के डर के कारण वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर हो गए। एक उपयुक्त प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए इन घटनाक्रमों को हमारी नीति मैट्रिक्स में शामिल करने की आवश्यकता है, यह देखते हुए कि वैश्विक स्पिलओवर के उलटफेर से अर्थव्यवस्था की रक्षा करना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना रिजर्व बैंक के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिर भी, घरेलू समष्टि आर्थिक स्थिति और विकसित होती मुद्रास्फीति गतिकी हमारी मौद्रिक नीति कार्रवाइयों की प्रमुख धुरी बनी रहेगी।

रिजर्व बैंक ने अपने पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह के बाजार परिचालनों के माध्यम से, घरेलू मांग के समर्थन में वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने के लिए महामारी की शुरुआत के बाद से पर्याप्त अधिशेष चलनिधि बनाए रखी है। पूंजी प्रवाह की नई तेजी और द्वितीयक बाजार में रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद से उत्साहित, प्रतिवर्ती रेपो के माध्यम से कुल अवशोषण जून में दैनिक औसत के ₹5.7 लाख करोड़ से बढ़कर जुलाई 2021 में ₹6.8 लाख करोड़ और इसके अलावा अब तक अगस्त 2021 में (4 अगस्त तक) ₹8.5 लाख करोड़ हो गया।

06 फरवरी 2020 को घोषित संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे के तहत, रिजर्व बैंक अपने मुख्य चलनिधि परिचालन के रूप में 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित कर रहा है। सामान्य चलनिधि परिचालन की शुरुआत के साथ, वीआरआरआर, जिसे अस्थायी रूप से महामारी के दौरान रोक दिया गया था, को 15 जनवरी 2021 से

फिर से आरंभ किया गया है और बाद की पाक्षिक नीलामी में ₹ 2 लाख करोड़ के प्रारंभिक अवशोषण को रोलओवर किया गया है। समानांतर में, स्थायी दर एक दिवसीय (ओवरनाइट) प्रतिवर्ती रेपो तक पहुंच को खुला रखा गया है। स्थायी दर एक दिवसीय प्रतिवर्ती रेपो के सापेक्ष इसके द्वारा ऑफर किए जाने वाले उच्च परिश्रमिक को ध्यान में रखते हुए बाजारों ने वीआरआरआर को अनुकूलित किया है और यहां तक कि इसका स्वागत भी किया है। आशंका है कि वीआरआरआर की शुरुआत चलनिधि की सख्ती के समान है, जिसे दूर कर दिया गया है। हमने नीलामियों में बोली-रक्षा अनुपात के संदर्भ में वीआरआरआर के लिए अधिक रुचि देखी है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अब 13 अगस्त 2021 को ₹2.5 लाख करोड़; 27 अगस्त 2021 को ₹3.0 लाख करोड़; 9 सितंबर 2021 को ₹3.5 लाख करोड़; और 24 सितंबर 2021 को ₹4.0 लाख करोड़ की पाक्षिक वीआरआरआर नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इन बढ़ी हुई वीआरआरआर नीलामियों को निभावकारी नीतिगत रुख के वापसी के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो के तहत अवशोषित राशि सितंबर 2021 के अंत में ₹4.0 लाख करोड़ से अधिक रहने की उम्मीद है। यह जोड़ने की जरूरत नहीं है कि वीआरआरआर विंडो के तहत स्वीकृत राशि, प्रणाली चलनिधि का हिस्सा बनता है।

रिज़र्व बैंक का द्वितीयक बाजार जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) बाजार सहभागियों से गहरी प्रतिक्रिया प्राप्त करते हुए प्रतिफल अपेक्षाओं को स्थिर करने में सफल रहा है। हम जी-एसएपी 2.0 के तहत 12 अगस्त और 26 अगस्त 2021 को ₹25,000 करोड़ की दो और नीलामी आयोजित करने का प्रस्ताव करते हैं। हम अन्य के साथ-साथ इन नीलामियों और अन्य कार्यों जैसे खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) और परिचालन ट्विस्ट (ओटी) को करना जारी रखेंगे, और उन्हें विकसित समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के अनुरूप कैलिब्रेट करेंगे।

इसके व्यवस्थित विकास के लिए प्रतिफल वक्र के सभी खंडों में सक्रिय व्यापार करना आवश्यक है। हमारी हालिया जी-एसएपी नीलामियों ने परिपक्वता अवधि में प्रतिभूतियों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिफल वक्र के सभी खंड तरल बने रहें। इसके अलावा, हमारे

विकल्प जी-एसएपी नीलामियों और परिचालन ट्विस्ट में ऑफ दरन और ऑन दर प्रतिभूतियाँ दोनों को शामिल करने के लिए हमेशा खुले हैं। यह उम्मीद की जाती है कि द्वितीयक बाजार की मात्रा में वृद्धि होगी और बाजार सहभागियों ने ऐसी स्थिति बना ली है जिससे प्रतिफल में दोतरफा गति हो रही है।

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि रोलओवर जोखिम को कम करते हुए उचित लागत पर उनके उधार कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके। अपने पहले के भाषण में, मैंने सार्वजनिक वस्तु के रूप में प्रतिफल वक्र के क्रमिक विकास पर जोर दिया है जिसमें बाजार सहभागियों और रिज़र्व बैंक दोनों की साझा जिम्मेदारी है। चूंकि जी-सेक प्रतिफल एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है और ऋण बाजार के अन्य क्षेत्रों के लिए उच्च संकेत मूल्य है, प्राथमिक बाजार परिचालन में नीलामी कट-ऑफ, हस्तांतरण, रद्दीकरण और ग्रीन शू विकल्पों के प्रयोग के माध्यम से प्रतिफल के व्यवस्थित पथ पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया था। 14 साल की अवधि तक की प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए हाल ही में घोषित एकसमान मूल्य नीलामियों की शुरुआत से उन जोखिमों को कम करने की उम्मीद है जो बोली लगाने वालों को प्राथमिक खंड में सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा नकद शेष के भीतर वर्ष की पहली छमाही के लिए राज्यों को जीएसटी मुआवजे के भुगतान को समायोजित करने के सरकार के निर्णय से इस वर्ष सरकार के उधार कार्यक्रम के आकार पर बाजार की चिंताओं को शांत करना चाहिए।

रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति उपायों और कार्यों की प्रभावशीलता वर्तमान सहजता चक्र के दौरान संचरण में महत्वपूर्ण सुधार में परिलक्षित होती है। फरवरी 2019 से रेपो दर में 250 आधार अंकों की कमी के परिणामस्वरूप नए रुपये के ऋणों पर भारत औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में 217 आधार अंकों की संचयी गिरावट आई है। कॉरपोरेट बॉन्ड, डिबेंचर, सीपी, सीडी और टी-बिल जैसे बाजार के साधनों पर ब्याज दरों सहित घरेलू उधारी लागत कम हुई है। ऋण बाजार में, एमएसएमई, आवास और बड़े उद्योगों के लिए उधार दरों का संचरण मजबूत हुआ है। कम ब्याज दर व्यवस्था ने घरेलू क्षेत्र को ऋण सेवा के बोझ को कम करने में भी मदद की है। व्यक्तिगत आवास ऋण और

वाणिज्यिक अचल संपत्ति क्षेत्र को ऋण पर ब्याज दरों में उल्लेखनीय कमी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि इन क्षेत्रों के पास व्यापक पिछला और आगे की सहलग्नता और गहन रोजगार हैं।

अतिरिक्त उपाय

महामारी की शुरुआत के बाद, रिज़र्व बैंक ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए 100 से अधिक उपायों की घोषणा की है। आगे, हमारा प्रयास उन उपायों की निगरानी जारी रखना होगा जो अभी भी चल रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे सभी उपायों का लाभ लक्षित हितधारकों तक पहुंचे। इस पृष्ठभूमि में और व्यापक आर्थिक स्थिति और वित्तीय बाजार की स्थितियों के हमारे निरंतर मूल्यांकन के आधार पर, आज कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा की जा रही है। इन उपायों का विवरण मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों (भाग-बी) पर वक्तव्य में निर्धारित किया गया है। मैं इन उपायों के बारे में बताता हूँ।

ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना – समय- सीमा का विस्तार

ऑन-टैप टीएलटीआरओ योजना का दायरा, शुरू में 9 अक्टूबर 2020 को पांच क्षेत्रों के लिए घोषित किया गया था, जिसे दिसंबर 2020 में कामथ समिति द्वारा पहचाने गए दवाबग्रस्त क्षेत्रों और फरवरी 2021 में एनबीएफसी को बैंक ऋण देने के लिए आगे बढ़ाया गया था। योजना की परिचालन अवधि को भी चरणों में 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। नवजात और नाजुक आर्थिक सुधार को देखते हुए, अब ऑन-टैप टीएलटीआरओ योजना को तीन महीने की अवधि, अर्थात् 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - छूट का बढ़ाया जाना

27 मार्च 2020 को सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत बैंकों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में सकल मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) में अतिरिक्त एक प्रतिशत तक अर्थात् संचयी रूप से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक निधि का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। बैंकों को उनकी चलनिधि आवश्यकताओं पर सुलभता उपलब्ध कराने और

उनकी चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह सुविधा जो 30 सितंबर 2021 तक उपलब्ध है, को तीन महीने की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 31 दिसंबर 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था ₹1.62 लाख करोड़ की सीमा तक धन की पहुंच प्रदान करती है और एलसीआर के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्यूएलए) के रूप में पात्र है।

लिबोर पारगमन - दिशानिर्देशों की समीक्षा – विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण और डेरिवेटिव संविदाओं की पुनर्चना

लंदन अंतर- बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) से पारगमन एक महत्वपूर्ण घटना है जो बैंकों और वित्तीय प्रणाली के लिए कुछ चुनौतियां पेश करती है। रिज़र्व बैंक सक्रिय रूप से कदम उठाने के लिए बैंकों और बाजार निकायों के साथ जुड़ रहा है। रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं और वित्तीय बाजारों के लिए भी एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सूचना जारी की है। इस संदर्भ में, (i) विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण और (ii) डेरिवेटिव संविदाओं की पुनर्चना से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। बैंकों को संबंधित मुद्रा में किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग करके विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण को प्रदान करने की अनुमति होगी। चूंकि लिबोर से संदर्भ दर में परिवर्तन एक “अप्रत्याशित घटना” है, बैंकों को सूचित किया जा रहा है कि संदर्भ दर में लिबोर /लिबोर-संबंधित बेंचमार्क से वैकल्पिक संदर्भ दर में परिवर्तन को पुनर्चना नहीं माना जाएगा।

समाधान ढांचा 1.0 के तहत वित्तीय मानकों की उपलब्धि के लिए समय- सीमा को स्थगित करना

6 अगस्त 2020 को घोषित कोविड-19 संबंधित दवाब के लिए समाधान ढांचा के तहत लागू की गई समाधान योजनाओं को कई वित्तीय मापदंडों के संबंध में क्षेत्र विशिष्ट श्रेसहोल्ड को पूरा करना आवश्यक है। इन मापदंडों में से, चार मापदंडों के संबंध में सीमाएं, उधार लेने वाली संस्थाओं के परिचालन निष्पादन से संबंधित हैं, अर्थात् ईबीआईडीटीए अनुपात की तुलना में कुल ऋण, वर्तमान अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात और औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात। इन अनुपातों को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने की आवश्यकता है। कोविड-19 की दूसरी लहर के

प्रतिकूल प्रभाव और कारोबारों के पुनरुद्धार पर परिणामी कठिनाइयों को देखते हुए और परिचालन मापदंडों को पूरा करने के लिए, लक्ष्य तिथि को 1 अक्टूबर 2022 तक उपरोक्त चार मापदंडों के संबंध में निर्दिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

समापन टिप्पणी

जैसे-जैसे कोविड-19 की दूसरी लहर में कमी आती है, आशा है कि पर्याप्त महामारी प्रोटोकॉल और टीकाकरण दर में बढ़ोतरी के साथ, यदि तीसरी लहर आती है तो हम उसका सामना करने में सक्षम होंगे। एक राष्ट्र के रूप में, हमें अभी भी सतर्कता रखनी चाहिए और वायरस के अधिक तेजी से फैलने वाले म्यूटेंट के साथ महामारी के किसी भी पुनरुत्थान से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, यदि अगर ऐसा हुआ।

बहाली सभी क्षेत्रों में असमान बनी हुई है और सभी नीति निर्माताओं द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है। रिज़र्व बैंक अपने सभी नीतिगत उत्तोलक - मौद्रिक, विवेकपूर्ण या विनियामक को तैनात करने के लिए तत्परता के साथ “चाहे जो भी हो” मोड में रहेगा। समानांतर में, वित्तीय स्थिरता के संरक्षण पर हमारा फोकस जारी है। इस समय, हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता यह है कि स्थिरता के साथ एक सतत संवृद्धि पथ सहित एक टिकाऊ बहाली सुनिश्चित करने के लिए विकास आवेगों का पोषण किया जाए। इस प्रयास में, हमने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर, सचेतन रूप से निराशा पर आशावाद को चुना है: “मैं एक अदम्य आशावादी हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने आशावाद को ठोस तथ्यों पर आधारित रखता हूँ”²।

धन्यवाद। सुरक्षित रहें। स्वस्थ रहें। नमस्कार।

² स्रोत: पुस्तक “महात्मा” द्वारा डी.जी. तेंदुलकर, वॉल्यूम 2

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प
4-6 अगस्त 2021

मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प*

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अगस्त 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं।

- यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया।

ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है।

इस निर्णय के पीछे की मुख्य सोच नीचे दिए गए विवरण में व्यक्त की गई हैं।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. जून 2-4, 2021 के दौरान एमपीसी की बैठक के बाद से, वैश्विक सुधार की गति दुनिया के कई हिस्सों में संक्रमण के

पुनरुत्थान से विशेष रूप से वायरस के डेल्टा वेरियंट के कारण कम होती दिख रही है। जून और जुलाई में, वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मई में अपने उच्चतम स्तर से फिसल गया। बढ़ती आम सहमति यह है कि रिकवरी भिन्न-भिन्न टू-ट्रैक मोड पर हो रही है। जो देश टीकाकरण में आगे हैं और नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान करने या बनाए रखने में सक्षम हैं, वे दृढ़ता से पलटवार कर रहे हैं। अन्य अर्थव्यवस्थाओं में विकास मंद और संक्रमण की नई लहरों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। 2021 की दूसरी तिमाही में वैश्विक व्यापार की मात्रा में गति धीमी हो गई है, और लदान शुल्क और लोजिस्टिक लागत वृद्धि के साथ विपरीत परिस्थिति हो रही है।

3. विशेष रूप से कच्चे तेल की पण्य कीमतों में काफी सख्तता आई सितंबर 2022 तक पूर्व-महामारी के स्तर पर उत्पादन की संभावित बहाली के लिए तेल उत्पादन बढ़ाने हेतु पेट्रोलियम देशों के संगठन (ओपेक) के बीच नवीनतम समझौते ने जुलाई की शुरुआत में हाल की वृद्धि से भविष्य में कच्चे तेल की कीमतों में क्षणिक नरमी प्रदान की। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के साथ-साथ अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ गई है, जिससे ईएमई में कुछ केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति को सख्त करने के लिए प्रेरित किया है। इसके विपरीत, सभी ईई में सॉवरेन बॉन्ड प्रतिफल में नरमी आई है क्योंकि ऐसा लगता है कि बाजार केंद्रीय बैंकों के विचारों से सहमत हो गए हैं कि मुद्रास्फीति काफी हद तक अस्थायी है। ईएमई में, मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं और देश-विशिष्ट कारकों पर बांड प्रतिफल अपेक्षाकृत अधिक रहता है। विदेशी मुद्रा बाजार में, जून के मध्य से पोर्टफोलियो बहिर्वाह के मद्देनजर ईएमई मुद्राओं का मूल्यहास हुआ है क्योंकि जोखिम कम हुआ है, जबकि अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

4. घरेलू मोर्चे पर, आर्थिक गतिविधियों ने जून-जुलाई में गति पकड़ी क्योंकि कुछ राज्यों ने महामारी नियंत्रण उपायों में ढील दी। जहां तक कृषि का संबंध है, दक्षिण-पश्चिम मानसून ने मध्य जुलाई में एक सुस्ती के बाद तीव्रता प्राप्त की; 1 अगस्त, 2021 तक संचयी वर्षा लंबी अवधि के औसत से एक प्रतिशत कम थी। ग्रामीण मांग के कुछ उच्च आवृत्ति संकेतक, विशेष रूप से ट्रैक्टर

* 06 अगस्त 2021 को जारी किया गया।

और उर्वरक की बिक्री के साथ खरीफ फसलों की बुवाई की गति जुलाई में तेज हुई।

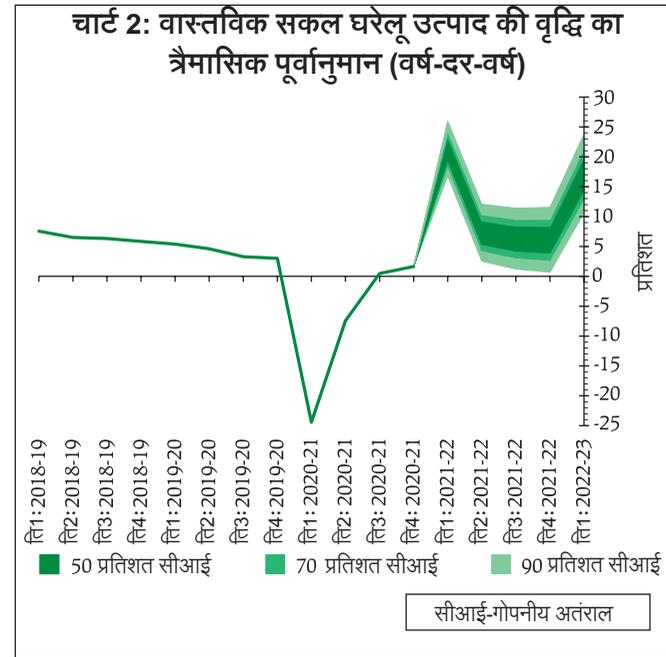
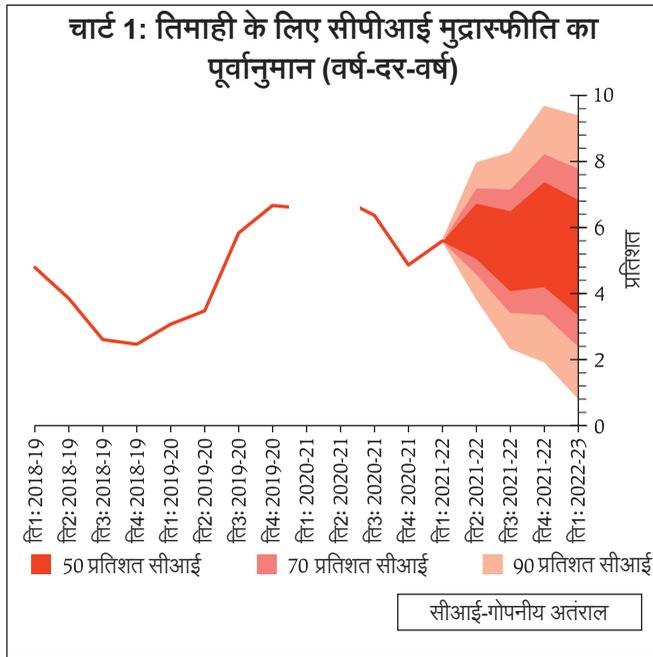
5. बड़े आधार प्रभावों को दर्शाते हुए, अप्रैल में भारी उछाल के साथ मई 2021 में औद्योगिक उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) दोहरे अंकों में विस्तार हुआ, लेकिन यह अभी भी मई 2019 के स्तर से 13.9 प्रतिशत नीचे था। विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जो 11 महीनों में पहली बार जून में संकुचन से गिरकर 48.1 पर आ गया था, जुलाई में 55.3 की रीडिंग के साथ विस्तार क्षेत्र में अच्छी तरह से पलट गया। उच्च आवृत्ति संकेतक - ई-वे बिल; टोल संग्रहण; विद्युत उत्पादन; वायु यातायात; रेलवे माल यातायात; बंदरगाह कार्गो; इस्पात की खपत, सीमेंट उत्पादन; पूंजीगत वस्तुओं का आयात; यात्री वाहन की बिक्री; दोपहिया वाहनों की बिक्री से -जून/जुलाई में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो कोविड संबंधित प्रोटोकॉल के अनुकूलन और नियंत्रण में ढील को दर्शाती है। कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के कारण सेवाएं पीएमआई संकुचन क्षेत्र में रही, हालांकि इसकी गति जो जून 2021 में 41.2 थी जुलाई में 45.4 से कम हो गई। क्यू1: 2021-22 के लिए गैर-वित्तीय कॉरपोरेट्स के प्रारंभिक तिमाही परिणाम सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों के नेतृत्व में बिक्री, वेतन वृद्धि और लाभप्रदता में स्वस्थ वृद्धि दर्शाते हैं।

6. मई 2021 में 207 आधार अंकों की वृद्धि के बाद जून में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 6.3 प्रतिशत पर पहुंच गई। खाद्य मुद्रास्फीति में जून में वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य तेलों, दालों, अंडे, दूध और तैयार भोजन में मुद्रास्फीति में वृद्धि और सब्जियों की कीमतों में तेजी के कारण हुई। एलपीजी, केरोसिन, और जलाऊ लकड़ी और चिप्स में मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण ईंधन मुद्रास्फीति मई-जून 2021 के दौरान दोहरे अंकों में चली गई। आवास, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, मनोरंजन, जूते, पान, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों (चूंकि एक साल पहले लगाए गए एकबारगी पोस्ट-लॉकडाउन कर का प्रभाव कम हो गया) और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव (सोने में मुद्रास्फीति में तेज कमी के कारण) में मुद्रास्फीति में नरमी के कारण मई में तेजी से 6.6 प्रतिशत तक बढ़ने के बाद, मुख्य मुद्रास्फीति जून में कम होकर 6.1 प्रतिशत हो गई।

7. प्रणालीगत तरलता पर्याप्त रही, एलएएफ के तहत औसत दैनिक अवशोषण जून में ₹5.7 लाख करोड़ से बढ़कर जुलाई में ₹6.8 लाख करोड़ और अगस्त में अब तक ₹8.5 लाख करोड़ (4 अगस्त 2021 तक) हो गया। द्वितीयक बाजार सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) के तहत अब तक 2021-22 की दूसरी तिमाही में ₹ 40,000 करोड़ की संचयी राशि की नीलामी ने प्रतिफल वक्र के अतरल खंड में तरलता को संतुलित किया। आरक्षित नकद (आरक्षित नकदी निधि अनुपात में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित) 30 जुलाई 2021 को मुद्रा की मांग से प्रेरित 11.0 प्रतिशत वाई-ओ-वाई द्वारा विस्तारित हुआ। 16 जुलाई 2021 तक, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा आपूर्ति (एम3) और बैंक ऋण में क्रमशः 10.8 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2021-22 (जुलाई के अंत तक) में 43.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 620.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

संभावनाएं

8. भविष्य में, दक्षिण-पश्चिम मानसून के पुनरुद्धार और खरीफ की बुवाई में तेजी, पर्याप्त खाद्य भंडार के साथ अनाज की कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उच्च आवृत्ति संकेतक सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप के जवाब में जुलाई में खाद्य तेलों और दालों में कीमतों के दबाव में कुछ नरमी का सुझाव देते हैं। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में इनपुट की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन कमजोर मांग और लागत में कटौती की दिशा में प्रयास उत्पादन की कीमतों में गिरावट को कम कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर होने से, केंद्र और राज्यों द्वारा पंप की कीमतों के अप्रत्यक्ष कर घटक की एक अंशांकित कमी, लागत दबाव को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2021-22 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति अब 5.7 प्रतिशत पर अनुमानित है: दूसरी तिमाही में 5.9 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 5.3 प्रतिशत; और 2021-22 की चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत, जिसमें जोखिम व्यापक रूप से संतुलित हैं। 2022-23 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है (चार्ट 1)।



9. दूसरी लहर के कम होने के साथ ही घरेलू आर्थिक गतिविधियां ठीक होने लगी हैं। आगे देखते हुए, कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग में लचीलापन रहने की उम्मीद है। शहरी मांग में देरी के साथ सुधार होने की संभावना है क्योंकि विनिर्माण और गैर-संपर्क गहन सेवाएं एक मजबूत गति से फिर से शुरू होती हैं, और रुकी हुई मांग की रिहाई टीकाकरण की त्वरित गति के साथ एक टिकाऊ स्थिति प्राप्त करती है। उत्साहजनक निर्यात, पूंजीगत व्यय सहित सरकारी व्यय में अपेक्षित वृद्धि और सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आर्थिक पैकेज समग्र मांग को और गति प्रदान करेगा। हालांकि निवेश की मांग अभी भी कमजोर है, क्षमता उपयोग में सुधार और अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थितियां लंबे समय से प्रतीक्षित पुनरुद्धार के लिए जमीन तैयार कर रही हैं। रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षणों में मतदान करने वाली फर्मों को 2021-22 की दूसरी तिमाही में उत्पादन मात्रा और नए ऑर्डर में विस्तार की उम्मीद है, जो चौथी तिमाही तक बने रहने की संभावना है। हालांकि, वैश्विक पण्य कीमतों का उंचा स्तर और वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव मुख्य नकारात्मक जोखिम हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 2021-22 में 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जिसमें पहली तिमाही में 21.4 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत; तीसरी तिमाही

में 6.3 प्रतिशत; और 2021-22 की चौथी तिमाही में 6.1 प्रतिशत शामिल है। पहली तिमाही: 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 17.2 प्रतिशत (चार्ट 2) पर अनुमानित है।

10. मुद्रास्फीति के दबावों की बारीकी से और लगातार निगरानी की जा रही है। एमपीसी मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर करने के अपने उद्देश्य के प्रति सचेत है। कुल मांग के लिए दृष्टिकोण में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी कमजोर और महामारी के कारण आच्छादित है। अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में सुस्ती है, जिसका उत्पादन महामारी से पहले के स्तर से नीचे है। वर्तमान आकलन यह है कि 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान मुद्रास्फीति के दबाव बड़े पैमाने पर प्रतिकूल आपूर्ति झटकों से प्रेरित हैं जिनके अस्थायी होने की उम्मीद है। जबकि सरकार ने आपूर्ति बाधाओं को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, आपूर्ति-मांग संतुलन को बहाल करने के लिए इस दिशा में ठोस प्रयास आवश्यक हैं। राजकोषीय, मौद्रिक और क्षेत्रीय नीति उत्तोलक के माध्यम से नवजात और हिचकती बहाली को पोषित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने मौजूदा रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था

पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

11. एमपीसी के सभी सदस्य – प्रो. जयंत आर. वर्मा को छोड़कर डॉ. शंशाक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, डॉ. मृदुल के. सागर, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास ने नीति रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया।

12. प्रो. जयंत आर. वर्मा को छोड़कर एमपीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य

में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने के लिए मतदान किया। प्रो. जयंत आर. वर्मा ने संकल्प के इस भाग पर आपत्ति व्यक्त की।

13. एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 20 अगस्त, 2021 को प्रकाशित किया जाएगा।

14. एमपीसी की अगली बैठक 6 से 8 अक्टूबर, 2021 के दौरान निर्धारित है।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य चलनिधि और विनियामक उपायों सहित विभिन्न विकासात्मक उपायों को निर्धारित करता है।

I. चलनिधि उपाय

1. ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना – समय- सीमा का विस्तार

विशिष्ट क्षेत्रों, जिसका पिछली और आगे दोनों से जुड़ाव है और जिनका संवृद्धि पर गुणक प्रभाव पड़ता है, में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2020 को पांच क्षेत्रों के लिए ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना की घोषणा की थी, जो कि 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध थी। कामथ समिति द्वारा पहचाने गए दवाबग्रस्त क्षेत्रों को भी 4 दिसंबर 2020 को योजना के दायरे में लाया गया और बाद में 5 फरवरी 2021 को एनबीएफसी को बैंक ऋण दिया गया। 7 अप्रैल को, इस योजना को छह महीने की अवधि के लिए, अर्थात् 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। नवजात और नाजुक आर्थिक बहाली को देखते हुए, अब ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना को तीन महीने की अवधि अर्थात् 31 दिसंबर 2021 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

2. सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - छूट का बढ़ाया जाना

27 मार्च 2020 को बैंकों को निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) में अतिरिक्त एक प्रतिशत तक सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को कम करते हुए अर्थात् संचयी रूप से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत निधि का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। यह सुविधा, जो शुरू में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, बाद में चरणों में 31 मार्च 2021 तक और फिर से 30 सितंबर 2021 तक छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दी गई, जिससे बैंकों को उनकी चलनिधि आवश्यकताओं पर सुलभता प्राप्त हो और उन्हें उनकी चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। यह व्यवस्था ₹1.62 लाख

करोड़ की सीमा तक निधि की पहुंच प्रदान करती है और एलसीआर के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्यूएलए) के रूप में पात्र है। अब एमएसएफ छूट को तीन महीने की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 31 दिसंबर 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

II. विनियामक उपाय

3. लिबोर पारगमन - दिशानिर्देशों की समीक्षा

लंदन अंतर- बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) पारगमन एक महत्वपूर्ण इवेंट है जो बैंकों और वित्तीय प्रणाली को चुनौतियां देती है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2021 को एक सूचना जारी की थी जिसमें बैंकों और अन्य रिजर्व बैंक-विनियमित संस्थाओं को ऐसे नए वित्तीय संविदा, जो लिबोर को संदर्भ दर के रूप में उपयोग करता है, को निष्पादित करने से रोकने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और इसके स्थान पर जितना व्यवहार्य हो सके और किसी भी हाल में 31 दिसंबर 2021 तक, किसी अन्य वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) का उपयोग करने के लिए कहा गया था। रिजर्व बैंक विनियमित संस्थाओं और वित्तीय बाजारों के लिए एक सुचारु पारगमन सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यकतानुसार, सक्रिय रूप से कदम उठाने के लिए बैंकों और बाजार निकायों के साथ जुड़ रहा है। इस संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण और डेरिवेटिव संविदाओं के पुनर्गठन से संबंधित दिशानिर्देशों में नीचे दिए गए अनुसार संशोधन किया जाए।

(i) विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण - बेंचमार्क दर

अधिकृत डीलरों को वर्तमान में लिबोर/यूरो-लिबोर/यूरिबोर संबंधित ब्याज दरों पर पोतलदान से पहले माल की खरीद, प्रसंस्करण, निर्माण या पैकिंग के वित्तपोषण के लिए निर्यातकों को विदेशी मुद्रा (पीसीएफसी) में पूर्व-पोतलदान क्रेडिट प्रदान करने की अनुमति है। बेंचमार्क दर के रूप में लिबोर के निकट में बंद होने को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को संबंधित मुद्रा में किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग करके निर्यात ऋण प्रदान करने की अनुमति दी जाए।

(ii) बैंकों के तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - डेरिवेटिव संविदाओं की पुनर्चना

डेरिवेटिव संविदाओं के लिए, मौजूदा निर्देशों के अनुसार, मूल संविदा के किसी भी मानदंड (पैरामीटर) में परिवर्तन को एक पुनर्चना के रूप में माना जाता है और पुनर्चना की तारीख पर संविदा के मार्क-टू-मार्केट मूल्य में परिणामी परिवर्तन का नकद निपटान किया जाना आवश्यक है। चूंकि लिबोर से संदर्भ दर में निकट परिवर्तन एक “अप्रत्याशित घटना” है, बैंकों को सूचित किया जा रहा है कि संदर्भ दर में लिबोर /लिबोर-संबंधित बेंचमार्क से वैकल्पिक संदर्भ दर में परिवर्तन को पुनर्चना नहीं माना जाएगा।

4. समाधान ढांचा 1.0. के तहत वित्तीय मानकों की उपलब्धि के लिए समय-सीमा को स्थगित करना

6 अगस्त 2020 को घोषित कोविड-19 संबंधित दवाब के लिए समाधान ढांचा के तहत लागू की गई समाधान योजनाओं को पाँच वित्तीय मापदंडों जिनमें से चार, जो उधार लेने वाली इकाई

के परिचालन निष्पादन से संबंधित हैं, अर्थात् कुल ऋण ईबीआईडीटीए अनुपात में (कुल ऋण/ईबीआईडीटीए), वर्तमान अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात और औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात, के संबंध में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट थ्रेसहोल्ड को 31 मार्च 2022 तक पूरा करना आवश्यक है। कारोबार के पुनरुद्धार पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव और परिचालन मापदंडों को पूरा करने में आने वाली कठिनाई को देखते हुए, उपरोक्त मापदंडों के संबंध में निर्दिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि को 1 अक्टूबर 2022 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

कुल बाह्य देयताओं/समायोजित कुल निवल मूल्य (टीओएल/एटीएनडब्ल्यू) के मापदंड के संबंध में, यह अनुपात संशोधित पूंजी संरचना (अर्थात्, ऋण-इक्विटी मिश्रण) को दर्शाता है, जैसा कि समाधान ढांचे के लिए कार्यान्वयन शर्तों के तहत आवश्यक है और समाधान योजना के हिस्से के रूप में अग्रिम रूप से सघन होने की उम्मीद थी। तदनुसार, इसे प्राप्त करने की तारीख अपरिवर्तित रहेगी, अर्थात् 31 मार्च 2022।

इससे संबंधित परिपत्र, 7 सितंबर 2020 के पिछले निर्देशों को संशोधित करते हुए, शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

भाषण

वित्तीय समावेशन - अतीत, वर्तमान और भविष्य
श्री शक्तिकांत दास

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (करेंसी) - क्या यह पैसे (मनी) का भविष्य है
टी रबी शंकर

वित्तीय समावेशन - अतीत, वर्तमान और भविष्य*

श्री शक्तिकांत दास

इस गरिमापूर्ण सम्मेलन को संबोधित करने हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं इकनॉमिक टाइम्स फाइनेंशियल इंकलूजन समिट के आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वित्तीय समावेशन सतत और संतुलित आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रेरक तत्व है जो आय की असमानता और गरीबी को कम करने में सहायता प्रदान करता है। यद्यपि हमने इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है, परंतु महामारी के कारण नई चुनौतियाँ और जटिलताएँ पैदा हो गई हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधार की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसलिए यह सर्वथा उपयुक्त है कि इस समय वित्तीय समावेशन पर विचार-विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और मैं इसके लिए आयोजकों की सराहना करता हूँ।

वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत की यात्रा के पीछे जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वह गांधीवादी दर्शन "अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय - सबसे कमजोर व्यक्ति के उत्थान के माध्यम से सभी लोगों का कल्याण" में प्रतिध्वनित होता है। 'समावेशी' और 'समानता' के मूल उद्देश्य इस दर्शन के केंद्र में हैं जिसका दायरा गरीबी उन्मूलन से आगे तक जाता है। इसके दायरे में गरीबों, महिलाओं, किसानों, छोटे उद्यमों और अन्य लोगों के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करना शामिल है। भारत में नीति निर्माताओं के रूप में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के महत्व को बहुत पहले स्वीकार कर लिया था और यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंचे।

मुझे विश्वास है कि आज इस मंच पर उभरते जोखिमों, नवोन्मेषी और अति परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के नए मॉडलों और संभावित नीतिगत हस्तक्षेपों के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। आज के अपने संबोधन में इस बात पर विचार करना मुझे

उपयुक्त लगा कि यह देखा जाए- हमने वित्तीय समावेशन के रास्ते पर अब तक कितनी दूर यात्रा कर ली है और आगे के रास्ते पर सोच-विचार किया जाए। पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के आयामों में इस क्षेत्र में हुई प्रगति का आकलन करते हुए, यह देखा गया है कि भारत में बैंकिंग सेवाओं तक समाज के अंतिम व्यक्ति की पहुंच को सुविधाजनक बनाने और वित्तीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में एक लंबा सफर तय किया गया है। इसे आगे बढ़ाते हुए, वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019-2024 (एनएसएफई)¹ और वित्तीय शिक्षण के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-2025 (एनएसएफई)² वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती हैं। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज़ में ऐसे कई मील के पत्थर और कार्यान्वित की जाने वाली कार्य-योजनाओं को तय किया गया है जिससे एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से वित्तीय सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध, सुलभ और सस्ती बनाया जा सके।

अब तक की प्रगति

यदि पीछे मुड़कर देखा जाए तो देश की वित्तीय समावेशन यात्रा 1950 के दशक में शुरू हो गई थी, जब अर्थव्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों और आबादी के कमजोर वर्गों को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके बाद के वर्षों में विभिन्न प्रकार की पहल की गईं जिनमें अन्य तमाम योजनाओं के अलावा शाखा नेटवर्क का विस्तार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल), अग्रणी बैंक योजना शुरू करना, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को बढ़ावा देना, कारोबार संवाददाता (बीसी) मॉडल का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं। बीसी मॉडल की सहायता से पारंपरिक बैंकिंग शाखाओं ने देश भर में बैंकिंग प्रणाली की पहुंच में सुधार किया है। हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशन के प्रसार और पहुंच में वास्तव में बहुत तेज वृद्धि हुई है।

प्रौद्योगिकी के विकास और इसे अपनाने से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सघन विस्तार में व्यापक सुधार हुआ है। जन-धन,

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गुरुवार, 15 जुलाई 2021 को इकनॉमिक टाइम्स फाइनेंशियल इंकलूजन समिट में दिया गया उद्घाटन वक्तव्य

¹ <https://m.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=1154>

² <https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=1156>

आधार और मोबाइल (जेएएम) से निर्मित परिदृश्य ने वित्तीय समावेशन के संपूर्ण क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाया है। इसके अलावा, एक सुविधाजनक, सुरक्षित, निरापद और किफायती तरीके से डिजिटल भुगतान को सर्वव्यापी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्षम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना बनाने के लिए अनेक पहल की गई हैं। पिरामिड के बुनियादी हिस्से के मूल्यगत उपयोग की अंतर्निहित संभावना को देखते हुए, पारंपरिक बैंकों से लेकर भुगतान बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) तथा संभावनाशील फिनटेक कंपनियों जैसी नई प्रकार की विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं को इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में उभरते भागीदारों के रूप में देखा गया है।

वित्तीय समावेशन के लिए एक योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण रखने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआईपी) बनाने की सलाह दी गई है, जिसमें कई मापदंडों के अनुसार उपलब्धियां शामिल हैं। इन मापदंडों के संबंध में पर्याप्त प्रगति हुई है, जिसका विवरण मई 2021 में जारी रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

अब उपभोक्ता संरक्षण और ग्राहकों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देते हुए अर्थव्यवस्था और आबादी के कमजोर वर्गों की समस्याओं को दूर करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वित्तीय सेवाओं के जिम्मेदार और स्थायी उपयोग के स्तर को प्राप्त किया जा सके। विभिन्न जनसंख्या समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विभिन्न प्रकार के बैंकों की शुरुआत उस दिशा में एक कदम था। हाल के दिनों में, जिन चुनौतियों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है वे हैं (i) ग्राहक की पहचान कैसे करें; (ii) अंतिम पायदान तक कैसे पहुंचें; और (iii) प्रासंगिक उत्पाद कैसे प्रदान करें जो विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किफायती और सुरक्षित हो।

विश्वस्तरीय भुगतान प्रणाली के साथ, डिजिटल आईडी (आधार) और मोबाइल फोन के प्रसार से, पहुंच और उपयोग की पहली दो चुनौतियों का समाधान काफी हद तक हो गया है। तीसरी चुनौती अर्थात् गुणवत्ता के लिए मांग और पूर्ति दोनों पक्षों

³ इन मानदंडों में आउटलेटों (शाखाओं और बीसी) की संख्या, बुनियादी बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए), इन खातों में ली गई ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) और सामान्य क्रेडिट कार्डों (जीसीसी) में हुए लेनदेन और कारोबारी संवाददाता-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (बीसी-आईसीटी) चैनल के माध्यम से हुए लेनदेन शामिल हैं।

में आवश्यक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) में खोले गए खातों ने वित्तीय सेवाओं तक लाखों भारतीयों की पहुंच को संभव बना दिया है जिससे उनकी मूलभूत वित्तीय उत्पादों की विविध आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। इससे आपूर्ति से जुड़ी समस्या को काफी हद तक हल कर लिया गया है। मांग से संबंधित पक्ष में हस्तक्षेप जनता के बीच जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है। वित्तीय समावेशन को सतत आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साक्षरता, ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण इसके केंद्र में रखा गया है। वित्तीय साक्षरता में सुधार की दिशा में हाल में दो पहल की गई हैं- नियामकों द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना का कार्यान्वयन।

भुगतान प्रणालियों को किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन-रेखा के रूप में देखा जाता है। वित्तीय समावेशन को हासिल करने और आर्थिक लाभ को पिरामिड के निचले भाग तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के एक साधन के रूप में उनकी पहचान बढ़ती जा रही है। यह अब सबको भली-भांति ज्ञात हो चुका है कि भारत विश्व के उन अग्रणी देशों में शामिल है जिनके पास अत्याधुनिक भुगतान संबंधी बुनियादी ढांचे और उत्पाद हैं, जिससे डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाया जा सके। उदाहरण के लिए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई)⁴ की संख्या में 53 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से वृद्धि हुई है और यह मई 2017 में रहे 41 करोड़ से बढ़कर मई 2021 में 226 करोड़ हो गई। इन प्रवृत्तियों से संकेत मिलता है कि ऐसे उपकरण छोटे मूल्य भुगतान लिए बेहद लोकप्रिय हुए हैं।

तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) जैसी त्वरित भुगतान प्रणालियों की शुरुआत से डिजिटल भुगतान में और तेजी आयी क्योंकि ये लाभार्थियों को तत्काल क्रेडिट प्रदान करती हैं और चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं। डिजिटल पहुंच की सीमा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जून 2021 के दौरान औसतन प्रत्येक दिन भारत में भुगतान प्रणाली से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये प्रतिदिन की राशि के 15 करोड़ से अधिक लेनदेन किए गए। भारत के भुगतान

⁴ मई 2021 तक, 91% पीपीआई वॉलेट और शेष कार्ड के रूप में था।

परिवृश्य में स्मार्टफोन के यूपीआई प्लेटफॉर्म माध्यम से दी जा रही भुगतान लेनदेन की सुविधा ने क्रांति ला दी है। जून 2021 में यूपीआई से 280 करोड़ से अधिक लेनदेन किए गए। विश्व स्तर पर, यूपीआई के प्रति अच्छा रुझान देखा गया है। इसी प्रकार, आधार सक्षम भुगतान सेवाएं (ईपीएस), आधार प्रमाणीकरण के उपयोग से माइक्रो-एटीएम और बीसी के माध्यम से निधि अंतरण/ भुगतान और नकद निकासी की सुविधा प्रदान करती हैं। महामारी के दौरान, माइक्रो-एटीएम के माध्यम से बीसी आउटलेट्स पर नकद लेनदेन में उल्लेखनीय बढ़त देखी गई, जिसमें वर्ष 2020-21 के दौरान 2.25 लाख करोड़ रुपये⁵ के 94 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए।

महामारी से निपटने के उपाय

भारत में, महामारी की दूसरी लहर ने जीवन और आजीविका दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में शुरू हुई बहाली अप्रैल-मई 2021 में महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित हुई। वित्तीय समावेशन की दिशा में हमारे प्रयासों ने सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा कमजोर वर्गों को निर्बाध और समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद की है।

जेएम ट्रिनिटी के घटकों में से एक महत्वपूर्ण घटक- आधार, विश्व की सबसे बड़ी पहल है जो बायोमेट्रिक पहचान प्रदान करती है। इसने अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान की है। एनएसीएच-आधार पेमेंट ब्रिज (एपीबी) प्रणाली और पीएमजेडीवाई ने मिलकर उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं के प्रभावी उपयोग को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो महामारी के दौरान सामने आई थी। क्योंकि इनके माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इन खातों में नकद लाभ दिए गए। आज की तारीख में लगभग 42.59 करोड़⁶ पीएमजेडीवाई खाताधारक हैं जिनमें 55 प्रतिशत से अधिक खाताधारक महिलाएं हैं। डीबीटी में डिजिटल भुगतान के प्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के

दौरान 5.53 लाख करोड़ रुपये का डिजिटल अंतरण 54 मंत्रालयों की 319 सरकारी योजनाओं के लिए किया गया।

कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों के वित्तीय प्रभाव को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने जरूरतमंद वर्गों को ऋण प्रवाह की लागत सस्ती करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। इन उपायों में नीति दर को कम करना, मांग के अनुसार चलनिधि योजनाओं की शुरुआत और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से चलनिधि का सुव्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित करना तथा वित्तीय संस्थानों को व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के तनावग्रस्त ऋणों को हल करना शामिल हैं। नए एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट संवितरण पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) छूट; एनबीएफसी को ऑन-लेंडिंग के लिए बैंक ऋण हेतु पीएसएल वर्गीकरण और ऑन-लेंडिंग के लिए लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) से माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफएल) को ऋण हेतु पीएसएल वर्गीकरण जैसे प्रभावित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, समावेशी विकास पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने पिछले वर्ष पीएसएल के दायरे को विस्तृत किया, जिसके तहत (क) स्टार्ट-अप को शामिल किया गया; (ख) अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को उधार देने की सीमा में वृद्धि की गई; (ग) छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाया गया; और (घ) बैंकों को अपेक्षाकृत कमतर ऋण व्यापन वाले जिलों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

महामारी ने, डिजिटल भुगतानों की अधिक व्यापक स्वीकार्यता के साथ-साथ, डिजिटलीकरण की गति को तीव्रतर कर दिया है। यह आवश्यक है कि वृहत्तर डिजिटलीकरण को वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों में समामेलित करने के लिए कदम उठाए जाएं। भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) का परिचालन- बैंकों और कार्ड नेटवर्कों के साथ आरबीआई की एक पहल- टियर-3 से 6 केन्द्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में भुगतान स्वीकृति अवसंरचना के विकास के लिए आवश्यक गति प्रदान करेगा। यह इन अनछुए इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकृति सुविधाओं (उदाहरण के लिए- पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस) के अधिकाधिक संस्थापन को सुगम बनाएगा और इस प्रकार डिजिटल भुगतान व्यवस्था की पहुँच और अधिक बढ़ेगी।

⁵ https://m.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=20366 - FY 2020-21

⁶ <https://pmjdy.gov.in/>

इसी प्रकार, प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में कम से कम एक जिले को शत प्रतिशत डिजिटली सक्षम बनाने हेतु, 2019 में 42 जिलों में बैंकों के साथ मिलकर आरंभ की गई रिजर्व बैंक की अग्रणी परियोजना, आम आदमी द्वारा डिजिटल भुगतानों की अधिकाधिक पहुँच और उपयोग को सुगम बनाएगी। मार्च 2021 तक बैंकों ने व्यक्तियों के मामले में 95.9 प्रतिशत और कारोबारों के मामले में 89.8 प्रतिशत डिजिटल कवरेज⁷ हासिल कर ली है। एसएलबीसी को निर्देश दिये गए हैं कि इन चिन्हित जिलों में डिजिटल प्रगति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नए फोकस और बल के साथ कार्य करें। इसके अलावा, एनएसएफआई के अंतर्गत, 'वित्तीय सेवाओं तक सर्वव्यापी पहुँच' को प्रोत्साहित करने के लिए, पहाड़ी इलाकों में 5 किमी के दायरे/500 परिवारों वाले 99.9 प्रतिशत लक्षित गाँवों में बैंकिंग आउटलेट के किसी न किसी रूप की पहुँच प्रदान की गई है।

विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने पर लगाए गए महामारी संबंधी प्रतिबंधों ने परंपरागत वित्तीय साक्षरता शिविरों पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता पैदा कर दी है। महामारी के दौरान, वित्तीय शिक्षण के प्रसार को जारी रखने के लिए पूरे देश में वैकल्पिक उपायों यथा- सोशल मीडिया, मास मीडिया (स्थानीय टीवी चैनल और रेडियो सहित) का रास्ता तेजी से अपनाया गया।

महामारी के बाद की दुनिया : आगे की राह

महामारी के बाद रिकवरी को अधिक समावेशी और सतत बनाए रखने के लिए, वित्तीय समावेशन हमारी नीतिगत प्राथमिकता बना रहेगा। अंतिम मील तक की दूरी पाटने में माइक्रोफाइनेन्स की अनुपूरक भूमिका को देखते हुए, माइक्रोफाइनेन्स क्षेत्र में विभिन्न विनियमित उधारदाताओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्कों को सुसंगत बनाने के वास्ते हाल ही में एक परामर्शी दस्तावेज जारी किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य माइक्रोफाइनेन्स उधारकर्ताओं की अति-ऋणग्रस्तता से

⁷ डिजिटली सक्षम/परिव्याप्त व्यक्तियों और कारोबारों की गणना कैसे सक्रिय बचत खातों और पात्रता-प्राप्त सक्रिय चालू/कारोबारी खातों पर विचार करते हुए की गई है, जो कम से कम एक डिजिटल भुगतान माध्यम (यथा- एटीएम/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ईपीएस, यूपीआई/यूसएएसडी, पीओएस, क्यूआर) से जुड़े हुए हैं।

संबंधित चिंताओं को दूर करना; ब्याज दरों को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए बाजार प्रणाली को सक्षम बनाना; और ऋण लागत की पारदर्शिता को बढ़ाकर सुविचारित निर्णय लेने के लिए उधारकर्ताओं को सशक्त बनाना है।

पूरे देश में मार्च, 2024 तक प्रखण्ड स्तर पर सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरसी (सीएफएल) प्रोजेक्ट के पहुँच जाने से आशा है कि वृहत्तर वित्तीय साक्षरता के लिए सामुदायिक नेतृत्व वाले सहभागी दृष्टिकोण की प्रभावोत्पादकता बढ़ेगी। साथ ही, वित्तीय साक्षरता की अवधारणाओं को कम उम्र में ही मन में बैठा लेने के महत्व को पहचानते हुए, स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता सामग्री को समाहित करना- वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-25 (एनएसएफआई) के रणनीतिक लक्ष्यों में से एक है। अब तक 15 राज्यों के शैक्षणिक बोर्डों ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल शामिल किए हैं। ऐसी अपेक्षा है कि ये सारे दृष्टिकोण जमीनी स्तर पर वित्तीय शिक्षण को मजबूत करेंगे, जिससे एनएसएफआई द्वारा प्रतिपादित वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण का स्वप्न साकार हो सकेगा।

देश में वित्तीय समावेशन का दायरा मापने के लिए, एक 'वित्तीय समावेशन सूचकांक' (एफआई इंडेक्स) बनाने और एक निश्चित अंतराल पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। इस सूचकांक में वित्तीय समावेशन के तीन आयामों के लिए मानदंड होंगे- पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता। एफआई इंडेक्स पर काम चल रहा है और आरबीआई द्वारा शीघ्र ही इसे प्रकाशित किया जाएगा।

निष्कर्ष

चूंकि मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, मैं यह बात दोहराना चाहता हूँ कि वित्तीय समावेशन समावेशी संवृद्धि को बढ़ावा देता है क्योंकि इससे पिरामिड के निचले स्तर तक ऋण और अन्य सुरक्षा उपायों समेत वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध हो पाती हैं। अतीत में मिली सीखें और कोविड-19 महामारी के दौरान अर्जित अनुभव स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि वित्तीय समावेशन और समावेशी संवृद्धि, वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करते हैं। सुदृढ़ उपभोक्ता सुरक्षा प्रणालियों के साथ, वृहत्तर वित्तीय साक्षरता और शिक्षण यह सुनिश्चित करेंगे कि पिरामिड के निचले स्तर तक के लोग सुविचारित वित्तीय निर्णय लेने में सशक्त हुए हैं। यह बैंकों,

एनबीएफसी, एमएफआई आदि को भी अपने ग्राहक-आधार और उत्पाद को बढ़ाने और अपने तुलनपत्र को विस्तृत करने में सक्षम बनाएगा।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि सबके समृद्ध भविष्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वृहत्तर वित्तीय समावेशन के हमारे प्रयासों को अनिवार्यतः जारी रखा जाए। बैंक खातों की सर्वव्यापी पहुँच और इसके साथ-साथ ऋण, निवेश, बीमा और पेंशन से संबंधित वित्तीय उत्पादों तक सुलभ पहुँच को और अधिक तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना सभी हितधारकों का दायित्व

है कि वित्तीय पारिस्थितिकी (डिजिटल माध्यम सहित) समावेशी हो और उत्पादों की अनुचित बिक्री, साइबर सुरक्षा, डेटा निजता जैसे जोखिमों का समाधान करने तथा समुचित वित्तीय शिक्षण और जागरूकता के जरिये वित्तीय व्यवस्था में भरोसा बढ़ाने में सक्षम हो। इन समस्त प्रयासों को एक सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली से समर्थित भी करना होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस फोरम से रोचक विचार आएंगे, जिनसे देश में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को और गति मिलेगी।

धन्यवाद। नमस्कार।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (करेंसी) - क्या यह पैसे (मनी) का भविष्य है*

टी रबी शंकर

भूमिका

"केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं" (सीबीडीसी) की अवधारणा कोई हाल की बात नहीं है। कुछ लोग सीबीडीसी की उत्पत्ति का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन¹ को देते हैं, जिन्होंने 1980 के दशक में सुझाव दिया था कि संयुक्त राज्य (यूएस) के फेडरल रिजर्व बैंक जनता को ऐसा 'माध्यम' उपलब्ध कराएँ जिसमें जमाराशियों की सुविधा और मुद्रा की सुरक्षा हो। हालांकि, डिजिटल मुद्रा की अवधारणा पर केंद्रीय बैंकों, अर्थशास्त्रियों और सरकारों द्वारा व्यापक चर्चा पिछले दशक में ही जाकर की गई है।

सिवाय करेंसी नोटों के, आधुनिक वित्तीय प्रणाली में कागज के अन्य सभी उपयोगों का स्थान, चाहे वह बॉण्ड, प्रतिभूतियों, लेनदेन, संचार, पत्राचार या संदेश के रूप में हो - अब तत्संबंधी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ले चुके हैं। अपुष्ट साक्ष्यों की मानें तो, हाल के वर्षों में लेन-देन में भी भौतिक नकदी का उपयोग गिरावट पर रहा है, एक प्रवृत्ति जो मौजूदा कोविड 19 महामारी से और मजबूत हुई है। इन घटनाक्रमों के कारण कई केंद्रीय बैंकों और सरकारों ने वैध मुद्रा के डिजिटल संस्करण की खोज के प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय बैंकों के बीच इसको लेकर कुछ रुचि स्थानीय कारणों से भी रही है जिसके द्वारा वे विशिष्ट नीतिगत उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकें - उदाहरण के लिए, ऋणात्मक ब्याज दर मौद्रिक नीति को आगे बढ़ाना। दूसरा कारक है जनता को अभौतिक/आभासी (वर्चुअल) मुद्राएं उपलब्ध कराना है जिसमें निजी अभौतिक (वर्चुअल) मुद्राओं के जायज फ़ायदे भी मिलें और साथ ही निजी मुद्राओं के हानिकारक सामाजिक और आर्थिक परिणामों से बचा जा सके।

* विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित वेबिनार में 22 जुलाई, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री टी रबी शंकर द्वारा दिया गया मुख्य भाषण वक्ता द्वारा व्यक्त विचार निजी हैं।

¹ <https://law.stanford.edu/projects/central-bank-digital-currencies-a-transatlantic-perspective/>

यह जानना और समझना महत्वपूर्ण है कि सीबीडीसी वास्तव में है क्या, और इसके लिए यह समझने की जरूरत है कि मुद्रा (करेंसी) क्या है और पैसा (मनी) क्या है।

करेंसी क्या है?

चलिए पैसे (मनी) से शुरू करते हैं। शिकार करने वालों और जुटाने वालों के स्तर से समाज जैसे-जैसे आगे बढ़ा, भौतिक आवश्यकताएं बढ़ीं, - घर बनाना, कपड़े पहनना, हथियार और औजार बनाना आदि। चूँकि इन आवश्यकताओं का उत्पादन व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जा सकता था, इसलिए लोगों को इन्हें दूसरों से खरीदना पड़ता था। इनका भुगतान शुरू में वस्तु-विनिमय द्वारा किया गया - एक भाले के बदले में हो सकता है चमड़े की खाल का लबादा। चूँकि वस्तु विनिमय की अपनी सीमाएं थीं - एक भाले के बदले कितने लबादे - वस्तु विनिमय को धातुओं या कौड़ी के संदर्भ में मानकीकृत किया गया था। अब लोग लबादे और भाले दोनों का मूल्य कांसे या कौड़ी के संदर्भ में जानने लगे। अभी भी यह वस्तु विनिमय ही था, क्योंकि कांसे और कौड़ी दोनों का अपना अंतर्भूत मूल्य था (कौड़िया अपनी सुंदरता के लिए वांछित थीं)। यह प्रणाली समय के साथ धातु मुद्राओं में विकसित हुई। सोने और चाँदी के सिक्के इस प्रणाली का प्रस्फुटन थे जिनमें वस्तु विनिमय (सोने और चाँदी दोनों का अंतर्भूत मूल्य था) के साथ पैसे (वे मूल्य को मानक रूप में दर्शाते थे) की भी विशेषताएं थीं। इस विकास क्रम में लोगों ने सुधार किया - वस्तु विनिमय के लिए वास्तविक वस्तुओं के बजाय उन्होंने वस्तुओं पर दावों का उपयोग करना शुरू कर दिया, वास्तव में एक विनिमय पत्र। ये मेसोपोटामिया की मिट्टी वाली पट्टियां होंगी या कागजी मुद्रा होंगी जैसी ग्यारहवीं शताब्दी में चीन में देखी गई।

पैसे (मनी) के संबंध में ऐतिहासिक रूप से दो तथ्य उभरते हैं।

- (i) पैसे ने या तो वस्तुओं (जिनका अंतर्भूत मूल्य है) या ऋण साधनों (डेट इन्सट्रूमेंट) का रूप ले लिया है। जब पैसे का अंतर्भूत मूल्य नहीं होता है, तो जरूरी है कि यह उन आंतरिक मूल्य वाली वस्तुओं या अन्य ऋण साधनों के अधिकार का प्रतिनिधित्व करे। कागजी मुद्रा (पेपर करेंसी) इसी प्रकार का एक प्रतिनिधि पैसा (मनी) है और मूलतः एक ऋण साधन (डेट इन्सट्रूमेंट) है। मुद्रा (करेंसी) का स्वामी जानता है कि कौन उसका देनदार

है या अंतर्निहित देयता किसकी है। प्रतिनिधि पैसे (मनी) का एक जारीकर्ता हमेशा होता है।

- (ii) पैसा आमतौर पर किसी शासक/ सरकार (सॉवरिन) द्वारा जारी किया जाता है। निजी स्तर पर धन (मनी) का निर्गम - चाहे सरकारी लाइसेंस के तहत या अन्य प्रकार से हो - अतीत में रहा है, लेकिन समय के साथ दो कारणों से इसके स्थान पर सरकारी (सॉवरिन) ने ले लिया है। सबसे पहले, एक ऋण निर्गम होने के कारण, निजी धन (मनी) की अहमियत उतनी ही होती है जितनी जारीकर्ता की साख (क्रेडिट)। परिभाषा के अनुसार, जारीकर्ता कई हो सकते हैं। यह बात निजी मुद्रा (प्राइवेट करेंसी) को अस्थिर बनाती है। दूसरी ओर, सार्वजनिक मुद्रा (पब्लिक करेंसी), के पीछे चूंकि सरकार (सॉवरिन) होती है, हर अर्थव्यवस्था के लिए यह अलग होती है और इसकी क्रेडिट स्थिति (स्टैंडिंग) बेहतर होती है; इसलिए, यह अधिक स्थिर है। दूसरे, कागजी मुद्रा में सिक्का ढलाई/कागज छपाई लाभ (सीनियोरिज) शामिल है - आंतरिक मूल्य और प्रतिनिधि मूल्य के बीच का अंतर जो जारीकर्ता को प्राप्त होता है। यह सिक्का ढलाई/कागज छपाई लाभ (सीनियोरिज) किसी निजी (प्राइवेट) व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। यह सरकार को जाना चाहिए और इस प्रकार इसका उपयोग सार्वजनिक खर्च के लिए होना चाहिए।

अब हम मुद्रा की परिभाषा देने की स्थिति में हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में, मुद्रा (करेंसी) धन (मनी) का एक रूप है जो विशेष रूप से सरकार (या इसके प्रतिनिधि के रूप में एक केंद्रीय बैंक) द्वारा जारी किया जाता है। यह जारी करने वाले केंद्रीय बैंक (और सरकार) की देयता है और धारक जनता की आस्ति है। मुद्रा (करेंसी) आधिकारिक आदेश है, यह वैध मुद्रा (लीगल टेंडर) है। करेंसी आमतौर पर कागज (या पॉलीमर) के रूप में जारी की जाती है, लेकिन मुद्रा का रूप (फॉर्म) इसकी निर्धारक विशेषता नहीं है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा क्या है?

करेंसी (मुद्रा) को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी देयता के रूप में परिभाषित करने के बाद, अब हम सीबीडीसी को परिभाषित करने की स्थिति में हैं। **एक केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी वैध मुद्रा सीबीडीसी है। यह आधिकारिक या वैध (फिएट) मुद्रा जैसी है और फिएट मुद्रा के साथ एक-के-बदले दूसरे के रूप में इसका विनिमय किया जा सकता है। केवल उसका रूप भिन्न है।**

8. यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि सीबीडीसी क्या नहीं है। सीबीडीसी एक डिजिटल या अभौतिक/आभासी (वर्चुअल) मुद्रा है, लेकिन पिछले एक दशक में पनप आई निजी अभौतिक (वर्चुअल) मुद्राओं से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। पैसे की ऐतिहासिक अवधारणा और निजी अभौतिक मुद्राओं में काफ़ी अंतर है। वे वस्तु नहीं हैं और न ही वस्तुओं पर दावे क्योंकि उनका अपना कोई अंतस्थ मूल्य नहीं है; कुछ दावे कि वे स्वर्ण के समान हैं स्पष्टतः अवसरवादी प्रतीत होते हैं। सामान्यतः, अभी जो सबसे लोकप्रिय हैं, उनके बारे में यह पक्का है कि वे किसी भी व्यक्ति के ऋण या देयताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कोई जारीकर्ता नहीं है। जिस तरह इस शब्द (पैसा (मनी)) को ऐतिहासिक रूप में समझा गया है, उस अर्थ में ये पैसे (मनी) नहीं हैं (और मुद्रा (करेंसी) तो बिलकुल नहीं)।

एक तर्क जिसने निजी आभासी मुद्राओं को कुछ हद तक वैधता हासिल करने में मदद की है, वह यह है कि आधुनिक समाजों में अधिकांश पैसा वास्तव में पहले से ही निजी है क्योंकि वे निजी बैंकों की जमाराशि देयताएं (डिपॉजिट लायबिलिटीज़) दर्शाते हैं। ऐसे दो कारक हैं जिन पर आसानी से पर्दा डाल दिया जाता है। एक, मुद्रा के सरकारी (सॉवरिन) जारीकर्ता (आमतौर पर केंद्रीय बैंक) के लाइसेंस के तहत, बैंक जमाराशि जारी करते हैं। दो, जनता द्वारा जमाराशियां केवल इसलिए स्वीकार की जाती हैं कि वे एक के साथ एक संप्रभु मुद्रा में परिवर्तनीय हैं। अंतर को समझने का एक सरल तरीका यह है कि जमाराशियों को जनता द्वारा बैंकों को ब्याज पर दिया गया उधार समझा जाए जो सरकारी मुद्रा (सावरिन करेंसी) के रूप में दिया गया है (इसका विपरीत पक्ष ऋण (क्रेडिट), बैंकों द्वारा जनता को ब्याज पर सावरिन करेंसी का उधार देना हुआ)। बैंक जमाराशियां धन (मनी) हैं जरूर, लेकिन सरकारी प्राधिकार और इससे जुड़े जनता के विश्वास से अलग करने पर धन के रूप में उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। चाहे जो हो, बैंक जमाराशियां निजी मुद्राओं से बहुत अलग हैं (ए) जिनका कोई जारीकर्ता नहीं है, और (बी) जो एक के साथ एक सरकारी मुद्रा (सावरिन करेंसी) में परिवर्तनीय नहीं हैं।

संक्षेप में, सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा के समान है लेकिन कागज (या पॉलीमर) से अलग रूप में। यह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में संप्रभु/सरकारी मुद्रा (सावरिन करेंसी) है और यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर देयता (संचलन में मुद्रा) के रूप में दिखाई देगी। सीबीडीसी से जुड़ी तकनीक, रूप और उपयोग को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जा सकता है। सीबीडीसी सममूल्य पर नकद से विनिमय होनी चाहिए।

एक ओर सीबीडीसी में रुचि अब लगभग सार्वभौमिक है, वहीं बहुत कम देश हैं जो अपनी सीबीडीसी को लॉन्च करने के प्रायोगिक चरण (पायलट स्टेज) तक भी पहुँच पाए हैं। केंद्रीय बैंकों के 2021 बीआईएस सर्वेक्षण में पाया गया कि सीबीडीसी की संभावना पर 86% सक्रिय रूप से शोध में लगे थे, 60% प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग कर रहे थे और 14% पायलट परियोजनाएं लगा रहे थे। अचानक यह दिलचस्पी क्यों? सीबीडीसी को अपनाया निम्नलिखित कारणों से उचित ठहराया गया है: -

- (i) कागजी मुद्रा के घटते उपयोग का सामना कर रहे केंद्रीय बैंक मुद्रा के एक अधिक स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं (स्वीडेन की तरह);
- (ii) भौतिक नकद के अधिक उपयोग वाले क्षेत्र जो निर्गमन को और अधिक कुशल बनाना चाहते हैं (जैसे डेनमार्क, जर्मनी, या जापान या यहाँ तक कि अमेरिका);
- (iii) केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के लिए जनता की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, जैसा कि निजी आभासी मुद्राओं के बढ़ते उपयोग में जाहिर हो रहा है, और इस प्रकार ऐसी निजी मुद्राओं के अधिक हानिकारक परिणामों से बचना चाहते हैं।

इसके अलावा, अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों की तुलना में सीबीडीसी कुछ फायदे एकदम साफ हैं - सीबीडीसी के प्रयोग से होने वाले भुगतान अंतिम/समापक (फाइनल) होते हैं और इस प्रकार वित्तीय प्रणाली में निपटान जोखिम को कम करते हैं। एक यूपीआई प्रणाली की कल्पना करें जहां बैंक शेषराशियों के बजाय सीबीडीसी का लेन-देन किया जाता है, जैसे कि नकद सौंप दिया गया हो - अंतरबैंक निपटान की आवश्यकता ही समाप्त। संभावना है कि सीबीडीसी भुगतान प्रणालियों के अधिक तत्काल और किफायती वैश्वीकरण में सहायक हो। एक भारतीय आयातक द्वारा बिना किसी बिचौलिए के, अपने अमेरिकी निर्यातक को डिजिटल डॉलर में तत्काल आधार पर भुगतान करने की बात सोची जा सकती है। यह लेन-देन अंतिम/समापक (फाइनल) होगा, जैसे कि नकद डॉलर सौंपे जाते हैं, और निपटान के लिए यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम खुला होना भी जरूरी नहीं होगा। मुद्रा निपटान (करेंसी सेटलमेंट) में समय क्षेत्र (टाइम ज़ोन) का अंतर अब कोई मायने नहीं रखेगा - कोई 'हस्टैंट' जोखिम नहीं होगा।

पिछले पैराग्राफ में सीबीडीसी जारी करने के फायदे पर संक्षिप्त चर्चा भारत द्वारा सीबीडीसी जारी करने का औचित्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो सकती है, हालांकि वैश्विक निपटान के लाभ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है कि मुद्रा लेनदेन में शामिल दोनों देशों के पास सीबीडीसी सुव्यवस्थित रूप में हो। तथापि, आइए इसे स्वयं भारत के दृष्टिकोण से देखें।

डिजिटल भुगतान संबंधी नवोन्मेषों के मामले में भारत दुनिया की अगुवाई कर रहा है। इसकी भुगतान प्रणालियां खुदरा और थोक दोनों ग्राहकों के लिए 24X7 उपलब्ध हैं, काफी हद तक तत्काल हैं, लेनदेन की लागत दुनिया में शायद सबसे कम है, उपयोगकर्ताओं के पास लेनदेन करने के विकल्पों का एक अच्छा-खासा मेनू है और डिजिटल भुगतान में 55% के प्रभावशाली सीएजीआर पर (पिछले पांच वर्षों में) वृद्धि हुई है। यूपीआई जैसी दूसरी भुगतान प्रणाली खोजनी मुश्किल होगी जो एक रुपये के लेनदेन की अनुमति देती हो। डिजिटलीकरण की प्रगति जब इतनी प्रभावशाली हो, क्या सीबीडीसी के लिए कोई आधार बनता है?

15. दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के बीच छह शहरों में व्यक्तियों की खुदरा भुगतान की आदतों पर रिजर्व बैंक द्वारा किया गया एक पायलट सर्वेक्षण, जिसके परिणाम अप्रैल, 2021 में प्रकाशित किए गए थे, बताता है कि भुगतान के तरीके के रूप में और नियमित खर्चों के लिए धन प्राप्त करने के लिए नकद पसंदीदा बना हुआ है। छोटे मूल्य के लेनदेन (₹500 तक की राशि के वाले) के लिए प्रधानतः नकद का उपयोग किया जाता है।

इस प्रकार देश में डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रसार के साथ-साथ विशेषतः छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए नकद के प्रयोग में बनी हुई रुचि का एक अनूठा परिदृश्य है। नकदी को दी जा रही तरजीह जिस हद तक डिजिटल भुगतान के तरीकों को लेकर असहजता के चलते है, वहाँ तक सीबीडीसी द्वारा नकद प्रयोग का स्थान लेने की संभावना नहीं है। लेकिन उदाहरण के रूप में बात करें तो नकदी को इसकी अनामिता (एनोनिमिटी) के लिए दी जा रही तरजीह को सीबीडीसी की स्वीकृति की ओर मोड़ा जा सकता है, जब तक कि अनामिता सुनिश्चित रहे।

भारत की उच्च मुद्रा जीडीपी अनुपात में सीबीडीसी का एक और लाभ है। बड़े पैमाने पर नकद के हो रहे प्रयोग के स्थान पर सीबीडीसी को जितना लाया जा सकेगा, मुद्रा की छपाई, परिवहन,

भंडारण और वितरण की लागत को उतना ही कम किया जा सकता है।

निजी आभासी मुद्राओं (वीसी) का आगमन इस बात का एक और कारण हो सकता है कि क्यों सीबीडीसी आवश्यक हो जाएं। यह स्पष्ट नहीं है कि ये निजी वीसी किस आवश्यकता विशेष को पूरा करती हैं जिसे आधिकारिक धन ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन अपने आप में वह उनके अपनाए जाने के रास्ते में नहीं भी आ सकता है। यदि इन वीसी को मान्यता मिल जाती है, तो सीमित परिवर्तनीयता वाली राष्ट्रीय मुद्राएं खतरे में आ सकती हैं। इतना तो है कि, यूएस डॉलर जैसी पूर्णतः परिवर्तनीय मुद्राएं, हो सकता है, प्रभावित न हों क्योंकि इनमें से अधिकांश वीसी यूएस डॉलर में मूल्यवर्गित हैं। वास्तव में, जैसा कि रैंडल क्वाल्स² का तर्क है, हो सकता है ये वीसी यूएस डॉलर के प्रयोग को प्रोत्साहित करें। अपनी स्वयं की सीबीडीसी को विकसित करने से, संभव है, जनता को वे उपयोगिताएं मिल जाएं जो कोई निजी वीसी दे सकती है और उस हद तक रुपये के लिए लोगों की पसंद को बरकरार रखा जा सकता है। हो सकता है कि इससे जनता को उस असामान्य अस्थिरता भी बचाया जा सके जिसका इनमें से कुछ वीसी अनुभव करते हैं। वास्तव में, यह केंद्रीय बैंकों को सीबीडीसी को डिजिटल मुद्रा का एक सुरक्षित और स्थिर रूप मानने में प्रमुख कारक हो सकता है। जैसा कि ईसीबी के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने बीआईएस वार्षिक रिपोर्ट में कहा है "... केंद्रीय बैंकों का कर्तव्य है कि वे हमारे पैसे (मनी) में लोगों के विश्वास की रक्षा करें। डिजिटल मुद्राओं की पड़ताल को दिशा देने के लिए केंद्रीय बैंकों को अपने घरेलू प्रयासों को घनिष्ठ सहयोग के साथ बढ़ाना चाहिए ताकि विश्वसनीय सिद्धांतों को चिह्नित और नवोन्मेष को प्रोत्साहित किया जा सके।"

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए सीबीडीसी का आधार इस प्रकार स्पष्ट है - भुगतान प्रणालियों में सीबीडीसी न केवल अपने द्वारा सृजित लाभों के लिए वांछनीय हैं, बल्कि अस्थिर निजी वीसी के परिवेश में आम जनता के संरक्षण के लिए भी आवश्यक हो सकते हैं।

सीबीडीसी, अपने उपयोग की सीमा के आधार पर, बैंक जमा के लिए लेनदेन संबंधी मांग में कमी ला सकता है। चूंकि सीबीडीसी में किए गए लेनदेन से निपटान जोखिम भी घटते हैं, वे लेनदेन के

निपटान के लिए तरलता/चलनिधि की जरूरतों को कम करते हैं (जैसे अंतर्दिवसीय चलनिधि)। इसके अलावा, बैंक जमाराशियों के लिए एक वास्तविक रूप से जोखिम मुक्त विकल्प प्रदान करके वे बैंक जमाराशियों को हटा (शिफ्ट कर) सकते हैं जिसके फलस्वरूप जमा पर सरकारी गारंटी की आवश्यकता कम हो सकती है (डायसन और हॉजसन, 2016)।

साथ ही बैंकों की मध्यस्थता में कमी के अपने जोखिम हैं। यदि समय के साथ बैंक जमा राशि खोने लगे, तो ऋण सृजन की उनकी क्षमता बाधित हो जाती है। चूंकि केंद्रीय बैंक निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए यह अच्छी तरह से समझना आवश्यक है कि बैंक ऋण की भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, चूंकि बैंक कम लागत वाले लेन-देन जमाराशियों की बड़ी मात्रा खो देते हैं, उनका ब्याज मार्जिन दबाव में आ सकता है जिससे ऋण (क्रेडिट) की लागत में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार, मध्यस्थता की संभावित लागत का अर्थ हुआ कि सीबीडीसी को इस तरह से बनाना और कार्यान्वित करना महत्वपूर्ण है जिससे बैंक जमा और सीबीडीसी की मांग साथ-साथ संभालने लायक हो।

सीबीडीसी का एक और जोखिम है जो महत्वपूर्ण हो सकता है। सीबीडीसी के होने से किसी भी बैंक पर दबाव की स्थिति में जमाकर्ताओं के लिए शेषराशियां (बैलेस) निकालना आसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में जमाराशियों का पलायन नकद निकासी की तुलना में बहुत तेजी हो सकता है। दूसरी ओर, सीबीडीसी की महज उपलब्धता भयजनित 'आहरण भगदड़' (पैनिक 'रन') को कम कर सकती है क्योंकि जमाकर्ताओं को पता है कि वे जल्दी निकाल सकते हैं। एक परिणाम यह हो सकता है कि बैंकों को बड़े स्तर की तरलता रखने को प्रेरित हों जिसके वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिलाभ (रिटर्न) घट सकते हैं।

वास्तव में, बैंक जमा की तुलना में सीबीडीसी के लाभों के बावजूद, चूंकि सीबीडीसी मुद्रा होने के कारण ब्याज का भुगतान नहीं करते, बैंक जमा पर वास्तव में उनका प्रभाव सीमित हो सकता है। जिन जमाकर्ताओं को लेन-देन के लिए सीबीडीसी की आवश्यकता होती है, वे दिवसांत शेष राशियों को ब्याज-अर्जक जमा खातों में स्वीप कर सकते हैं।

सीबीडीसी रखने वाले लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। और उस परिवर्तन की प्रकृति क्या होगी, इसका

² <https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/quarles20210628a.htm>

अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि किसी भी केंद्रीय बैंक ने सीबीडीसी लॉन्च नहीं की है। यदि सीबीडीसी की मांग अत्यधिक हो, और सीबीडीसी अधिकांशतः बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से जारी हो, जैसी कि संभावना है, बैंकिंग प्रणाली से मुद्रा रिसाव की भरपाई के लिए अधिक तरलता/चलनिधि (लिक्विडिटी) डालने की आवश्यकता हो सकती है।

हाल ही की चर्चा में एक कारण विशेष से मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के लिए ऋणात्मक ब्याज वाले सीबीडीसी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेहद कम मुद्रास्फीति के परिवेश ने ब्याज दरों को कम करने की उनकी क्षमता को बाधित कर दिया है क्योंकि हटकर (शिफ्ट होकर) नकद की ओर जाने के कारण ऋणात्मक ब्याज दरें प्रभावी नहीं हैं। हालांकि, यदि मुद्रा स्वयं ऋणात्मक ब्याज दर लेकर चले तो मांग को बढ़ावा देने में ऋणात्मक नीतिगत दरों का मौद्रिक संचरण अधिक प्रभावी होगा। इस प्रकार खर्च को बढ़ावा देने के लिए एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण के रूप में सीबीडीसी पर ऋणात्मक ब्याज दर के भुगतान के पक्ष में तर्क का एक कारण बनता है। ऐसे कदमों को सावधानी से उठाने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि ब्याज (धनात्मक या ऋणात्मक) का भुगतान करने वाला कोई भी साधन पूरी तरह से मुद्रा नहीं है।

26. सीबीडीसी परितंत्र के लिए साइबर हमलों का जोखिम वैसा ही हो सकता है जैसी वर्तमान भुगतान प्रणालियों में है। इसके अलावा, कम वित्तीय साक्षरता स्तर वाले देशों में, डिजिटल भुगतान संबंधी धोखाधड़ी में वृद्धि सीबीडीसी में भी फैल सकती है। इसलिए सीबीडीसी व्यवहार करने वाले किसी भी देश के लिए साइबर सुरक्षा के उच्च मानकों और वित्तीय साक्षरता पर समानांतर प्रयासों को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अर्थव्यवस्था में सीबीडीसी का समावेश प्रौद्योगिकी तैयारियों पर भी निर्भर है। जनसंख्या के पैमाने पर डिजिटल मुद्रा प्रणाली का निर्माण उच्च गति वाले इंटरनेट व दूरसंचार नेटवर्क के विकास तथा सीबीडीसी में भंडारण और लेनदेन हेतु आम जनता के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने पर निर्भर है। विकासशील देशों में, प्रौद्योगिकी अंगीकरण का निम्न स्तर सीबीडीसी की पहुँच को सीमित कर सकता है और इस प्रकार वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच के मामले में मौजूदा असमानताएं बढ़ सकती हैं।

28. दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सीबीडीसी को खँगालने में लगे हुए हैं और कुछ देश सीबीडीसी पर अवधारणा/ प्रयोगों (पायलट्स) के प्रमाण भी लेकर आए हैं। आभासी / क्रिप्टो मुद्राओं के विनियमन के लिए नीतिगत व विधिक संरचना की जाँच के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा गठित उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति (नवंबर 2017) ने भारत में सीबीडीसी को आधिकारिक या वैध मुद्रा (फिएट मनी) के डिजिटल रूप के तौर पर प्रस्तुत करने की सिफारिश की थी। अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह, आरबीआई भी काफी समय से सीबीडीसी जारी करने के गुण-दोषों पर विचार कर रहा है।

आम तौर पर, देशों ने थोक और खुदरा क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्य वाले सीबीडीसी लागू किए हैं। आगे चलकर, इन मॉडलों के प्रभाव का अध्ययन करने के बाद, सामान्य प्रयोजन वाले सीबीडीसी की शुरुआत का मूल्यांकन किया जाएगा। आरबीआई वर्तमान में एक चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति की दिशा में काम कर रहा है और उपयोग के मामलों की जाँच कर रहा है जिसे बहुत कम या बिना किसी व्यवधान के लागू किया जा सकता है। जाँच के प्रमुख मुद्दे हैं - (i) सीबीडीसी का दायरा - इनका उपयोग खुदरा भुगतान में किया जाए या थोक भुगतान में भी; (ii) अंतर्निहित तकनीक - उदाहरण के लिए, इसमें वितरित खाताबही (डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर) हो या एक केंद्रीकृत खाताबही, और क्या उपयोग के मामलों के अनुसार प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) चुनी जाए; (iii) प्रमाणीकरण व्यवस्था (वैलिडेशन मेकानिज्म) - टोकन आधारित हो या खाता आधारित, (iv) वितरण संरचना - सीधे आरबीआई द्वारा या बैंकों के माध्यम से जारी किया जाए; (v) अनामिता का स्तर आदि। हालांकि, निकट भविष्य में थोक और खुदरा क्षेत्रों में प्रयोगों का संचालन एक संभावना हो सकती है।

यद्यपि सीबीडीसी अवधारणात्मक रूप से बैंक नोटों से अलग नहीं हैं, सीबीडीसी की शुरुआत के लिए एक समर्थक कानूनी ढाँचे की आवश्यकता होगी क्योंकि मौजूदा कानूनी प्रावधान मुद्रा (करेंसी) के कागजी रूप को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत, बैंक को "... भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक नोटों के निर्गम और आरक्षित निधियों के रखे जाने के विनियमन तथा देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली का देश हित में सामान्य संचालन का अधिकार है।" (प्रस्तावना)। रिजर्व बैंक को आवश्यक वैधानिक शक्तियाँ आरबीआई अधिनियम की विभिन्न

धाराओं से प्राप्त होती हैं - मूल्यवर्ग (धारा 24), बैंक नोटों का स्वरूप (धारा 25), विधिमान्य मुद्रा (लीगल टेंडर) के रूप में स्थिति (धारा 26(1)) आदि के संबंध में। सिक्का अधिनियम, 2011, फेमा, 1999, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 आदि अन्य अधिनियमों में परिणामी संशोधनों की जांच करने इसकी आवश्यकता है। यद्यपि, सीबीडीसी मुख्यतः तकनीक चालित उत्पाद होंगे, यह वांछनीय होगा कि कानून को तकनीक-निष्पक्ष रखा जाए ताकि विभिन्न प्रकार के तकनीक के चयन को इसमें कवर किया जा सके।

सीबीडीसी शुरू करने में बड़े लाभों की संभावना है, जैसे कि नकदी पर कम निर्भरता, कम लेनदेन लागत के कारण सिक्का ढलाई/कागज छपाई में उच्च लाभ (सीनियोरेज), कम निपटान जोखिम। सीबीडीसी शुरू होने से संभवतः अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित और वैध मुद्रा आधारित भुगतान विकल्प

का मार्ग प्रशस्त होगा। बेशक, इससे जुड़े जोखिम हैं, लेकिन संभावित लाभों की तुलना में ध्यान से उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। भारत के सीबीडीसी की दिशा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आरबीआई का यह प्रयास होगा कि भुगतान प्रणालियों में भारत की अग्रणी स्थिति को पुनः सिद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

आने वाले समय में हर केंद्रीय बैंक के तरकश सीबीडीसी के होने की संभावना है। इसे स्थापित करने के लिए कार्यान्वयन में सावधानीपूर्वक नपे-तुले और बारीकियों पर ध्यान देने वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। योजना स्तर पर विचार विमर्श और हितधारक परामर्श महत्वपूर्ण हैं। तकनीकी चुनौतियों का भी अपना महत्व है। जैसा कि कहा जाता है, हर विचार को अपने समय की प्रतीक्षा करनी होगी। शायद सीबीडीसी का समय समीप है।

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारत में खाद्य मूल्य वर्धन पर कोविड-19 का प्रभाव

टीएलटीआरओ और संरचनात्मक चलनिधि:
एनबीएफसी के लिए एक अनुकूल स्थिति?

लघु वित्त बैंकों का प्रदर्शन - एक प्रारंभिक समीक्षा

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

महामारी की दूसरी लहर की धीमी गति से खत्म होने से पिछले डेढ़ महीने में अर्थव्यवस्था की दिशा बदल गई है। अनलॉक के बाद दबी हुई मांग फिर से बढ़ने से समग्र मांग की स्थिति में तेजी आई है, जबकि मानसून के अपने सामान्य स्तर तक पहुंचने और बुवाई गतिविधि में तेजी आने से आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो रहा है। अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है, इसकी पुष्टि करते हुए विनिर्माण गतिविधि धीरे-धीरे बदल रही है, जबकि सेवाओं में संकुचन कम हुआ है। पर्याप्त सुविधाजनक चलनिधि स्थितियों से प्रेरित वित्तीय स्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं और पुनरुत्थान में सहायक हैं।

भूमिका

अर्थव्यवस्था की स्थिति का यह संस्करण भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शालिवाहन शक के चौथे महीने से मेल खाता है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में आ जाता है। यह बलिदान और उपवास का समय है, और भौतिक कृतियों, विशेष रूप से जल के उत्सव का समय है। यह कोहरे और मधुर फलदायिता की ऋतु है, इसका संगीत वसंत के गीतों घुल जाता है¹। श्रावण के महीने की भावना को ध्यान में रखते हुए, देश भर में प्रमुख फसलों की बुवाई तेज हो गई है, बरसात होने में शुरुआती देरी से बुवाई क्षेत्र में तेजी से कमी आई है; वास्तव में, जुलाई 2021 के अंत तक, बुवाई के तहत सामान्य क्षेत्र को पार कर लिया गया था। सिम्फनी में, ट्रैक्टर की बिक्री महामारी से पहले के स्तर से काफी ऊपर उठ गई है और उर्वरक की बिक्री भी मजबूती से बढ़ी है। ग्रामीण बेरोजगारी कम हो रही है और इसी तरह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम की मांग करने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या भी घट रही है, जो यह दर्शा रहा कि कृषि श्रम के लिए बाजार सीमित हो रहा है क्योंकि कृषि गतिविधि में तेजी

* यह आलेख माइकल देब्रत पात्र, जीबिन जोस, शशिधर एम. लोकरे, राजीव जैन, कुणाल प्रियदर्शी, विनीत कुमार श्रीवास्तव, सार्थक गुलाटी, अभिलाषा, कृष्ण मोहन कुशवाहा, शशिकांत, अभिनंदन बोराड, शोभित गोयल, ऋषभ कुमार, रिज्जेन यांगडोल, सक्षम सूद, अवनीश कुमार, जितेंद्र सोकल, मनु शर्मा, राजस सरॉय, भानु प्रताप, आशीष थॉमस जॉर्ज, देबा प्रसाद रथ और समीर रंजन बेहरा द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को व्यक्त करते हों।

¹ जॉन कीट्स, 1820 की कविता "टू अॉटम" से लिया गया

आ रही है। इसलिए, गरज और बिजली के साथ आर्थिक बहाली का पहला असर दिखने लगा है क्योंकि मानसून तेज हो गयी है।

एक और वृद्धि संवेग वित्तीय बाजारों को प्रदीप्त कर रहा है। वर्ष 2021 भारत के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का वर्ष साबित हो सकता है। भारतीय यूनिकॉर्न द्वारा पहली पेशकश ने घरेलू शेयर बाजारों में आग लगा दी है जो कि गैर-सूचीबद्ध स्टार्ट-अप – फूड डिलिवरी ऐप के शानदार आईपीओ द्वारा शुरु की गई, जिसे 38 बार ओवरसब्सक्राइब किया गया था और वैश्विक निवेशकों में उत्साह पैदा कर दिया है। इसके बाद, भुगतान और वित्तीय सेवा ऐप द्वारा प्रस्तावित 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रस्तावित सूचीकरण भारत के डिजिटलीकरण - डिजिटल भुगतान समाधान; ई-कॉमर्स; लोजीस्टिक्स का परिवेश निवेशकों के उत्साह का प्रतीक है। एक स्पेशियलिटी केमिकल मैनुफैक्चरिंग एक्सपोर्टर का आईपीओ 180 गुना सब्सक्राइब हुआ था। नए जमाने की कंपनियों के ये आईपीओ भारत के संबंध में तेजी के रूप में आते हैं, खासकर भारतीय तकनीक से संबंधित। वास्तव में, मजबूत वैश्विक और घरेलू मांग के साथ भारत के तकनीकी उछाल का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, जिसके लिए माना जाता है कि प्रारंभिक नुकसान के बावजूद विश्व स्तर के कारोबार पाइपलाइन में है, जो बड़े पैमाने पर उनके द्वारा अपनाए गए गहरे छूट वाले व्यापार मॉडल से निकली हैं। ये लिस्टिंग भारतीय कंपनियों द्वारा बाजार का दोहन करने के लिए बड़े पैमाने पर आपाधापी मची है और निवेशकों को आकर्षित करने वाले फोमो (लापता होने का डर) कारक हैं, जिन्होंने बेंचमार्क सूचकांकों को रिपोर्ट में शामिल कर लिया है।

स्पष्ट रूप से एक नए युग की शुरुआत हुई है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 100 यूनिकोर्न्स (क्रेडिट सुइस, 2021²) हैं, जिसमें 2019 में 10 नए, महामारी के बावजूद 2020 में 13 और 2021³ में अब तक एक महीने में 3 बनाए गए हैं। वे विरासत में मिली संपत्ति या बैंक ऋण या अतिरिक्त-कारोबारी कनेक्शन पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि प्रतिभा और नवीन विचारों पर

² 100 यूनिकॉर्न्स: इंडियाज चेंजिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, इंडिया मार्केट स्ट्रेटेजी, क्रेडिट सुइस, 10 मार्च 2021।

³ टाइम्स ऑफ इंडिया, 17 जुलाई 2021।

निर्भर हैं। ये उदारीकरण की उपज हैं, अमीरों की नहीं (अय्यर, 2021⁴)। वास्तव में, बाजार उन्हें 'अवधारणा स्टॉक' के रूप में मानते हैं क्योंकि वे मौजूदा परिपाटी की धज्जियां उड़ाते हैं - उन्होंने न तो लाभ कमाया है और न ही कभी लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए कोई मार्गदर्शन जारी किया है। जाहिर है, इन कारोबारों को महत्व देने के लिए सादे वैनिला वित्तीय मेट्रिक्स के एक स्थापित सेट के बिना, निवेशकों ने दिखाया है कि वे खुले विचार वाले हैं। ये आईपीओ इस मिथक को भी दूर करते हैं कि स्टार्ट-अप को सार्वजनिक बाजार का दोहन करने के लिए भारत से बाहर रहना पड़ता है। स्टार्टअप्स के घरेलू इकोसिस्टम के लिए यह एक बड़ी सकारात्मक प्रगति है। यह घरेलू इक्विटी बाजारों की ताकत, परिपक्वता और पैमाने को प्रदर्शित करता है। यह पहले की तुलना में उद्यम पूंजी में बचत के एक बड़े प्रवाह को प्रोत्साहित करेगा, और रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे, नवाचार और धन को पूंजी उपलब्ध कराएगा। वे युवा भारतीयों को अपने सपनों को पंख देने और पारंपरिक सांचों या जड़ता के घेरे से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

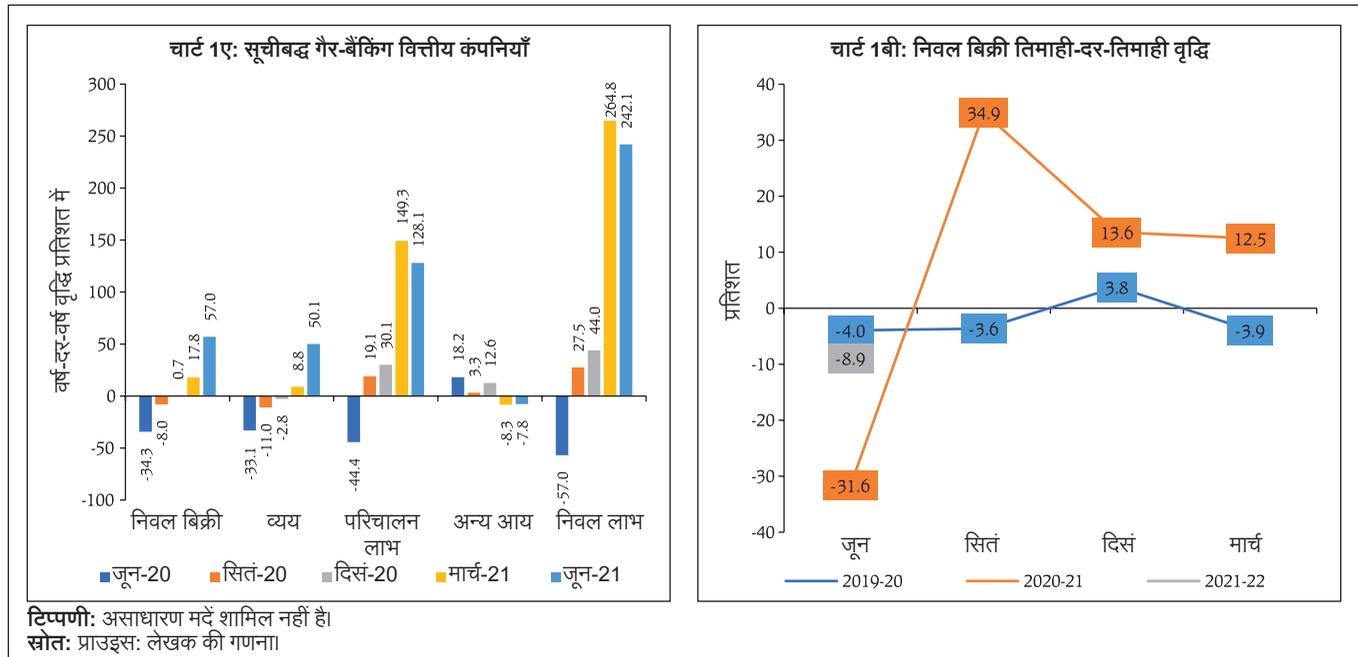
फिर भी, इन कंपनियों में रुचि की यह अचानक वृद्धि केवल तभी जारी रहेगी जब वे कारोबार विकास लागतों को खर्च किए बिना, ब्याज, करों, मूल्यहास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) स्तर से पहले आय के स्तर पर भी नए विचारों और उसके बाद नकदी प्रवाह और मुनाफा को मेट्रिक्स में परिवर्तित करने में सक्षम हों। निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए डेटा और लॉजिस्टिक्स जैसे सहज लाभों का विस्तारित और गतिशील दोहन आवश्यक होगा। फैसला अभी होना है। निवेशक उनकी कहानियों की बारीकी से जांच करेंगे। विश्लेषक इसे शेयर बाजारों के मूर्खतापूर्ण व्यवहार, निवेशकों के लालच और अंधानुकरण प्रभावों के विषय में सोचेंगे, जिसमें लिस्टिंग दिन वाले लाभ की अदूरदर्शी खोज भी शामिल है। वित्तीय स्थिरता के लिए प्रणालीगत जोखिमों की पहले से ही चेतावनियां हैं कि

⁴ स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर, "व्हाइ जॉमैटो आईपीओ इज रिजन फॉर चीयर", *टाइम्स ऑफ इंडिया*, 17 जुलाई 2021।

मौद्रिक नीति प्राधिकारणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि यूनिकॉर्न आईपीओ पार्टि जा रही है (रानडे, 2021⁵)। वर्ष 2001 में डॉटकॉम बुलबुले के फटने से पता चला कि कई स्टार्ट-अप बेकार हो सकते हैं, लेकिन कई नए लोगों पर इस जोखिम को फैलने से रोकने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में बदलाव आया है। और जो बच जाएंगे वे भविष्य के गूगल, फेसबुक और अमेज़न बन सकते हैं।

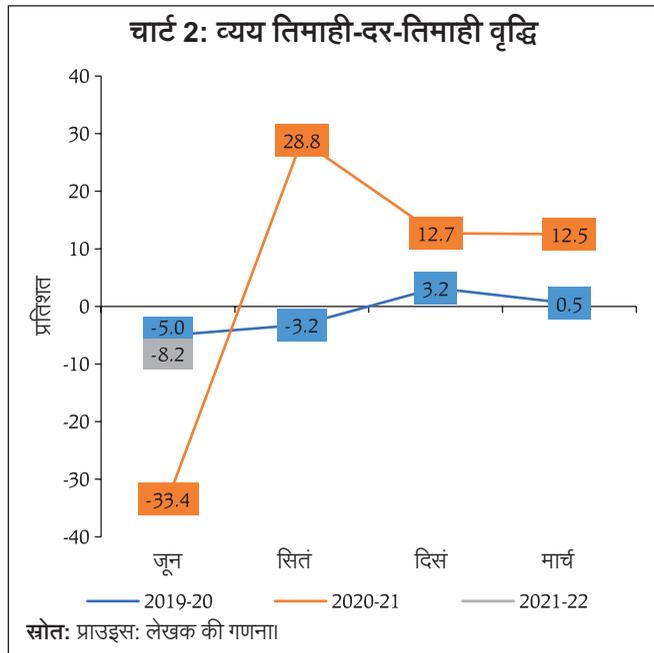
फिर भी अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का एक और संकेत यह है कि जिस तरह से कॉर्पोरेट भारत ने पहली के सापेक्ष महामारी की दूसरी लहर का सामना किया है, 1,427 सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों ने अब तक अपनी आय के परिणाम घोषित किए हैं और भारत में सभी सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में उनकी हिस्सेदारी 86.8 प्रतिशत है। जून 2021 में समाप्त हुई तिमाही के दौरान, इन कंपनियों की निवल बिक्री में वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अप्रैल-जून 2020 में 34 प्रतिशत की गिरावट आई थी, जब पहली लहर आई थी (चार्ट 1ए), उपाख्यानात्मक उच्च-आवृत्ति प्रमाणों के बावजूद ग्रामीण बिक्री पर पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर की बड़ी मार पड़ी। पिछले साल की इसी तिमाही में बड़ी गिरावट के कारण इस साल निवल बिक्री में वर्ष-दर-वर्ष उछाल मूल प्रभावों से भरा हुआ है; हालांकि, क्रमिक आधार (तिमाही-दर-तिमाही) पर भी, जो आधार प्रभावों को कम करता है, इन कंपनियों की निवल बिक्री में लगभग 9 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो एक साल पहले की गिरावट की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है (चार्ट 1बी)। इससे पता चलता है कि दूसरी लहर के कम होने के साथ, मांग सामान्य स्तर की ओर वापस आ रही है, लेकिन भरपाई करने में कुछ और समय लगेगा।

⁵ अजीत रानडे, "मोनेटरी पॉलिसी मस्टनॉट इग्नोर द रिस्क ऑफ ऐन आईपीओ", *मिंट*, 27 जुलाई 2021। इसके बाद, हालांकि, उन्होंने इस घटना को 'बड़ा मील का पत्थर' बताया है। "आफ्टर ए रिलेटिवली एक्स्टेंडेड ड्राउट, इट हैज ब्राउट बैक एकसाइटमेंट इन द इनिशियल पब्लिक ऑफर मार्केट। "द स्ट्रेंज रश एमोंग इंडियन कंपनीज टू लिस्ट अब्रोड," *मिंट*, 12 अगस्त 2021।



इन कंपनियों के व्यय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई और पिछली तिमाहियों (चार्ट 2) की तुलना में तिमाही-दर-तिमाही में कम गिरावट दर्ज की गई, जो घरेलू स्तर पर बढ़ी हुई अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों और लागत दबावों को दर्शाती है। विशेष रूप से, वेतन और वेतन पर खर्च पिछली पांच तिमाहियों में दर्ज की गई वृद्धि से

ऊपर चला गया, जो स्टेप-अप पुनर्नियुक्ति का संकेत है। सभी सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों (सारणी 1) द्वारा भुगतान किए गए कुल भत्ते और वेतन में उच्चतम अनुपात दो क्षेत्रों में सूचीबद्ध कंपनियां, यथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और ऑटो एवं संबद्ध उद्योग का है। तीन शीर्ष आईटी कंपनियों द्वारा काम पर रखने की गतिविधि तेजी से पुनरुद्धार का संकेत दे रही है। इसके विपरीत, ब्याज व्यय में तेजी से गिरावट आई, जो कर्जभार को कम करने के प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट 3)।



व्यय के सापेक्ष बिक्री में तेजी से वृद्धि के साथ, परिचालन और निवल लाभ दोनों में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई और वास्तव में, इस वर्ष अप्रैल-जून में निवल लाभ 250 प्रतिशत के करीब बढ़ गया। इस तिमाही में महामारी की शुरुआत के बाद से डाउनग्रेड के सापेक्ष क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड में सबसे तेज वृद्धि देखी गई। धातु और बुनियादी सामग्री की बंदौलत आगे की कमाई बढ़ रही है, जो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में बहाली गति

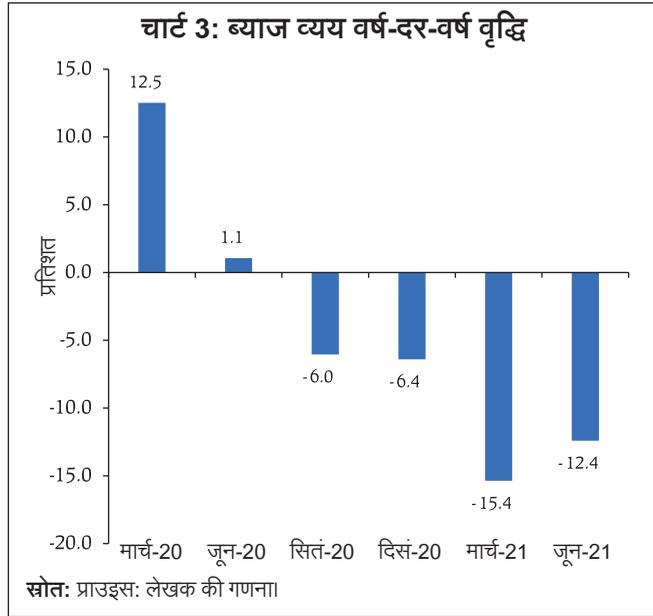
⁶ <https://www.livemint.com/companies/news/tcs-infosys-wipro-to-hire-more-than-1-lakh-freshers-11626423589375.html>

⁷ <https://timesofindia.indiatimes.com/india/your-salary-cuts-and-job-losses-have-resulted-in-this/articleshow/84790072.cms>

सारणी 1: उद्योग-वार भत्ते और वेतन वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)

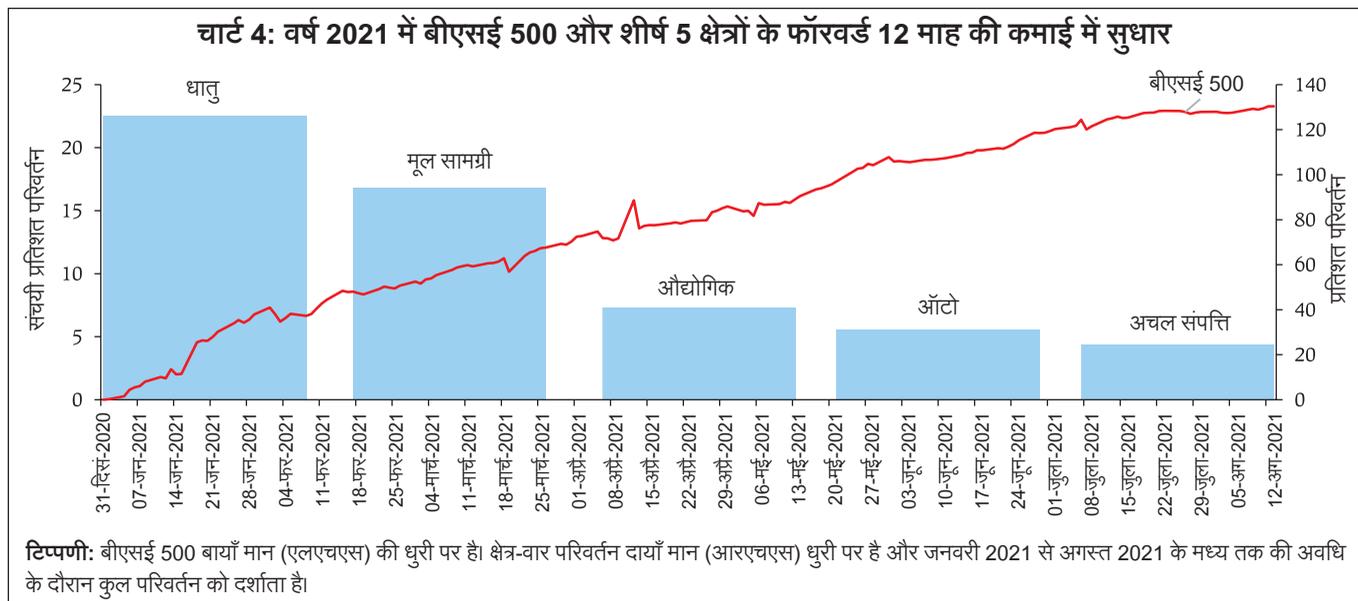
समाप्त तिमाही	ऑटो और सहायक	रसायन	संचार सेवाएँ	निर्माण एवं रियल एस्टेट	निर्माण सामग्री	टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ	एफएनसीजी	होटल एवं टूरिज्म	सूचना प्रौद्योगिकी	मशीनरी	धातु एवं खनन	तेल एवं गैस	दवाइयाँ	ऊर्जा	वस्त्र	परिवहन सेवाएँ	अन्य
मार्च-20	-13.2	14.3	2.5	31.6	2.4	5.6	3.0	0.2	10.5	2.2	-0.5	-3.9	9.2	7.3	2.1	-20.2	8.0
जून-20	-21.1	-0.3	11.3	22.1	-8.5	-13.1	2.6	-34.5	7.3	-11.4	-2.3	-4.1	9.4	7.6	-29.8	-25.5	-4.9
सितं-20	-7.2	5.6	4.6	-2.8	-5.1	-9.1	6.5	-40.2	5.5	-6.7	0.9	10.5	7.8	16.4	-19.2	-23.6	-6.6
दिसं-20	4.7	10.8	13.1	-0.7	2.8	-3.6	9.4	-38.1	6.8	-3.5	14.6	18.9	9.6	10.9	-8.8	-17.4	-2.3
मार्च-21	6.2	5.9	7.3	0.1	7.9	4.1	11.5	-35.1	8.6	0.7	25.3	13.3	4.1	3.6	0.1	-12.1	2.8
जून-21	25.5	16.1	7.4	13.6	15.9	21.5	10.6	4.3	16.4	8.9	22.6	18.6	8.8	11.6	37.7	1.8	13.9

स्रोत: प्राउडिस: लेखक की गणना।

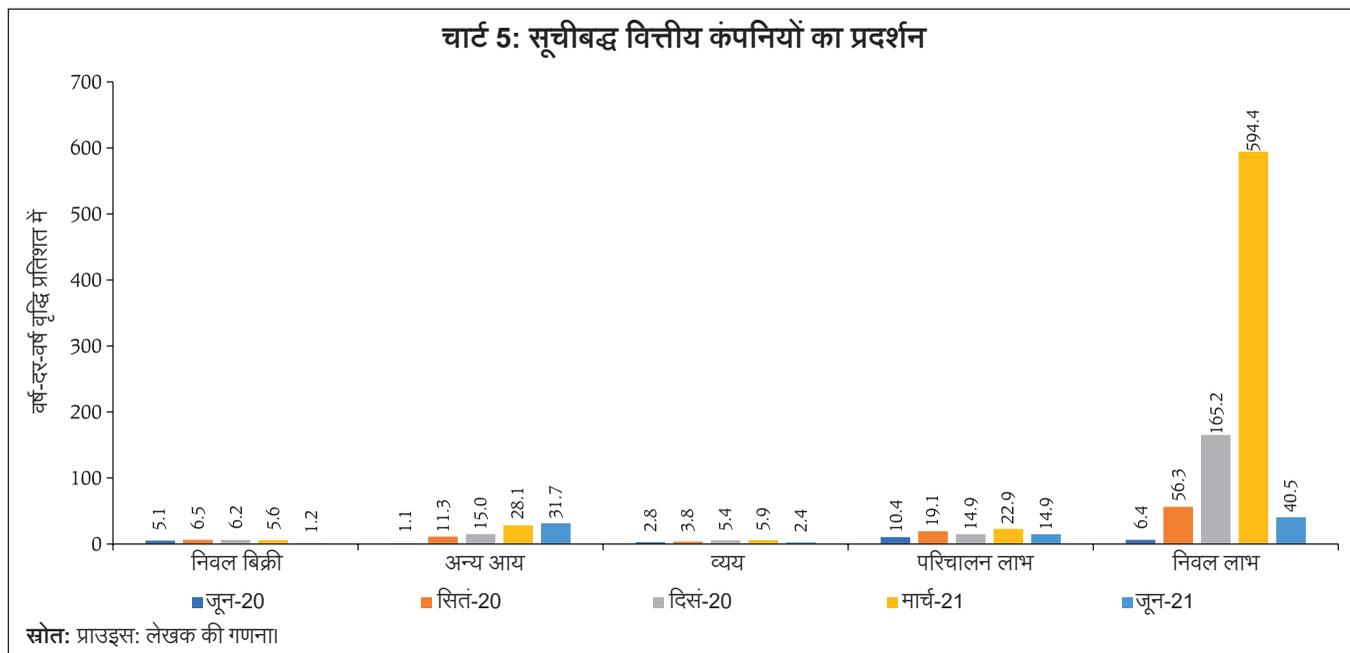


पकड़ रही रही है और अपने शीर्ष स्तर से बहुत दूर है (चार्ट 4)। जुलाई 2021 में 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश वर्ष-दर-वर्ष आधार पर चार गुना बढ़ा, जिसमें आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) कंपनियों के नेतृत्व में 119 फंडिंग सौदे हुए⁸

सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों - भारत में सभी सूचीबद्ध वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के 88.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली 390 कंपनियां - में निवल बिक्री, जिसमें मुख्य रूप से ब्याज आय शामिल है, मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य आय, जिसमें प्रतिभूतियों में लेनदेन से शुल्क, कमीशन और लाभ/हानि शामिल है, ब्लश को बचाया और एक साल पहले की तुलना में तेज वृद्धि दर्ज की। रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि का विस्तार करने और वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने के



⁸ <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/pe-vc-funding-grew-4x-y-o-y-in-july/articleshow/84987167.cms>

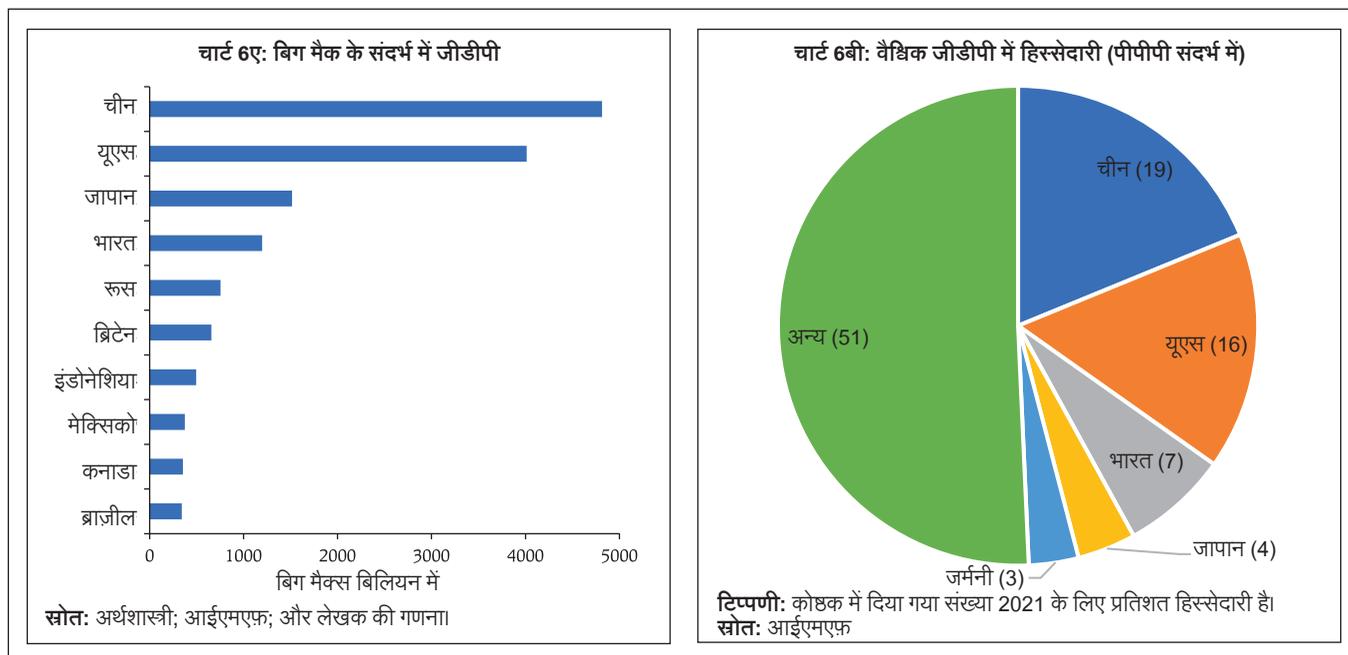


उपायों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में आसान लागत स्थितियों को दर्शाते हुए व्यय वृद्धि मंद रही। कुल मिलाकर, इन कारकों ने वित्तीय कंपनियों को परिचालन मुनाफे में पर्याप्त वृद्धि दर्ज करने में मदद की, जो सचमुच दूसरी लहर की प्रचंडता से छीन ली गई थी। इसके अलावा, प्रावधान लागत में गिरावट ने इन कंपनियों द्वारा दर्ज किए गए निवल लाभ के तेज वृद्धि में योगदान दिया (चार्ट 5)।

इस खंड को हल्की-फुल्की नोट के साथ समाप्त करने और इस लेख के व्यावसायिक हिस्से की ओर आगे बढ़ने के लिए, *द इकोनॉमिस्ट* पत्रिका ने अपने बिग मैक इंडेक्स को अपडेट किया है, जिसे यह एक व्यर्थ गाइड के रूप में प्रोजेक्ट करता है कि मुद्राएं अपने "सही" स्तर पर हैं या नहीं। यह इस धारणा पर आधारित है कि लंबे समय में, विनिमय दरों को उस दर की ओर बढ़ना चाहिए, जो किन्हीं दो देशों में वस्तुओं और सेवाओं की एक समान समूह (इस मामले में, एक बर्गर) की कीमतों के बराबर होगी। यह कभी भी मुद्रा अपसंरेखण के सटीक माप के रूप में नहीं था, लेकिन यह एक वैश्विक मानक बन गया है और कई आर्थिक पाठ्यपुस्तकों का एक हिस्सा और दर्जनों शैक्षणिक अध्ययनों का विषय है। इसके अपडेट कभी-कभी गलत मूल्यांकन के विचित्र अनुमान उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, अपने नवीनतम जीडीपी प्रति व्यक्ति

समायोजित अद्यतन में, स्विस् फ्रैंक का मूल्य 6.5 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जिससे यूएस ट्रेजरी द्वारा मुद्रा जोड़तोड़ के लेबल का मज़ाक उड़ाया गया है। भारतीय रुपये का मूल्यांकन उसी मीट्रिक द्वारा 18 प्रतिशत कम किया गया है, लेकिन यहां किसी भी गोमांस उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाता है - महाराजा मैक जिसमें चिकन पैटी का उपयोग किया जाता है, मूल्यांकन का आधार बनता है। इसके अलावा, जो लगभग भुला दिया गया है, वह यह है कि अमेरिकी डॉलर, संख्यात्मक मुद्रा जिसके विरुद्ध इन गलत-मूल्यांकनों को मापा जाता है, पर 253 प्रतिशत की गिरावट आई है और अमेरिकी बर्गर की कीमत, परिणामस्वरूप, अमेरिकी डॉलर 1.60 से बढ़ी है जब इसे 35 साल पहले 5.65 अमेरिकी डॉलर में पेश किया गया था।

इसलिए हमने बिग मैक की मुद्रा मूल्यांकन शक्तियों के अनुसार चलाने देने का फैसला किया और इसे चालू कर कर दिया। सामर्थ्य को देखते हुए या अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष एक मुद्रा कितने बर्गर खरीद सकती है, हम मापते हैं कि क्रय शक्ति के संदर्भ में किसी देश की जीडीपी का कितना मूल्य है। देखा! परिणाम पारंपरिक ज्ञान को बनाए रखते हैं - महाराजा मैक के संदर्भ में, भारत वर्तमान में चीन, अमेरिका और जापान के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है (चार्ट 6)। यह मोटे



तौर पर अप्रैल 2021 तक आईएमएफ़ के नवीनतम अपडेट के अनुरूप है - क्रय शक्ति समानता पर, भारत पीपीपी के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है (चार्ट 6 बी)।

II. वैश्विक व्यवस्था

वैश्विक आर्थिक सुधार जोर पकड़ रहा है, हालांकि इसकी विचलन और असमान गति नकारात्मक जोखिमों से भरा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डबल्यूईओ) के अपने जुलाई अपडेट में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने वैक्सीन पहुँच को प्रमुख दोष लाइन के रूप में पहचाना है, जिसके साथ वैश्विक रिकवरी विभाजित है, तेजी से टीकाकरण के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में प्रमुख शुरुआत हो रही है जबकि अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) अभी भी टीके की आपूर्ति को हासिल करने और संक्रमण और मृत्यु दर को कम करने के लिए जूझ रही हैं।

इसलिए, वर्ष 2021 के लिए आईएमएफ़ का वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा है, लेकिन देश के

⁹ प्रत्येक देश के लिए यूएस डॉलर में बिग मैक की कीमत बिग मैक की स्थानीय मुद्रा मूल्य को प्रचलित बाजार विनिमय दर (स्थानीय मुद्रा/अमेरिकी डॉलर) से विभाजित करके निकाली की गई थी। प्रत्येक देश के लिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक डेटाबेस से प्राप्त क्रय शक्ति समानता के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (बिग मैक के संदर्भ में) के माप पर पहुंचने के लिए अमेरिकी डॉलर में बिग मैक की कीमत से विभाजित किया गया था।

समूहों में ऑफसेटिंग भिन्नताएं हैं। जहां ईई पहले के अनुमान (अप्रैल 2021 में) की तुलना में उच्च गति से बढ़ने की ओर अग्रसर हैं, वहीं उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुख्य रूप से चिह्नित वृद्धि पूर्वानुमानों के कारण ईएमई के धीमी गति से बढ़ने की उम्मीद है (सारणी 2)।

वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में, अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, टीकाकरण की तीव्र गति और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता/कारोबार विश्वास के चलते रीओपनिंग होने और दी जा रही सरकारी सहायता की वजह से यूके 20.7 प्रतिशत (ति-द-ति, एसएएआर)¹⁰ की वृद्धि के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी, इसके बाद यूरो क्षेत्र में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। दूसरी ओर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो आम सहमति अनुमान (8.5-9 प्रतिशत) से काफी कम थी। इन्वेंट्री ड्रॉडाउन और कम आवासीय निवेश से मजबूत उपभोक्ता खर्च बाधित हो गया। फिर भी, अमेरिका ने तिमाही के दौरान अपने जीडीपी के महामारी से पूर्व के स्तर को पार कर लिया।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) 55.7 पर जुलाई 2021 में 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस

¹⁰ तिमाही-दर-तिमाही मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर।

सारणी 2: जीडीपी वृद्धि अनुमान – चुनिंदा एई एवं ईएमई (प्रतिशत)

देश	2021		2022	
	अप्रै 2021	जुला 2021	अप्रै 2021	जुला 2021
 विश्व	6.0	6.0	4.4	4.9
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ				
 यूएस	6.4	7.0	3.5	4.9
 यूके	5.3	7.0	5.1	4.8
 यूरो क्षेत्र	4.4	4.6	3.8	4.3
 जापान	3.3	2.8	2.5	3.0
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ				
 ब्राजील	3.7	5.3	2.6	1.9
 रूस	3.8	4.4	3.8	3.1
 भारत	12.5	9.5	6.9	8.5
 चीन	8.4	8.1	5.6	5.7
 दक्षिण अफ्रीका	3.1	4.0	2.0	2.2

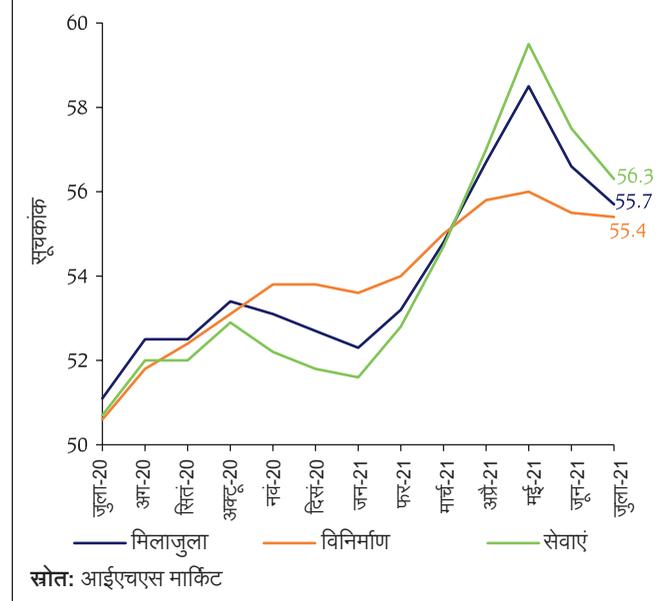
स्रोत: आईएमएफ

सहजता के तहत, विनिर्माण और सेवाओं का पीएमआई भी गिर गया, भले ही सभी सूचकांक लगातार 13 महीनों तक विस्तार मोड में रहे (चार्ट 7)।

अन्य संकेतकों में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक स्तर पर रोजगार की स्थिति में सुधार हो रहा है। यूरोपीय संघ में बेरोजगारी दर मई में 7.3 प्रतिशत से घटकर जून में 7.1 प्रतिशत हो गई, जिसमें 4,87,000 नौकरियां पैदा हुईं। अमेरिका में, बेरोजगारी की दर जुलाई में घटकर 5.4 प्रतिशत हो गई, जिसमें गैर-कृषि पेट्रोल अपेक्षा से अधिक बढ़ गया। बेरोजगारी दर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके सहित अन्य एई में भी कम हुई है।

भले ही वैश्विक उत्पाद व्यापार में उछाल बना हुआ है, सेवाओं में व्यापार पिछड़ गया है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की

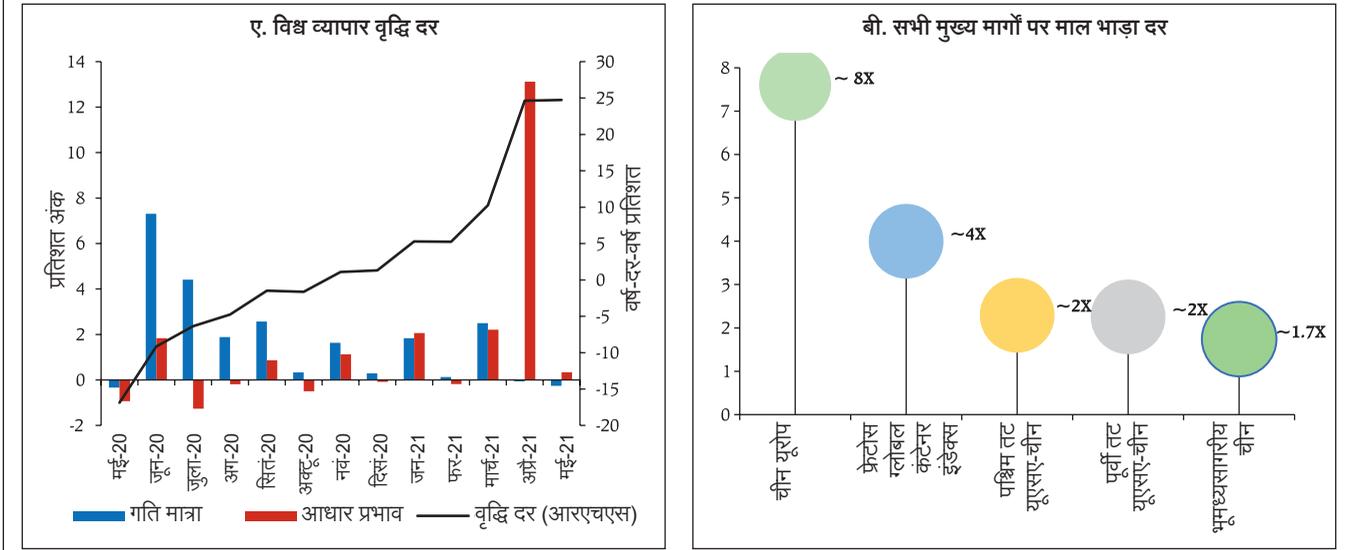
चार्ट 7: वैश्विक पीएमआई



23 जुलाई 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, वर्ष 2020 में 21.0 प्रतिशत की गिरावट के बाद, वैश्विक सेवा व्यापार वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 9.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) गिर गया। यात्रा में लगातार कमजोरी सेवा व्यापार के मुख्य बाधा के रूप में कार्य करती है। मासिक उत्पाद व्यापार संबंधी ग्रैन्यूलर आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर दोहरे अंकों में रही, लेकिन मुख्य रूप से अनुकूल आधार पर (चार्ट 8 ए)। महामारी संबंधी व्यवधानों के कारण चीन से यूरोप के लिए आउटबाउंड शिपमेंट हेतु माल ढुलाई दरों में लगभग 8 गुना वृद्धि होने से जुलाई के दौरान प्रमुख मार्गों पर वैश्विक माल भाड़ा कीमतों में वृद्धि हुई। इन मार्गों का उपयोग भारतीय निर्यातकों द्वारा अपने उत्पादों को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में भेजने के लिए भी किया जाता है, जो भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्य हैं (चार्ट 8बी)।

तेजी से रिकवरी के साथ पण्य की कीमतों में तेजी आई है। ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स अब तक अगस्त में सहज होने से पहले चार महीने (एंड-टू-एंड) तक बढ़ा (चार्ट 9ए)। कच्चे तेल की कीमतें अब तक 2021 में बड़े पैमाने पर ऊपर की ओर रही हैं; डब्ल्यूईओ का जुलाई अपडेट मानता है कि यह वर्ष 2020 के अपने निम्न आधार से लगभग 60 प्रतिशत ऊपर उठेगा। हालांकि, जुलाई के मध्य के आसपास, डेल्टा वेरिएंट वायरस के तेजी से प्रसार के

चार्ट 8: विश्व व्यापार और शिपिंग लागत

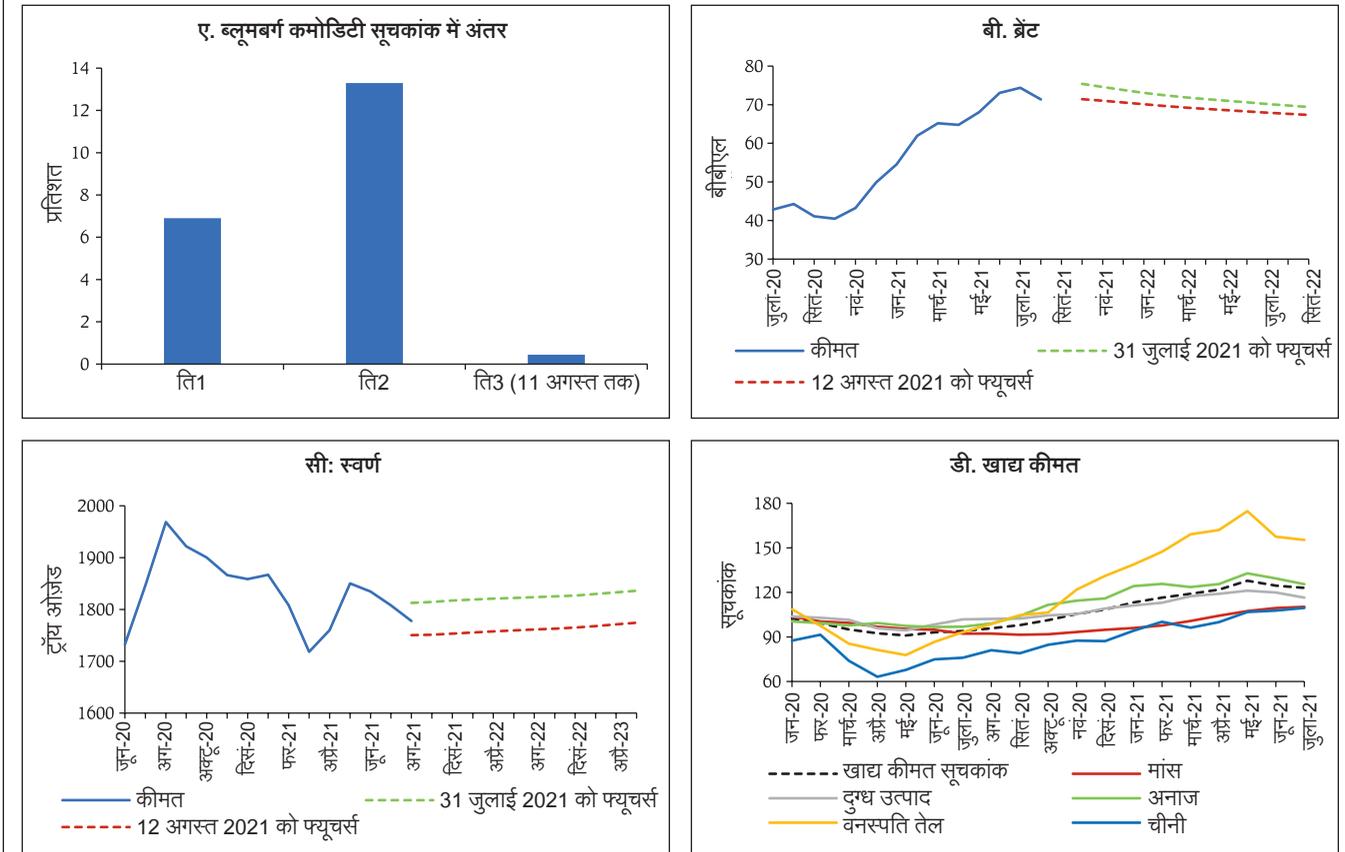


स्रोत: सीपीबी नीदरलैंड; ब्लूमबर्ग; रायटर्स एवं लेखक की गणना।

कारण मांग की चिंताओं के कारण कीमतों में तेजी से गिरावट आई थी। और ओपेक प्लस अगस्त से हर महीने 400,000 बैरल प्रति

दिन के अतिरिक्त उत्पादन के साथ आपूर्ति को आसान बनाने के लिए करार कर रहे हैं। मांग की चिंताओं के साथ-साथ अमेरिका में

चार्ट 9: पण्य वस्तुएं और खाद्य कीमतें



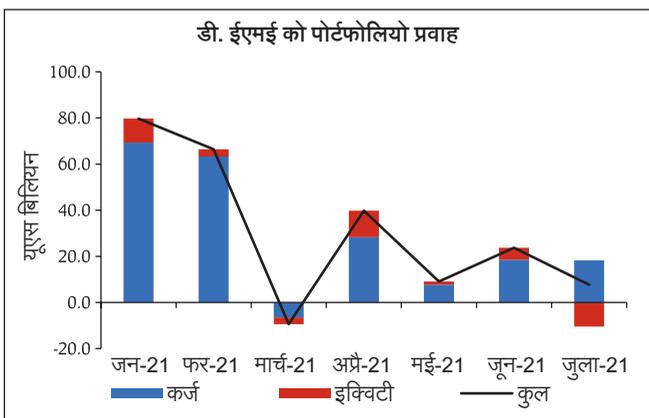
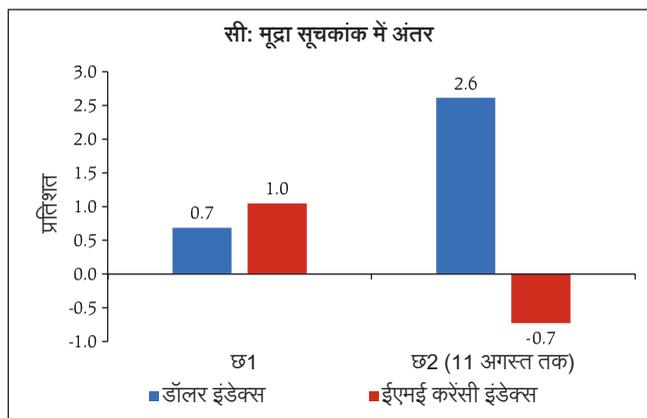
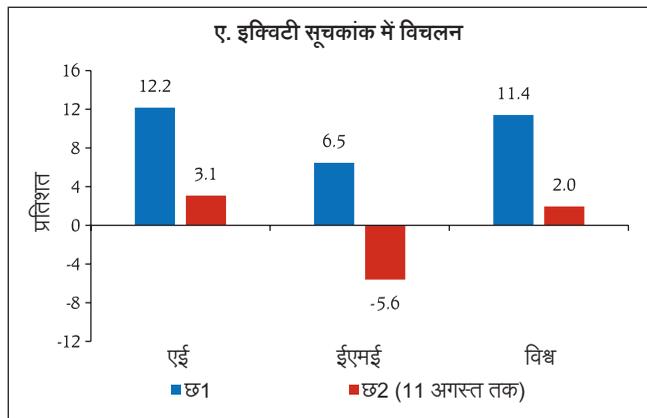
स्रोत: वर्ल्ड बैंक; ब्लूमबर्ग; फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।

उच्च भंडार के संबंध में अगस्त की शुरुआत से सहजता का एक और दौर शुरू हो गया है (चार्ट 9बी)। यूएस ट्रेजरी प्रतिफल में निरंतर सुरक्षित आश्रय मांग और रैलियों के कारण, बुलियन जुलाई में अमेरिकी डॉलर 1,800 प्रति ट्रॉय औंस के निशान के आसपास स्थिर हो गया था, लेकिन डॉलर के मजबूत होने और उच्च प्रतिफल पर अगस्त के दूसरे सप्ताह तक 4 महीने के निचले स्तर पर गिर गया (चार्ट 9सी)। चीनी और मांस को छोड़कर खाद्य कीमतों में जुलाई में लगातार दूसरे महीने नरमी रही (चार्ट 9डी)। फिर भी, जुलाई 2021 में खाद्य मूल्य सूचकांक एक साल पहले के स्तर से 31.0 प्रतिशत अधिक था।

वित्तीय बाजारों में मजबूत रैलियों से एई शेयरों में तेजी आई। जुलाई में चीन में नियामकीय कार्रवाई के कारण बड़े पैमाने पर बिकवाली हुई, जिसने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर समग्र ईएमई सूचकांक को लाल रंग में ला दिया (चार्ट 10ए)। दूसरी ओर, अमेरिका में 10-वर्षीय ट्रेजरी प्रतिफल में जुलाई तक गिरावट

जारी रही। 19 जुलाई को, जब डेल्टा संस्करण की चिंताओं ने दुनिया भर में शेयर बाजारों में तेज गिरावट शुरू की और मजबूत सुरक्षित आश्रय की मांग को बढ़ा दिया, तब फरवरी के दूसरे सप्ताह के बाद से 10-वर्षीय प्रतिफल अपने निम्नतम स्तर पर आ गई। फेडरल रिजर्व द्वारा डॉविश आश्वासन के साथ संकोचपूर्ण हॉकिश फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) वक्तव्य को अपनाने से दीर्घावधि ट्रेजरी प्रतिफल नरम रही। हालाँकि, जुलाई के लिए नौकरियों की रिपोर्ट ने तेजी को रोक दिया है (चार्ट 10बी)। दूसरी ओर, अमेरिकी डॉलर बेहतर आर्थिक प्रदर्शन और अमेरिका के लिए मुद्रास्फीति दृष्टिकोण में सुधार के कारण मजबूत हुआ। जुलाई में अमेरिकी डॉलर की रैली तेज थी और अगस्त में जारी रही, जबकि अधिकांश अन्य मुद्राओं, विशेष रूप से ईएमई मुद्राओं में डॉलर के मुकाबले मूल्यहास हुआ है (चार्ट 10 सी)। कुल मिलाकर, जुलाई में ईएमई को पूंजी प्रवाह में तीव्र कटौती हुई है, जिसमें इक्विटी खंड से निवल बहिर्वाह हुआ है (चार्ट 10डी)।

चार्ट 10: वित्तीय बाजार



स्रोत: ब्लूमबर्ग; एफआईबीएल एण्ड आईआईएफए

मुद्रास्फीति अधिकांश ईएमई के मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है, साथ ही एई भी हाल के महीनों में इसमें हुई बढ़ोतरी से जूझ रहे हैं। अमेरिका में, मुख्य व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मुद्रास्फीति जून में 3.5 प्रतिशत पर 30 साल के उच्चतम स्तर पर थी। जुलाई में सीपीआई मुद्रास्फीति पिछले महीने के 13 साल के उच्च स्तर पर बनी रही। हालांकि, नवीनतम एफओएमसी बयान में कहा गया है कि मुद्रास्फीति में हालिया उछाल काफी हद तक अस्थायी कारकों के कारण है। आईएमएफ ने अपने नवीनतम डबल्यूईओ में इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है। अमेरिका में मुख्य मुद्रास्फीति में वृद्धि का मुख्य कारण पुरानी कारों, इमारती लकड़ी और हवाई यात्रा की कीमतों में वृद्धि है, जो अतिरिक्त क्षमता के समाप्त होने के बजाय महामारी जनित व्यवधानों का परिणाम है। जुलाई में 2.2 प्रतिशत की मुद्रास्फीति प्रिंट वाले यूरो क्षेत्र खुलेआम रूप से लक्ष्य से ऊपर मुद्रास्फीति वाला नवीनतम एई है। ईएमई में, पण्य की कीमतों में मजबूती और आपूर्ति में व्यवधान के कारण मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है (चार्ट 11)।

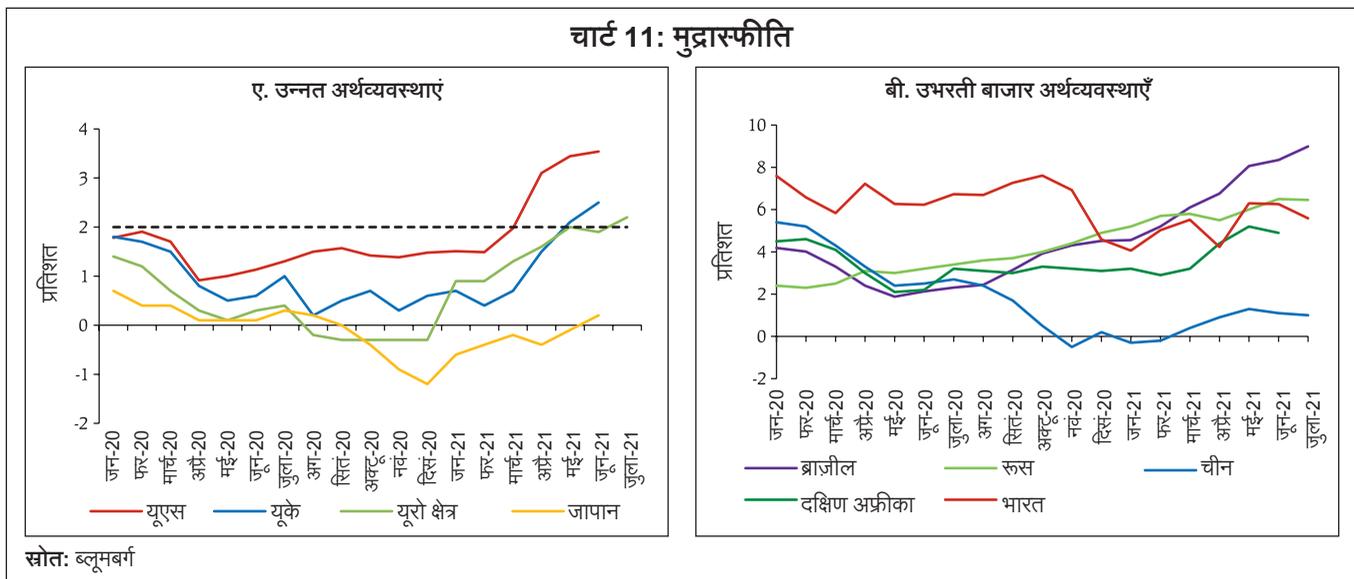
ऐतिहासिक रूप से कम ब्याज दरों, लॉकडाउन के दौरान जमा हुई बचत और अधिक जगह की अभिलाषा से लगभग हर बड़ी अर्थव्यवस्था में घर की कीमतें फलफूल रही हैं क्योंकि लोग घर से काम करके मांग को बढ़ा रहे हैं¹¹।

केंद्रीय बैंकों द्वारा अलग-अलग मौद्रिक नीति मार्ग बनाए जा रहे हैं। ब्राजील और रूस दोनों ने जुलाई और अगस्त में क्रमशः

100 आधार अंकों (बीपीएस) के बराबर परिमाण के साथ, वर्ष 2021 में अपनी चौथी दर वृद्धि को प्रभावित किया। जुलाई में 25 बीपीएस की वृद्धि के साथ चिली नीतिगत सामान्यीकरण शुरू करने वाला नवीनतम ईएमई है, जबकि मेक्सिको ने अगस्त में लगातार दूसरी बार 25 बीपीएस की बढ़ोतरी की।

एई में, बैंक ऑफ कनाडा ने अपने साप्ताहिक बॉन्ड खरीद कार्यक्रम को तीसरी बार कनाडाई डॉलर 1 बिलियन से कनाडाई डॉलर 2 बिलियन कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भले ही दर और आसित खरीद की मात्रा पर विराम बनाए रखा है, लेकिन इस पर मार्गदर्शन प्रदान करता है कि यह अपनी मात्रात्मक सहजता को कैसे कम करेगा। स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार उदार मौद्रिक नीति रुख बनाए रखा है। इसने एक भावी मार्गदर्शन निर्धारित किया कि मुद्रास्फीति लक्ष्य स्थायी रूप से प्राप्त होने तक ब्याज दरें अपने मौजूदा स्तर पर या कम रहेंगी। ईसीबी ने महामारी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम के तहत न तो गति और न ही खरीद की मात्रा में बदलाव किया है।

अपनी जुलाई की बैठक के बाद, फेडरल रिजर्व ने कहा कि अमेरिका अधिकतम रोजगार और मूल्य स्थिरता के अपने लक्ष्यों के संबंध में "अच्छी खासी इसके आगे की प्रगति" से थोड़े से दूर था। इससे बाजार की धारणा शांत हुई। इसके अलावा, फेड ने एकदिवसीय संपार्श्विक उधार देने वाली दो स्थायी रिपो सुविधाएं



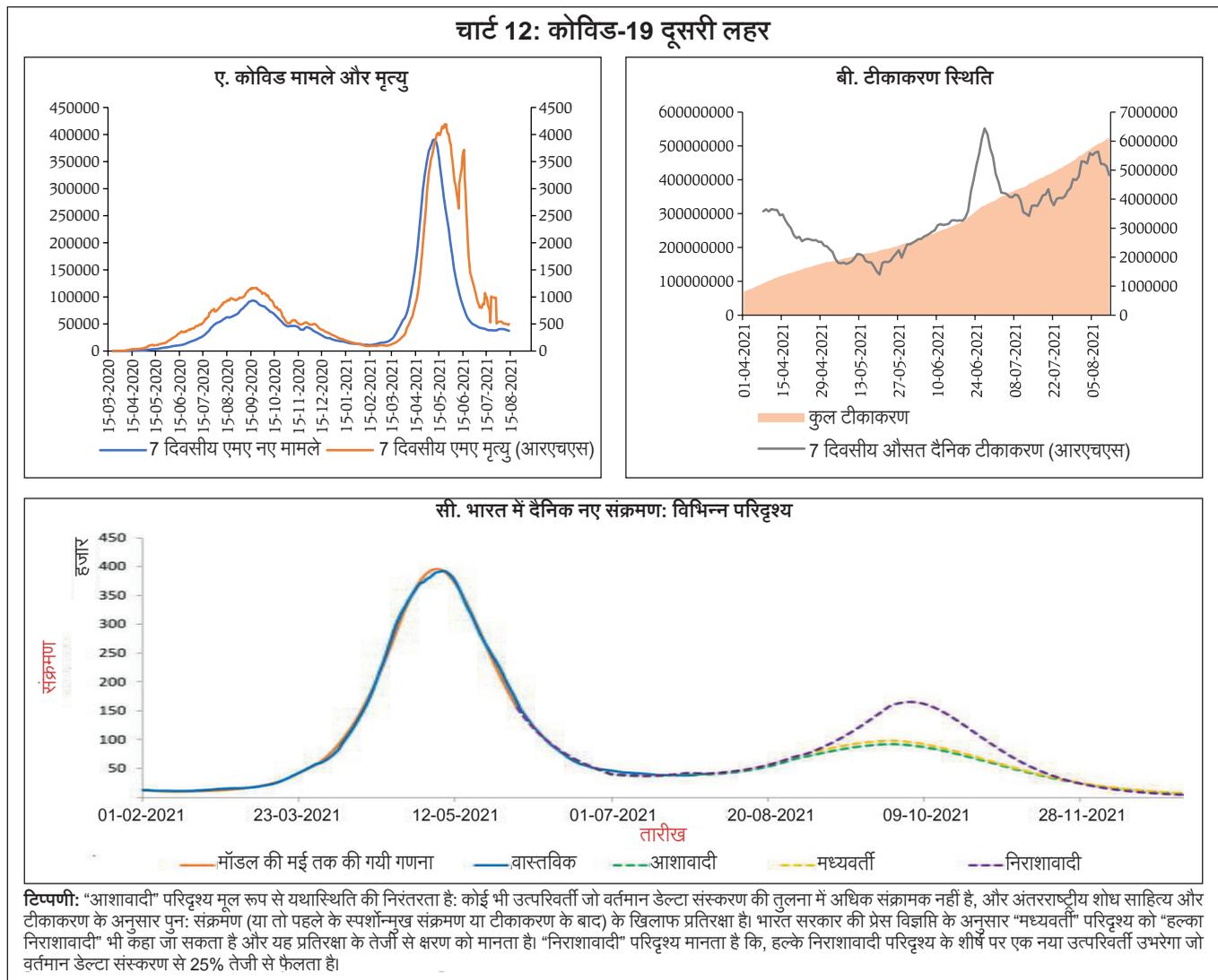
¹¹ फाइनेंशियल टाइम्स, 2 अगस्त 2021।

पेश की - एक घरेलू स्थायी रिपो सुविधा और विदेशी एवं अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्राधिकरणों के लिए एक रिपो सुविधा (एफआईएमए रिपो सुविधा)¹²

कुल मिलाकर, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निकट-अवधि का दृष्टिकोण अत्यधिक संक्रामक डेल्टा संस्करण के संबंध में बढ़ती चिंताओं से बना हुआ है, जो दुनिया के कई हिस्सों को तबाह कर रहा है। वर्तमान समय में वैश्विक वृद्धि के प्रति जोखिम नीचे की ओर झुके हुए हैं। मुद्रास्फीति की बिगड़ती प्रत्याशाएँ और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थितियाँ सख्त होने से समष्टि-आर्थिक और वित्तीय प्रभाव-प्रसार से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में कमी आ सकती है।

III. घरेलू प्रगति

महामारी की दूसरी लहर की धीमी गति से थमने से पिछले महीने में अर्थव्यवस्था की दिशा बदल गई है। मई के पहले सप्ताह में चरम पर पहुंचने के बाद, दैनिक नए मामलों का 7-दिवसीय मूविंग एवरेज (एमए) जुलाई 2021 की पहली छमाही में लगभग 40,000 से गिर गया और 16 अगस्त 2021 को 36,074 के निचले स्तर को छू लिया। टीकाकरण के मोर्चे पर, 16 अगस्त 2021 तक 55 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। 26 जुलाई से 8 अगस्त की अवधि के दौरान, ग्रामीण टीकाकरण में तेज उछाल आया है: अकेले इस अवधि में प्रशासित कुल 9.87 करोड़ खुराक में से 63 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थीं¹³।



¹² यह सुविधा मार्च 2020 के अंत में शुरू की गई थी और इसे सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था, और अब इसे स्थायी कर दिया गया है।

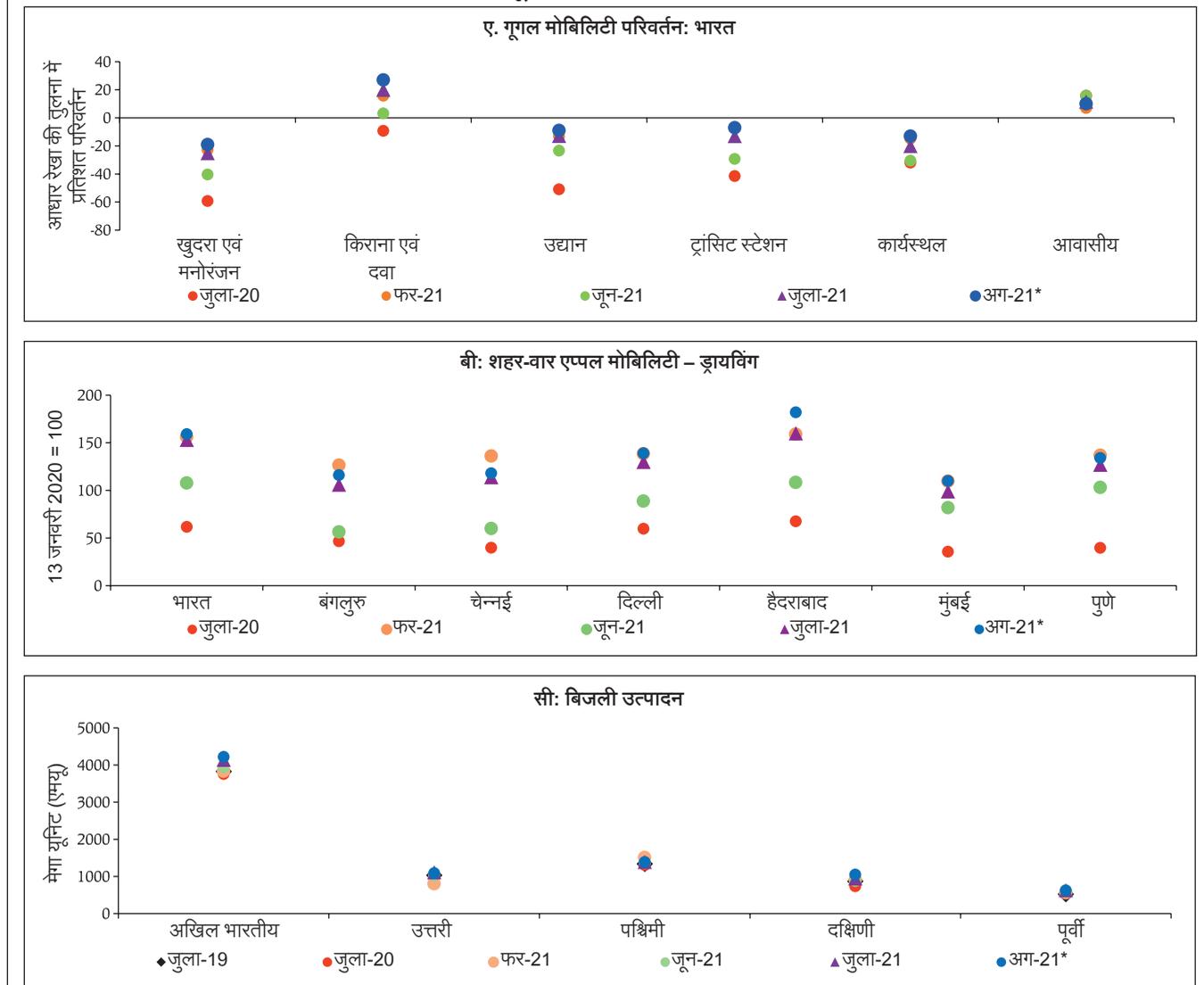
¹³ इंडियन एक्सप्रेस, 10 अगस्त 2021।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा किए गए चौथे राष्ट्रीय सेरोप्रेवलेंस सर्वे¹⁴ के अनुसार, भारत की 6 वर्ष से अधिक आयु की लगभग 68 प्रतिशत आबादी में सार्स-कोव-2 एंटीबॉडी पायी गयी है, जिससे पता चलता है कि देश समूह प्रतिरक्षा की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर, मॉडल-आधारित सिमुलेशन से पता चलता है कि भारत में एक नई लहर में कोविड संक्रमण में वृद्धि देखने की संभावना है जो अक्टूबर में चरम पर हो सकती है¹⁵। यह पूर्वानुमान नए स्वरूपों के उभरने की

संभावना के मद्देनजर भारत को अपने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने, उभरते हुए हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए निगरानी पद्धतियों को विनियोजित करने और जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से सतर्क रहने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

राज्यों द्वारा प्रतिबंधों को सावधानीपूर्वक हटाने से दूसरी लहर की शुरुआत से पहले फरवरी 2021 में मानव गतिशीलता पिछले स्तर तक बढ़ गई है (चार्ट 13ए और 13बी)। बिजली उत्पादन रीडिंग भी, अप्रैल 2021 में देखे गए चरम स्तर पर पहुंच

चार्ट 13: कोविड-19 की दूसरी लहर का आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव



*: 11 अगस्त 2021 तक के आंकड़े को दर्शाता है।
 स्रोत: गूगल: सीएमआई; सीआईसी तथा पीओएसओसीओ

¹⁴ 1सर्वेक्षण 70 जिलों में किया गया था, जिसमें पहली बार 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को शामिल किया गया था।

¹⁵ हैदराबाद और कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में मथुकुमल्ली विद्यासागर और मनिंद्र अग्रवाल द्वारा विकसित।

गई है और महामारी के पहले के स्तर, यानी जुलाई 2019 तक पहुंच गयी है (चार्ट 13सी)।

कुल मांग

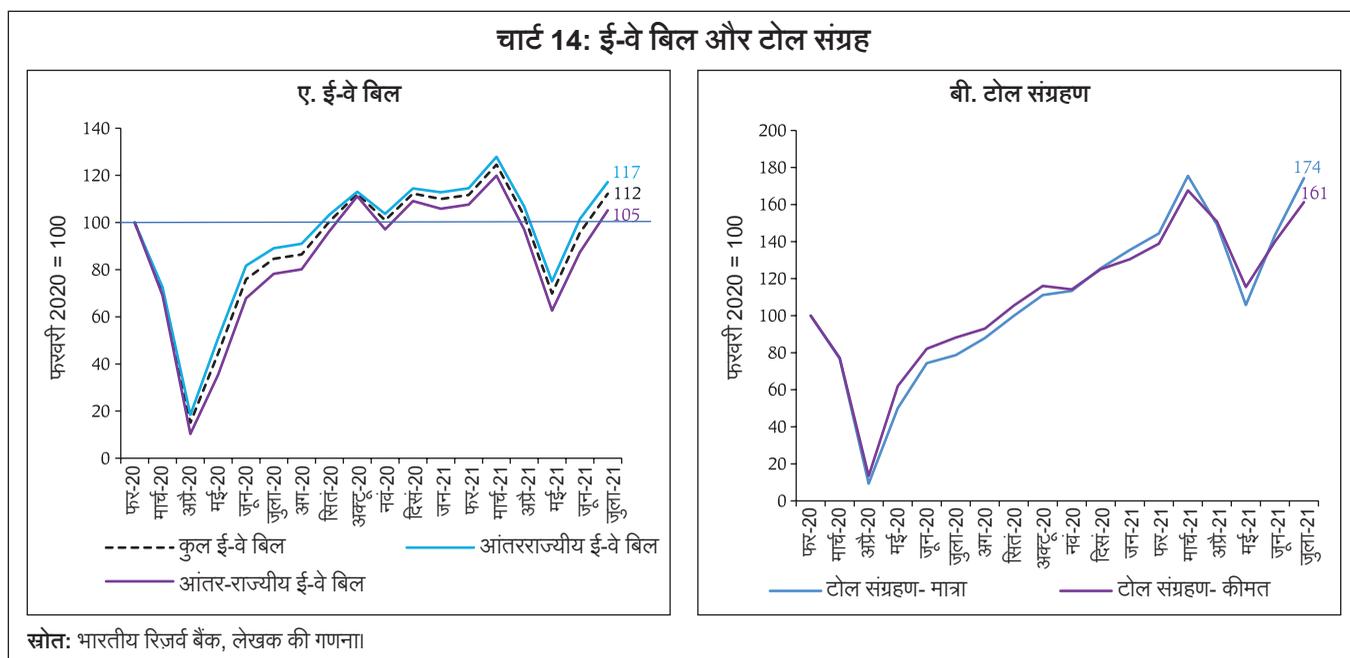
अनलॉक और टीकाकरण के कारण दबी हुई मांग बढ़ने से कुल मांग की स्थिति में उछाल आया है। ई-वे बिल संग्रह पिछले चार महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे जून 2021 की तुलना में क्रमिक रूप से 17.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। फरवरी 2020 के स्तर के लिए सामान्यीकृत, ई-वे बिल, आंतर-राज्य और अंतर-राज्य दोनों महामारी से पहले के स्तर को पार कर गया (चार्ट 14ए)। अगस्त में अब तक (8 अगस्त, 2021 तक), दैनिक औसत ई-वे बिल में क्रमिक रूप से 5.8 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिसका आगे चलकर जीएसटी संग्रह पर प्रभाव पड़ेगा।

जुलाई में टोल संग्रह मार्च 2021 के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गया, जब फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था (चार्ट 14बी)। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग (आईएफटीआरटी)¹⁶ के अनुसार, टोल संग्रह में वृद्धि को कारखाने

के उत्पादन में वृद्धि और प्रेषण में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि के कारण ट्रक के किराये में वृद्धि को भी बल मिला। अगस्त में अब तक (12 अगस्त 2021 तक) टोल संग्रह एक महीने पहले की इसी अवधि की तुलना में स्थिर रहा।

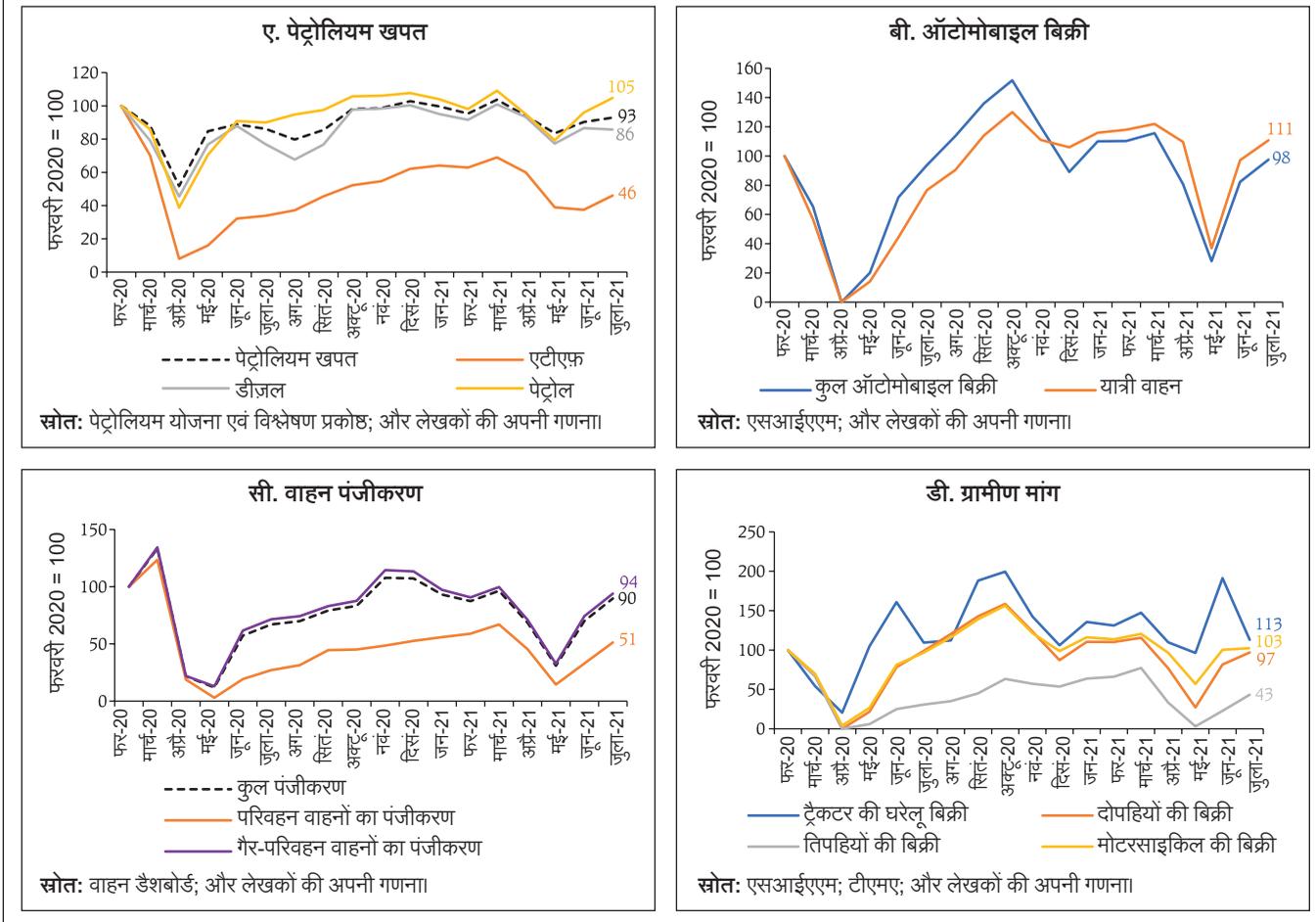
जुलाई 2021 में ईंधन की खपत में वृद्धि दर्ज की गई। जहां पेट्रोल की खपत महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गई और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) में क्रमिक सुधार दर्ज किया गया, वहीं डीजल की खपत में मामूली गिरावट आई (चार्ट 15ए)। जुलाई में ऑटोमोबाइल की थोक बिक्री में तेजी दर्ज की गई, यात्री वाहन खंड की वृद्धि में सकारात्मक गति के साथ निर्माताओं ने उत्पादन बढ़ाया और इन्वेंट्री स्तर को फिर से भरने के लिए डीलरशिप को भेजा। मोटर वाहनों की खुदरा बिक्री जुलाई में 33.7 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष और 27.7 प्रतिशत माह-दर-माह की वृद्धि को पार कर गई। फरवरी 2020 तक सामान्यीकृत, परिवहन और गैर-परिवहन वाहन पंजीकरण दोनों में सुधार हुआ, गैर-परिवहन खंड पूर्व-महामारी के स्तर के सामान्य होने के करीब और परिवहन खंड महामारी से पहले के स्तर के 50 प्रतिशत तक पहुंच गया (चार्ट 15बी और सी)।

चार्ट 14: ई-वे बिल और टोल संग्रह



¹⁶ मनी कंट्रोल, 3 अगस्त 2021।

चार्ट 15: परिवहन क्षेत्र संकेतक

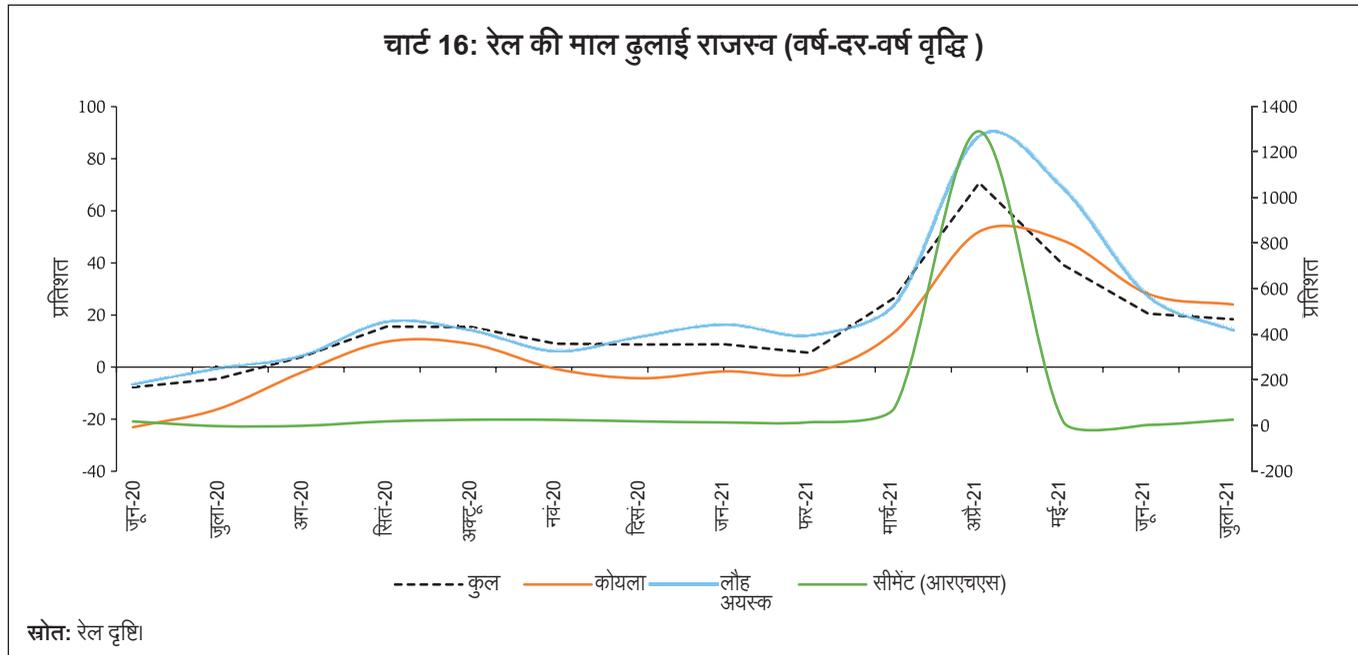


जुलाई में ट्रैक्टर की बिक्री में वर्ष-दर-वर्ष 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के साथ ग्रामीण मांग में तेजी रही, जो महामारी से पहले के स्तर से काफी ऊपर थी। सामान्य मानसून और बुवाई में तेजी से उद्योग के विशेषज्ञ इस सेगमेंट के संबंध में उत्साहित हैं क्योंकि आने वाले महीनों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। भले ही जुलाई 2021 में दोपहिया वाहनों की बिक्री मध्यम रही हो लेकिन मोटरसाइकिलों की बिक्री फिर से बढ़ गयी (चार्ट 15डी)।

भारतीय रेलवे द्वारा ढुलाई की गयी माल एक साल पहले के स्तर की तुलना में जुलाई (112.7 मिलियन टन) में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सुदृढ़ रहा। प्रमुख जिंसों में से, सीमेंट के भाड़े में

भारी वृद्धि दर्ज की गई जो निर्माण गतिविधि में तेजी का संकेत है (चार्ट 16)। विमानन क्षेत्र ने आखिरकार अगस्त के पहले सप्ताह में हवाई यात्रियों की संख्या में कुछ सुधार दर्ज किया क्योंकि एयरलाइंस ने विशेष किराए की शुरुआत की, और टीकाकरण से यात्रा भावनाओं में सुधार हुआ। वर्तमान में, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें केवल उन 28 देशों के लिए संचालित हो रही हैं जिनके साथ भारत ने "एयर बबल"¹⁷ करार किए हैं।

¹⁷ एयर बबल दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जिसके तहत दोनों देशों की एयरलाइंस निर्धारित नियमों और प्रतिबंधों के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित कर सकती हैं।

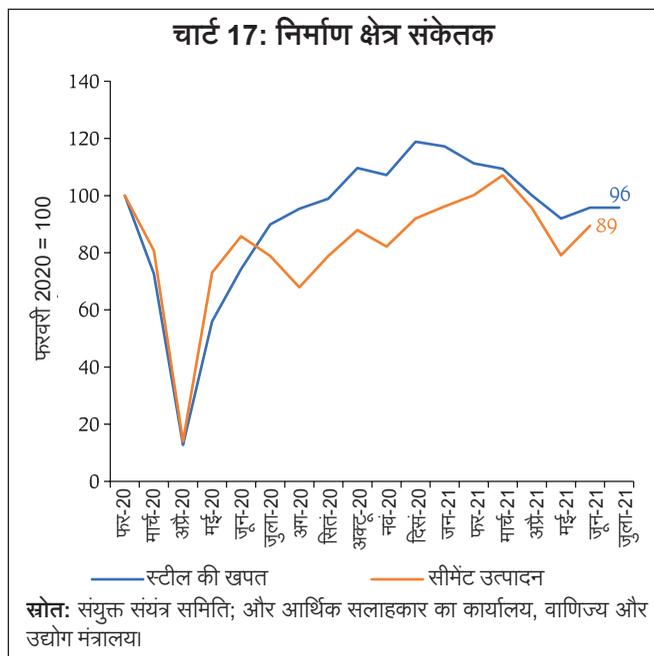


फरवरी 2020 के स्तर के लिए सामान्यीकृत, निर्माण गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतक - स्टील की खपत और सीमेंट उत्पादन - बेसलाइन के करीब आ गए (चार्ट 17)।

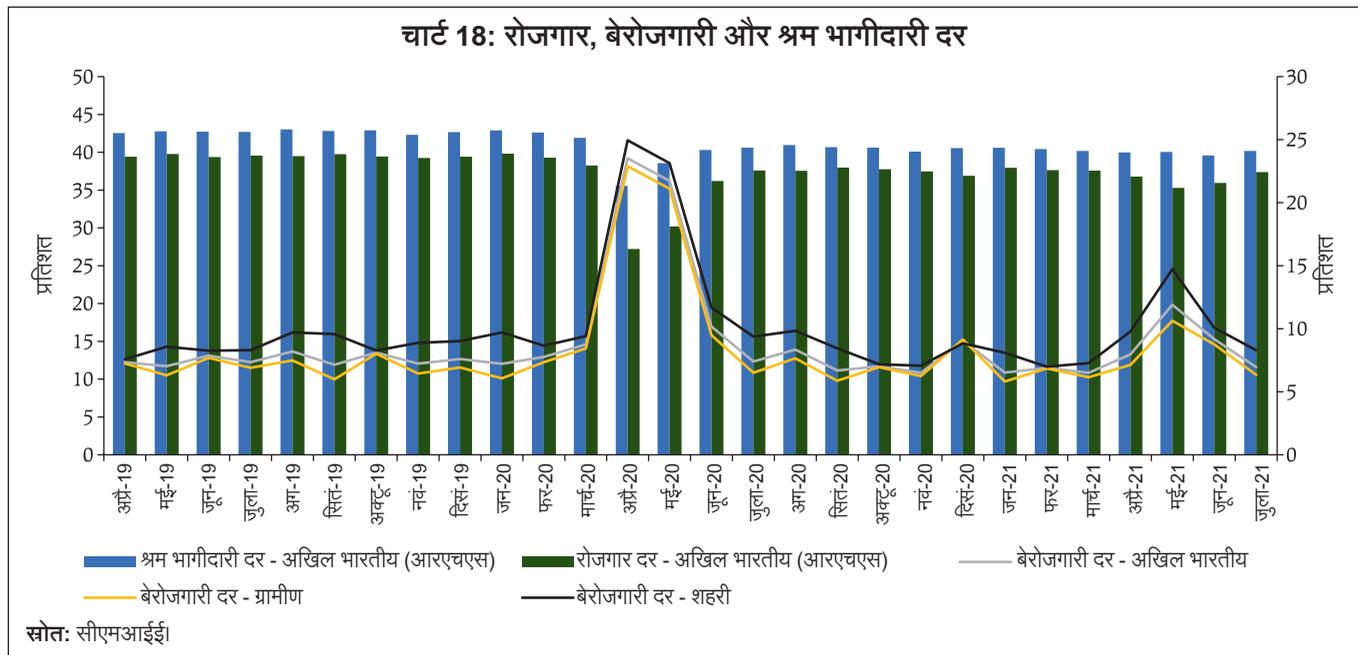
जुलाई 2021 में, शीघ्र खपत वाली उपभोक्ता वस्तु (एफएमसीजी) क्षेत्र ने ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में बिक्री में तेजी देखी, क्योंकि अनुकूल मानसून के कारण भावनाओं में

सुधार हुआ। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ने जुलाई में अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की, जो मांग में कमी के कारण हुई। चालू किराना आउटलेट्स की सक्रिय संख्या में जुलाई में 17 प्रतिशत एम-ओ-एम की वृद्धि हुई¹⁸।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई में बेरोजगारी दर घटकर 6.95 प्रतिशत हो गई, जो एक महीने पहले 9.17 प्रतिशत थी। श्रम भागीदारी दर में भी एक महीने पहले की तुलना में जुलाई 2021 में 60 आधार अंकों का सुधार हुआ, जो मार्च 2021 के स्तर तक पहुंच गया (चार्ट 18)। बेरोजगारी में गिरावट शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट थी, जो कि उज्ज्वल कृषि संभावनाओं पर ग्रामीण क्षेत्र के आघात-सहनीयता की ओर इशारा कर रही थी। 23 जुलाई और 2 अगस्त 2021 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने जुलाई 2019-जून 2020 की अवधि के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया, जो श्रम बाजार स्थिति के संबंध में महामारी की पहली लहर के प्रभाव का पहला औपचारिक प्रमाण प्रदान करता है (अनुबंध)।

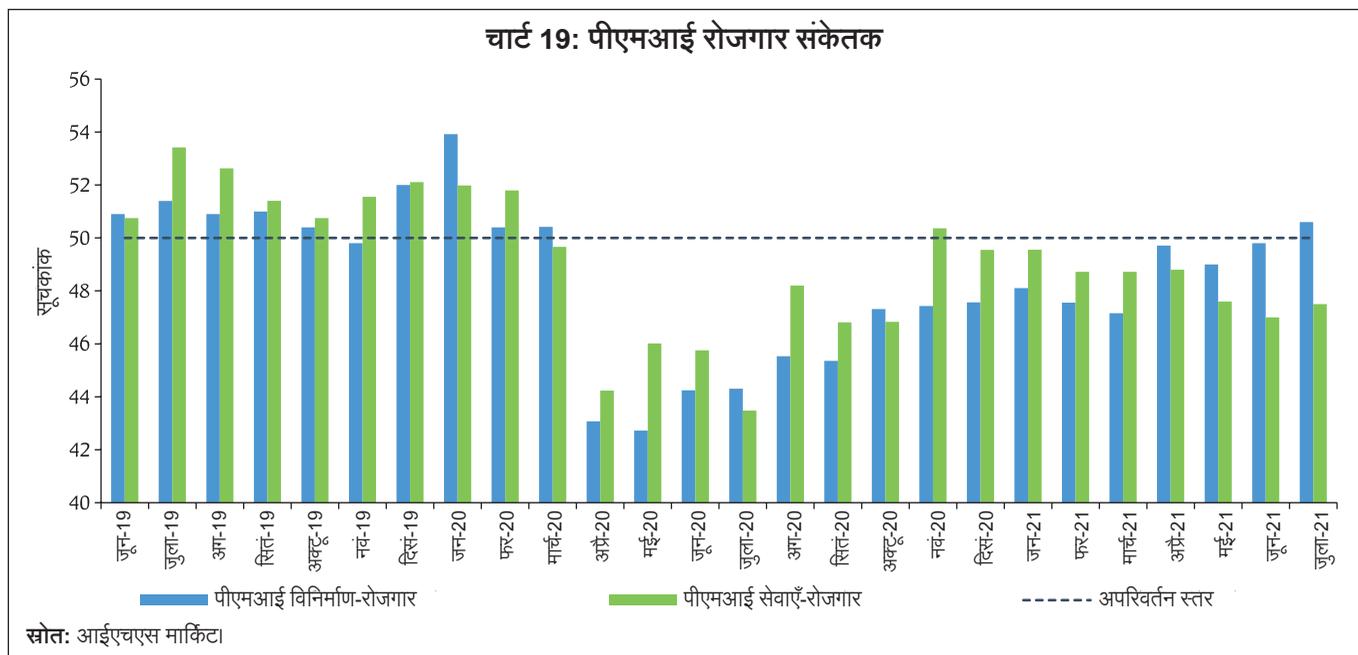


¹⁸ ब्लूमबर्गक्विंट, 30 जुलाई 2021।

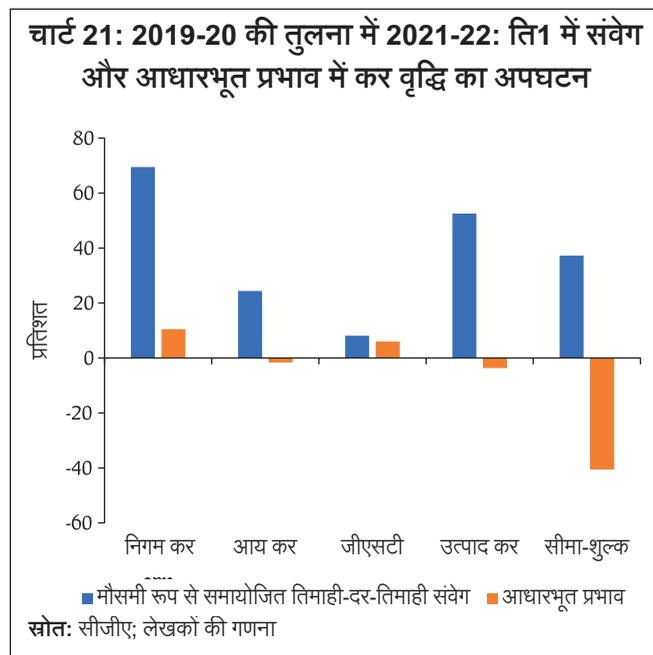
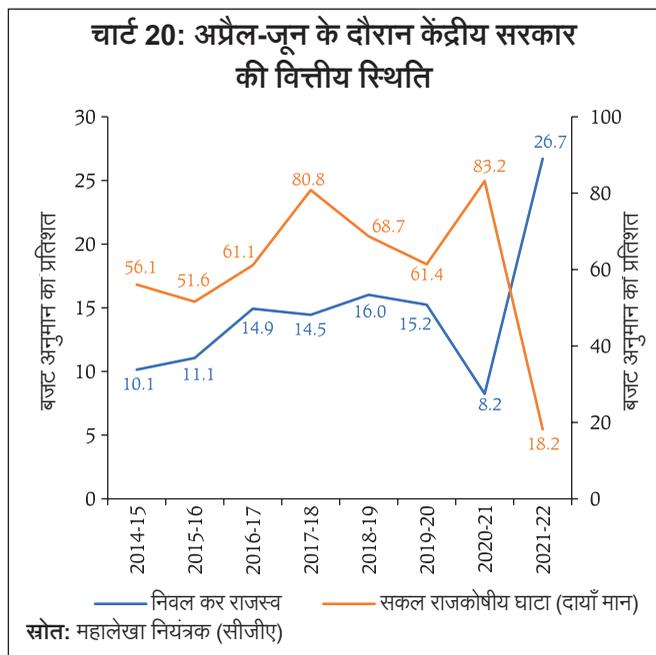


एम्प्लॉयमेंट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (ईपीएमआई) से पता चलता है कि विनिर्माण क्षेत्र में नियुक्ति में तेजी आई है जबकि सेवा क्षेत्र में अभी भी जुलाई में संकुचन दिख रहा है¹⁹ (चार्ट 19)।

वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान, केंद्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को नियंत्रण में रखा गया था, जिसे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उच्च कर और गैर-कर राजस्व और कम राजस्व व्यय से मदद मिली (चार्ट 20)।



¹⁹ आईएचआईएस मार्किट ने पीएमआई डेटा जारी किया।



सकल कर राजस्व में काफी सुधार हुआ है- 2019-20 की तुलना में भी सकल कर राजस्व में 32.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें अधिकांश कर शीर्षों ने संग्रह में द्वि-अंकी वृद्धि दर्ज की (सारणी 3)।

सभी प्रमुख कर शीर्षों के तहत एक मजबूत सकारात्मक गति है, जो निगम कर और जीएसटी के मामले में सकारात्मक आधारभूत प्रभावों से पूरित है (चार्ट 21)। बड़ी मुख्य कंपनियों की लाभप्रदता में वृद्धि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ जीएसटी डेटा

साझा करने से बेहतर अनुपालन और प्रवर्तन, ईंधन पर उच्च कर से गति उत्पन्न हो रही है और निर्यात और आयात दोनों में तीव्र समुत्थान के परिणामस्वरूप गति उत्पन्न हो रही है।

जुलाई 2021 के महीने में ₹1.16 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह फिर से ₹1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, जो यह दर्शाता है कि जून में हुई अर्थहीन रुकावट क्षणिक हो सकती है (चार्ट 22)।

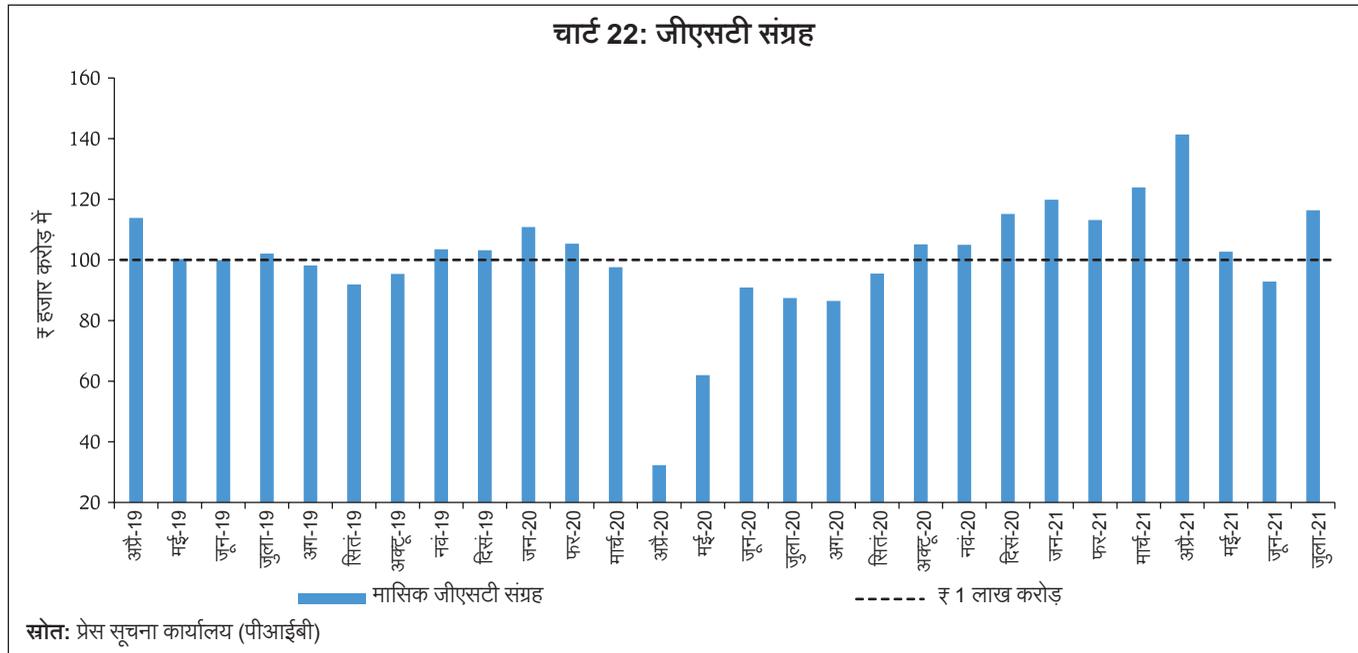
2021-22 में पहली तिमाही में, एक वर्ष पहले की तुलना में केंद्र सरकार के पूंजीगत परिव्यय में 41.1 प्रतिशत का सुधार हुआ है, जो मध्यम अवधि के विकास की संभावनाओं के लिए अच्छा है। पूंजीगत परिव्यय की तुलना में राजस्व व्यय (आरईसीओ) व्यय की गुणवत्ता का एक सूचक है, 5.7 के बजट अनुमान (बीई) की तुलना में 2021-22 में पहली तिमाही में 6.8 पर रहा। सकल राजकोषीय घाटे के अनुपात में राजस्व घाटा (आरडी-जीएफडी) 75.7 प्रतिशत के बजट अनुमान के मुकाबले 62 प्रतिशत है (चार्ट 23) (मिश्रा और अन्य, 2021)²⁰

सारणी 3: केंद्रीय सरकार का कर राजस्व

	ति1 (₹ करोड़)			20210-22: ति1 में वृद्धि	
	2019-20	2020-21	2021-22	2020-21 की तुलना में	2019-20 की तुलना में
सकल कर राजस्व	4,00,421	2,69,686	5,31,606	97.1	32.8
प्रत्यक्ष कर	1,69,898	1,18,910	2,51,418	111.4	48.0
जिसमें से:					
निगम कर	70,640	54,212	1,23,689	128.2	75.1
आय कर	96,927	62,123	1,22,692	97.5	26.6
अप्रत्यक्ष कर	2,30,523	1,50,775	2,80,188	85.8	21.5
जिसमें से:					
जीएसटी	1,52,601	98,888	1,69,084	71.0	10.8
उत्पाद कर	36,951	35,347	67,907	92.1	83.8
सीमा-शुल्क	39,480	15,416	41,356	168.3	4.8

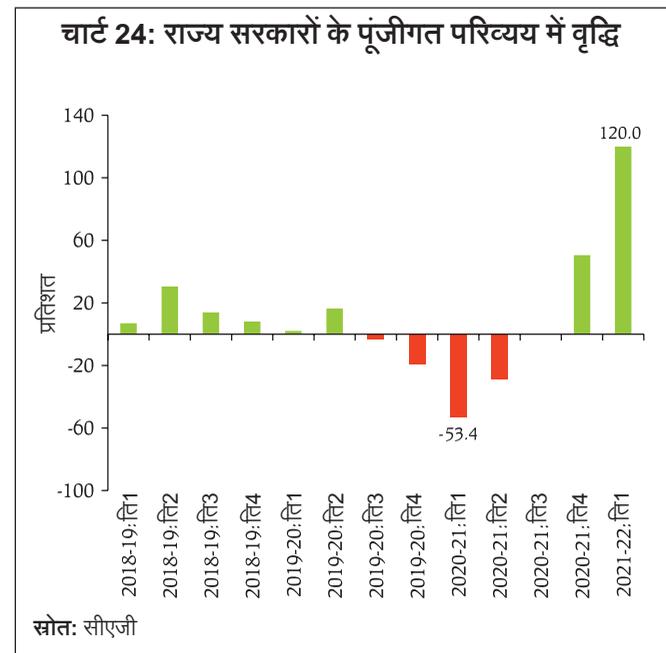
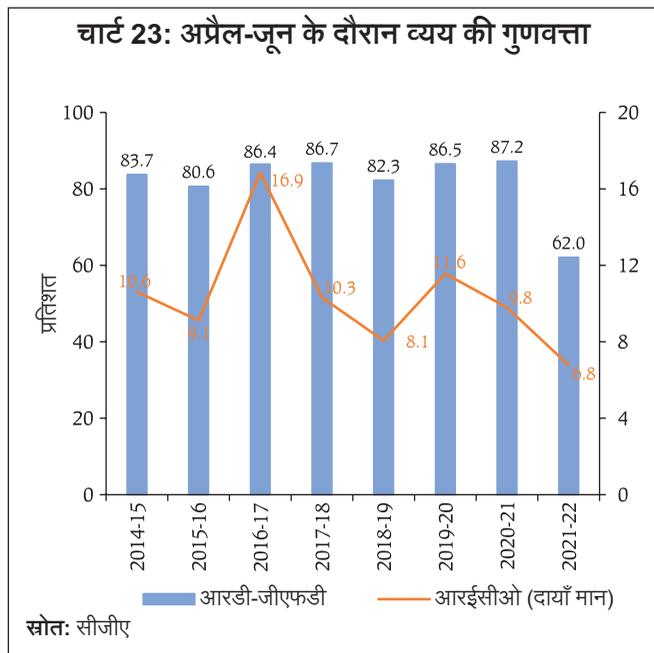
स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए)

²⁰ सामान्य सरकार के लिए, 5 से अधिक का आरईसीओ अनुपात और 40 प्रतिशत से अधिक का आरडी-जीएफडी अनुपात अनुभवजन्य रूप से स्थायी विकास प्रक्षेपवक्र के लिए उपयुक्त पाया जाता है। मिश्रा, एस., बेहरा, एसआर, सेठ, बी. और सूद, एस. (2021)। "राजकोषीय ढांचा और भारत में व्यय की गुणवत्ता"। भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, जून।

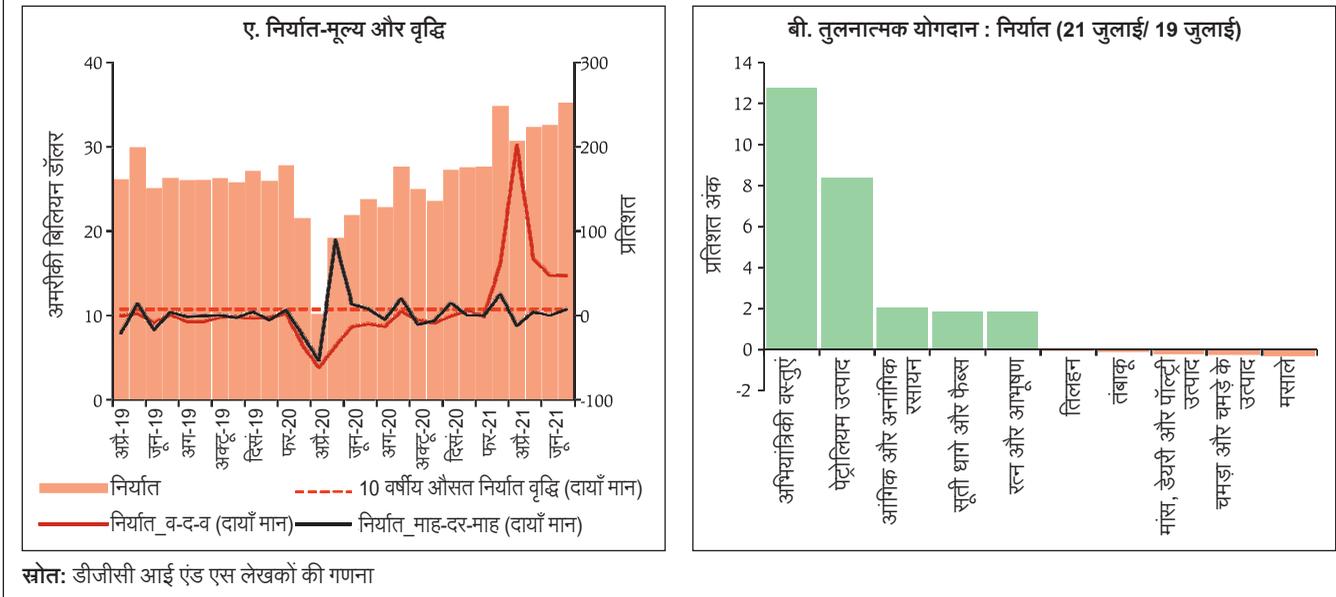


19 राज्यों के लिए उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, उनके पूंजी परिव्यय में 2020-21 में पहली तिमाही में 53.4 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 2021-22 में पहली तिमाही के दौरान तेजी से विस्तार हुआ है (चार्ट 24)। सरकार के सामान्य पूंजीगत व्यय में राज्यों की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक है।

भारत का व्यापारिक निर्यात जुलाई 2021 में लगातार पांचवें महीने में 30 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक रहा। इंजीनियरी वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों के लिए भागीदार देशों में मजबूत मांग ने निर्यात प्रदर्शन को संचालित किया (चार्ट 25ए और 25बी)। वास्तव में, 30 प्रमुख जिंस समूहों में से 22 इस व्यापक-आधार वाले विस्तार में शामिल थे।



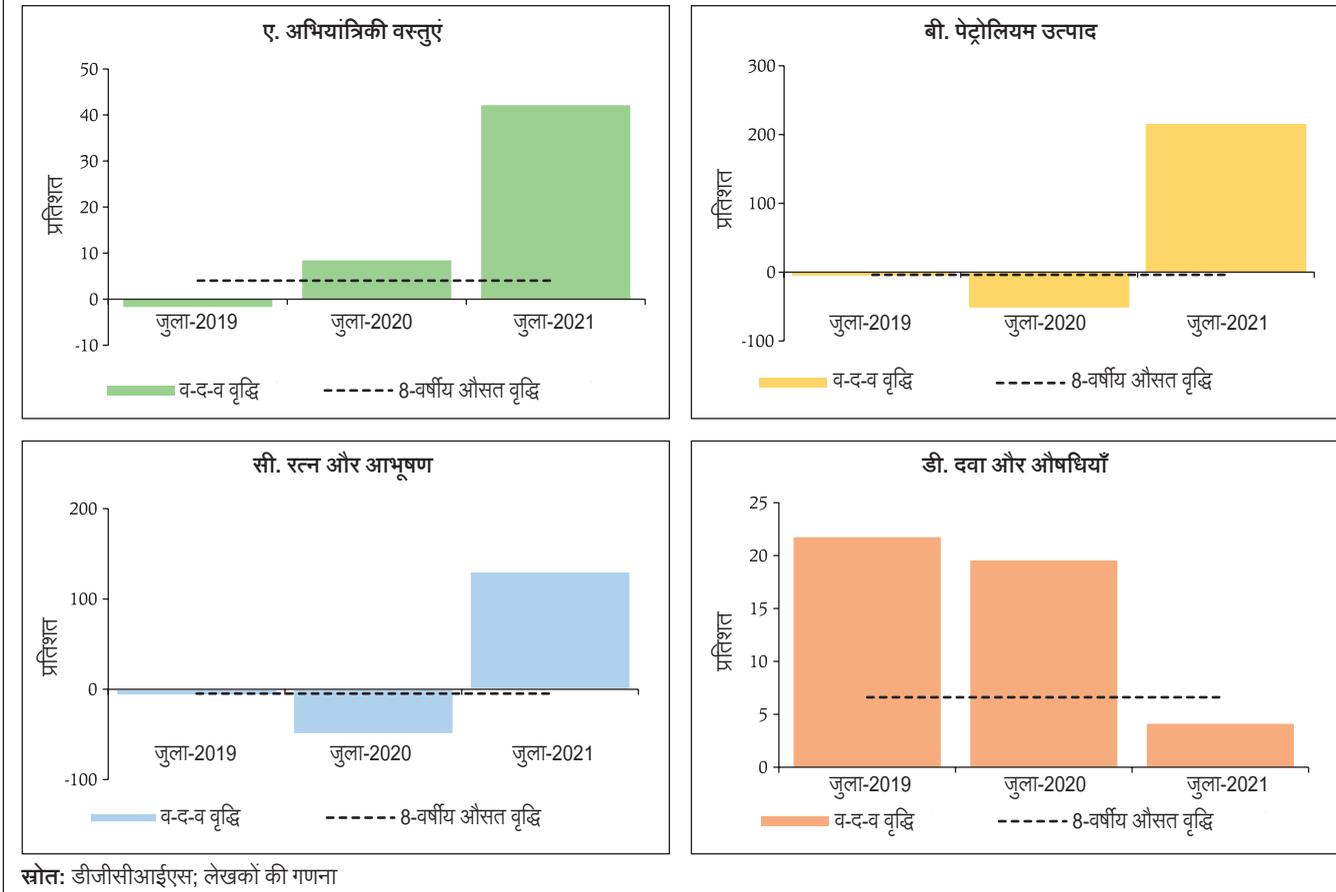
चार्ट 25: भारत का पण्य निर्यात- जुलाई 2021

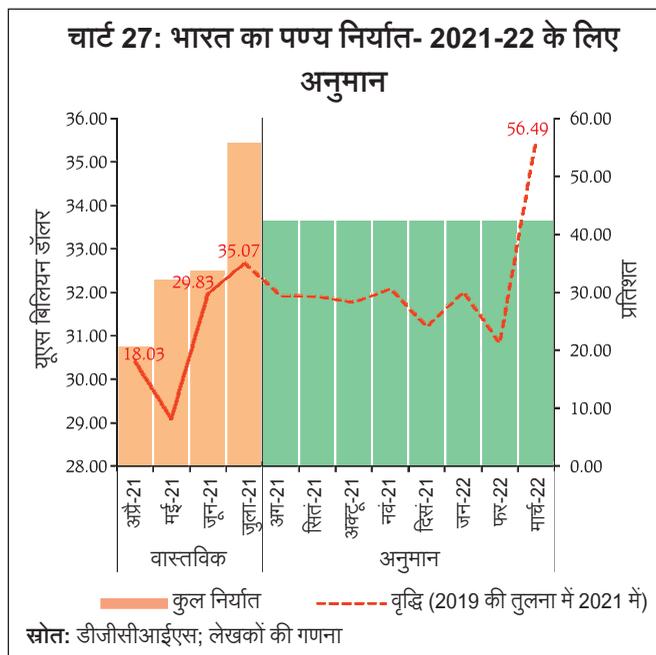


निर्यात प्रयासन की विकसित अवस्था कुछ वस्तुओं द्वारा प्रदान की जा रही है, जो एक साथ 2013-2020 की अवधि के मध्य

कुल निर्यात का लगभग 57.3 प्रतिशत हिस्सा था (चार्ट 26ए से 26डी)। इंजीनियरी वस्तुओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।

चार्ट 26: प्रमुख जिंसों में निर्यात वृद्धि





अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान, भारत का पण्य निर्यात 130.8 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जो भारत के 2021-22 के लिए निर्धारित 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निर्यात लक्ष्य का एक-तिहाई हिस्सा है (चार्ट 27)।

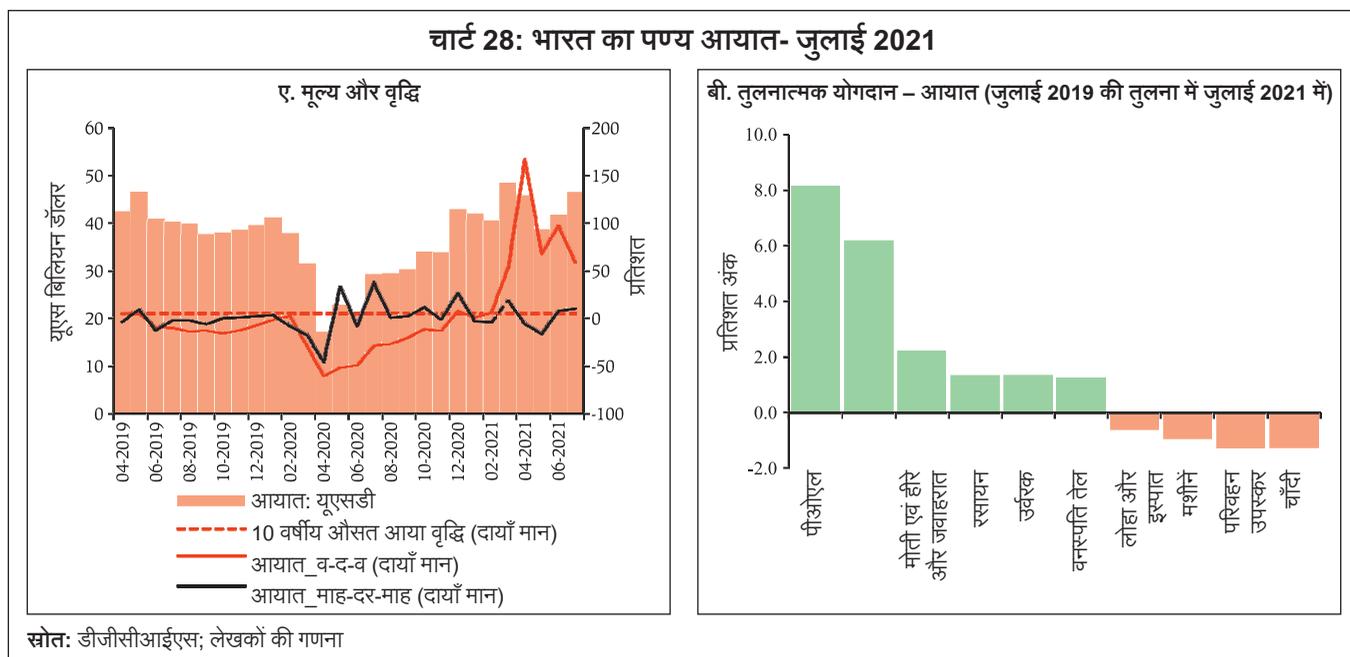
भारत का पण्य आयात महामारी-पूर्व के स्तर से अधिक हो गया है, जो आर्थिक गतिविधियों के मजबूत समुत्थान को दर्शाता

है (चार्ट 28ए)। तेल और सोने से इतर वस्तुओं का आयात लगातार आठ महीनों से 25 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हुआ है, जो घरेलू मांग के पुनरुद्धार की पुष्टि करता है। जुलाई 2019 के स्तर की तुलना में, 30 प्रमुख जिंस समूहों में से 18 के साथ व्यापक-आधार वाली आयात वृद्धि बनी हुई है (चार्ट 28बी)।

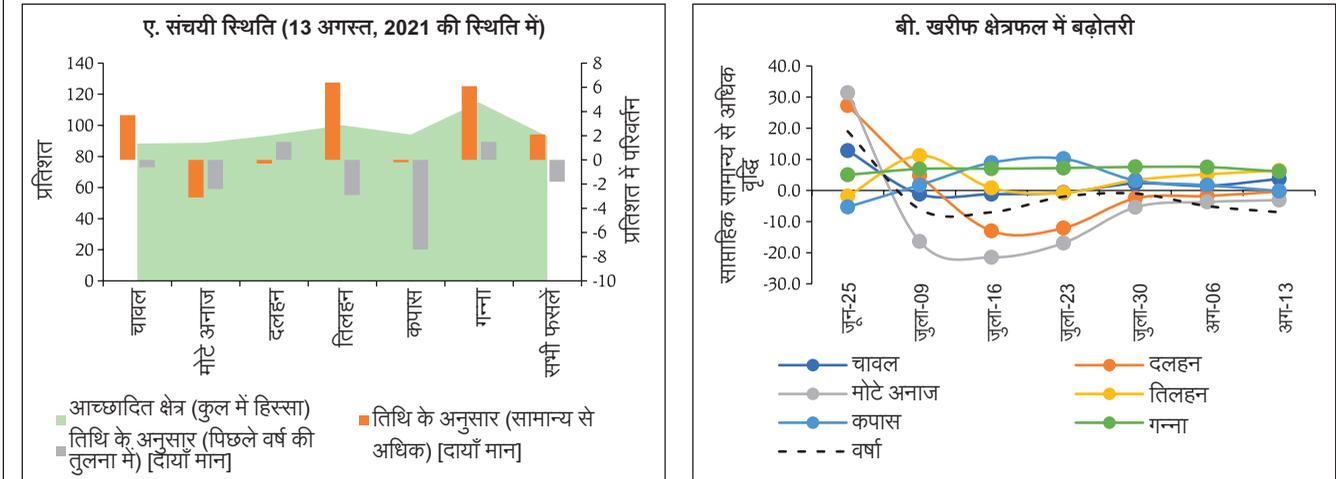
सकल आपूर्ति

दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने सामान्य स्तर पर पहुंच रहा है। संचयी वर्षा 1 जून से 13 अगस्त तक दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 7 प्रतिशत कम है, जबकि एक साल पहले एलपीए से 2 प्रतिशत अधिक थी।

मानसून की प्रगति के अनुरूप, बुवाई गतिविधि धीरे-धीरे गति पकड़ रही है। 13 अगस्त 2021 तक खरीफ का क्षेत्रफल 997.1 लाख हेक्टेयर था – जो एक साल पहले के स्तर से 1.8 प्रतिशत कम, लेकिन सामान्य क्षेत्रफल से 2.1 प्रतिशत अधिक था। कुल मिलाकर, लगभग 93 प्रतिशत बुवाई पहले ही पूरी हो चुकी है, जिसमें गन्ने का क्षेत्रफल सामान्य से अधिकतम 114.7 प्रतिशत दर्ज किया गया है। मुख्य खरीफ दलहन -अरहर का क्षेत्रफल एक साल पहले की तुलना में 5.2 प्रतिशत अधिक रहा है। अन्य दलहन और मोटे अनाज अभी भी सामान्य स्तर तक नहीं पहुंचे हैं (चार्ट 29)।



चार्ट 29: खरीफ बुवाई में सामाहिक प्रगति

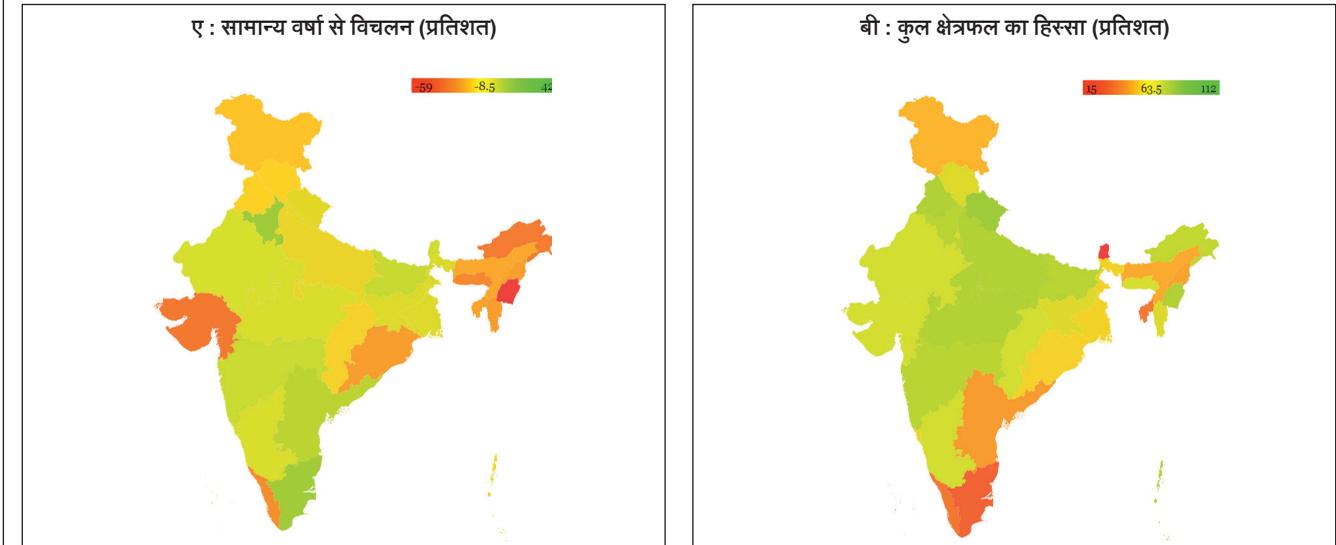


टिप्पणी: 2 जुलाई 2021 के लिए डेटा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था। फसलों के लिए "कुल क्षेत्रफल" और "सामाहिक सामान्य" 5 वर्षों का औसत है (2015-16 से 2019-20) सामान्य वर्षा को दीर्घावधि औसत (एलपीए) के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात 1951 और 2001 के मध्य 50 वर्षों की अवधि में हुई वर्षा का औसत।
स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एवं आईएमडी

राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि देश के उत्तरी और मध्य भागों में प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीफ की बुवाई पूरी होने के कगार पर है (चार्ट 30)। जून और जुलाई में उर्वरक बिक्री की गति मजबूत रही (चार्ट 31ए)।

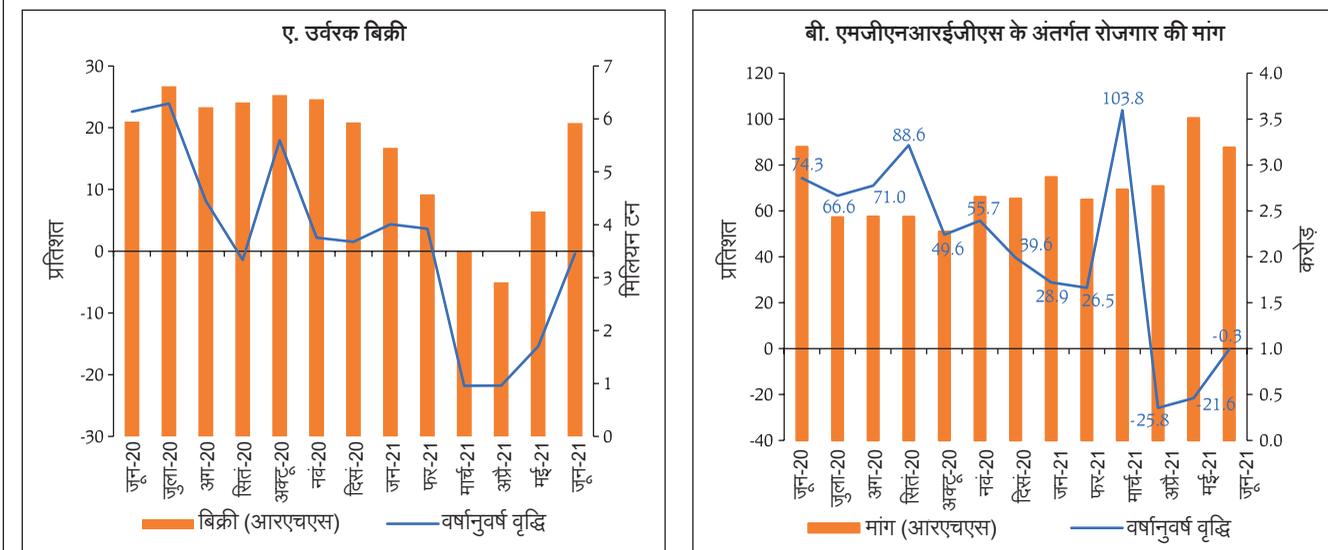
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए कृषि फसलों के उत्पादन का चतुर्थ अग्रिम अनुमान 11 अगस्त, 2021 को जारी किया है (चार्ट 32)। वर्ष 2020-21 लगातार पांचवें वर्ष खाद्यान्नों के रिकॉर्ड उत्पादन के रूप में

चार्ट 30: 6 अगस्त 2021 को राज्यवार वर्षा और फसल की स्थिति (खरीफ-2021)



टिप्पणी: कुल क्षेत्रफल 5 वर्षों का औसत है (2015-16 से 2019-20)
स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; आईएमडी; www.gramener.com

चार्ट 31 : कृषिगत गतिविधि संकेतक

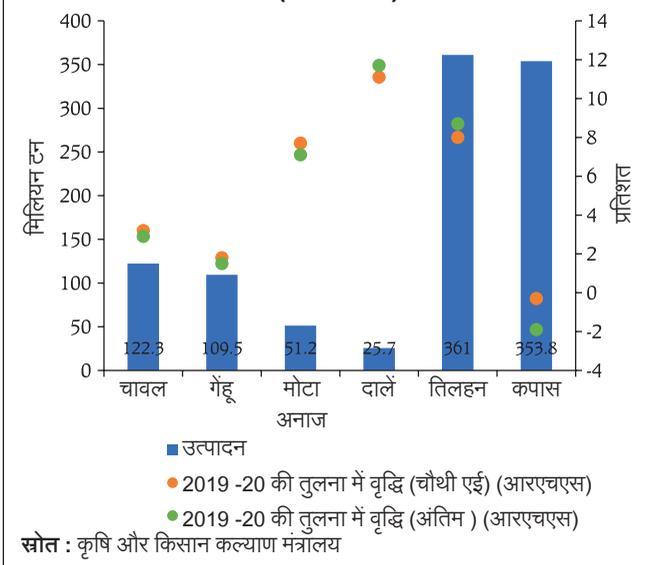


स्रोत : रसायन और उर्वरक मंत्रालय; ग्रामीण विकास मंत्रालय

चिह्नित हुआ है। उत्पादन में यह उच्च वृद्धि उच्च सार्वजनिक खरीद की प्रत्याशा में रिकॉर्ड उच्च एकड़, पर्याप्त अस्थायी और साथ ही स्थानिक वर्षा वितरण, श्रम की पर्याप्त आपूर्ति, निर्यात मांग में वृद्धि और उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायक नीतिगत उपायों से उपजी है।

198.8 लाख टन के कुल आवंटन में से 9 अगस्त, 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) 4.0 के तहत लाभार्थियों को कुल 41.8 लाख टन अनाज (चावल और गेहूँ) वितरित किया गया है। जुलाई के अंत तक, अनाज की स्टॉक स्थिति आरामदायक थी (बफर मानदंडों का 2.5 गुना) खाद्य सुरक्षा पर दृष्टिकोण के लिए अच्छा संकेत दे रही थी। हाल के नीतिगत उपाय, घरेलू आपूर्ति दबावों को दूर करने के उद्देश्य से अर्थात् खाद्य तेलों के आयात पर टैरिफ मूल्य में 112 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक की कमी, दाल के आयात पर सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना और दालों पर स्टॉकिंग मानदंड लागू करना भी शामिल हैं।

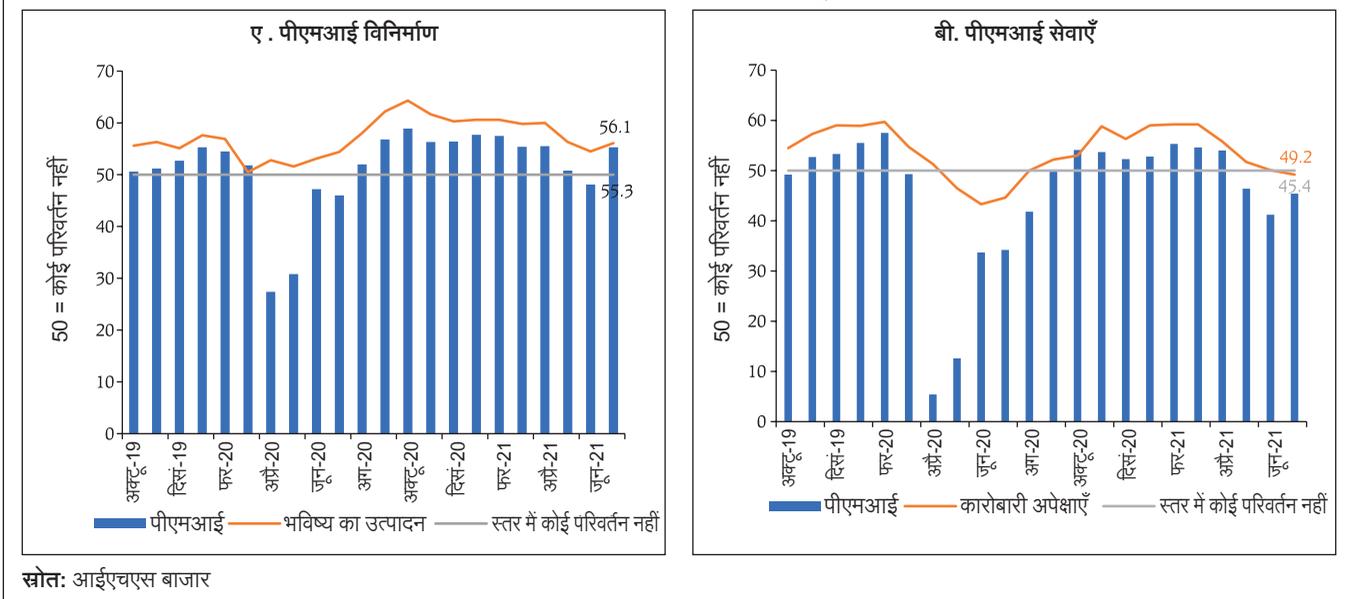
चार्ट 32 : फसल उत्पादन का चौथा अग्रिम आकलन (2020-21)



स्रोत : कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

अर्थव्यवस्था में तेजी की पुष्टि करते हुए, पीएमआई मैनुफैक्चरिंग इंडेक्स जुलाई में 11 महीने के अंतराल के बाद जून में दर्ज किए गए संकुचन से 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। सभी उप-सूचकांकों ने विस्तार का प्रदर्शन किया, आउटपुट और नए ऑर्डर में तेज रिबाउंड रिकॉर्ड किया गया (चार्ट 33ए)। दूसरी ओर, सेवा सूचकांक में लगातार तीसरे महीने संकुचन हुआ, लेकिन संकुचन एक महीने पहले के 41.2 से जुलाई में घटकर 45.4 पर आ गया (चार्ट 33 बी)।

चार्ट 33 : क्रय प्रबन्धक की सूची



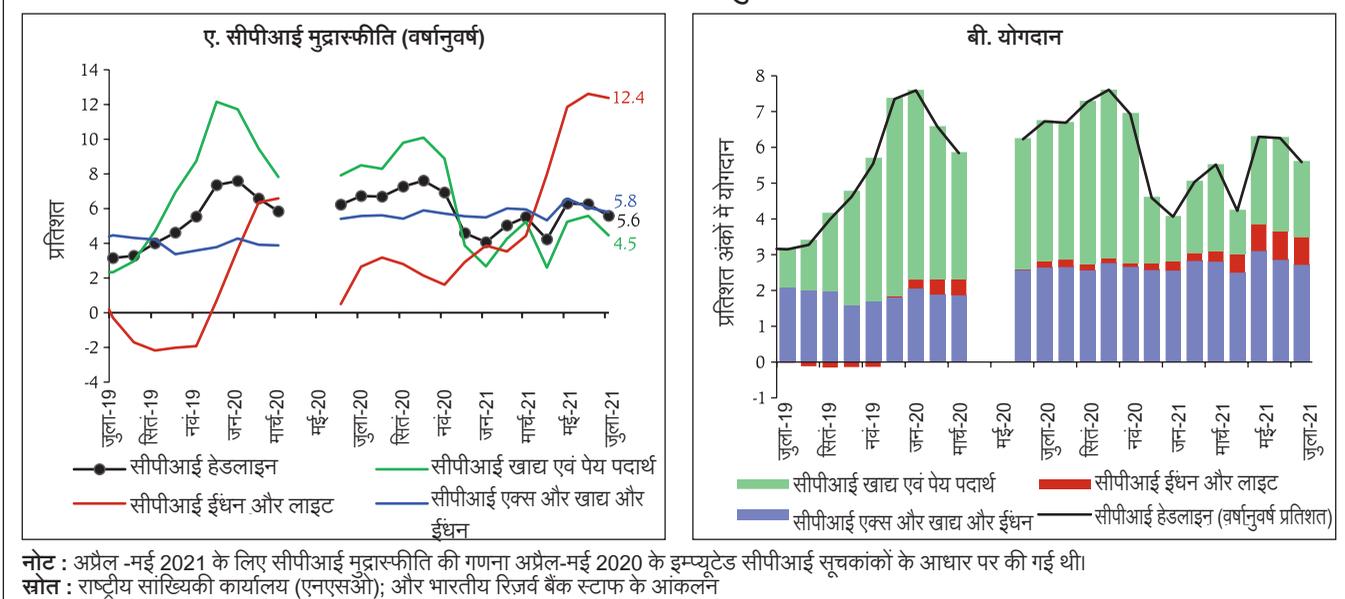
मुद्रास्फीति

12 अगस्त को, जुलाई 2021 के महीने के लिए हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 5.6 प्रतिशत पर आ गई, जो एक महीने पहले 6.3 प्रतिशत से 70 बीपीएस कम थी और इस विचार को मजबूत करती है कि हाल ही में उछाल चरम पर है और सबसे खराब हमारे पीछे होगा (चार्ट 34ए) लगभग 70 बीपीएस की सकारात्मक गति (चालू महीने में कीमतों में महीने-दर-महीने

बदलाव) के बावजूद, जो मुद्रास्फीति को बढ़ानी चाहिए थी, 140 बीपीएस के करीब बड़े अनुकूल आधार प्रभाव (एक साल पहले कीमतों में महीने-दर-महीने बदलाव) इसे संतुलित किया और जुलाई में हेडलाइन मुद्रास्फीति में मॉडरेशन लाया।

घटकों में, खाद्य और पेय पदार्थ मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 4.5 प्रतिशत हो गई, जो जून में 5.6 प्रतिशत थी जो तेल और वसा, फलों, दालों, तैयार भोजन और मसालों में मुद्रास्फीति में

चार्ट 34 : सीपीआई मुद्रास्फीति



नरमी के साथ सब्जियों की कीमतों में गिरावट और चीनी की कीमतें अपस्फीति की ओर बढ़ रही हैं। दूसरी ओर, मांस, मछली, अंडे और दूध में मुद्रास्फीति बढ़ी।

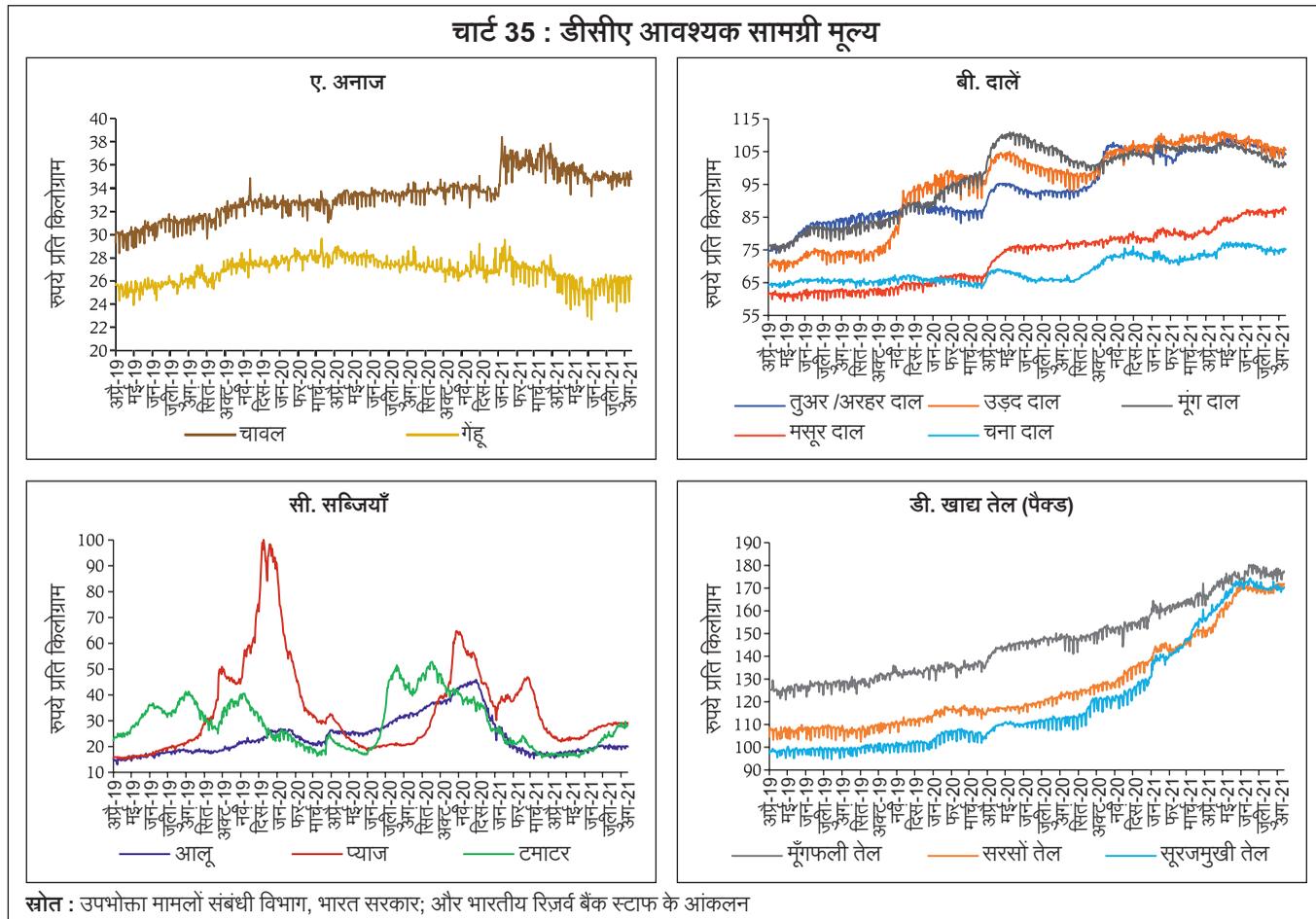
ईंधन मुद्रास्फीति जुलाई में 12.4 प्रतिशत पर दोहरे अंकों में रही, हालांकि यह जून में 12.6 प्रतिशत के ऐतिहासिक उच्च स्तर से लगभग 20 बीपीएस कम थी। एलपीजी, केरोसिन, और जलाऊ लकड़ी और चिप्स में उच्च मुद्रास्फीति ने समग्र ईंधन मुद्रास्फीति को ऊंचा रखा। सीपीआई ईंधन और लाइट (सीपीआई में 6.84 प्रतिशत का भार) ने जुलाई में हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 14 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट 34बी)।

खाद्य और ईंधन या मूल मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति जुलाई 2021 में 30 बीपीएस के करीब 5.8 प्रतिशत तक नरम हो गई, जो जून में 6.1 प्रतिशत थी, जो परिवहन और संचार (मुख्य रूप से मोबाइल टेलीफोन शुल्क, बस किराए और

मोटर वाहन), व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव (मुख्य रूप से सोने और चांदी के कारण), घरेलू सामान और सेवाएं (मुख्य रूप से घरेलू रसोइया / नौकर जैसी घरेलू सेवाओं के कारण) और शिक्षा (मुख्य रूप से ट्यूशन और अन्य शुल्क से) में मुद्रास्फीति में कमी के कारण थी। दूसरी ओर मनोरंजन (मुख्य रूप से टेलीविजन, कंप्यूटर और समाचार पत्रों के कारण), पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ, कपड़े और जूते, और आवास में मुद्रास्फीति बढ़ी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामलों संबंधी विभाग) के उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा अगस्त में अब तक (1-12 अगस्त, 2021) अनाज की कीमतों में तेजी का संकेत देते हैं। दूसरी ओर दालों की कीमतों में नरमी जारी है। खाद्य तेल की कीमतों में कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। प्रमुख सब्जियों में आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में कुछ मौसमी वृद्धि देखी गई (चार्ट 35)।

चार्ट 35 : डीसीए आवश्यक सामग्री मूल्य



सारणी 4: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

मद	इकाई	घरेलू कीमतें			महीने दर महीने (प्रतिशत)	
		अग-20	जुला-21	अग-21 [^]	जुला-21	अग-21
पेट्रोल	₹/लीटर	83.80	102.81	103.56	4.5	0.7
डीजल	₹/लीटर	77.40	93.51	93.68	2.8	0.2
मिट्टी का तेल (सब्सिडी)	₹/लीटर	22.92	33.34	34.29	3.8	2.8
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	604.88	845.13	845.13	3.1	0.0

[^]: 1-12 अगस्त, 2021 की अवधि के लिए

नोट: केरोसिन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की औसत कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मिट्टी के तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का आकलन है।

जुलाई 2021 के मध्य से 12 अगस्त, 2021 तक, पंप की कीमतें पेट्रोल के लिए ₹103.56 प्रति लीटर (चार प्रमुख महानगरों में पंप की कीमतों का औसत) और डीजल के लिए ₹93.68 प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई हैं। जबकि मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई, अगस्त की पहली छमाही में रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया (सारणी 4)।

इनपुट लागत, जैसा कि पीएमआई में परिलक्षित होता है, जुलाई में विनिर्माण और सेवाओं में और बढ़ गया, लेकिन लागत में वृद्धि की दर मामूली रही। जुलाई में विनिर्माण और सेवाओं के लिए बिक्री मूल्य में वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि इनपुट लागत के पास-थ्रू की सीमा शांत रही। औद्योगिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण पर रिजर्व बैंक के इन-हाउस सर्वेक्षण से पता चलता है कि उच्च इनपुट लागत दबाव ति.2: 2021-22 में बने रहने की संभावना है। फर्मों से यह अपेक्षा है कि वे दूसरी तिमाही में विशेष रूप से सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए बिक्री मूल्य बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर लागत का बोझ डाल सकती हैं।

IV. वित्तीय स्थितियां

बाजार के विश्वास को पोषित करने, वित्तीय स्थितियों को अनुकूल रखने और वित्तीय प्रणाली में निधियों की लागत को कम करने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए रिजर्व बैंक ने चलनिधि प्रबंधन के लिए कई उपायों की घोषणा की। सबसे पहले,

इसने जुलाई 2021 में द्वितीयक बाजार जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम संस्करण 2.0 (जी-एसएपी 2.0) शुरू किया, जो कि 2021-22 की दूसरी तिमाही में ₹ 1,20,000 करोड़ मूल्य के जी-सेक खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें से 8 और 22 जुलाई, 2021 को आयोजित नीलामी के माध्यम से ₹20,000 करोड़ के दो चरणों में ₹40,000 करोड़ के जी-सेक का अधिग्रहण किया गया था। प्रत्येक ₹25,000 करोड़ की दो और नीलामी की घोषणा 6 अगस्त को की गई थी, जिनमें से एक 12 अगस्त को आयोजित की गई थी और दूसरी है 26 अगस्त 2021 के लिए निर्धारित की गई है। प्रतिफल वक्र के सुचारु विकास को चलाने के लिए और टर्म संरचना में चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 14 साल तक की परिपक्वता अवधि में प्रतिभूतियों को खरीदा है, जिसमें 5 से 9 वर्ष से अधिक की परिपक्वता बकेट पर जोर दिया गया है। (सारणी 5)। इसके अलावा, 6 अगस्त के अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में, गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने समझाया कि जी-एसएपी नीलामी और ऑपरेशन ट्विस्ट में ऑफ द रन और ऑन रन सिक्क्योरिटीज दोनों को शामिल करने के लिए विकल्प हमेशा खुले हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, उम्मीद यह है कि "द्वितीयक बाजार की मात्रा में वृद्धि होगी और बाजार सहभागियों [होने वाले] ऐसे पदों को ले लेंगे जो प्रतिफल में दो-तरफा गतिविधियों को अंजाम देंगे"।²¹

दूसरा, रिजर्व बैंक ने विशिष्ट महामारी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऑन-टैप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन (टीएलटीआरओ)

सारणी 5: जी-एसएपी के तहत खरीदी गई सरकारी**प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल (12 अगस्त 2021 तक)**

अगस्त 2021 (वर्षों) में अवशिष्ट परिपक्वता	खरीदी गई सरकारी प्रतिभूति का अंकित मूल्य (₹ करोड़)	कुल खरीद में हिस्सा (प्रतिशत)
5 तक	34.174	21.4
5 से 10 से अधिक	1,05,792	66.3
10 से 14 से अधिक	19,609	12.3
कुल	1,59,575*	

*: जी-एसएपी के अंतर्गत की गई कुल खरीदारी ₹1,65,000 करोड़ थी, जिसमें 17 जून, 2021 को ₹1,59,575 करोड़ की सरकारी प्रतिभूति और ₹5,425 करोड़ की एसडीएल की खरीद शामिल है।

²¹ गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य, 6 अगस्त, 2021।

²² इस योजना की घोषणा 9 अक्टूबर, 2020 को पांच क्षेत्रों के लिए की गई थी और दिसंबर 2020 में कामथ समिति द्वारा पहचाने गए तनावग्रस्त क्षेत्रों और फरवरी 2021 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक ऋण देने के लिए विस्तारित की गई थी।

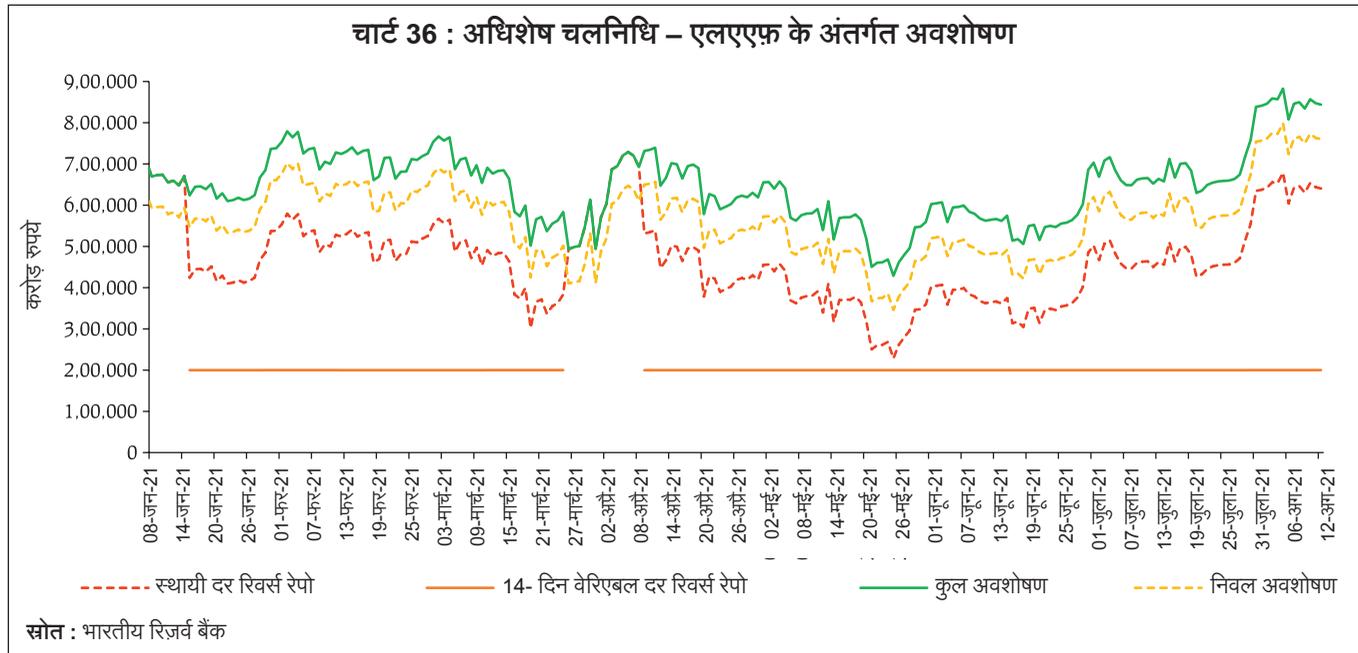
योजना²² को दिसंबर 2021 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त, चलनिधि व्याप्तता अनुपात (एलसीआर), को पूरा करने सहित उनकी चलनिधि आवश्यकताओं के संबंध में बैंकों को राहत प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने भी बैंकों के लिए सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) के तहत धन का लाभ उठाने के लिए वैधानिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में अतिरिक्त एक प्रतिशत तक की छूट की अवधि को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के अतिरिक्त एक प्रतिशत तक, यानी कुल मिलाकर एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक घटाने के माध्यम से बढ़ा दिया है।

तीसरा, 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी के तहत राशि को 13 अगस्त, 2021 को बढ़ाकर ₹2.5 लाख करोड़ कर दिया गया है; 27 अगस्त, 2021 को ₹3.0 लाख करोड़; 9 सितंबर, 2021 को ₹3.5 लाख करोड़; और 24 सितंबर 2021 को ₹4.0 लाख करोड़। जवाब में, मीडिया के एक वर्ग ने 11 जनवरी, 2021 के भूतों को फिर से जीवित करने की कोशिश की है, जब बाजारों ने ₹ 2 लाख करोड़ की वीआरआरआर नीलामी की पहली घोषणा को चलनिधि की सख्ती के रूप में गलत समझा। वे आशंकाएँ निराधार साबित हुईं।

इस बार कुछ वर्गों में, वीआरआरआर समय पथ को मुद्रास्फ़िति पूर्वानुमान में ऊपर की ओर समायोजन से जोड़ा गया है और इसे संयोग से कहीं अधिक रूप में गलत समझा गया है। हम उन्हें स्पष्ट रूप से अलग के रूप में देखते हैं और इसलिए, मुद्रास्फ़िति पूर्वानुमान के आसपास के मुद्दों को समापन खंड में संबोधित किया गया है; यहाँ, वीआरआरआर का औचित्य निर्धारित किया गया है। पहला, वीआरआरआर नीलामियों के तहत राशि बढ़ाने का सुझाव और नीति-पूर्व परामर्श के हिस्से के रूप में बाजार सहभागियों की ओर से प्रगतिशील कार्रवाई के समान गति वाले समय पथ की पूर्व-घोषणा करने का सुझाव दिया गया। हम मानते हैं कि अनुरोध उन प्रतिभागियों के दृष्टिकोण से उचित है जो अपने चलनिधि संचालन की अच्छी तरह से योजना बनाते हैं और उच्च पारिश्रमिक के रूप में समय वरीयता के लिए

एक इनाम चाहते हैं, जो 'निष्क्रिय' बैंकिंग के विपरीत है, जो ओवरनाइट आधार पर फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो दर पर आलस्य के अधीन पार्किंग के पक्ष में है। दूसरा, रिजर्व बैंक ने बड़ी मेहनत से इस बात पर जोर दिया है कि वीआरआरआर नीलामियां सिस्टम चलनिधि अधिशेष का एक अभिन्न अंग हैं। परिवर्तनीय दर नीलामी या फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो का चुनाव पूरी तरह से बाजार सहभागियों के पास है। वे शुरू से ही ओवरनाइट फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो का विकल्प चुन सकते हैं या भले ही उन्होंने 14 दिनों के लिए रिजर्व बैंक के पास फंड रखा हो, वे नीलामी अवधि के अंत में वापस ले सकते हैं और या तो उन्हें रात भर के लिए फिक्स्ड रेट पर पार्क कर सकते हैं या उन्हें बाजार में तैनात कर सकते हैं। तीसरा, वीआरआरआर की चुपके से चलनिधि निकासी उपकरण होने की धारणा बेतुकी है जब रिजर्व बैंक एक साथ जीएसएपी और अन्य चलनिधि इंजेक्शन संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सितंबर के अंत में, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत ₹ 8.5 लाख करोड़ की चलनिधि के वर्तमान ओवरहैंग में से, लगभग ₹4.5 लाख करोड़ अभी भी निश्चित दर पर रातोंरात रिवर्स रेपो विंडो में पार्क किए जाएंगे यदि यह तब तक भी आगे नहीं बढ़ा है तो। चौथा, मार्च 2020 से, रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन संचालन को ऑटो-पायलट मोड में रखा गया है, जिसमें केवल सीमांत स्थायी सुविधा और निश्चित दर रिवर्स रेपो निष्क्रिय रूप से उपलब्ध है। रोकथाम के उपायों में ढील दिए जाने, कार्यस्थलों पर सामान्य स्थिति में लौटने और वित्तीय बाजार के समय को बहाल करने के साथ, यह केवल चलनिधि प्रबंधन संचालन को नियमित करने के लिए उपयुक्त है - 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर नीलामी इसके मुख्य साधन के रूप में है - ताकि वे अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठा सकें।

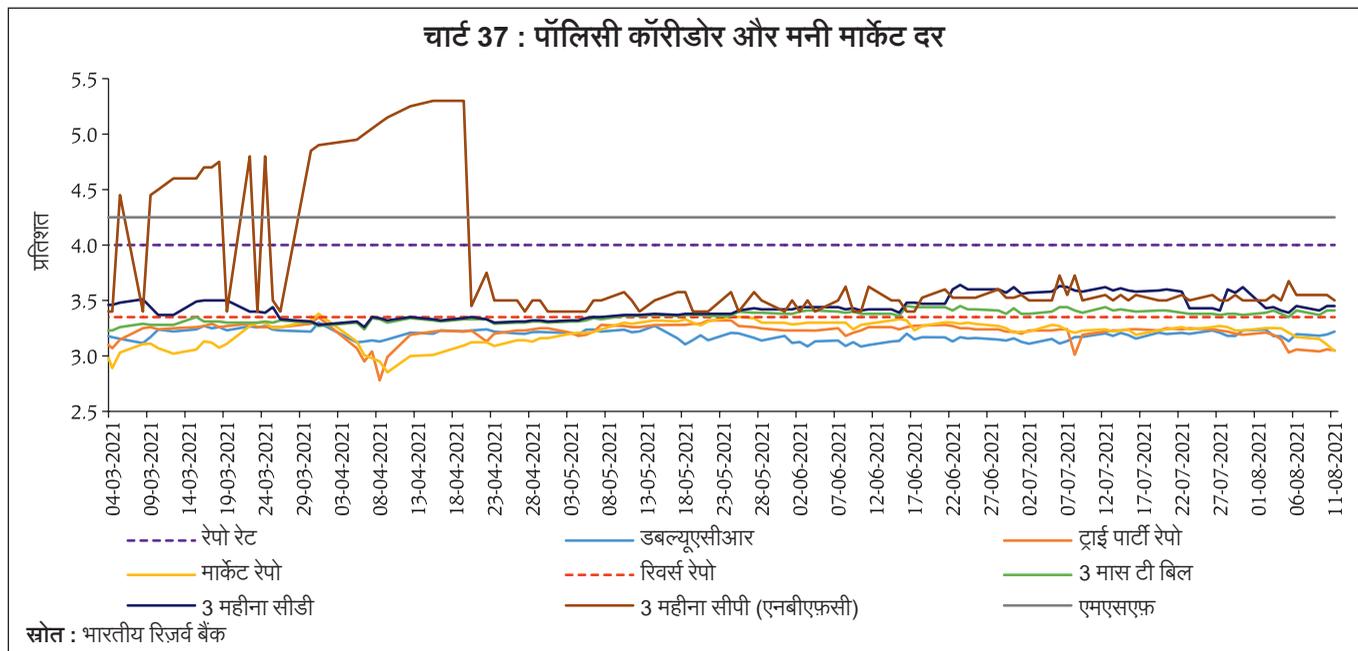
रिजर्व बैंक के चलनिधि बढ़ाने के उपायों से उत्साहित, सिस्टम चलनिधि से भरा रहा, एलएएफ के तहत औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण के रूप में अधिशेष जुलाई के दौरान ₹ 6.0 लाख करोड़ और अगस्त में ₹4.9 लाख करोड़ एक महीने पहले की तुलना में ₹ 7.6 लाख करोड़ (12 अगस्त तक) तक बढ़ गया (चार्ट 36)।

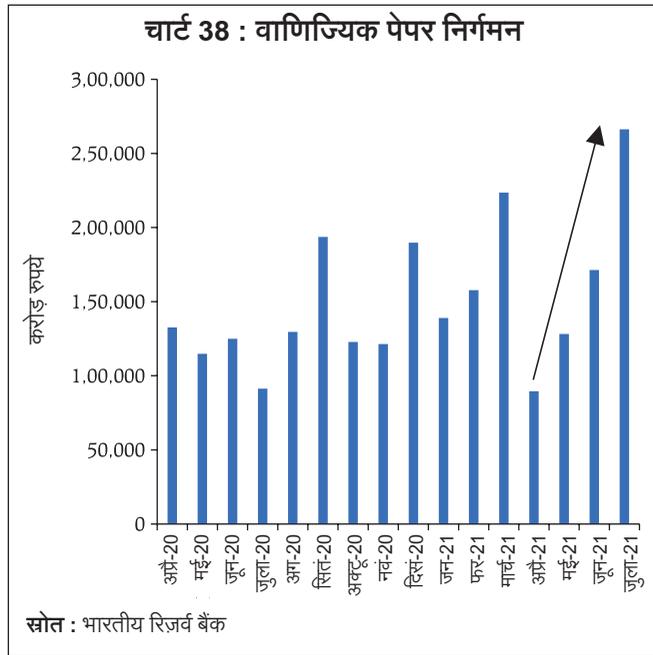


अनुकूल चलनिधि स्थितियों से प्रेरित होकर, ओवरनाइट मुद्रा बाजार दर - भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर), त्रि-पक्षीय रेपो और बाजार रेपो दर - जुलाई के मध्य से अगस्त 2021 (12 अगस्त तक) के दौरान क्रमशः 15 बीपीएस, 18 बीपीएस और 14 बीपीएस द्वारा रिवर्स रेपो दर से नीचे कारोबार किया गया। सावधि मुद्रा बाजार दरें, जिसमें जमा प्रमाणपत्र (सीडी) दरें, 3

महीने का वाणिज्यिक पत्र [गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)] दरें और 3 महीने की टी-बिल दर शामिल हैं, रिवर्स रेपो दर से थोड़ा ऊपर कारोबार करती हैं (चार्ट 37)।

अनुकूल चलनिधि स्थितियों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कॉरपोरेट्स ने धन जुटाने के लिए वाणिज्यिक पत्र (सीपी) बाजार का सहारा लिया है, भले ही बैंक ऋण मंद रहा हो। जुलाई





2021 में सीपी निर्गम 190 प्रतिशत से अधिक बढ़कर ₹2.66 लाख करोड़ हो गया, जो जून में ₹1.71 लाख करोड़ और पहली तिमाही में ₹3.89 लाख करोड़ था। संचयी रूप से, अप्रैल-जुलाई 2021 के लिए सीपी जारी करना 41.3 प्रतिशत बढ़कर ₹6.55 लाख करोड़ हो गया, जो अप्रैल-जुलाई 2020 के दौरान ₹4.64 लाख करोड़ था (चार्ट 38)।

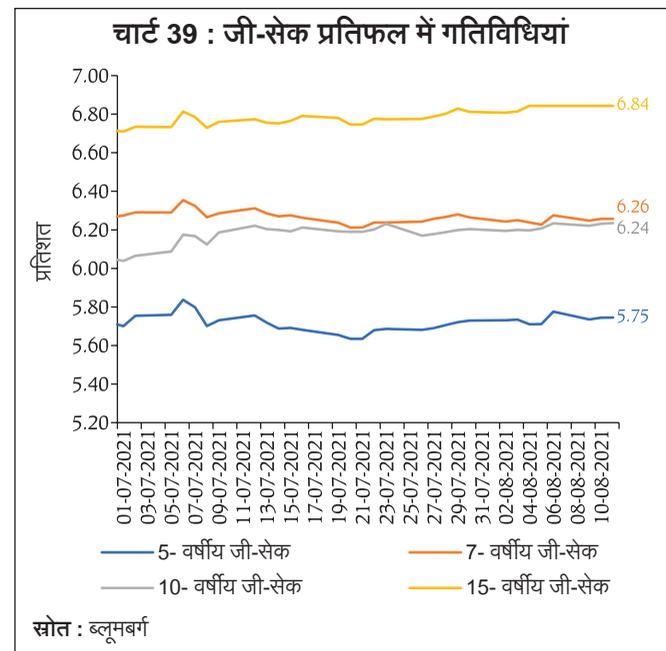
इस लेख के जुलाई संस्करण में, यह आशा की गई थी कि 9 जुलाई की प्राथमिक नीलामी के परिणामों में सन्निहित नीति मार्गदर्शन और बाजार की अपेक्षाओं का संगम शेष वर्ष में प्रतिफल वक्र के क्रमिक विकास को बनाए रखेगा और सुविधा प्रदान करेगा। अनुकूल रूप से, इस अभिसरण के लिए स्थितियां भी बन गईं। सबसे पहले, जीएसटी की कमी के कारण अतिरिक्त उधारी की आशंका को दूर किया गया। दूसरा, रिज़र्व बैंक ने बहु मूल्य प्राथमिक नीलामियों में विजेता के अभिशाप के संबंध में निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक समान मूल्य नीलामियों का सहारा लिया। तीसरा, जीएसएपी और अन्य संचालन पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने और प्रतिफल वक्र के साथ इसके वितरण को सुनिश्चित करने के लिए किए गए थे। चौथा, 12 जुलाई को आई सीपीआई की जून रीडिंग में खुदरा हेडलाइन मुद्रास्फीति का स्तर गिर गया, हालांकि यह पिछले महीने के ऊंचे स्तर पर था, और उल्लेखनीय बात यह है कि कोर मुद्रास्फीति में 40

आधार अंकों की गिरावट आई है। द्वितीयक बाजार में, अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में गिरावट और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कमी के अनुसरण में जुलाई के मध्य तक प्रतिफल कम हुआ।

23 जुलाई और 6 अगस्त की प्राथमिक नीलामियों में, हालांकि, नीति-बाजार की आम सहमति टूट गई क्योंकि बाजार सहभागियों ने पहले वर्णित सभी घटनाओं के लिए अभेद्य हो गए और विशेष रूप से बेंचमार्क कागजात के संबंध में अधिक मंदी की बोली लगाई।

रिज़र्व बैंक इस बात पर ज़ोर देता रहा है कि वह सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल को पत्थर के रूप में नहीं देखता है, बल्कि वह इन्हें अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप व्यवस्थित तरीके से विकसित होता हुआ देखता है। इसने अन्य वित्तीय बाजार खंडों के लिए बेंचमार्क स्थापित करके मौद्रिक संचरण को सुविधाजनक बनाने में सरकारी प्रतिभूति बाजार की प्रमुख भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है। यह तब महत्व रखता है जब क्रेडिट चैनल मंद है और महामारी की लहरों से वित्तीय बाजारों और संस्थानों के अस्थिर हो जाने का खतरा बना हुआ है।

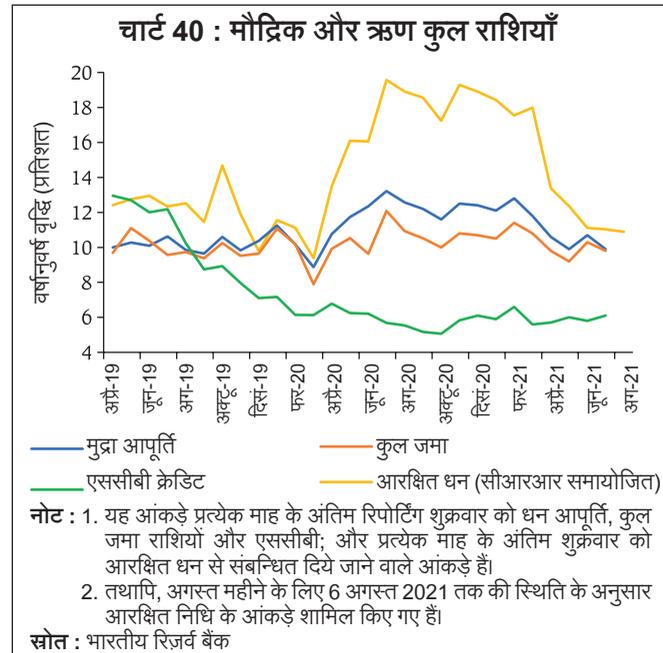
जुलाई के मध्य से, 12 अगस्त, 2021 को 10 वर्षीय बेंचमार्क (6.31 जीएस 2031) प्रतिफल के 6.23 प्रतिशत पर समाप्त होने के साथ प्रतिफल सख्त हो गए हैं (चार्ट 39)।



जी-सेक गतिविधियों को प्रतिबिंबित करते हुए, कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिफल सख्त हो गया और एक महीने पहले से जुलाई और अगस्त के पहले आधे भाग में रेटिंग स्पेक्ट्रम और जारीकर्ता श्रेणियों में फैल गया (सारणी 6)। (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), बैंकों और वित्तीय संस्थान (एफआई), (ii) कॉरपोरेट्स और (iii) एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए संगत परिपक्वता के जी-सेक प्रतिफल पर 3-वर्षीय एए रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड का औसत प्रसार अगस्त (12 अगस्त तक) में क्रमशः 14 बीपीएस, 8 बीपीएस और 6 बीपीएस तक बढ़ा।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की बहाली के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर आरक्षित निधि (आरएम) वास्तव में एक साल पहले दर्ज की गई वृद्धि के संबंध में धीमा हो गया (चार्ट 40)। परिचालन में मुद्रा - आरएम का सबसे बड़ा घटक है - 10.0 प्रतिशत की दर पर बढ़ा (एक साल पहले 22.4 प्रतिशत), जो नवंबर 2017 के बाद से दर्ज की गई मुद्रा मांग की सबसे धीमी गति है। पहली तिमाही में मौसमी मंदी के बाद जमा संग्रहण लचीला बना हुआ है; तथापि, वाणिज्यिक क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का ऋण अभी भी काफी पीछे है।

अधिशेष चलनिधि की स्थिति और बाहरी बेंचमार्क-आधारित मूल्य निर्धारण के कारण मार्च 2020 के बाद से एससीबी की उधारी और जमा दरों में नीतिगत दरों में बदलाव के संचरण में



काफी सुधार हुआ है। मार्च 2020 से जुलाई 2021 के दौरान फंड-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की 1 साल की औसत सीमांत लागत में संचयी रूप से 100 बीपीएस की नरमी आई। इसी अवधि के दौरान, सभी अवधियों में औसत सावधि जमा दर (ताजा जमा पर) 150 बीपीएस से कम हो गई (चार्ट 41ए), एक वर्ष (178 बीपीएस) तक की परिपक्वता जमाराशियों में गिरावट के

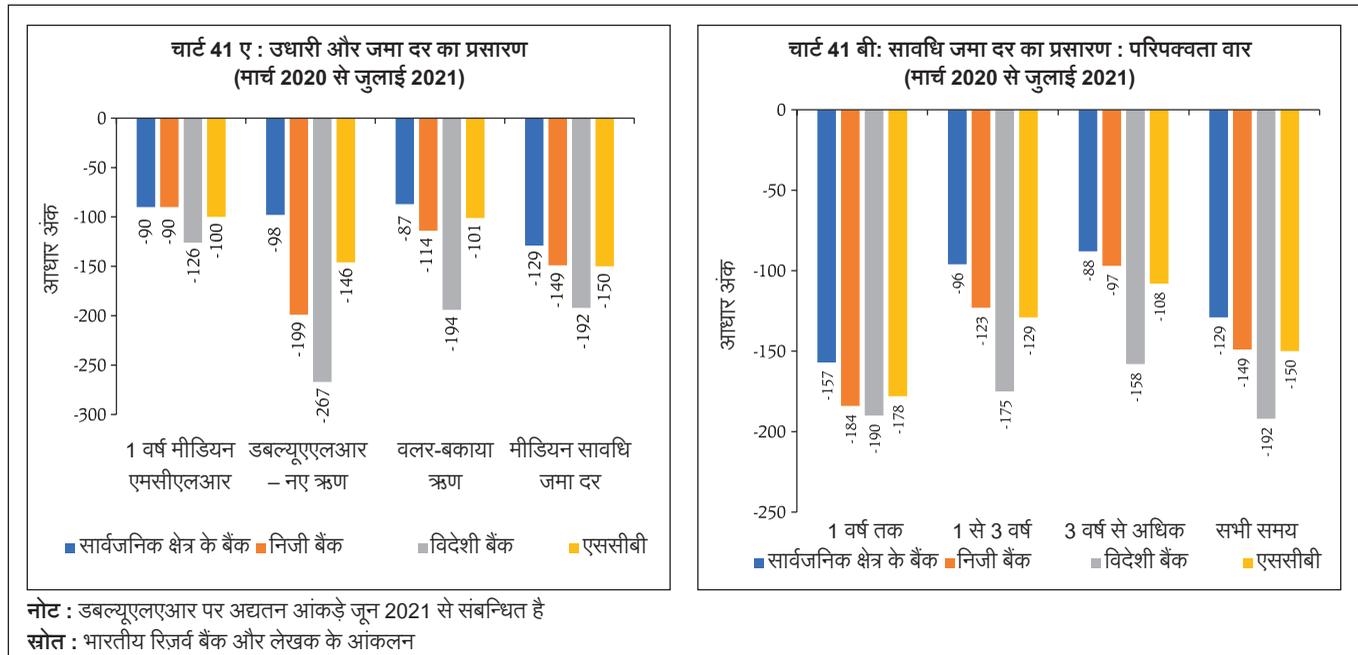
सारणी 6 : कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल और स्प्रेड

जारीकर्ता	रेटिंग	प्रतिफल					स्प्रेड				
		अग-20	जुला-21	अग-21*	परिवर्तन (अगस्त 2020 की तुलना में अगस्त 2021)	परिवर्तन (जुलाई 2021 की तुलना में अगस्त 2021)	अग-20	जुला-21	अग-21*	परिवर्तन (अगस्त 2020 की तुलना में अगस्त 2021)	परिवर्तन (जुलाई 2021 की तुलना में अगस्त 2021)
		(प्रतिशत)			(बीपीएस)		(बीपीएस)			(बीपीएस)	
पीएसयू, बैंक और एफआई	एए	5.23	5.49	5.59	36	10	45	45	59	14	14
	एए	5.95	6.30	6.32	37	2	117	126	132	15	6
	बीबीबी-	9.13	9.45	9.46	33	1	435	441	446	11	5
कॉर्पोरेट्स	एए	5.38	5.22	5.26	-12	4	60	18	26	-34	8
	एए	6.30	6.10	6.11	-19	1	152	105	111	-41	6
	बीबीबी-	10.23	9.98	10.06	-17	8	545	496	506	-39	10
एनबीएफसी	एए	5.56	5.43	5.44	-12	1	78	38	44	-34	6
	एए	6.73	6.42	6.32	-41	-10	195	138	132	-63	-6
	बीबीबी-	10.95	10.57	10.51	-44	-6	617	553	551	-66	-2

*:12 अगस्त 2021 तक

नोट : प्रतिफल और स्प्रेड 3 वर्षों के कारपोरेट बॉन्ड का मासिक औसत है

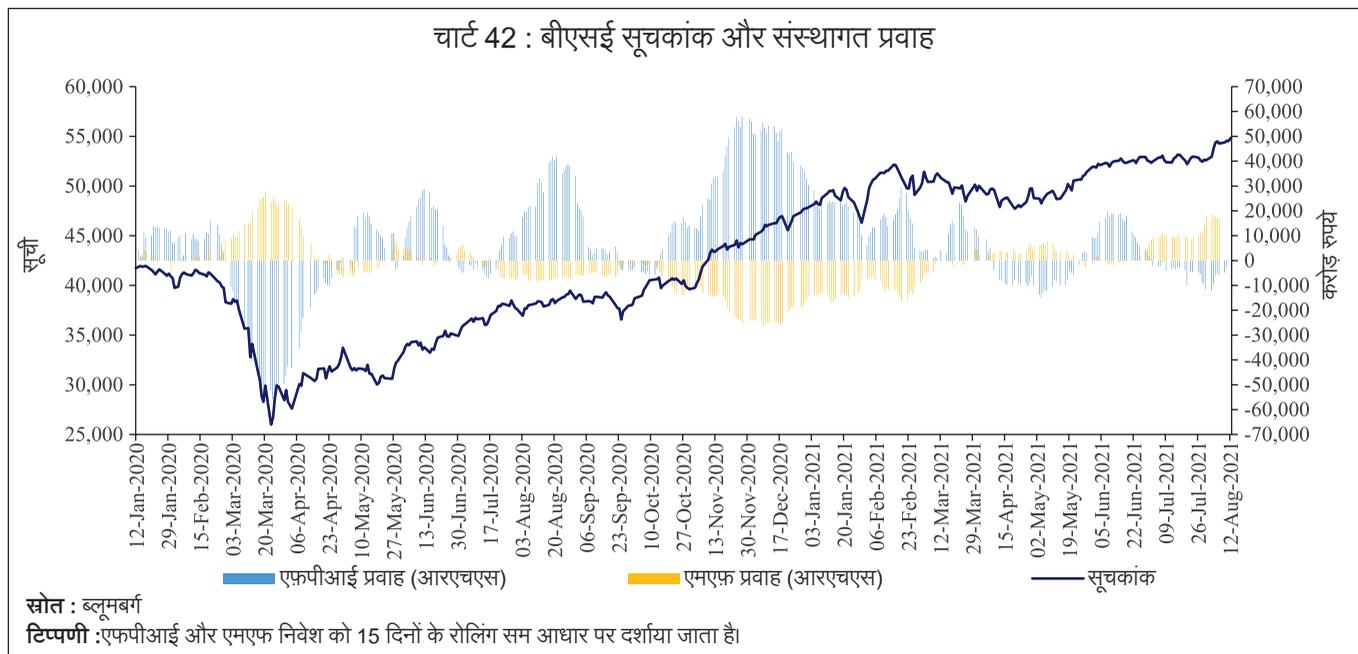
स्रोत : एफआईएमएमडीए

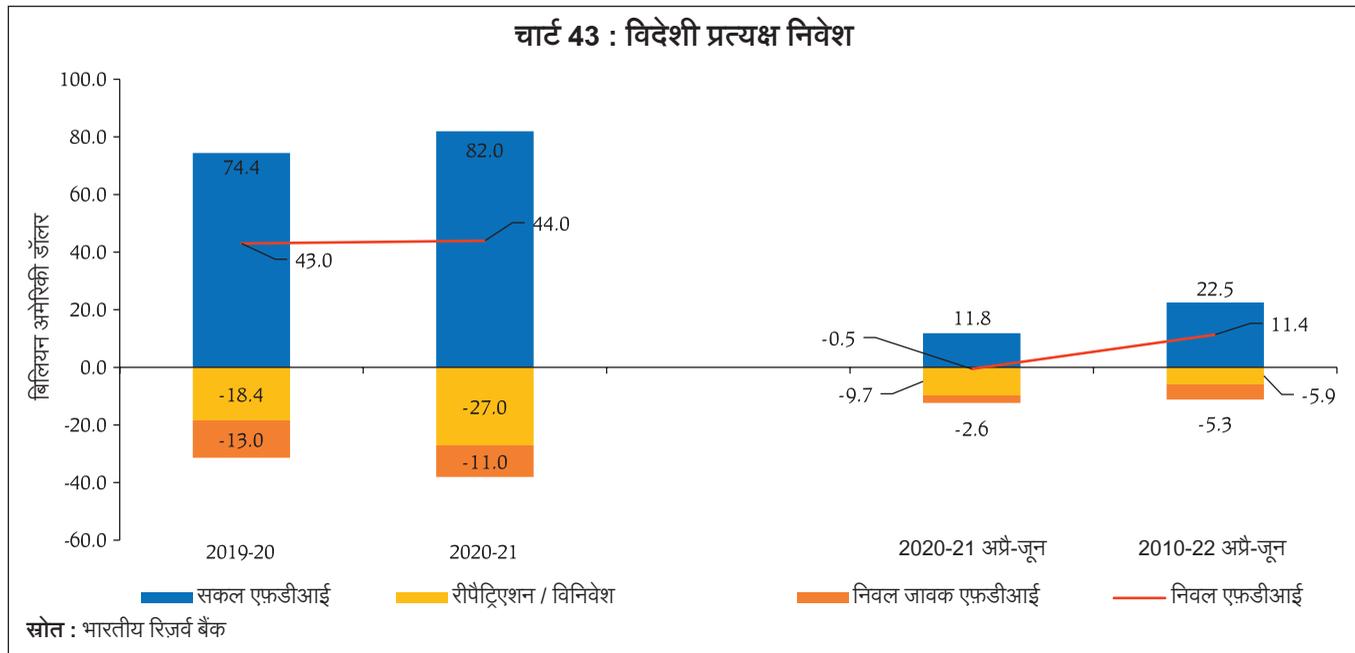


साथ (चार्ट 41 बी)। निजी बैंकों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की तुलना में सावधि जमा दरों में अधिक कमी की है।

जुलाई 2021 के दौरान बीएसई सेंसेक्स 0.2 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 52,587 (चार्ट 42) पर बंद हुआ। जबकि एफपीआई से इक्विटी बाजार में प्रवाह जुलाई में नकारात्मक था, म्यूचुअल फंड ने महीने के दौरान ₹19,716 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की।

ऑटो बिक्री में सुधार, मजबूत जीएसटी संग्रह और जुलाई 2021 के महीने के लिए भारत के विनिर्माण पीएमआई में वृद्धि से उत्साहित घरेलू इक्विटी अगस्त 2021 में सकारात्मक नोट पर शुरू हुई। अगस्त 2021 के दौरान अब तक 5.4 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, बीएसई सेंसेक्स 13 अगस्त, 2021 को जीवनकाल के उच्चतम 55,437 स्तर पर बंद हुआ।

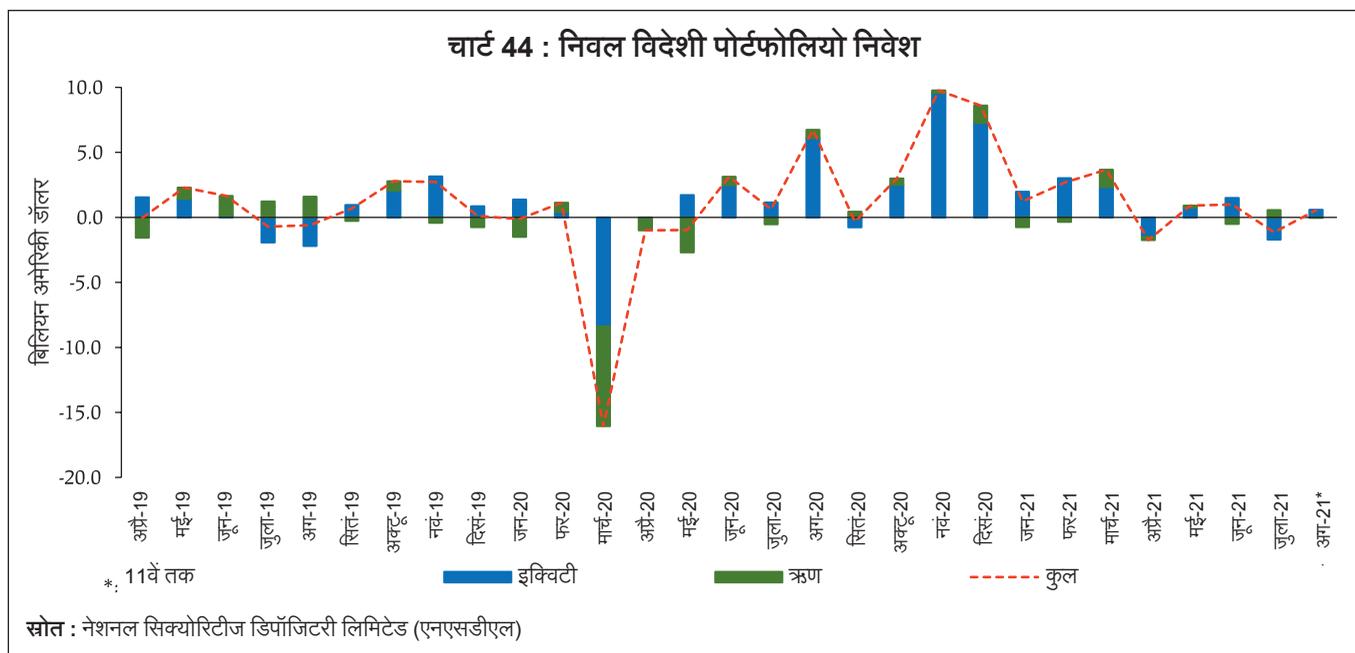


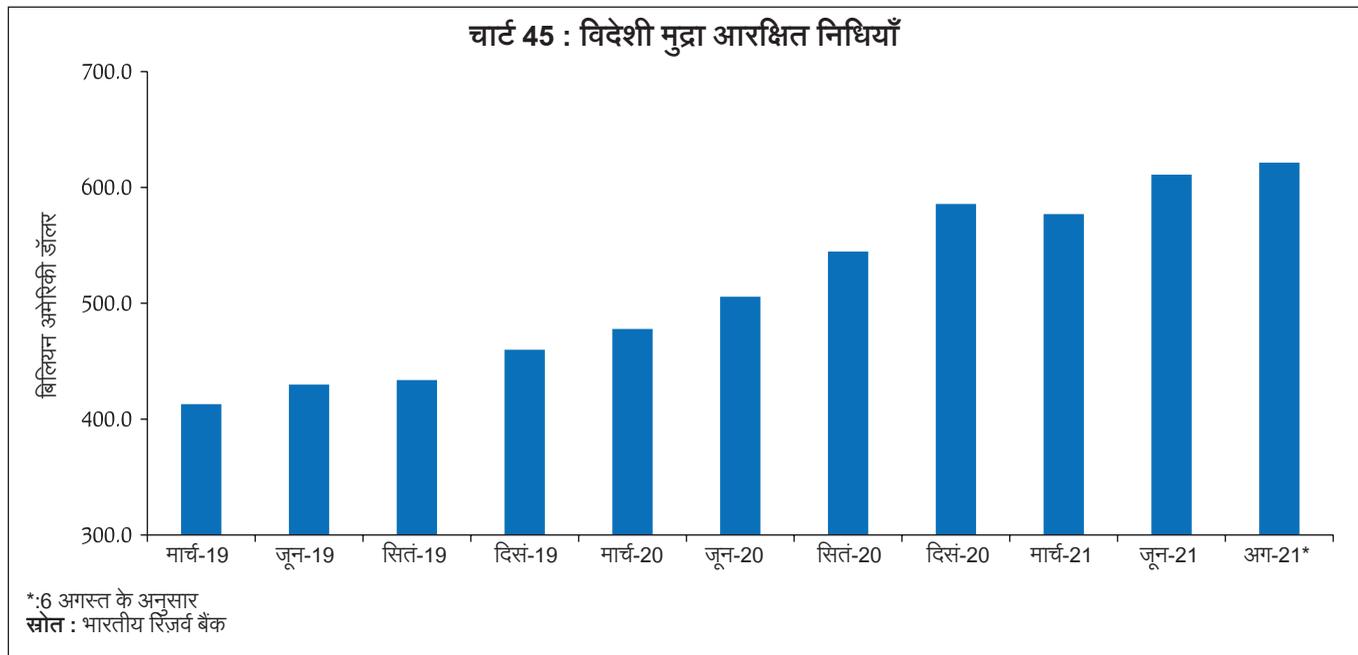


विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाह 2021-22 में अब तक मजबूत रहा है (चार्ट 43)। संचयी रूप से, शुद्ध एफडीआई अप्रैल-जून 2021 में बढ़कर 11.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले (-)0.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल-जून 2019 में 14.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था।

महीनों में शुद्ध खरीदार होने के बाद जुलाई 2021 में इक्विटी बाजार में शुद्ध विक्रेता बन गए। जुलाई 2021 में 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध एफपीआई बहिर्वाह हुआ (चार्ट 44)। एफपीआई ने अन्य प्रमुख ईएमई में भी शेयर बेचे। अगस्त में (11 तारीख तक), एफपीआई भारतीय और अन्य प्रमुख ईएमई इक्विटी बाजारों में शुद्ध खरीदार थे।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) 'डेल्टा' वेरिएंट और तेल की बढ़ती कीमतों पर चिंताओं के मद्देनजर पिछले दो

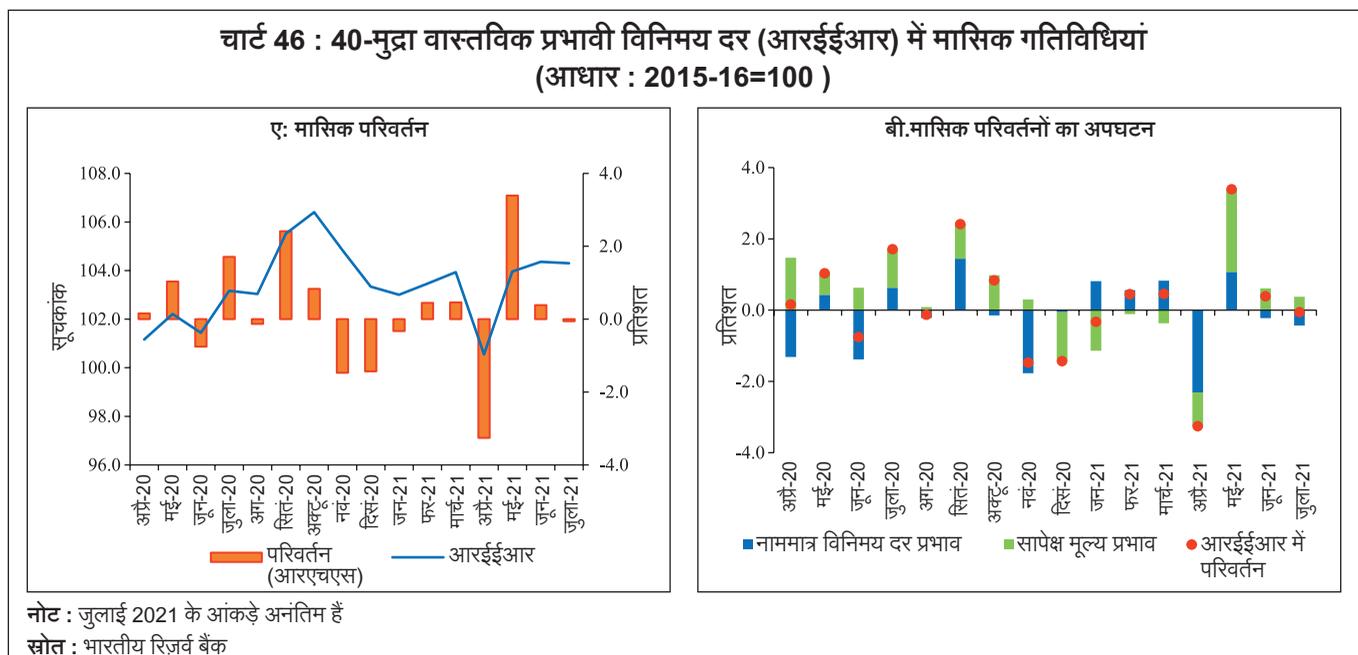




विदेशी मुद्रा भंडार 6 अगस्त, 2021 को 621.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 2021-22 (चार्ट 45) के लिए अनुमानित 15 महीने से कम के आयात के बराबर है।

विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया (भारतीय रुपया) जुलाई 2021 में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और महीने के दौरान एफपीआई की बिकवाली के साथ अमेरिकी डॉलर के

मुकाबले मूल्यहास हुआ हालांकि, अगस्त (12 तक) में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में तेजी आई है। 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक के संदर्भ में, घरेलू मुद्रास्फीति में कमी और सापेक्ष मूल्य प्रभाव में सहवर्ती गिरावट और नाममात्र की शर्तों के अधीन भारतीय रुपये के मूल्यहास के कारण जुलाई 2021 में भारतीय रुपए में 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट 46ए और 46बी)।

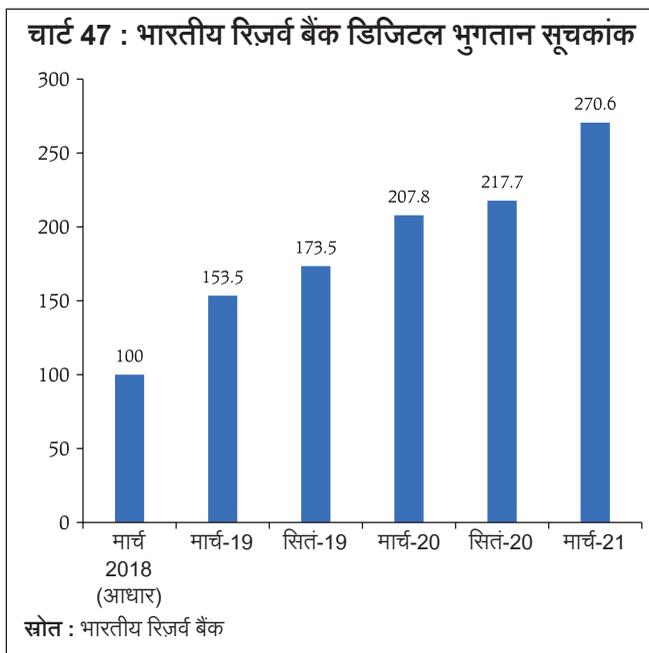


भुगतान प्रणालियां

सभी डिजिटल भुगतान मोड में लेनदेन ने जुलाई में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) प्रदर्शित की। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) भुगतानों ने मूल्य और मात्रा दोनों के लिहाज से मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो व्यावसायिक गतिविधि में तेजी को दर्शाता है। खुदरा क्षेत्र में, लेन-देन की मात्रा ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) में एक बढ़ती गति का प्रदर्शन किया।

अर्थव्यवस्था का तेजी से औपचारिकीकरण और डिजिटलीकरण रिजर्व बैंक के डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई)²³ (चार्ट 47) से भी स्पष्ट था।

रिजर्व बैंक ने अधिकृत गैर-बैंक भुगतान सेवा प्रदाताओं (पीएसपी), जैसे प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता, कार्ड नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस और एनईएफटी) में सदस्यता का विस्तार करने का निर्णय लिया। इससे भुगतान और निपटान में दक्षता लाने, लेन-देन की विफलताओं को कम करने और डिजिटल भुगतान में जनता के विश्वास को बढ़ावा देने की उम्मीद है। भारत सरकार और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम



(एनपीसीआई) ने 2 अगस्त, 2021 को 'ई-आरयूपीआई' - एक बार का क्यूआर कोड/एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित भुगतान तंत्र - लॉन्च किया है। इसे प्री-पेड ई-वाउचर, जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर डिलीवर किया जा सकता है, और बिना कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की आवश्यकता के रिडीम किया जा सकता है। यह एक व्यक्ति/उद्देश्य-विशिष्ट डिजिटल भुगतान समाधान है, जिससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को और अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद है।

सारणी 7 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

भुगतान प्रणाली	लेनदेन मात्रा वृद्धि (वर्षानुवर्ष, प्रतिशत)				लेनदेन मूल्य वृद्धि (वर्षानुवर्ष, प्रतिशत)			
	जून-2020	जून-2021	जुला-2020	जुला-2021	जून-2020	जून-2021	जुला-2020	जुला-2021
आरटीजीएस	1.2	28.8	-2.1	34.4	-27.9	17.9	-33.7	28.9
एनईएफटी	14.2	28.6	9.4	32.0	9.0	10.0	10.0	12.3
यूपीआई	77.2	110.0	82.1	116.7	78.6	109.1	98.5	108.5
आईएमपीएस	16.1	52.8	17.3	1361.3	19.6	37.3	24.0	168.4
एनएसीएच	28.2	0.8	8.6	1.9	44.7	-4.1	19.9	1.8
एनईटीसी	207.8	92.7	217.7	122.0	153.6	70.4	166.8	83.4
बीबीपीएस	83.2	157.7	97.0	153.7	88.8	167.2	113.1	159.3

²³ डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण की सीमा को पकड़ने के लिए एक समय सूचकांक है। इसमें पांच व्यापक मापदंडों के तहत वर्गीकृत विभिन्न संकेतक शामिल हैं - भुगतान सक्षमकर्ता (25 प्रतिशत), भुगतान अवसंरचना - मांग-पक्ष कारक (10 प्रतिशत), भुगतान अवसंरचना - आपूर्ति-पक्ष कारक (15 प्रतिशत), भुगतान प्रदर्शन (45 प्रतिशत) प्रतिशत) और उपभोक्ता केन्द्रितता (5 प्रतिशत)। आधार अवधि मार्च 2018 निर्धारित की गई है।

V. निष्कर्ष

श्रावण 2021 भी वर्ष का एक ऐसा समय है जब रिजर्व बैंक भीतर की दिव्य शांति से जुड़ता है। इस आंतरिक शांति में डूबे हुए, इसने कल की दुनिया पर चिंतन करने के लिए वर्तमान में उपस्थित दुविधाओं और ट्रेड-ऑफ्स से परे देखा।

संकटग्रस्त बैंकों में जमाराशियों की सुरक्षा और पहुंच के बारे में व्यापक चिंता की पृष्ठभूमि में, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम में हालिया संशोधन जमाकर्ता संकट को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब से, जब कोई बैंक तनाव का सामना करता है, तो उसके जमाकर्ता 90 दिनों के भीतर ₹5 लाख (जिस तक जमा राशि का डीआईसीजीसी

द्वारा बीमा किया जाता है) तक की जमा राशि वापस पाने में सक्षम होंगे। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह डीआईसीजीसी के अधिदेश को सीमित पे-बॉक्स फ्रंक्शन से पे-बॉक्स प्लस वन तक बढ़ाता है जो बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ावा देगा। यह उपभोक्ता संरक्षण और समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए शुभ संकेत है।

एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की दिशा में प्रगति पर काम का जायजा लेते हुए - खाते की राष्ट्रीय इकाई में एक कानूनी दायित्व जो डिजिटल रूप से जारी किया गया है और सभी आर्थिक एजेंटों के लिए सुलभ है - इसमें एक विश्वास है कि इसका समय निकट है²⁴। सीबीडीसी एक सुरक्षित, प्रतिरक्षित और विश्वसनीय भुगतान और वित्तीय प्रणाली प्रदान करने के रिज़र्व बैंक के प्रयास का एक हिस्सा है, जो दुनिया भर में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में देश की मुख्य स्थिति का भी फायदा उठाएगा।

सीबीडीसी बैंकों में जमा डिमांड डिपॉजिट को सीधे तौर पर नहीं बदल सकता है और यह भौतिक नकदी का पूरक होगा। यह अन्य ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान विधियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा और निजी डिजिटल मुद्राओं से जुड़े जोखिमों को दूर करते हुए अधिक लचीला और विविध भुगतान प्रणाली का समर्थन करेगा। रिज़र्व बैंक इस बात के प्रति सचेत है कि सीबीडीसी को सावधानीपूर्वक नियोजित, डिज़ाइन और परीक्षण किया जाना है।

आगे चलकर, सीबीडीसी एक अत्यधिक कुशल नई डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन सकता है, व्यापक पहुंच को सक्षम कर सकता है और मजबूत डेटा अभिशासन और गोपनीयता मानकों को प्रदान कर सकता है, और अवैध गतिविधियों के खिलाफ भुगतान प्रणाली की सुरक्षा कर सकता है।

लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट (लिबोर) के समाप्त होने के बारे में यूके वित्तीय आचरण प्राधिकरण की 5 मार्च, 2021 की घोषणा जो कि वित्तीय बाजारों के इतिहास में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले बेंचमार्क को व्यापक रूप से बिना वाटरशेड के रूप में माना जाता है जिसका कोई समानांतर नहीं है²⁵। भारतीय

रिज़र्व बैंक इस संक्रमण काल से संबंधित वैश्विक विकास की निगरानी कर रहा है और उसने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को एक संक्रमण काल योजना तैयार करने का काम सौंपा है। बैंकों को इसमें शामिल होना होगा: (i) एमआईएफओआर को प्रतिस्थापित करने के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर (दरों) का विकास; (ii) फॉलबैक क्लॉज का विकास जो भारतीय बाजार के लिए अनुकूलित है लेकिन विश्व स्तर पर अपनाई गई प्रथाओं पर आधारित है; (iii) अनुबंध पर फिर से बातचीत से निपटने के लिए हितधारक जागरूकता को बढ़ावा देना; और (iv) लिबोर समाप्ति तिथि के करीब एक कट-ऑफ तारीख को अधिसूचित करना जिसके बाद संस्थानों को लिबोर का संदर्भ देने वाले नए अनुबंधों में प्रवेश करना बंद कर देना चाहिए। 8 जून 2021 को रिज़र्व बैंक ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को सूचित किया कि वे नए अनुबंधों में प्रवेश करना बंद कर दें जो लिबोर को संदर्भ दर के रूप में उपयोग करते हैं और इसके बजाय किसी भी वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) को जल्द से जल्द अपनाएं और यह किसी भी स्थिति में 31 दिसंबर 2021 से पहले कर लें। 6 अगस्त को भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत एआरआर का उपयोग करके निर्यात ऋण प्रदान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। इसने यह भी संकेत दिया कि डेरिवेटिव अनुबंधों के मामले में, संदर्भ दर में बदलाव को पुनर्गठन के रूप में नहीं माना जाएगा।

रिज़र्व बैंक द्वारा अपने पर्यवेक्षी कार्य की सुपुर्दगी की बढ़ती तीव्रता और पहुंच के साथ, रिज़र्व बैंक के 'निरंतर पर्यवेक्षण' के नए दृष्टिकोण का ध्यान जोखिमों की शीघ्र पहचान और पर्यवेक्षी कार्यों के संचालन पर है, जिससे पर्यवेक्षित संस्थाओं को उनकी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलती है और लचीलापन और मूल कारण विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना है। निरंतर जुड़ाव और जोखिम प्रोफाइल की लगातार समीक्षा और परिकल्पित किए गए पर्यवेक्षी आकलन, प्रिज्म²⁶ के साथ एक वेब-आधारित और एक एंड-टू-एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम से यह अपेक्षित है कि वह पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) द्वारा अनुपालन को मजबूत करेगा। प्रिज्म में बिल्ट-इन रेमेडिएशन वर्कफ्लो, टाइम ट्रेकिंग, नोटिफिकेशन और अलर्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम

²⁴ https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1111

²⁵ 5 मार्च 2021 को यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) ने घोषणा की कि 31 दिसंबर 2021 के बाद सभी मुद्राओं के लिए सभी लिबोर सेंटिंस या तो समाप्त हो जाएंगी या अब प्रतिनिधि नहीं होंगी।

²⁶ एकीकृत पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए विनियमित संस्थाओं के लिए मंच

(एमआईएस) रिपोर्ट और डैशबोर्ड के साथ विभिन्न फंक्शनलिटी (निरीक्षण; अनुपालन; साइबर सुरक्षा के लिए इंसिडेंट फंक्शनलिटी; शिकायतें; और रिटर्न फंक्शनलिटी) होंगे।

अंत में, हम 4-6 अगस्त, 2021 के दौरान आयोजित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की एक चुनौतीपूर्ण बैठक की ओर मुड़ते हैं। जून में मुद्रास्फीति के बढ़ने की पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, यद्यपि, टोलरेंस बैंड के बाहर बढ़े हुए स्तर पर और महामारी की दो लहरों से कमजोर हुई अर्थव्यवस्था, के कारण एमपीसी ने नीतिगत ब्याज दर को अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया और अपनी पिछली बैठक में व्यक्त किए गए समायोजन के रुख को बनाए रखने के लिए 5/1 बहुमत से मतदान किया। यह शायद सबसे व्यापक रूप से प्रत्याशित एमपीसी बैठक का परिणाम था और फिर भी कुछ निंदा हुई और कुछ गलतफहमी हुई।

केंद्रीय बैंकिंग में सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में, उच्च स्तर की मौद्रिक नीति के संबंध में पूर्वानुमान लगाना वांछनीय माना जाता है। पूर्वानुमान का केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता से गहरा संबंध हो गया है। वास्तव में, पिछले कुछ दशकों में, केंद्रीय बैंकों ने अपने कार्यों की पारदर्शिता और पूर्वानुमान लगाने पर अपना जोर उत्तरोत्तर बढ़ाया है, उद्देश्य और व्यवस्थित व्यवहार के रूप में अधिक जवाबदेही की आवश्यकता को पहचानते हुए, सही ढंग से निर्णय लेना और मौद्रिक नीति ढांचे को समझना, जो जनता की मौद्रिक नीति का अनुमान लगाने की क्षमता को बढ़ाता है। उम्मीदों के गठन पर स्थायी प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता अपने आप में अपर्याप्त है; मार्गदर्शक अपेक्षाओं के लिए न केवल दूरदेशी संचार की आवश्यकता होती है, बल्कि शब्दों और कार्यों के बीच निरंतरता भी होती है।

एमपीसी ने अपने आगे के मार्गदर्शन में यही हासिल करने की मांग की है। गतिविधि में मंदी के अधिक स्पष्ट होने की प्रत्याशा में जून 2019 में मौद्रिक नीति का रुख तटस्थता से समायोजन की ओर स्थानांतरित हो गया - वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2016-17 में 8.3 प्रतिशत से घटकर 2017-19 में औसतन 6.7 प्रतिशत हो गई और 2019-20 में 4 प्रतिशत गिर गई। अक्टूबर 2019 में, एमपीसी ने अपने आगे के मार्गदर्शन को और अधिक स्पष्ट किया। इसने निर्णय लिया कि "जब तक विकास को

पुनर्जीवित करना आवश्यक है, तब तक एक उदार रुख जारी रखना है, जबकि यह सुनिश्चित करना है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे।" ²⁷ इसके माध्यम से कर्मों और शब्दों में इस मार्गदर्शन का पालन किया गया है, इसे (ए) मार्च 2020 में "अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रभाव को कम करने"²⁸ के लिए जब महामारी आई, (बी) अक्टूबर 2020 में समय-आकस्मिक एकोमोडेशन मार्गदर्शन लाने के लिए - "कम से कम चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और अगले वित्तीय वर्ष में" ²⁹, (सी) अप्रैल 2021 में "अर्थव्यवस्था पर कोविड -19 के प्रभाव को कम करना जारी रखें" ³⁰ चूंकि महामारी की दूसरी लहर तेज हो गई है, और (डी) जून 2021 में टिकाऊ आधार पर विकास को "पुनर्जीवित और बनाए रखने"³¹ के लिए प्रतिबद्ध है।

एमपीसी का निर्णय सभी उपलब्ध साक्ष्यों - गतिशीलता-गतिविधि- और सर्वेक्षण-आधारित के साथ समर्थित है। फिर भी, अंतिम विश्लेषण में, इस पर निर्णय लेना होगा क्योंकि विकास और मुद्रास्फीति के बीच संबंध के केंद्र में एक सेक्रीफाइस निहित है। मुद्रास्फीति की दर में कमी केवल वृद्धि में कमी के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है; विकास में वृद्धि केवल मुद्रास्फीति में वृद्धि की कीमत चुकाने से ही संभव है, हमेशा और हर जगह। अर्थशास्त्र में सेक्रीफाइस रेशियो कहा जाता है, भारत के लिए नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि मुद्रास्फीति की दर में एक प्रतिशत अंक की कमी के लिए, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के 1.5-2 प्रतिशत अंक को छोड़ना होगा। एमपीसी ने विकास को पुनः वापस आने का मौका देने के लिए वोट किया। आखिरकार, विकास 2019-20 में गिरकर 2011-12 आधारित जीडीपी श्रृंखला में अपनी सबसे कम दर पर आ गया था और 2020-21 में महामारी की दो लहरों और 2021-22 की पहली छमाही के बाद, 2019-

²⁷ चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 4 अक्टूबर 2019 को (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=48319)

²⁸ मार्च, 2020 का सातवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=49581)

²⁹ 9 अक्टूबर 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=50479)

³⁰ मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का 5-7 अप्रैल 2021 का 7 अप्रैल 2021 को संकल्प (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=51381)

³¹ 4 जून 2021 का मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=51683)

20 में यह अनुमानतः इससे अधिक नहीं हो सकता था।

लेकिन क्या होगा अगर एमपीसी महामारी से तबाह अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के बावजूद आपूर्ति के झटके से प्रेरित मूल्य दबावों पर हठपूर्वक हमला करती है और इसके परिणामस्वरूप, आर्थिक गतिविधि अवसाद में बदल जाती है? तब सहानुभूति की कोई भी मात्रा आंसू नहीं पोंछ पाएगी। साथ ही हमारी एमपीसी भारत केंद्रित है; और इसे ऐसा ही होना चाहिए। उसे चुनना होगा कि, भारत के लिए क्या सही है और किसी का अनुकरण नहीं किया जा रहा है, न ही उभरते हुए और न ही उन्नत सहकर्मी का।

इस प्रक्रिया में, क्या मौद्रिक नीति ने अपने धर्म, मूल्य स्थिरता के अपने प्राथमिक आदेश को छोड़ दिया है? तथ्यों को बोलने देना चाहिए। सेक्रीफाइस रेशियो द्वारा लगाए गए नाइफ -एज ट्रेड -ऑफ को देखते हुए मौद्रिक नीति का संचालन क्रमिक अवस्फीति के एक ग्लाइडपथ में परिवर्तित हो गया है जो एक 'कोल्ड टर्की' दृष्टिकोण के बजाय एक अवधि में अंतर्निहित आउटपुट नुकसान को फैलाता है जो स्लेज हैमर को लागू करता है लेकिन बड़े सकल घरेलू उत्पाद के नुकसान का कारण बनता है जो अभी -अभी आरंभ हुई बहाली को खत्म करता है और

नीतिगत कार्रवाई के कारण कई वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देता

एमपीसी ने 2016-20 के दौरान 4 प्रतिशत के लक्ष्य के आसपास मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने की अपनी प्रतिबद्धता और क्षमता का प्रदर्शन किया। सदी में एक बार की महामारी ने पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति को तेज कर दिया और भारत इससे अछूता नहीं था। एमपीसी को 2020-21 में उच्च औसत मुद्रास्फीति को सहन करना पड़ा। वर्ष 2021-22 के लिए, मुद्रास्फीति औसत 5.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो कि महामारी की दूसरी लहर के बीच में होने के बावजूद पिछले वर्ष के औसत से 50 आधार अंकों की गिरावट है। इसके अलावा, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान में जून में 5.1 प्रतिशत से अगस्त में 5.7 प्रतिशत तक की वृद्धि अनिवार्य रूप से अतीत के विचलन के लिए एक सुधार है - मुद्रास्फीति के लिए 5.2 प्रतिशत के अनुमान के विपरीत अप्रैल-जून में, अपूर्ण कवरेज और रोकथाम उपायों की गहनता के कारण वास्तविक परिणाम 5.6 प्रतिशत निकला। अब तक, मुद्रास्फीति परिकल्पित प्रक्षेपवक्र के भीतर रहने की राह पर है और शेष वर्ष के दौरान इसके स्थिर होने की संभावना है। हमारे विचार में, यह मुद्रास्फीति के पथ के लिए एक विश्वसनीय भविष्योन्मुखी मिशन वक्तव्य है।

अनुबंध

बॉक्स: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के परिणाम

एमओएसपीआई के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में³² में तेज गिरावट के साथ, बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से गिरकर 2019-20 में 4.8 प्रतिशत हो गई। इस अवधि के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सुधार के साथ श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में भी सुधार हुआ (सारणी 1)।

श्रम बाजार संरचना, जो पिछले सर्वेक्षण दौर के दौरान सेवाओं की ओर स्थानांतरित हुई, उसमें 2019-20 में परिवर्तन देखा गया। सभी क्षेत्रों में, रोजगार के हिस्से में गिरावट आई, जबकि कृषि ने अपना हिस्सा बढ़ाकर 2019-20 में यह प्रमुख रोजगार प्रदाता बन गया (सारणी 2)। ग्रामीण क्षेत्रों में, इस अवधि के दौरान कृषि में स्वरोजगार की हिस्सेदारी में भी वृद्धि हुई। कृषि के प्रति रोजगार में यह बदलाव आंशिक रूप से महामारी की पहली लहर के प्रभाव को दर्शाता है जब प्रवासी श्रमिकों का गांवों में पलायन हुआ था।

कोविड -19 की पहली लहर के दौरान रोजगार में गिरावट शहरी क्षेत्रों में भी परिलक्षित होती है, जिसके लिए जुलाई-सितंबर 2020 तक की

सारणी 1: श्रम बाजार संकेतक

प्रतिशत में

सर्वेक्षण अवधि	बेरोजगारी दर	श्रम भागीदारी दर
ग्रामीण		
पीएलएफएस 2019-20	4	40.8
पीएलएफएस 2018-19	5	37.7
पीएलएफएस 2017-18	5.3	37.0
शहरी		
पीएलएफएस 2019-20	7.0	38.6
पीएलएफएस 2018-19	7.7	36.9
पीएलएफएस 2017-18	7.8	36.8
ग्रामीण+शहरी		
पीएलएफएस 2019-20	4.8	40.1
पीएलएफएस 2018-19	5.8	37.5
पीएलएफएस 2017-18	6.1	36.9

सारणी 2: उद्योग द्वारा श्रमिक विभाजन (ग्रामीण+शहरी)

प्रतिशत में

उद्योग प्रभाग (एनआईसी के अनुसार)	पीएलएफएस 2019-20	पीएलएफएस 2018-19	पीएलएफएस 2017-18
कृषि	45.6	42.5	44.1
खनन और उत्खनन	0.3	0.4	0.4
उत्पादन	11.2	12.1	12.1
बिजली, पानी आदि	0.6	0.6	0.6
निर्माण	11.6	12.1	11.7
व्यापार, होटल और रेस्तरां	13.2	12.6	12.0
परिवहन, भंडारण और संचार	5.6	5.9	5.9
अन्य सेवाएं	11.9	13.8	13.2
सेवा क्षेत्र	42.3	44.4	42.8
सभी	100.0	100.0	100.0

स्रोत: एमओएसपीआई

जानकारी भी उपलब्ध है। ति.1: 2020-21 के दौरान रोजगार और एलएफपीआर में उल्लेखनीय गिरावट के बाद, ति.2 ने श्रम बाजार संकेतकों में सुधार दर्ज किया। महामारी का खामियाजा ज्यादातर आकस्मिक श्रमिकों द्वारा महसूस किया गया, जिनके रोजगार में हिस्सेदारी 2020-21 की पहली तिमाही में 50 प्रतिशत घट गई। प्रतिबंधों में ढील के साथ, इस श्रेणी में रोजगार 2020-21 की दूसरी तिमाही में सामान्य स्थिति में वापस आ गया। हालांकि, 2019-20 की तुलना में श्रम बाजार में रिकवरी अभी भी पूरी नहीं हुई है (सारणी 3)।

सारणी 3: त्रैमासिक श्रम बाजार संकेतक-शहरी (व्यक्ति-सभी उम्र)

(प्रतिशत में)

तिमाही	श्रम बल भागीदारी दर	श्रमिक जनसंख्या दर	बेरोजगारी दर
अप्रैल-जून 2019	36.2	32.9	8.9
जुलाई-सितंबर 2019	36.8	33.7	8.4
अप्रैल - जून 2020	35.9	28.4	20.9
जुलाई-सितंबर 2020	37.0	32.1	13.3

स्रोत: एमओएसपीआई

³² हालांकि पीएलएफएस संदर्भ अवधि (जुलाई 2019-जून 2020) महामारी के प्रारंभिक चरण (अप्रैल 2020-जून 2020) को कवर करती है, यह श्रम बाजार पर महामारी के पूर्ण प्रभाव को नहीं दर्शाती है क्योंकि 'सामान्य स्थिति' पद्धति एक व्यक्ति रोजगार प्राप्त तब मानती है जब उसने सर्वेक्षण की तारीख से पहले के 365 दिनों के अपेक्षाकृत लंबे हिस्से के लिए काम किया हो।

भारत में खाद्य मूल्य वर्धन पर कोविड-19 का प्रभाव*

22 खाद्य पदार्थों के खुदरा और थोक मूल्यों पर दैनिक डेटा का उपयोग करते हुए, यह लेख भारत में खाद्य मूल्य वर्धन पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करता है। परिणाम बताते हैं कि मार्च-मई 2020 की पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि के दौरान मूल्यवर्धन में औसतन वृद्धि हुई और बाद के अनलॉकिंग चरण के दौरान भी बनी रही, यह मुख्य रूप से बाजार केंद्रों द्वारा संचालित थी जिन्होंने गतिशीलता सूचकांकों द्वारा मापे गए उच्च तीव्रता वाले लॉकडाउन का सामना किया। हालांकि, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, लॉकडाउन की कम कठोर और स्थानीयकृत प्रकृति के साथ-साथ बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को देखते हुए, मूल्यवर्धन में वृद्धि की सीमा अपेक्षाकृत मामूली थी।

भूमिका

खाद्य मूल्यवर्धन की प्रवृत्ति ने कोविड-19 के प्रकोप और इसके प्रसार को रोकने के लिए संबंधित लॉकडाउन उपायों के बाद नाटकीय बदलाव प्रदर्शित किया। हालांकि लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान भी खाद्य सहित आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही की अनुमति दी गई थी, यह देखा गया है कि इस अवधि के दौरान भारत के खाद्य बाजार और आपूर्ति श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा – मंडियों में आवक कम हो गई (महाजन और तोमर, 2020) ; कृषि बाजार बंद थे¹; और ट्रकों की दैनिक आवाजाही सामान्य स्तर के 10 प्रतिशत तक गिर गई²। गूगल का मोबिलिटी सूचकांक, जो क्षेत्र और विभिन्न श्रेणियों के स्थानों की आवाजाही के रुझान को देखता है, 18 अप्रैल, 2020 को पहली लहर के दौरान खुदरा और मनोरंजन श्रेणी के लिए 87 प्रतिशत और 16 मई, 2021 को दूसरी लहर के दौरान फिर से 70 प्रतिशत गिर

* यह लेख आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के जिबिन जोस, विमल किशोर और बिनोद बी. भोई द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

¹ द हिंदू बिजनेसलाइन: <https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/covid-19-impact-state-border-curbs-disrupt-farm-food-supply-chain/article31144732.ece>

² द टाइम्स ऑफ इंडिया: <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/worlds-biggest-lockdown-brings-trucks-to-a-standstill-in-india/articleshow/75027027.cms>

गया³। मूल्यवर्धन को बदलने के लिए ऐसी स्थितियों में कई कारक कई चैनलों के माध्यम से काम कर सकते हैं। सबसे पहले, एक लॉकडाउन खाद्य उत्पादों (महाजन और तोमर, 2020) की आवाजाही को प्रभावित कर सकता है जिससे उच्च लेनदेन लागत हो सकती है क्योंकि भारत में खपत होने वाले सभी खाद्य पदार्थों का 92 प्रतिशत खरीदा जाता है (रीर्डन आदि, 2020)। दूसरा, प्रवासी श्रमिकों की संख्या में गिरावट के परिणामस्वरूप श्रमिकों की कमी के कारण कुछ कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं (इब्राहिमी, इगन और पेरिया, 2020)। तीसरा, लॉकडाउन की अवधि और तीव्रता के बारे में अनिश्चितता भी उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य पदार्थों की खरीद और जमाखोरी का सहारा लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे लॉकडाउन अवधि के दौरान मांग में अस्थायी वृद्धि हो सकती है (इब्राहिमी, इगन और पेरिया, 2020; सुखवानी, देशकर और शॉ, 2020)। इसके अलावा, आपूर्ति में रुकावटों के बीच, मांग में इस तरह की वृद्धि खुदरा विक्रेताओं को उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर उच्च मार्जिन (या मूल्यवर्धन)⁴ लेने में सक्षम कर सकती है। यह आलेख उपर्युक्त चैनल का मूल्यांकन करने का इरादा रखता है - लॉकडाउन से प्रेरित खाद्य पदार्थों पर मूल्यवर्धन में वृद्धि और इसके फलस्वरूप भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति में अचानक बदलावा सीपीआई बास्केट के लगभग आधे हिस्से में खाद्य के साथ, इन खुदरा मूल्य मार्जिन की सीमा और दृढ़ता का न केवल खाद्य मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र में बल्कि हेडलाइन मुद्रास्फीति पथ के लिए भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो लॉकडाउन और वस्तुओं और केंद्रों में खुदरा मार्जिन पर मोबिलिटी की भूमिका को समझने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारतीय संदर्भ में खाद्य कीमतों पर लॉकडाउन के प्रभाव का विश्लेषण करने वाले कई अध्ययनों ने मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों पर ध्यान केंद्रित किया है। मार्च-अप्रैल 2020 में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद तीन हफ्तों में थोक बाजारों में खाद्य पदार्थों की आवक में 62 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि थोक कीमतों में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और

³ मोबिलिटी में गिरावट आधारभूत रेखा दिन की तुलना में है, यानी उस दिन के लिए पांच-सप्ताह की अवधि 3 जनवरी - 6 फरवरी, 2020 से औसत मूल्य।

⁴ इस आलेख में मार्जिन और मूल्यवर्धन का परस्पर उपयोग किया गया है।

इस सहसंबंध का स्थानीय प्रतिक्रियाओं की तुलना में राज्य-स्तरीय लॉकडाउन नीति भिन्नता से अधिक लेना-देना है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में (लोव, नधनेल और रोथ, 2020)। लॉकडाउन का प्रभाव खराब नहीं होने वाली वस्तु (गेहूँ) और खराब होने वाली (टमाटर और प्याज) वस्तुओं में भिन्न था और प्रतिकूल झटकों की सीमा को अधिक से अधिक कृषि बाजार सुधार उपायों (वाष्णैय, रॉय और मीनाक्षी, 2020) को अपनाने से कम किया जाता है। उत्पाद की उपलब्धता और आवक की मात्रा में गिरावट उन वस्तुओं के लिए अधिक है जो खुदरा केंद्रों से दूर खेती या निर्मित की जाती हैं, इससे यह पता चलता है कि महामारी के दौरान लंबी दूरी की खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है (महाजन और तोमर, 2020)। उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीसीए), नारायणन और साहा (2020) द्वारा जारी दैनिक कीमतों के आंकड़ों के आधार पर लॉकडाउन से पहले के महीने की तुलना में 28 दिनों के लॉकडाउन के बाद (24 मार्च-21 अप्रैल, 2020) में कई दालों के लिए औसत खुदरा मूल्य वृद्धि 6 प्रतिशत से अधिक, अधिकांश खाद्य तेलों के लिए 3.5 प्रतिशत से अधिक, आलू के लिए 15 प्रतिशत और टमाटर के लिए 28 प्रतिशत थी। शोधपत्र ने कुल थोक और खुदरा खाद्य मूल्य सूचकांकों का भी निर्माण किया और पाया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान इन दोनों के बीच का अंतर बढ़ गया था, जिसका श्रेय मुख्य रूप से परिवहन प्रतिबंधों के कारण व्यापारियों द्वारा सामना की जाने वाली उच्च लेनदेन लागत के कारण था। इस पृष्ठभूमि के आधार पर, यह आलेख खाद्य मूल्य गतिकी को समझने के लिए गूगल मोबिलिटी सूचकांक और खुदरा मार्जिन द्वारा लिए गए मोबिलिटी में लॉकडाउन प्रेरित परिवर्तनों को जोड़ने का प्रयास करता है।

डीसीए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार (भारत सरकार) की निगरानी में एकत्रित देश भर में 135 केंद्रों के लिए 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों का दैनिक मूल्य डेटा (मई 2021 के लिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार) अनुभवजन्य विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। इस डेटासेट की नवीनता इस तथ्य से आती है कि यह किसी भी केंद्र पर प्रत्येक वस्तु के लिए वास्तविक खुदरा मार्जिन (यानी, खुदरा और थोक कीमतों के बीच का अंतर) की गणना को सक्षम

करते हुए, खुदरा और थोक दोनों कीमतों की रिपोर्ट करता है। चूंकि यहां मार्जिन को किसी दिए गए वस्तु-केंद्र जोड़ी के लिए परिभाषित किया गया है, यह शुद्ध वर्धन प्रभाव को देखता है, मोटे तौर पर लॉकडाउन के दौरान आपूर्ति में व्यवधान के कारण परिवहन लागत के प्रभाव को दूर करता है। डीसीए मूल्य डेटा के केंद्रों को मूल्य मार्जिन के व्यवहार पर मोबिलिटी के साथ ही लॉकडाउन प्रभाव को मापने के लिए व्यापक मैनुअल मैपिंग के माध्यम से गूगल मोबिलिटी सूचकांकों के साथ मिलान किया जाता है। गूगल मोबिलिटी सूचकांक आधाररेखा से भूगोल के अनुसार समय के साथ मूवमेंट ट्रेंड की रिपोर्ट करते हैं और देश, राज्य और शहर के स्तर पर उपलब्ध हैं⁵। गूगल मोबिलिटी इंडेक्स के साथ केंद्र-वार कीमतों के बीच मिलान किए गए डेटा का उपयोग करते हुए, इस आलेख में बताया गया है कि पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि (25 मार्च - 31 मई, 2020) के दौरान मूल्यवर्धन में औसतन वृद्धि हुई और यह वृद्धि अनलॉक चरण (जून-नवंबर 2020) में भी बनी रही। इसके अलावा, मूल्यवर्धन में वृद्धि मुख्य रूप से बाजार केंद्रों द्वारा संचालित थी, जिसने उच्च तीव्रता वाले लॉकडाउन (या कम मोबिलिटी) का सामना किया और यह कि दालों, खाद्य तेलों और आलू के उच्च मूल्यवर्धन

दिखाने के साथ, वस्तुओं में प्रभाव काफी भिन्न था। हालांकि, दूसरी लहर के दौरान, मार्जिन पर लॉकडाउन/प्रतिबंधों का प्रभाव समग्र स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं था, भले ही कमोडिटी स्तर के अंतर बने रहे, जो लॉकडाउन की कम कठोर और स्थानीयकृत प्रकृति (गूगल मोबिलिटी सूचकांक में कम गिरावट) का सुझाव देता है साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक खाद्य पदार्थों की बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, जैसा कि पहले लॉकडाउन की तुलना में मंडी आवक, विशेष रूप से सब्जियों और राजमार्ग टोल संग्रह में परिलक्षित होता है।

शेष लेख इस प्रकार व्यवस्थित है। खंड II कुछ शैलीगत तथ्य प्रस्तुत करता है। खंड III अनुभवजन्य रणनीति और परिणामों पर चर्चा करता है। खंड IV समापन अवलोकन प्रदान करता है।

⁵ यह दर्शाता है कि वर्गीकृत स्थानों पर आने वाले आगंतुक (या व्यतीत समय) आधारभूत दिन की तुलना में कैसे परिवर्तित हुए, जो सप्ताह के उस दिन के सामान्य मान को दर्शाता है। आधारभूत दिन 3 जनवरी से 6 फरवरी, 2020 की 5-सप्ताह की अवधि से औसत मूल्य है।

II. कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भारत में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति

1. सीपीआई-डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति

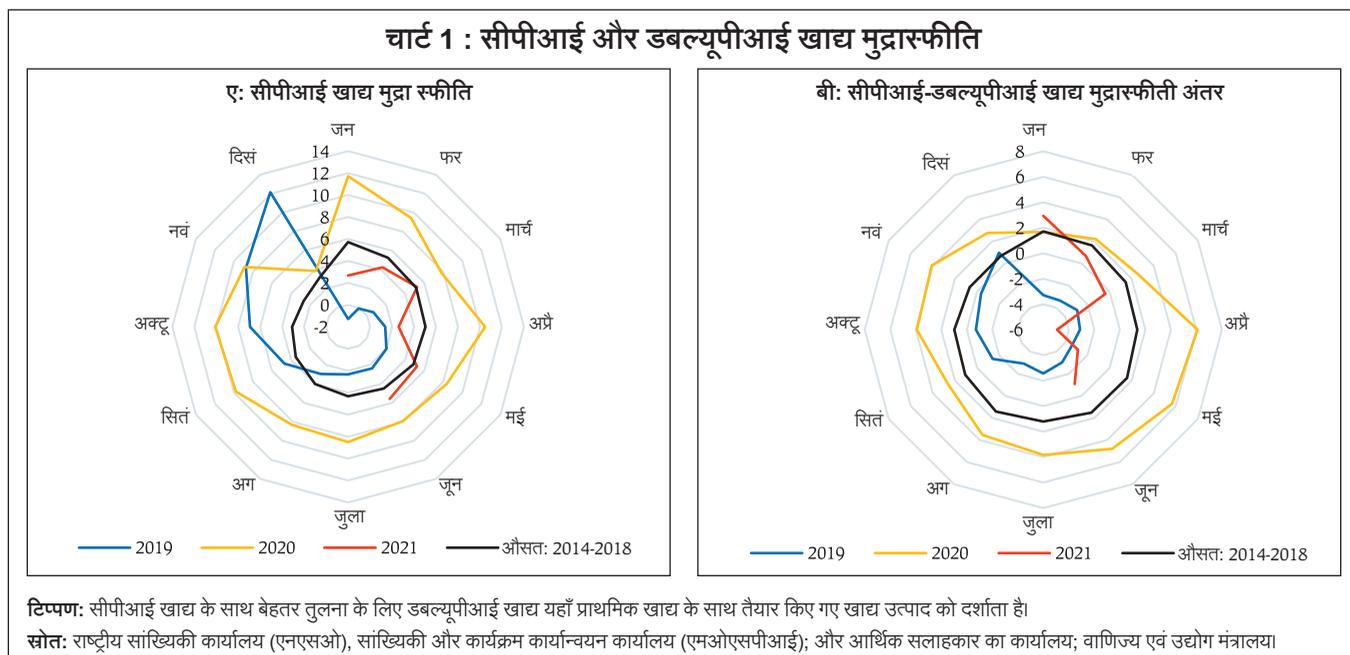
मार्च-मई 2020 की लॉकडाउन अवधि के दौरान खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में असामान्य उतार-चढ़ाव देखा गया। सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति जो दिसंबर 2019 से नरम हो रही थी, अप्रैल 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के साथ बढ़ गई (चार्ट 1 ए)। मई 2020 में कुछ नरमी के बावजूद, यह नवंबर 2020 तक अधिक बनी रही। सामान्य सर्दी की शुरुआत के साथ, दिसंबर 2020 से खाद्य मुद्रास्फीति कम होने लगी।

इसके विपरीत, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति में इतनी तेज वृद्धि नहीं दिखाई दी, जिससे अप्रैल 2020 में सीपीआई-डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति के बीच की खाई और चौड़ी हो गई, जो अनलॉक के चरण के दौरान भी अपने ऐतिहासिक औसत स्तर की तुलना में ऊंची बनी रही (चार्ट 1बी)। हालांकि, मार्च-मई 2021 में यह अंतर नकारात्मक हो गया क्योंकि प्रतिकूल आधार प्रभावों (अप्रैल को छोड़कर) ने

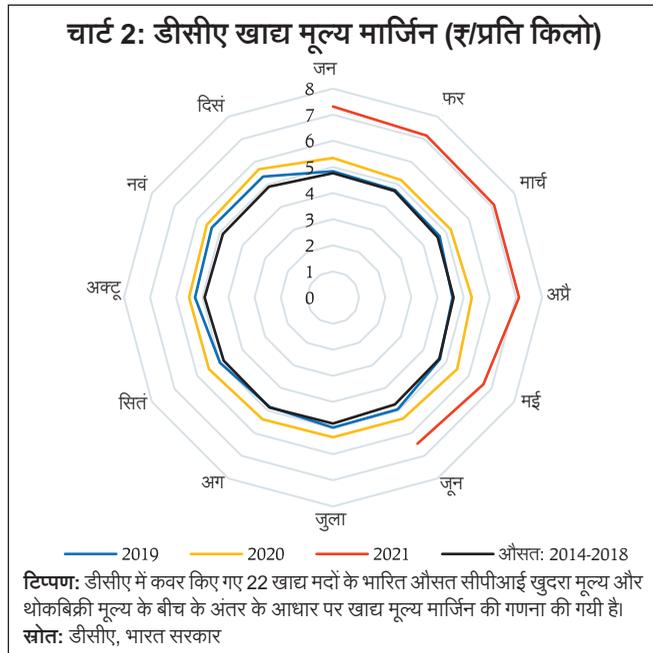
डब्ल्यूपीआई की कुल खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया। हालांकि अंतराल समय के अलग-अलग मार्जिन के प्रभाव को प्रतिबिंबित कर सकता है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में खाद्य बास्केट की संरचना में अंतर, दो बास्केट में अलग-अलग वस्तुओं से जुड़े भार, मूल्य संग्रह के लिए बाजारों का कवरेज, और मूल्य सूचकांकों से मार्जिन निकालना सीधा नहीं है, जो सभी समग्र मूल्य सूचकांकों के निर्माण और संबंधित मापी गई मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकते हैं।

इस संबंध में, खुदरा और थोक स्तर पर डीसीए द्वारा एकत्र किए गए केंद्र-वार दैनिक कमोडिटी कीमतों के आंकड़ों का उपयोग मूल्य मार्जिन (यानी खुदरा और थोक कीमतों के बीच अंतर) को मापने के लिए किया जा सकता है। किसी दिए गए कमोडिटी-केंद्र जोड़ी के लिए इस प्रकार परिभाषित खाद्य मूल्य मार्जिन, वस्तुओं और केंद्रों में औसत, अप्रैल और मई 2020 में, पिछले वर्षों के इसी महीनों की तुलना में एक स्पष्ट मूल्यवर्धन दिखाते हैं, जो मूल्यवर्धन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की भूमिका को दर्शाता है (चार्ट 2)। हालांकि समग्र स्तर पर मार्जिन जून 2020 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरे 2020 में वे ऊंचे बने रहे⁶।

चार्ट 1 : सीपीआई और डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति

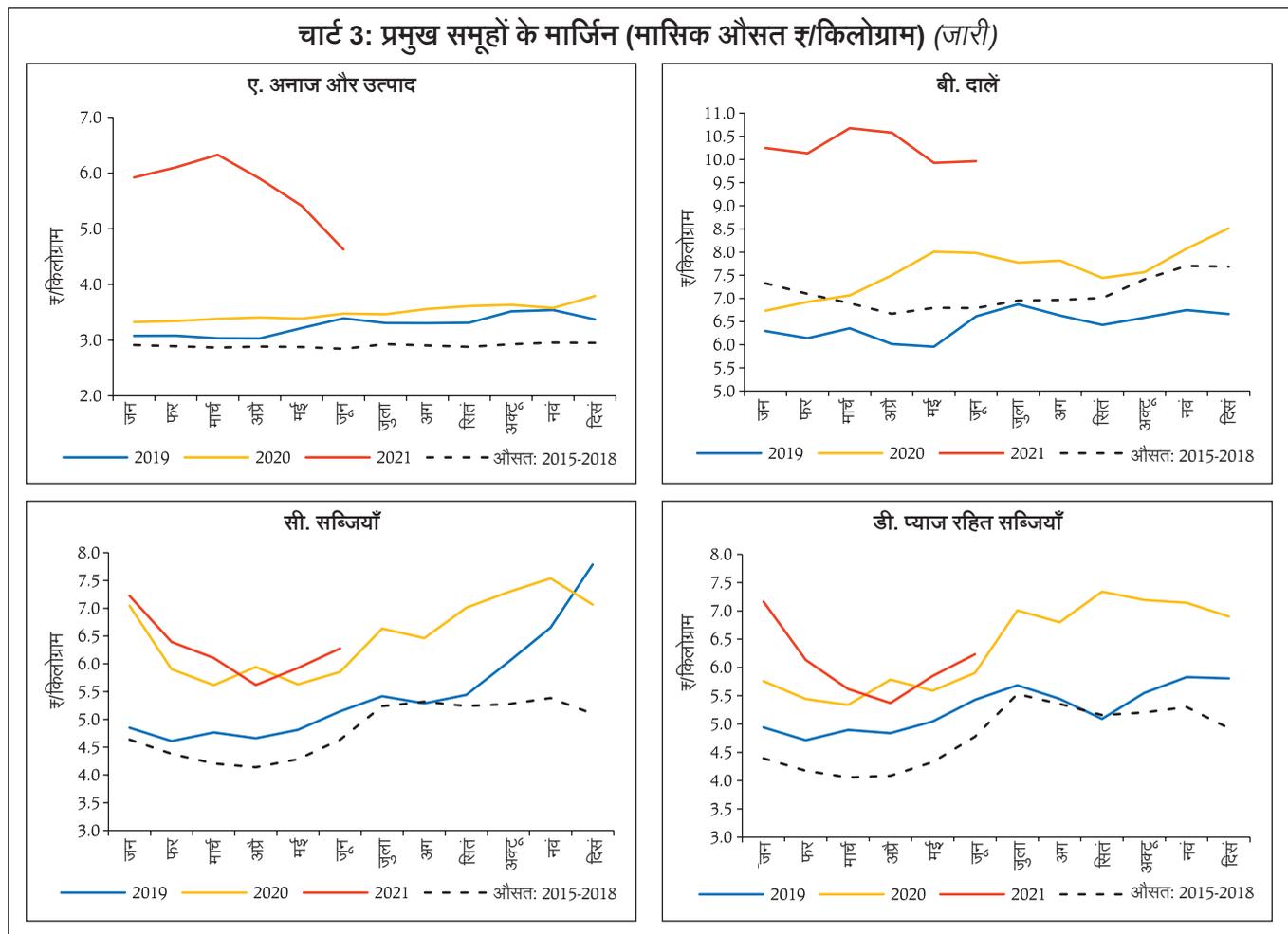


⁶ अन्य कारण, लॉकडाउन के अलावा, बाद की अवधि में मार्जिन में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगस्त-सितंबर 2020 में दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में अधिक बारिश से भी खरीफ की फसल को नुकसान हुआ, जिसने बाद में उनके मार्जिन में वृद्धि में योगदान दिया।



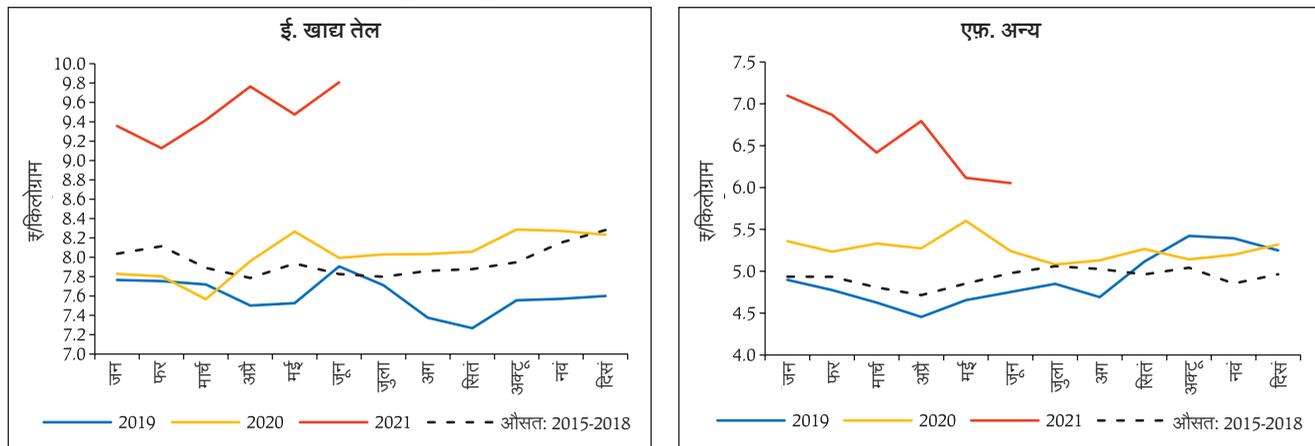
उप-समूह स्तर पर, मार्जिन का व्यवहार काफी विषम रहा है। अप्रैल-मई 2020 के दौरान दालों, खाद्य तेलों और 'अन्य खाद्य' में मार्जिन में उठाव देखा जा सकता है, जबकि अनाज और सब्जियों ने मई 2020 में कम होने से पहले अप्रैल 2020 में मामूली वृद्धि दिखाई (चार्ट 3)।

हालांकि, 2021 में, समग्र स्तर पर और उप-समूह स्तरों पर (सब्जियों को छोड़कर) मार्जिन में 2020 की तुलना में तेज उछाल दिखा। यह प्रवृत्ति जनवरी 2021 से दिखाई दी यानी राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन/प्रतिबंध लगने के पहले। यह अनिवार्य रूप से मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों से मूल्य डेटा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार के लिए 1 जनवरी, 2021 को डीसीए द्वारा एक मोबाइल ऐप में डेटा संग्रह तंत्र में बदलाव को दर्शाता है⁷। ऐप को जियो-टैग किया गया है और इसमें औसत



⁷ <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1701493>

चार्ट 3: प्रमुख समूहों के मार्जिन (मासिक औसत ₹/किलोग्राम) (समाप्त)



टिप्पण: अन्य में चीनी, चायपत्ती, दूध, गुड़, नमक शामिल हैं। ज्यादातर वस्तुओं में 2021 में मार्जिन में उठाव जनवरी 2021 से डीसीए द्वारा डेटा संग्रहण प्रक्रिया में बदलाव के प्रभाव को दर्शाते हैं।
स्रोत: डीसीए, भारत सरकार

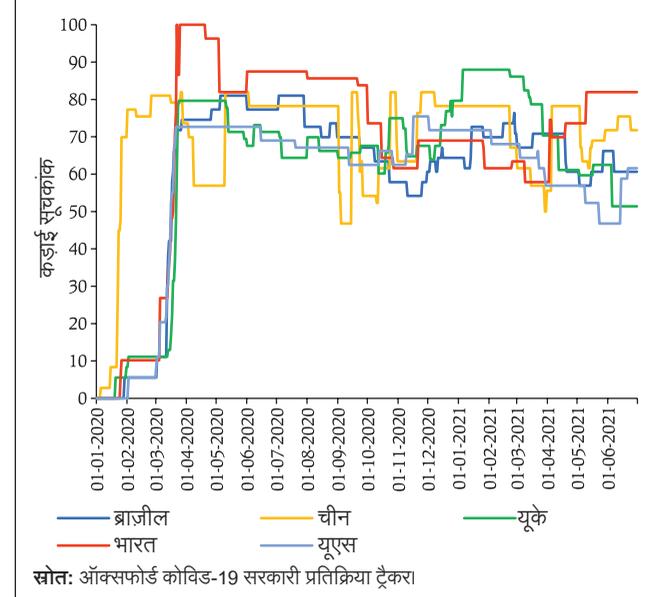
मूल्य की गणना और रिपोर्ट करने के लिए अंतर्निहित विशेषताएं हैं, जो गणना में मानवीय त्रुटियों को कम करता है और डेटा संग्रह प्रक्रिया में सुधार करता है। कवरेज को भी 2020 में 122 केंद्रों से बढ़ाकर 2021 में 135 केंद्रों (मई 2021 तक) कर दिया गया है। इस प्रकार, 2021 के दौरान डीसीए डेटा के अनुसार मार्जिन के स्तर में असामान्य उछाल काफी हद तक बेहतर डेटा संग्रह प्रक्रिया और बाजारों के कवरेज का परिणाम था। बहरहाल, मई 2021 में – दूसरी लहर में लॉकडाउन जब चरम पर था उस चरम महीने में – अनाज, दाल, खाद्य तेलों और अन्य में मार्जिन कम हुआ, जबकि सब्जियों में यह बढ़ा।

2. भारत में कोविड-19 संबंधित उपाय और मोबिलिटी सूचकांक

आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए, निर्दिष्ट दुकानों - राशन की दुकानों सहित, भोजन, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध उत्पाद, मांस और मछली, पशु चारा, बीज और कीटनाशकों से निपटने वाली दुकानों - को देशव्यापी लॉकडाउन उपाय से छूट दी गई थी, जबकि उनके लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य किया गया था, हालांकि, लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाला लॉकडाउन दुनिया में सबसे कठोर साबित हुआ (चार्ट 4)। 25 मार्च, 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन

लागू होने के साथ भारत का कठोरता सूचकांक 100 के अधिकतम मूल्य पर पहुंच गया और 19 अप्रैल, 2020 तक उस स्तर पर रहा⁸। लॉकडाउन को और तीन और चरणों में बढ़ाया गया: 15 अप्रैल से 3 मई (चरण 2); मई 4-मई 17 (चरण 3); और 18 मई-31 मई (चरण 4)। इसके बाद 1 जून, 2020 से

चार्ट 4: देशों में कड़ाई



⁸ 22 मार्च, 2020 को जनता कर्फ्यू के दिन कठोरता सूचकांक भी 100 पर पहुंच गया था।

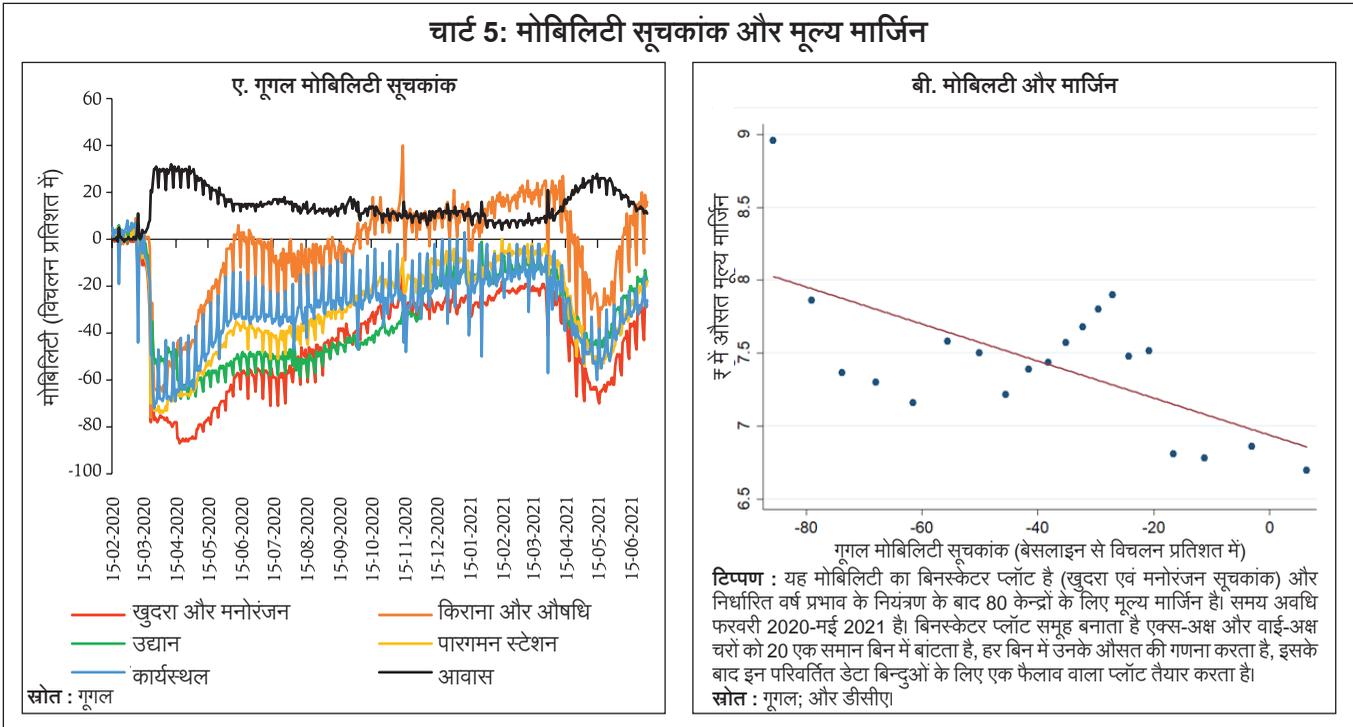
धीरे-धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अप्रैल 2021 से कठोरता सूचकांक फिर से बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि राज्यों ने संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए सप्ताहांत कर्फ्यू, रात के कर्फ्यू और आंशिक और स्थानीय लॉकडाउन लगाए, लेकिन इसकी सीमा मई 2021 में 82 पर पहुंच गयी, जो पहली लहर की तुलना में अभी भी कम था। इस प्रकार, भले ही दूसरी लहर संक्रमित मामलों और मौतों की संख्या के मामले में अधिक गंभीर थी, फिर भी कोई राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन नहीं था और पहली लहर की तुलना में कठोरता कम गंभीर थी।

लॉकडाउन की कठोरता के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मोबिलिटी कम हो गई, खुदरा और मनोरंजन क्षेत्र पर पहले लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक प्रभाव पड़ा (चार्ट 5 ए)। इसके अलावा, मोबिलिटी और मूल्य मार्जिन के बीच एक स्पष्ट नकारात्मक संबंध देखा जा सकता है (चार्ट 5 बी)। ये शैलीगत

तथ्य हमारे अनुभवजन्य विनिर्देश और रणनीति को प्रेरित करते हैं, जिसकी चर्चा खंड III में की गई है।

इसके अलावा, लॉकडाउन की स्थानीयकृत और कम कठोर प्रकृति के अलावा, देश में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के मामले में दूसरी लहर को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया गया है। यह पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर की लॉकडाउन अवधि के दौरान - तत्काल पूर्व-लॉकडाउन शिखर और बाद में गर्त के बीच गिरावट के संदर्भ में टोल संग्रह में कम गिरावट में परिलक्षित होता है (चार्ट 6ए)। समवर्ती रूप से, मंडी आवक में अप्रैल 2021 में अधिकांश वस्तुओं के लिए अप्रैल 2020 की तुलना में और सब्जियों के लिए मई 2021 में कम गिरावट देखी गई (चार्ट 6बी)। इसके विपरीत, दालों और तिलहनों (खाद्य तेलों के लिए प्रमुख पदार्थ) की आवक में दोनों चरणों में तेजी से गिरावट आई, जो तंग घरेलू आपूर्ति की स्थिति को दर्शाता है।

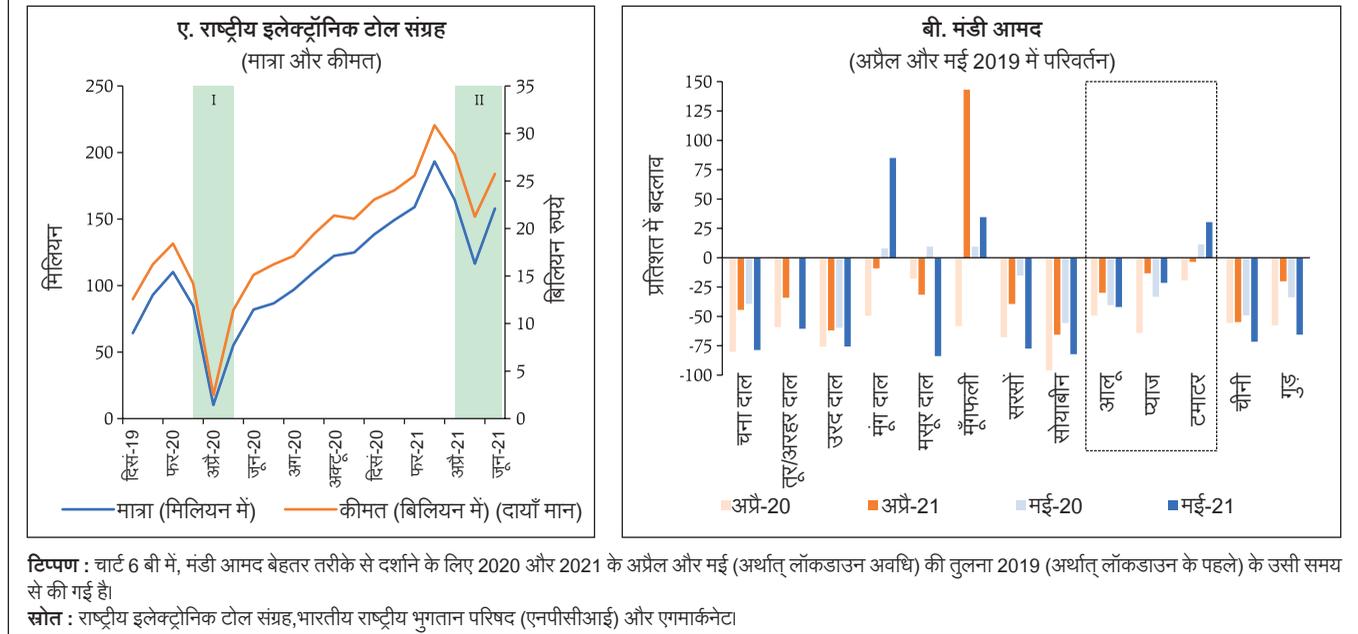
चार्ट 5: मोबिलिटी सूचकांक और मूल्य मार्जिन



⁹ कठोरता सूचकांक पर डेटा केवल सार्वजनिक प्रक्षेत्र में देश स्तर पर उपलब्ध है, जबकि गूगल मोबिलिटी सूचकांक उप-राष्ट्रीय केंद्रों और क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।

¹⁰ रिपोर्टों से पता चलता है कि टोल संग्रह का 70 प्रतिशत से अधिक वाणिज्यिक वाहनों से है (बिजनेस स्टैंडर्ड, 14 अक्टूबर, 2019)।

चार्ट 6: टोल संग्रह और बाज़ार आमद



III. अनुभवजन्य विश्लेषण

1. डेटा

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह लेख मूल्यवर्धन या मार्जिन के व्यवहार को समझने के लिए 135 बाजार केंद्रों¹¹ में 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए दैनिक खुदरा और थोक मूल्य डेटा का विश्लेषण करता है। इन केंद्रों का गूगल मोबिलिटी डेटा¹² के साथ एक और मिलान करने से अंतिम डेटासेट को 80 केंद्रों¹³ तक छॉट कर छोटा कर दिया जाता है। एक केंद्र को पहली लहर के दौरान लॉकडाउन (कम तीव्रता वाले लॉकडाउन केंद्र) से कम प्रभावित होने के रूप में परिभाषित किया जाता है, यदि इसका औसत गूगल मोबिलिटी सूचकांक लॉकडाउन के प्रत्येक चरण में माध्य औसत सूचकांक से अधिक था। इसी तरह, एक केंद्र को अत्यधिक प्रभावित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उसका औसत गूगल मोबिलिटी सूचकांक किसी एक चरण में भी माध्य

औसत सूचकांक से कम था। दूसरी लहर के लिए, वर्गीकरण अप्रैल-मई 2021 में औसत मोबिलिटी के वितरण पर आधारित है - एक केंद्र को कम (अत्यधिक) प्रभावित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसका औसत गूगल मोबिलिटी सूचकांक माध्य औसत सूचकांक से अधिक (कम) था।

2. पहचान कार्यनीति

आवश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्य मार्जिन पर पहले लॉकडाउन के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए दो-चरणीय दृष्टिकोण का पालन किया जाता है। पहले चरण में, सभी 122 केंद्रों (जिनके लिए डेटा 2020 में उपलब्ध थे) को कवर करते हुए जनवरी-जून 2020 की अवधि के लिए दैनिक डेटा पर एक घटना अध्ययन, लॉकडाउन के तत्काल प्रभाव की जांच के लिए निम्नलिखित रूप में किया जाता है, इसी तरह महाजन और तोमर (2020) में अपनाए गए दृष्टिकोण के लिए:

$$Y_{ijt} = \sum_{t=-12}^{13} \beta_{1T} \times Time\ Period_T + \alpha_i + \gamma_j + \varepsilon_{ijt} \dots (1)$$

जहां Y_{ijt} बाज़ार केंद्र i में समय t (दैनिक)¹⁴ पर क्मोडिटी j के लिए रिकार्ड की गई कीमत की मार्जिन है; समय अवधि T प्रतिरूपी

¹¹ 2020 में, डीसीए द्वारा 122 केंद्रों से डेटा मैन्युअल रूप से एकत्र किया गया था, जबकि 2021 में डेटा संग्रह को डेटा गुणवत्ता में सुधार के लिए 135 केंद्रों को कवर करते हुए मोबाइल ऐप-आधारित में स्थानांतरित कर दिया गया था।

¹² खुदरा और मनोरंजन क्षेत्र के गूगल मोबिलिटी इंडेक्स का उपयोग इस विश्लेषण में किया गया है क्योंकि इसमें लॉकडाउन के बाद सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है (चार्ट 5 ए)। हालाँकि, परिणाम गुणात्मक रूप से नहीं बदलते हैं, भले ही अन्य सूचकांकों का उपयोग किया जाए क्योंकि सभी सूचकांक अत्यधिक सहसंबंधित हैं।

¹³ ये मिलान केंद्र 2020 में डीसीए द्वारा कवर किए गए कुल केंद्रों के 65 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

¹⁴ इस पूरे लेख में, आश्रित चर निरपेक्ष मूल्य मार्जिन (खुदरा-थोक) है। हालाँकि, भले ही थोक मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल्य मार्जिन को आश्रित चर के रूप में लिया जाता है, परिणाम गुणात्मक रूप से नहीं बदलते हैं।

चर है जो हर एक 13सप्ताह¹⁵ के लिए वैल्यू 1 लेता है लॉकडाउन घोषणा के पहले (अर्थात् जनवरी 1-मार्च 24,2020) और बाद में; α_{ij} केंद्र निर्धारित प्रभाव (एफ़ई) है और अपरिवर्तनीय-समय केंद्र और कमोडिटी विशिष्टता को नियंत्रित करने के लिए γ_j कमोडिटी एफ़ई है; और ε_{ijt} एक त्रुटि शब्द है। जिस सप्ताह में लॉकडाउन की घोषणा की गयी थी उसे 0 और उससे पहले के सप्ताह को (-1) आधार अवधि के रूप में लिया जाता है। समय अवधि के लिए प्रतिरूपी चर का गुणांक आधार अवधि (घोषणा के एक सप्ताह पहले) के सापेक्ष प्रत्येक समय अवधि (लॉकडाउन घोषणा के पहले और बाद) में कीमत मार्जिन के अंतर को देखता है। अगर लॉकडाउन ने वास्तव में मार्जिन को बढ़ाया है, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि 0 से शुरू हुई समय अवधि में सकारात्मक और महत्वपूर्ण गुणांक देखने मिलेंगे।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है पहला दृष्टिकोण (विनिर्देश 1), हालांकि, खाद्य कीमतों में मौसमी बदलाव को ध्यान में नहीं रखता है, जो कि मानसून पर कृषि की बड़ी निर्भरता को देखते हुए भारत के मामले में महत्वपूर्ण है। इस तरह के मौसमी रुख को ध्यान में रखते हुए, अंतर-में-अंतर विनिर्देश (लोव, नधानेल और रोथ, 2020; वाष्ण्य, रॉय और मीनाक्षी, 2020) का उपयोग दूसरे चरण में किया जाता है, जहां 2020 की मार्जिन को 2019 की इसी अवधि के साथ तुलना किया जाता है:

$$Y_{ijt} = \sum_{T=1}^2 \beta_{1T} \times Time\ Period_T + \sum_{T=1}^2 \beta_{2T} \times (Time\ Period_T \times 2020) + \alpha_{ij} + \gamma_{1jm} + \gamma_{2jy} + \delta_{1lm} + \delta_{2ly} + \varepsilon_{ijt} \quad \dots (2)$$

जहां Y_{ijt} बाज़ार केंद्र i में समय t (दैनिक) पर कमोडिटी j के लिए रिकार्ड की गई कीमत की मार्जिन है; समय अवधि T प्रतिरूपी चर है जो लॉकडाउन अवधि 25 मार्च-31 मई 2020 के लिए वैल्यू 1 लेता है; समय अवधि 2 एक प्रतिरूपी चर है जो जून-नवंबर

2020 की अनलॉकिंग अवधि के लिए वैल्यू 1 लेता है; 2020 एक प्रतिरूपी चर है जो वर्ष 2020 के लिए वैल्यू 1 लेता है; α_{ij} केंद्र कमोडिटी-एफ़ई है; γ_{2jy} कमोडिटी-वर्ष एफ़ई है; δ_{1lm} राज्य-माह एफ़ई नियंत्रण करता है; ; δ_{2ly} राज्य-वर्ष एफ़ई¹⁶ नियंत्रण करता है; और ε_{ijt} एक त्रुटि शब्द है। यहाँ नमूना जनवरी 2019-नवंबर 2020 की अवधि के लिए मिलान किया हुआ डेटासेट है (80 केन्द्र)। मानक त्रुटि (1) और (2) दोनों विनिर्दिष्टता के लिए कमोडिटी-केंद्र स्तर पर जुड़ा हुआ है।

ब्याज का गुणांक β_{21} है। यह वर्ष 2019 के सापेक्ष वर्ष 2020 के लिए समय अवधि (25 मार्च-31 मई) और संदर्भ अवधि (1 जनवरी-मार्च 24) के बीच मूल्य मार्जिन में अंतर का अनुमान लगाता है। यह माना जाता है कि यदि घटना – कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन - नहीं हुआ होता, तो 2020 में मूल्य मार्जिन 2019 की समान प्रवृत्ति का पालन करता, अगर अन्य बातें पूर्ववत् रहीं। इसी तरह, गुणांक β_{22} मूल्यांकन करता है कि क्या जून 2020 में अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू होने पर भी लॉकडाउन का प्रभाव बना रहा¹⁷। राज्य-दर-माह (वर्ष) और कमोडिटी-दर-माह (वर्ष) निश्चित प्रभाव समय के लिए अलग-अलग राज्य-स्तर पर या कमोडिटी-स्तर के झटके (अवलोकन या बिना देखे) गैर-पैरामीट्रिक रूप से नियंत्रण करते हैं। यह 2020 और 2019 के बीच मूल्य मार्जिन की तुलना राज्य के भीतर या कमोडिटी के भीतर की सुविधा प्रदान करता है।

इसी तरह की कार्यनीति जनवरी 2021-मई 2021 की अवधि के लिए मिलान किए गए डेटासेट का उपयोग करके दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए नियोजित की जाती है जिसमें 2021 के मूल्य मार्जिन की तुलना 2019 (जनवरी-मई 2019) से की जाती है। हालांकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस अवधि के दौरान कोई राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन नहीं था; राज्यों ने वायरस के स्थानीय प्रसार और

¹⁵ जनवरी 1-मार्च 24, 2020 की पूर्ण पूर्व-लॉकडाउन अवधि को ध्यान में रखते हुए 13 सप्ताह करीब, और घटना से पहले के सप्ताह (यानी, 18-24 मार्च, 2020) को एक मानदंड के रूप में ध्यान में रखते हुए मानदंड की तुलना करने के लिए प्रतिरूपी समय अवधि की शुरुआत की गई है। तदनुसार, सममित निरूपण के लिए, घटना को समझने के लिए लॉकडाउन के 13 सप्ताह बाद भी विचार किया जाता है।

¹⁶ "अंग्रेजी का छोटा आई" केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है और "अंग्रेजी का बड़ा आई" उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जिससे केंद्र संबंधित है।

¹⁷ हमारी नमूना अवधि नवंबर में समाप्त होती है क्योंकि अनलॉकिंग प्रक्रिया को 30 नवंबर, 2020 तक चरणों में बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा, गूगल मोबिलिटी सूचकांक भी नवंबर 2020 में आधारभूत रेखा से लगभग 30 प्रतिशत विचलन पर स्थिर हो गया। तदनुसार, जनवरी-नवंबर 2020 की तुलना जनवरी-नवंबर 2019 के साथ की जाती है।

परीक्षण संक्रमण दर के आधार पर लॉकडाउन जैसे उपायों को अलग अलग जगहों पर लागू किया¹⁸। इसलिए, इस विनिर्देश में राज्यों में उपचार की अवधि अलग-अलग है, महाराष्ट्र के लिए 5 अप्रैल, 2021 से, दिल्ली के लिए 19 अप्रैल, 2021 से और इसी तरह बाकी की¹⁹।

$$Y_{ijt} = \beta_3 \times Time\ Period_{it} + \beta_4 \times (Time\ Period_{it} \times 2021) + \alpha_{ij} + \gamma_{1jm} + \gamma_{2jy} + \delta_{1lm} + \delta_{2ly} + \epsilon_{ijt} \quad \dots (3)$$

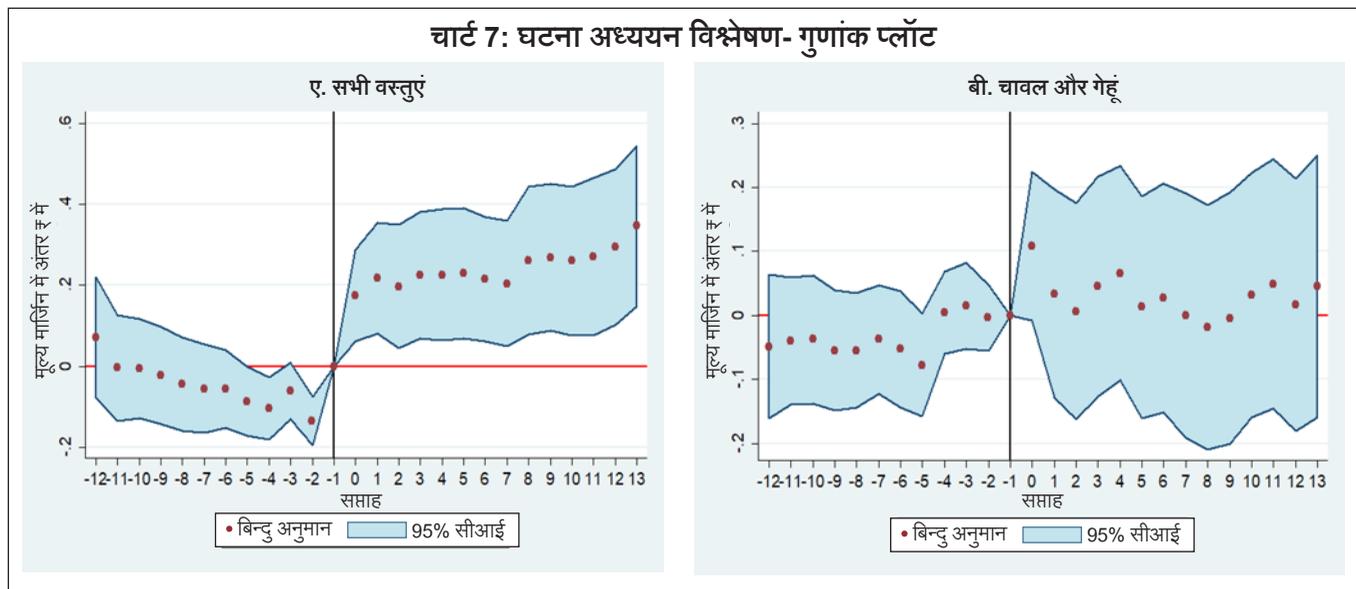
जहां 2021 एक प्रतिरूपी चर है जो वर्ष 2021 होने पर मान 1 लेता है और समय अवधि एक प्रतिरूपी चर है जो उस राज्य के आधार पर लॉकडाउन की प्रासंगिक समय अवधि के लिए मान 1 लेता है जिससे केंद्र संबंधित है। ब्याज का गुणांक β_4 है जो वर्ष 2019 के सापेक्ष वर्ष 2021 के लिए समय अवधि और संदर्भ अवधि के बीच मूल्य मार्जिन में अंतर को मापता है। समीकरण (2) और (3) लॉकडाउन की तीव्रता (उच्च या निम्न तीव्रता) और कमोडिटी समूहों पर आधारित 80 मिलान केंद्रों के उप-नमूनों के लिए चलाए जाते हैं।

3. परिणाम

3.1: पहली लहर के दौरान लॉकडाउन का असर

संपूर्ण नमूने (सभी 22 वस्तुओं) के लिए विनिर्देश 1 के अनुमान और विभिन्न समूहों के उप-नमूनों के साथ-साथ उनके 95 प्रतिशत विश्वास अंतराल से पता चलता है कि पहले लॉकडाउन (चार्ट 7 ए) की घोषणा के तुरंत बाद मूल्य मार्जिन में औसतन वृद्धि हुई। हालांकि, यह वृद्धि एक समान नहीं थी; यह मुख्य रूप से दालों, खाद्य तेलों, आलू और टमाटर द्वारा संचालित था (चार्ट 7बी-7एच)²⁰।

घटना अध्ययन विश्लेषण के निष्कर्षों की पुष्टि विनिर्देश (1) के आधार पर अनुमानों द्वारा की जाती है। 2019 की समान अवधि के सापेक्ष 2020 में आधारभूत की तुलना में 25 मार्च-31 मई, 2020 के दौरान सभी 22 वस्तुओं के लिए मूल्य मार्जिन में औसतन ₹0.44 की वृद्धि हुई। यह आधारभूत औसत (जनवरी-मार्च, 2020) से 7 प्रतिशत की वृद्धि जो कि ₹6.26 है को दर्शाता है, जो अनलॉक अवधि (जून-नवंबर) में भी जारी रहा। इसके अलावा, मार्जिन में इस तरह की वृद्धि मुख्य रूप से उच्च तीव्रता

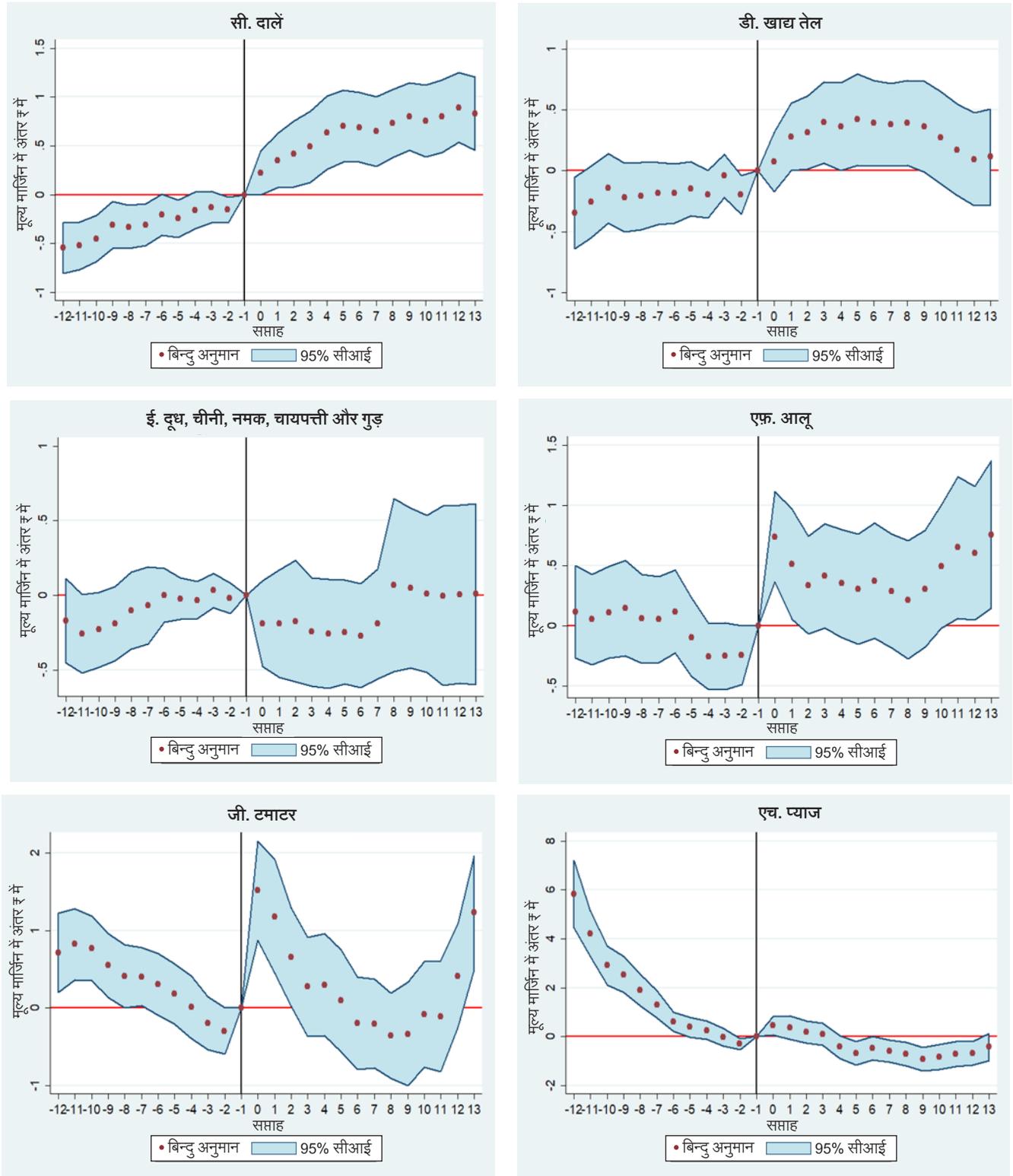


¹⁸ दूसरी लहर के लिए एक घटना अध्ययन विश्लेषण का प्रयास नहीं किया गया है क्योंकि लॉकडाउन के उपायों को राज्यों में क्रमिक/सांतर तरीके से लागू किया गया था।

¹⁹ प्रत्येक राज्य के लिए लॉकडाउन अवधि की जानकारी समाचार पत्रों और राज्य सरकार की वेबसाइटों से प्राप्त की गई थी।

²⁰ मार्च-मई 2020 की अवधि के लिए मद स्तरीय सीपीआई डेटा कोई तुलना करने के लिए उपलब्ध नहीं था।

चार्ट 7: घटना अध्ययन विश्लेषण- गुणांक प्लॉट (समाप्त)



टिप्पणी: सप्ताह जिसमें लॉकडाउन की घोषणा की गयी थी उसे 0 और उससे एक सप्ताह पहले को (-1) आधार अवधि के तौर पर लिया जाता है। गुणांक और 95 प्रतिशत विश्वास अंतराल जो यहाँ प्लॉट किया गया है (वाई-अक्ष) आधार अवधि (घोषणा के पहले वाले सप्ताह) की तुलना में हर सप्ताह (लॉकडाउन के पहले और बाद के सप्ताह) में मूल्य मार्जिन के अंतर को देखता है।

स्रोत : डीसीए; और लेखक की गणना।

सारणी 1: पहली लहर के दौरान केन्द्रों पर मूल्य मार्जिन²¹

	सभी केंद्र	अधिक तीव्रता वाले लॉकडाउन केंद्र	कम तीव्रता वाले लॉकडाउन केंद्र
	(1)	(2)	(3)
2020=1 × मार्च 25-मई 31=1 #	0.441*** (0.0914)	0.602*** (0.116)	0.136 (0.142)
2020=1 × जून-नवंबर=1#	0.312** (0.144)	0.372* (0.191)	0.228 (0.185)
आधारभूत औसत (जन-मार्च 24, 2020)	6.26	6.54	5.63
समायोजित आर ² प्रेक्षण	0.779 834133	0.776 573750	0.800 260383

टिप्पणी : केंद्र × क्मोडिटी एफई, राज्य × माह एफई, राज्य × वर्ष एफई, क्मोडिटी × माह एफई, और क्मोडिटी × वर्ष एफई उपरोक्त सभी विनिर्देशों में शामिल हैं। मानक त्रुटियों को क्मोडिटी-सेंटर स्तर पर क्लस्टर किया जाता है।

2020 एक प्रतिरूपी चर है, जो 2020 होने पर मान 1 लेता है। 25 मार्च-31 मई और जून-नवंबर प्रतिरूपी चर हैं जो मान 1 लेते हैं यदि तारीख उन अवधियों से संबंधित है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

मानक त्रुटियां कोष्ठक में हैं।

*, ** और *** क्रमशः 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत पर महत्व दर्शाते हैं।

वाले लॉकडाउन केंद्रों द्वारा संचालित होती है, जहां आधारभूत औसत (सारणी 1) की तुलना में इसमें 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, कम तीव्रता वाले केंद्रों में मार्जिन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

समग्र स्तर पर मूल्य मार्जिन में वृद्धि मुख्य रूप से दालों, खाद्य तेलों और आलू के मामले में मार्जिन में वृद्धि से प्रेरित

थी²², जबकि लॉकडाउन का अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों के मार्जिन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा (सारणी 2)। उनके संबंधित आधारभूत औसत की तुलना में दालों के लिए मार्जिन में 19.3 प्रतिशत, खाद्य तेलों के लिए 11.2 प्रतिशत और आलू के लिए 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मार्जिन पर लॉकडाउन के प्रभाव के संदर्भ में क्मोडिटी स्तर के अंतर उनकी कीमत में नरमी के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं में अंतर को उजागर करते हैं। अनाज, दालें और खाद्य तेल जैसे खराब नहीं होने वाली वस्तुओं का उपभोक्ताओं द्वारा भंडारण किया जा सकता था जिससे महामारी के दौरान उच्च मांग हो सकती थी। हालांकि, सरकार द्वारा पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत प्रति माह गरीबों को 5 किलो चावल या गेहूं के मुफ्त वितरण और समय पर खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से स्टॉक जारी करने के कारण अनाज के मार्जिन में कोई वृद्धि नहीं हुई। दालों के मामले में, आम तौर पर तंग घरेलू आपूर्ति-मांग की स्थिति के कारण, 2019-20 में कम खरीफ उत्पादन से उपलब्धता कम हो गई, जबकि लॉकडाउन के कारण मांग में अचानक वृद्धि हुई, जिससे मार्जिन में वृद्धि हुई। इसी तरह, खाद्य तेलों के मामले में, जहां घरेलू मांग का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 60 प्रतिशत) विशेष रूप से ताड़ के तेल के आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है,

सारणी 2: पहली लहर के दौरान वस्तुओं पर मूल्य मार्जिन

	अनाज	दालें	खाद्य तेल	अन्य खाद्य पदार्थ	सब्जियां	आलू
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020=1 × मार्च 25-मई 31=1	-0.0391 (0.108)	1.324*** (0.191)	0.732*** (0.195)	0.119 (0.227)	-0.547*** (0.190)	0.640** (0.242)
2020=1 × जून-नवंबर=1	-0.0842 (0.140)	0.861*** (0.278)	0.459* (0.276)	0.408 (0.446)	-0.603** (0.246)	0.717** (0.315)
आधारभूत औसत (जन-मार्च 24, 2020)	3.27	6.87	6.51	7.09	6.51	5.20
समायोजित आर ² प्रेक्षण	0.638 119747	0.699 202747	0.733 206226	0.832 183315	0.684 122098	0.738 40724

टिप्पणी : केंद्र × क्मोडिटी एफई, राज्य × माह एफई, राज्य × वर्ष एफई, क्मोडिटी × माह एफई, और क्मोडिटी × वर्ष एफई उपरोक्त सभी विनिर्देशों में शामिल हैं। अनाज में आटा, गेहूं और चावल शामिल हैं; दालों में चना, मसूर, मूंग, अरहर और उड़द शामिल हैं; खाद्य तेलों में मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, ताड़ का तेल, सोया तेल, सूरजमुखी का तेल और वनस्पति तेल शामिल हैं; अन्य खाद्य पदार्थों में दूध, चीनी, नमक, गुड़ और चाय की पत्तियां शामिल हैं; सब्जियों में आलू, टमाटर और प्याज शामिल हैं। मानक त्रुटियों को क्मोडिटी-सेंटर स्तर पर क्लस्टर किया जाता है।

मानक त्रुटियां कोष्ठक में हैं।

*, ** और *** क्रमशः 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत पर महत्व दर्शाते हैं।

²¹ यह समग्र स्तर का परिणाम आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अध्याय 2 में बॉक्स II.2.1 (पृष्ठ 50) में प्रकाशित किया गया था, लेकिन दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन के लिए उप-समूह स्तर के अनुमानों और अनुमानों के साथ एक तुलनात्मक तस्वीर प्रदान करने के लिए यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है।

²² टमाटर के लिए, वृद्धि केवल लॉकडाउन के पहले चरण (25 मार्च-14 अप्रैल, 2020) में हुई।

लॉकडाउन ने भारतीय बाजारों में आयात के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी, जबकि उपभोक्ताओं द्वारा भंडारण (एहतियाती खरीद) की मांग में वृद्धि हुई, जिसने मार्जिन को बढ़ा दिया।

डीसीए डेटा में शामिल अन्य खराब नहीं होने वाली वस्तुओं जैसे चाय की पत्ती, नमक, गुड़ और चीनी ने मार्जिन में केवल एक थोड़ी सी वृद्धि दिखाई। अधिक घरेलू उत्पादन के कारण चीनी के मामले में मार्जिन में अधिक वृद्धि नहीं हुई, जबकि चीनी का एक करीबी विकल्प होने के कारण गुड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लॉकडाउन के दौरान चाय की मांग बढ़ने से मार्जिन में थोड़ी तेजी देखी गई।

प्याज, टमाटर, आलू और दूध जैसी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए प्रभाव अलग था। दूध का मामला अजीबोगरीब है, क्योंकि इसकी एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला है जो देश में उत्पादन और वितरण की सहकारी संरचना पर हावी है। इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटी डेयरियों से आपूर्ति के अनौपचारिक चैनलों द्वारा औपचारिक आपूर्ति को और बढ़ाया जाता है, जिससे भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन जाता है। इस प्रकार, तेजी से आपूर्ति प्रतिक्रिया के साथ अधिशेष घरेलू उत्पादन के परिणामस्वरूप दूध की कीमतों पर लॉकडाउन का केवल एक मामूली प्रभाव पड़ा।

सब्जियों में, प्याज की कीमतें दिसंबर 2019 में लॉकडाउन के समय अपने चरम पर पहुँचने के बाद मौसमी सुधार पर थीं, जबकि रबी की बेहतर फसल बाजार में आ रही थी, जिससे कीमतों के दबाव को कम करने में मदद मिली। लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही टमाटर की कीमतों और मार्जिन में अचानक और बड़ा उछाल दिखा, लेकिन रबी की फसल के बाजार में बहुतायत में आने से उसमें सुधार आ गया और आपूर्ति श्रृंखला में शुरुआती अड़चनों को राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों से संबोधित किया गया। दो प्रमुख उत्पादक राज्य - जिससे आपूर्ति बाधित हो गई थी मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश में फसल की क्षति और मई 2020 में चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल में और अधिक नुकसान होने के बावजूद आलू में मार्जिन, हालांकि, रबी की आवक अवधि के साथ होने के बावजूद, लॉकडाउन के दौरान बढ़ा और स्थिर रहा। साथ ही, लॉकडाउन के दौरान आलू की उपभोक्ता मांग भी बढ़ गई

होगी, क्योंकि उन्हें प्याज और टमाटर की तुलना में अधिक समय तक संग्रहीत किया जा सकता है, जिससे उनके मार्जिन में वृद्धि हुई।

3.2: दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन का असर

विनिर्देश (3) के आधार पर विश्लेषण को दूसरी लहर में विस्तारित करने से संकेत मिलता है कि अप्रैल-मई 2021 में स्थानीयकृत लॉकडाउन के दौरान समग्र स्तर पर मार्जिन में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई थी²³। भले ही समय अवधि × 2021 का गुणांक उच्च गहन लॉकडाउन केंद्र के लिए सकारात्मक है, यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है (सारणी 3)।

कमोडिटी/उप-समूह स्तर पर, हालांकि, दूसरी लहर के दौरान मार्जिन पर लॉकडाउन का प्रभाव काफी अलग था। दालों और खाद्य तेलों ने मार्जिन में वृद्धि दर्ज की, हालांकि पहली लहर की तुलना में (19.3 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत, क्रमशः दालों और तेलों के लिए) उनके आधारभूत रेखा से प्रतिशत के संदर्भ में दूसरी लहर के दौरान बहुत कम मात्रा में (5.3 प्रतिशत और 7.9 प्रतिशत, क्रमशः दालों और तेलों के लिए) वृद्धि हुई। दूसरी ओर, पहली लहर की तुलना में अनाज के मामले में मार्जिन में गिरावट

सारणी 3: दूसरी लहर के दौरान केन्द्रों पर मूल्य मार्जिन

	सभी केंद्र	अधिक तीव्रता वाले लॉकडाउन केंद्र	कम तीव्रता वाले लॉकडाउन केंद्र
	(1)	(2)	(3)
2021=1 × दूसरी लहर =1	-0.0362 (0.188)	0.0900 (0.281)	-0.151 (0.251)
आधारभूत औसत (राज्य-विशेष)	9.13	10.93	7.51
समायोजित आर ²	0.694	0.699	0.706
प्रेक्षण	335204	170153	165051

टिप्पणी : केंद्र × कमोडिटी एफई, राज्य × माह एफई, राज्य × वर्ष एफई, कमोडिटी × माह एफई, और कमोडिटी × वर्ष एफई उपरोक्त सभी विनिर्देशों में शामिल हैं। मानक त्रुटियों को कमोडिटी-सेंटर स्तर पर क्लस्टर किया जाता है।

मानक त्रुटियां कोष्ठक में हैं

*, ** और *** क्रमशः 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत पर महत्व दर्शाते हैं।

²³ अनलॉकिंग 1 जून, 2021 से उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, इसके बाद दिल्ली (7 जून) और महाराष्ट्र (14 जून) का स्थान रहा।

सारणी 4: दूसरी लहर के दौरान वस्तुओं पर मूल्य मार्जिन

	अनाज	दालें	खाद्य तेल	अन्य खाद्य मदें	सब्जियाँ	टमाटर और प्याज
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021=1 × दूसरी लहर=1	-0.557** (0.235)	0.540** (0.261)	0.742** (0.372)	-0.693 (0.643)	-0.785*** (0.220)	-1.142*** (0.260)
आधारभूत औसत (राज्य-विशेष)	5.50	10.31	9.40	11.96	6.03	6.14
समायोजित आर ²	0.575	0.674	0.617	0.725	0.617	0.603
प्रेक्षण	48562	82752	80691	74241	48957	32605

टिप्पणी : केंद्र × कमोडिटी एफई, राज्य × माह एफई, राज्य × वर्ष एफई, कमोडिटी × माह एफई, और कमोडिटी × वर्ष एफई उपरोक्त सभी विनिर्देशों में शामिल हैं। अनाज में आटा, गेहूं और चावल शामिल हैं; दालों में चना, मसूर, मूंग, अरहर और उड़द शामिल हैं; खाद्य तेलों में मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, ताड़ का तेल, सोया तेल, सूरजमुखी का तेल और वनस्पति तेल शामिल हैं; अन्य खाद्य पदार्थों में दूध, चीनी, नमक, गुड़ और चाय की पत्तियां शामिल हैं; सब्जियों में आलू, टमाटर और प्याज शामिल हैं। मानक त्रुटियों को कमोडिटी-सेंटर स्तर पर क्लस्टर किया जाता है।

मानक त्रुटियां कोष्ठक में हैं।

*, ** और *** क्रमशः 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत पर महत्व को दर्शाते हैं।

आई और सब्जियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक, जो कि दर्शाता है खाद्यान्न के बड़े बफर स्टॉक और बेहतर आपूर्ति प्रबंधन को (सारणी 4)। मार्जिन में इन विरोधी आंदोलनों के साथ एक दूसरे की बराबरी करने के साथ, कुल स्तर के मार्जिन में कोई वृद्धि नहीं हुई। कुल मिलाकर, इन परिणामों से संकेत मिलता है कि पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर के दौरान मूल्यवर्धन पर लॉकडाउन उपायों का प्रभाव कम गंभीर था, जैसा कि सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन की कम कठोर और स्थानीय प्रकृति के साथ-साथ बेहतर आपूर्ति प्रबंधन के कारण अपेक्षित था।

IV. निष्कर्ष

यह लेख भारत में आवश्यक खाद्य पदार्थों में मूल्य मार्जिन पर कोविड-19 की दोनों लहरों के दौरान लॉकडाउन के प्रभाव की जांच करता है। यह दो आयामों पर अंतर-में-अंतर अनुभवजन्य कार्यनीति को नियोजित करता है - केंद्रों में (जो लॉकडाउन की तीव्रता के आधार पर विभेदित होते हैं) और खाद्य पदार्थों में (जो विशिष्ट मदों के लिए उनकी आपूर्ति श्रृंखला और सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर विभेदित होते हैं)। परिणाम बताते हैं कि पहले लॉकडाउन अवधि के दौरान मूल्य मार्जिन में औसतन 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बाद के अनलॉकिंग चरण में कुछ कमी के साथ बनी रही। इसके अलावा, मार्जिन में वृद्धि मुख्य रूप से उच्च

तीव्रता वाले लॉकडाउन केंद्रों द्वारा संचालित पाई गई, जो लॉकडाउन की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा, सभी कमोडिटी के मार्जिन पर लॉकडाउन के प्रभाव में काफी विविधता थी - दालों और खाद्य तेलों में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो तंग घरेलू आपूर्ति-मांग की स्थिति को दर्शाती है, जबकि अनाज और दूध ने अधिक आपूर्ति और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिखाया। दूसरी लहर के दौरान, स्थानीयकृत लॉकडाउन का समग्र स्तर पर केंद्रों पर मार्जिन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा, हालांकि कमोडिटी/उप-समूह स्तर के अंतर बने रहे। दालों और खाद्य तेलों ने लगातार तंग आपूर्ति-मांग की स्थिति के कारण मार्जिन में वृद्धि दर्ज की, हालांकि अपेक्षाकृत कम परिमाण की, जबकि अनाज और सब्जियों के मामले में मार्जिन में गिरावट आई, जो दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन की कम कठोर प्रकृति के साथ-साथ सरकारों द्वारा बेहतर आपूर्ति प्रबंधन को दर्शाता है।

संदर्भ:

Ebrahimi, E., D. Igan, and S. M. Peria (2020), "The Impact of COVID-19 on Inflation: Potential Drivers and Dynamics", *Special Notes Series on COVID-19*, International Monetary Fund.

Lowe, M., G. V. Nadhanael, and Benjamin N. Roth (2020). "India's Food Supply Chain during the Pandemic", *Harvard Business School Working Paper 21-070*.

Mahajan, K., and S. Tomar (2020). "Here Today, Gone Tomorrow: COVID-19 and Supply Chain Disruptions", *Discussion Paper Series in Economics* (DP No. 28), Ashoka University.

Narayanan, S., and S. Saha (2020), "Urban Food Markets and the Lockdown in India", *Indira Gandhi Institute of Development Research*, WP-2020-017.

Reardon, T., A. Mishra, Chandra S R Nuthalapati, M. F. Bellemare, and D. Zilberman (2020). "COVID-19's Disruption of India's Transformed Food Supply Chains", *Economic & Political Weekly*, 18-22.

Sukhwani, V., S. Deshkar, and R. Shaw (2020). "COVID-19 Lockdown, Food Systems and Urban-Rural Partnership: Case of Nagpur, India", *International Journal of Environmental Research and Public Health*.

Varshney, D., D. Roy, and J. V. Meenakshi (2020), "Impact of COVID 19 on Agricultural Markets: Assessing the Roles of Commodity Characteristics, Disease Caseload and Market Reforms." *Indian Economic Review* S83-S103.

टीएलटीआरओ और संरचनात्मक चलनिधि: एनबीएफसी के लिए एक अनुकूल स्थिति?*

कोविड-19 महामारी ने एनबीएफसी सहित घरेलू स्तर पर सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। हाल की अवधि के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसने उनकी चलनिधि की स्थिति को बढ़ा दिया। रिजर्व बैंक और सरकार ने इस क्षेत्र में निधियों के प्रवाह को सुगम बनाने और समग्र वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए अंशांकित उपाय किए। यह लेख डिफरेंस-इन-डिफरेंस कार्यनीति को नियोजित करके एनबीएफसी की संरचनात्मक चलनिधि पर लक्षित दीर्घावधि रेपो संचालन (टीएलटीआरओ) योजना के प्रभाव की जांच करता है। परिणाम बताते हैं कि टीएलटीआरओ के माध्यम से निधि प्राप्त करने वाली एनबीएफसी ने दूसरों की तुलना में अपनी अल्पावधि चलनिधि बकेट में सुधार देखा।

भूमिका

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भारत की वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में उभरी हैं और समाज के बैंक रहित और कम-बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों के साथ-साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों, वाहन ऋण और इंफ्रास्ट्रक्चर का वित्तपोषण जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को वित्तीय पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रौद्योगिकी-संचालित व्यवसाय और परिचालन मॉडल, वक्र से आगे रहने में चपलता और अनुकूलन क्षमता और नवीन उत्पाद की प्रस्तुति ने न केवल एनबीएफसी को एक तेजी से प्रतिस्पर्धी वित्तीय परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहने में सक्षम बनाया है, बल्कि उनके क्षेत्रीय उदय को भी सुविधाजनक बनाया है। पिछले एक दशक में, एनबीएफसी क्षेत्र ने जबरदस्त वृद्धि का

प्रदर्शन किया है, जैसा कि मार्च 2012 में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और वित्तीय सेवाओं के कारण हुई कठिनाइयों (आईएल एंड एफएस) मामले, कुछ अन्य एनबीएफसी द्वारा चूक और बाद में विश्वास की हानि, रेटिंग में गिरावट और चलनिधि की कमी के बावजूद उनके तुलन पत्र का आकार ₹10.6 लाख करोड़ से बढ़कर सितंबर 2020¹ में ₹35.9 लाख करोड़ हो गया है।

भारत में एनबीएफसी बड़े पैमाने पर पारंपरिक उधार गतिविधियों में लगी हुई हैं जिसमें परिपक्वता का परिवर्तन शामिल है; अर्थात्, वे अक्सर अपने ग्राहकों के दीर्घकालिक ऋण के लिए वित्त के कई अल्पावधि स्रोतों पर निर्भर होते हैं। कोविड-19 महामारी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था अवरुद्ध है, ने एनबीएफसी सहित सभी क्षेत्रों को घरेलू स्तर पर प्रभावित किया है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, एनबीएफसी को हाल की अवधि के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा – पहला, कोविड-19-प्रेरित लॉकडाउन ने एनबीएफसी की गतिविधियों को एक ठहराव में ला दिया, जिसमें उनका संग्रह और संवितरण बंद हो गया और उनकी चलनिधि स्थिति अत्यधिक खराब हो गई और दूसरा, महामारी-प्रेरित बिकवाली ने वित्तीय बाजारों में वित्तीय स्थितियों को सख्त कर दिया और सुरक्षित आस्तियों में निवेश की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। अप्रैल 2020 में म्यूचुअल फंड क्षेत्र में प्रतिकूल गतिविधियों ने दोनों के बीच अंतर्संबंधों के कारण एनबीएफसी क्षेत्र के संकट को और बढ़ा दिया (बित्रा और अन्य, 2020)। जोखिम से बचने और अनिश्चितता के कारण बाजार और बैंकों के पीछे हटने से एनबीएफसी की निधीयन चुनौतियां अधिक बढ़ गईं। गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जैसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बाजार लिखतों को इस अवधि के दौरान प्रतिफल में स्पाइक्स का सामना करना पड़ा। चूंकि एनबीएफसी का केंद्रीय बैंक से उधार लेना के गोपनीय नहीं हैं, इसलिए रिजर्व बैंक और सरकार ने इस क्षेत्र में निधि के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और समग्र वित्तीय स्थिरता बहाल करने के लिए कैलिब्रेटेड उपाय किए हैं। इसके लिए, लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (टीएलटीआरओ), विशेष चलनिधि योजना (एसएलएस), आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 (पीसीजीएस 2.0)

* यह लेख के एम नीलिमा, नंदिनी जयकुमार और जिबिन जोस द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के अशोक साहू और गोपाल प्रसाद के कुशल मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। लेखक पल्लवी चव्हाण के मार्गदर्शन और उपयोगी टिप्पणियों के लिए आभारी हैं जिन्होंने इस लेख को समृद्ध किया। लेखक उपयोगी टिप्पणियों और सुझावों के लिए अज्ञात निर्णायकों के भी आभारी हैं। पर्यवेक्षण विभाग द्वारा डेटा समर्थन के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

¹ भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, 2019-20।

और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के लिए पुनर्वित्त सुविधा जैसी कई चलनिधि बढ़ाने वाली योजनाएं शुरू की गईं (रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, 2021)। इन उपायों ने एनबीएफसी के सामने आने वाली निधीयन चुनौतियों को कम करने में मदद की, उनकी उधारी लागत को कम किया और बाजार के विश्वास में सुधार किया। हालांकि, किसी भी अध्ययन ने इन चलनिधि योजनाओं की प्रभावशीलता की अनुभवजन्य जांच नहीं की है। इस पृष्ठभूमि में, यह लेख इस बात की जांच करने का प्रयास करता है कि टीएलटीआरओ ने डिफरेंस-इन-डिफरेंस पद्धति को नियोजित करके एनबीएफसी की संरचनात्मक चलनिधि को कैसे प्रभावित किया, जिसने भारत में एनबीएफसी से संबंधित नवजात साहित्य में योगदान दिया।

इस लेख के शेष भाग को पाँच भागों में विभाजित किया गया है। भाग II और III क्रमशः एनबीएफसी और टीएलटीआरओ योजना की उधारी प्रोफाइल पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। भाग IV डेटा और कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। परिणामों की चर्चा भाग V में की गई है और भाग VI के निष्कर्ष दिया गया है।

II. एनबीएफसी के उधार

एनबीएफसी बड़े पैमाने पर अपनी गतिविधियों को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करते हैं, जो उनकी देनदारियों का लगभग दो-तिहाई है। वे निधि जुटाने के लिए विभिन्न स्रोतों पर निर्भर

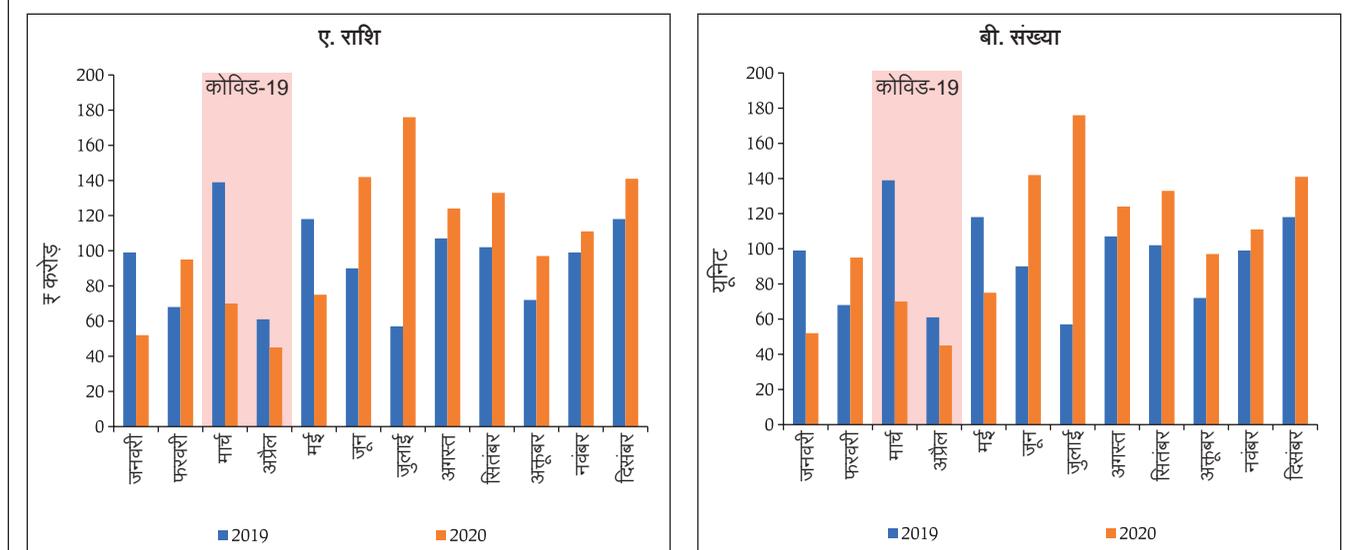
रहते हैं, जिसमें एनसीडी और सीपी जैसे बाजार लिखत जारी करना, बैंकों से उधार लेना, वित्तीय संस्थाओं और अंतर-कॉर्पोरेट उधार, अन्य शामिल हैं (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2020)। दिसंबर 2020 में बाजार और बैंकों ने अपनी कुल उधारी का 76.7 प्रतिशत का गठन किया (जयकुमार और अन्य, 2021)। इस भाग में, एनबीएफसी के बाजार और बैंक उधार का विश्लेषण यह समझने के लिए किया गया है कि एनबीएफसी को बुरी स्थिति से निकालने के लिए चलनिधि उपायों की आवश्यकता क्यों थी।

II.1 बाजार उधार

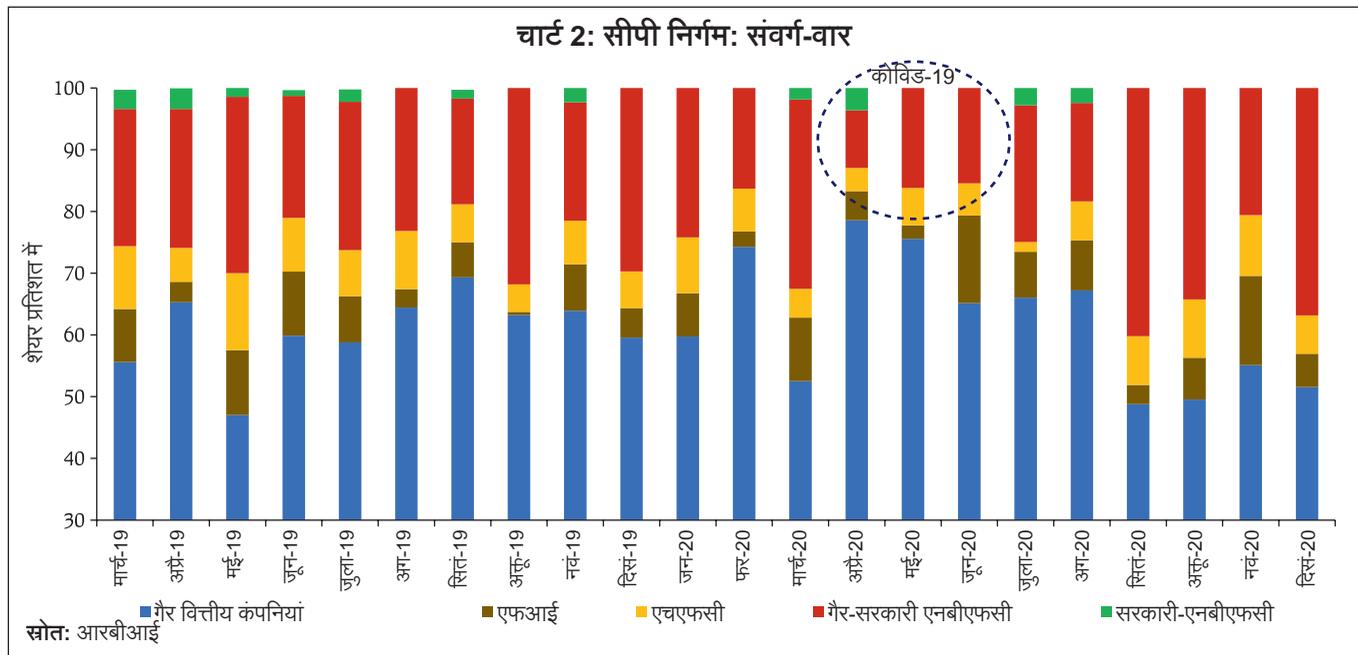
कोविड-19 के तत्काल बाद, एनबीएफसी के मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स - एनसीडी और सीपी दोनों का निर्गम कम होने के साथ-साथ प्रतिफल में भी बढ़ोतरी देखी गई (रितुराज और अन्य, 2020)। मार्च और अप्रैल 2020 में, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद की अवधि में, एनबीएफसी द्वारा बॉण्ड निर्गम - राशि और निर्गम की संख्या दोनों - में कमी आई लेकिन बाद में बहाल हुई (चार्ट 1 ए और 1 बी)।

इसी तरह, इसी अवधि में सीपी के निर्गम भी कम रहे। एनबीएफसी द्वारा सीपी निर्गम की राशि अप्रैल-जून 2020 के दौरान अप्रैल-जून 2019 की तुलना में तीन गुना कम हो गई। हालांकि, गैर-बैंक ऋणदाताओं को चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक और सरकार द्वारा किए गए उपायों के

चार्ट 1: एनबीएफसी द्वारा एनसीडी निर्गम



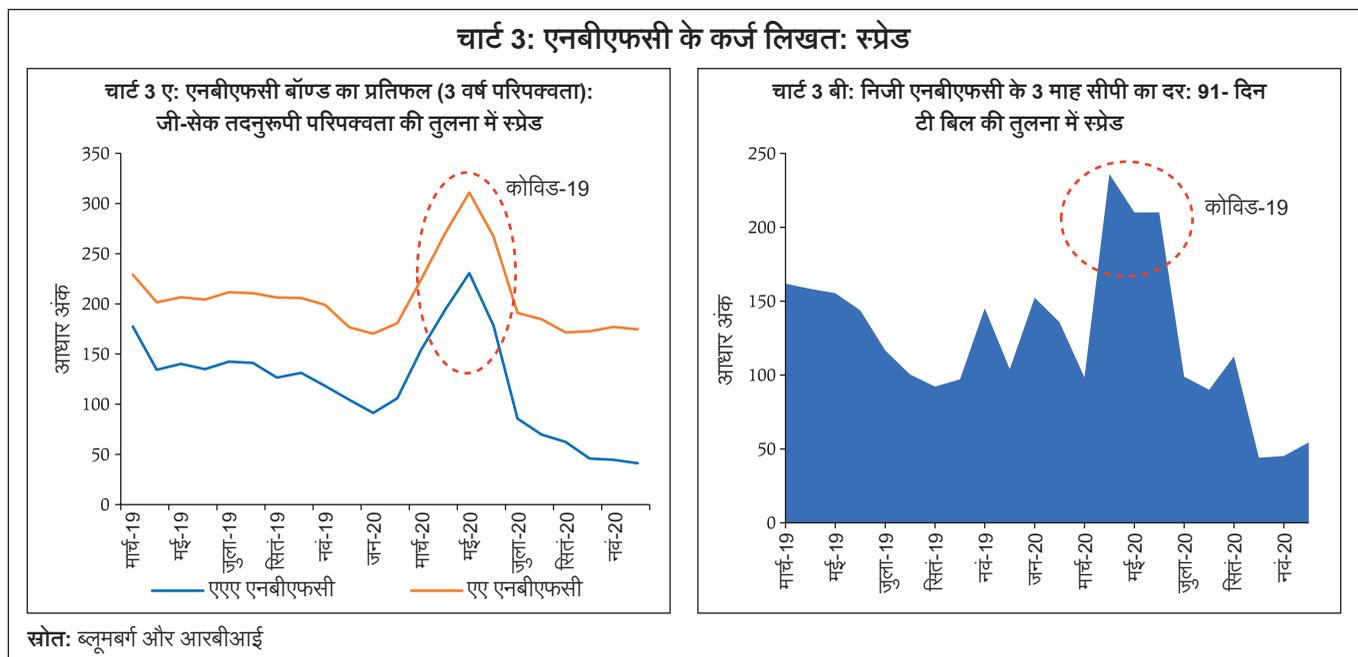
स्रोत: ब्लूमबर्ग डेटा पर आधारित लेखक की गणना



प्रतिसाद में, सीपी निर्गम में एनबीएफसी की हिस्सेदारी सितंबर 2020 से तेजी से बढ़ी (चार्ट 2)।

कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने से बाजारों में खलबली मच गई और यह एनबीएफसी के प्रति मनोभाव में भी परिलक्षित हुआ। अप्रैल 2020

में कुछ क्रेडिट रिस्क फंड्स को बंद करने (बित्रा और अन्य, 2020) ने एनबीएफसी² के प्रति बाजार के जोखिम को इस हद तक बढ़ा दिया कि एए रेटेड एनबीएफसी को भी प्रतिफल में रिकॉर्ड वृद्धि का सामना करना पड़ा (चार्ट 3 ए)। इस अवधि के दौरान विदेशी निवेशकों और म्यूचुअल फंडों द्वारा सीपी में भारी बिक्री देखी गई,



² कई म्यूचुअल फंड एनबीएफसी के पेपर में निवेश करते हैं।

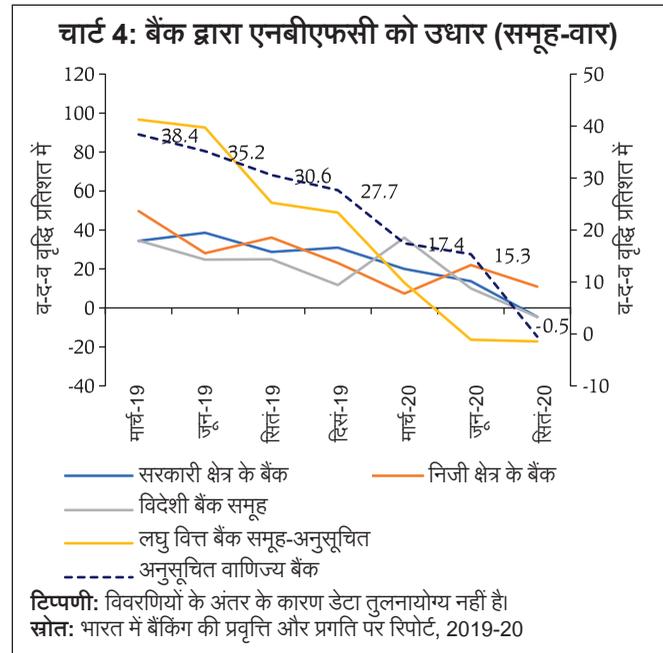
जिसके कारण ट्रेजरी बिलों (टी-बिल) विशेष रूप से निजी एनबीएफसी के स्प्रेड में वृद्धि हुई (चार्ट 3 बी)।

II.2 बैंक द्वारा एनबीएफसी को उधार

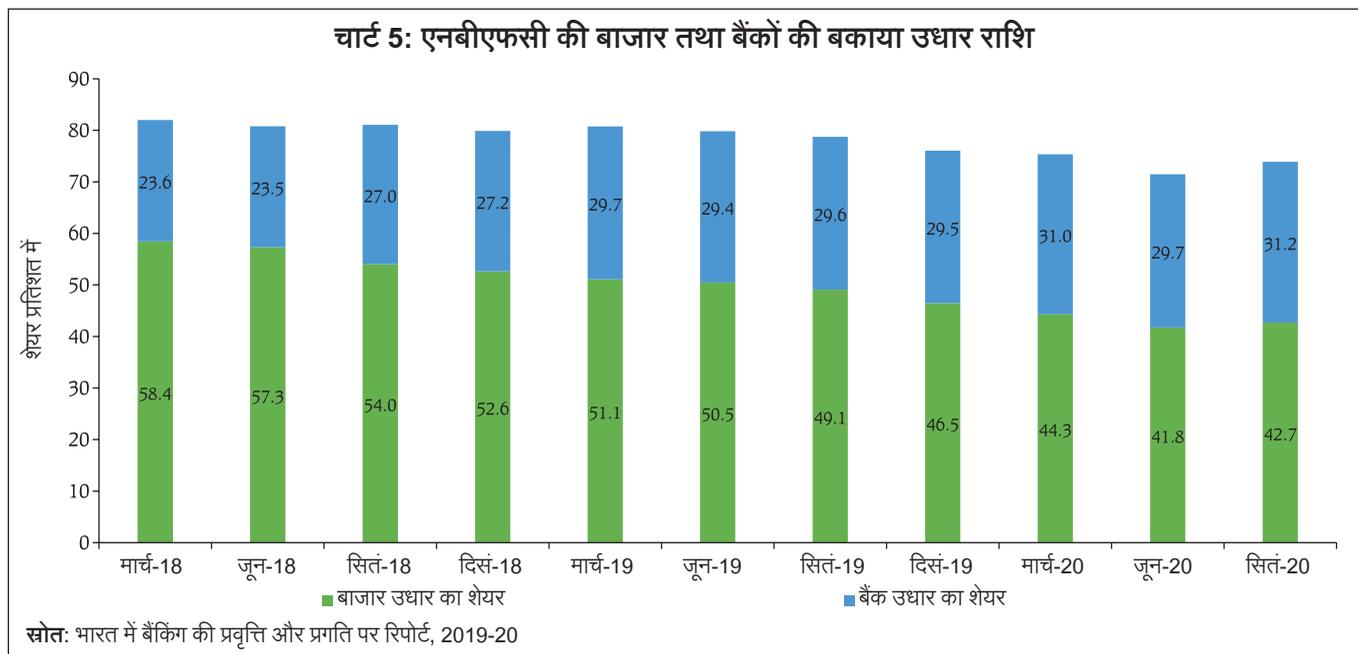
डिबेंचर के बाद एनबीएफसी के लिए निधीयन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बैंक हैं। आईएल एंड एफएस मामले के बाद, एनबीएफसी की बैंक उधार पर निर्भरता बाजार उधार की तुलना में बढ़ गई और उन्होंने अपनी आस्ति-देयता प्रोफाइल को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए दीर्घावधि के उधार के लिए अल्पावधि उधार को स्वैप करके अपने उधार मिश्रण को बदलना शुरू कर दिया। जबकि एनबीएफसी को बैंक उधार में कमी आयी थी, जो सितंबर 2020 में कोविड-19 के आघात के बाद प्रमुख खिलाड़ी - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा उधार देने से इनकार के कारण संकुचित हुआ (चार्ट 4)।

कुल उधारी में एनबीएफसी की बाजार और बैंक उधारी की संयुक्त हिस्सेदारी मार्च 2019 में 80.8 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2020 में 73.9 प्रतिशत हो गई (चार्ट 5)।

संक्षेप में, यह स्पष्ट है कि एनबीएफसी को कोविड-19 के बाद निधि जुटाने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, रिजर्व बैंक द्वारा किए गए पर्याप्त चलनिधि



और आक्रामक दरों में कटौती के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित चलनिधि प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं। अगला भाग इस अध्ययन के लिए रुचि के विषय पर चर्चा करता है, अर्थात् टीएलटीआरओ।



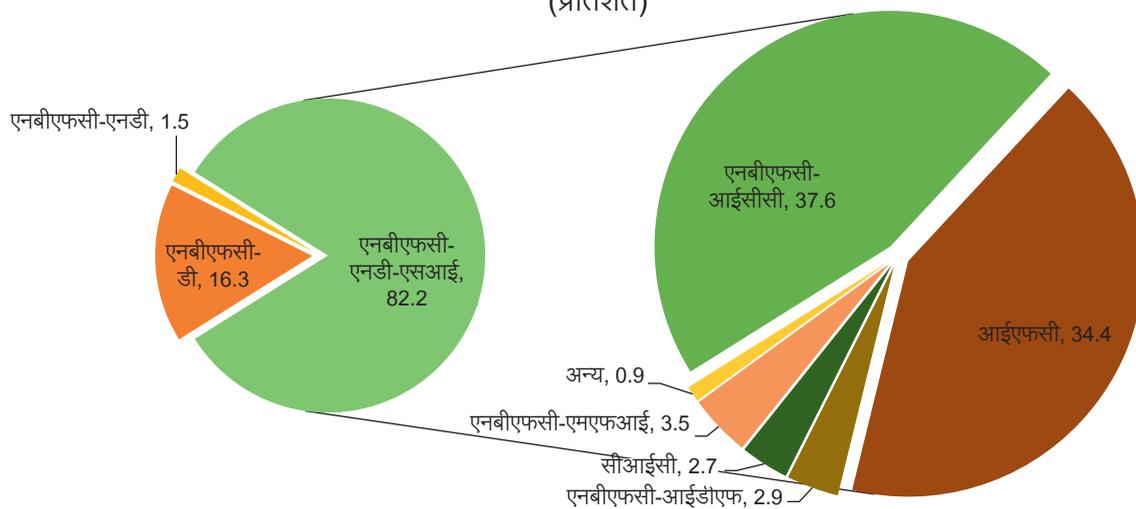
III. लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

रिजर्व बैंक ने चलनिधि की उपलब्धता के साथ-साथ दरों के संचरण को सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 2020 में अपने शस्त्रागार में दीर्घकालिक रेपो संचालन (एलटीआरओ) को शामिल किया। एलटीआरओ के तहत, रिजर्व बैंक, बैंकों को आमतौर पर 1-3 साल की परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करता है, जो कि सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर पॉलिसी रेपो दर से जुड़ी फ्लोटिंग दर पर संपार्श्विक के रूप में होता है जो बैंकों को वास्तविक अर्थव्यवस्था को अधिक उधार देने में सक्षम बनाता है। जब कोविड-19 की शुरुआत हुई, तो रिजर्व बैंक ने महामारी के कारण चलनिधि की कमी और प्रतिबंधित बाजार पहुंच का सामना करने वाले क्षेत्रों और संस्थाओं को लक्षित चलनिधि प्रदान करने के लिए टीएलटीआरओ की शुरुआत की³। बैंकों द्वारा प्राप्त निधि का निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण में निवेश किया जाना था। ऑपरेशन दो चरणों में किए गए। टीएलटीआरओ 1.0 के तहत, जिसकी घोषणा 27 मार्च 2020 को की गई थी, रिजर्व बैंक ने ₹25,000 करोड़ की किश्तों में कुल ₹1,00,000 करोड़ की चार नीलामियां आयोजित की। पॉलिसी रेपो दर से जुड़ी फ्लोटिंग दर पर तीन वर्ष तक की अवधि थी। टीएलटीआरओ 1.0 के तहत ₹1,00,050 करोड़ आबंटित किए गए। टीएलटीआरओ 2.0 की घोषणा 17 अप्रैल 2020 को की गई थी, जिसमें एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) सहित छोटे और मध्यम आकार के

कॉरपोरेट्स की चलनिधि समस्याओं को दूर करने की मांग की गई थी। टीएलटीआरओ 2.0 विंडो के तहत, तीन साल तक की अवधि के लिए पॉलिसी रेपो दर पर ₹50,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी। पहली किश्त में, 0.5 के अनुपात को कवर करने के लिए बोली के साथ, कुल बोलियों की राशि ₹12,850 करोड़ थी⁴। इसके बाद, 9 अक्टूबर 2020 को, रिजर्व बैंक ने कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और सुरक्षित खुदरा जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि की बहाली के लिए पॉलिसी रेपो दर से जुड़ी फ्लोटिंग दर पर ₹1,00,000 करोड़ तक की कुल राशि के तीन साल की अवधि के लिए ऑन-टैप टीएलटीआरओ शुरू करने की घोषणा की और इसे 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

टीएलटीआरओ के पहले दो चरणों के तहत वितरित निधि से पता चलता है कि ₹ 61,586 करोड़ एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को वितरित किए गए थे, जिनमें से 60 प्रतिशत एनबीएफसी को मिले थे। एनबीएफसी में, जमा न लेने वाली एनबीएफसी, विशेष रूप से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई), 82.2 प्रतिशत धनराशि प्राप्त करने वाले प्रमुख लाभार्थी थे। एनबीएफसी-एनडी-एसआई के अंतर्गत, निवेश और क्रेडिट कंपनियों (एनबीएफसी-आईसीसी) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों (आईएफसी) ने लगभग तीन-चौथाई निधि प्राप्त किया (चार्ट 6)।

चार्ट 6: एनबीएफसी के विविध संवर्गों में संवितरित टीएलटीआरओ निधि (प्रतिशत)



स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, 2019-20

³ https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=49582

⁴ https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMMO.aspx?prid=49736

IV. डेटा और प्रविधि

इस लेख में टीएलटीआरओ के माध्यम से निधि प्राप्त करनेवाले तथा निधि प्राप्त न करने वाले एनबीएफसी की तुलना से एनबीएफसी की चलनिधि की स्थिति पर टीएलटीआरओ के पहले दो चरणों के प्रभाव का अनुभवजन्य आकलन करने का प्रयास किया गया है⁵। विभिन्न परिपक्वता बकेट में आस्ति-देयता असंतुलन पर नीति के प्रभाव की जांच की गयी है क्योंकि टीएलटीआरओ चलनिधि बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य साधन था और एनबीएफसी कथित तौर पर अपने अल्पावधि आस्ति देयता असंतुलन (एएलएम) बकेट में समस्याओं का सामना कर रहे थे। इस विश्लेषण में उपयोग किया गया डेटासेट - एनबीएफसी का पर्यवेक्षी डेटा जो प्राप्त निधि की राशि और अन्य तुलन पत्र संकेतक दर्ज करता है - एक डिफरेंस-इन-डिफरेंस अभ्यास करने के लिए आदर्श है जिसमें एनबीएफसी को टीएलटीआरओ निधीयन (लाभार्थी एनबीएफसी) प्राप्त करने वाले एनबीएफसी के साथ

तुलना की जाती है (नियंत्रित एनबीएफसी)। डिफरेंस-इन-डिफरेंस प्रतिगमन प्रयास प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन की भावना में किए जाते हैं जिसमें एक प्राकृतिक प्रयोग के रूप में एक लाभार्थी समूह और एक गैर लाभार्थी समूह होता है।

IV.1 डेटा और शोधपरक तथ्य

136 एनबीएफसीयों ने टीएलटीआरओ के माध्यम से निधि के लिए अनुरोध किया था, जिनमें से अधिकांश एनबीएफसी-एनडी-एसआई थे, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक तिमाही आधार पर, पर्यवेक्षी डेटाबेस से उनका तुलन पत्र और वित्तीय प्रदर्शन डेटा एकत्र किया गया था और एनबीएफसी के समूह के साथ मिलान किया गया था, जिन्हें निधि प्राप्त हुआ था। जिन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्त पोषण नहीं मिला, उन्हें गैर लाभार्थी समूह में शामिल किया गया है (सारणी 1)। प्रत्येक तिमाही में कंपनियों की संख्या पर्यवेक्षी मंच में उनकी रिपोर्टिंग के आधार पर भिन्न होती है।

सारणी 1: लाभार्थी और गैर लाभार्थी एनबीएफसी का आस्ति आकार

(₹ करोड़)

अवधि	लाभार्थी एनबीएफसी								कुल
	एनबीएफसी-डी	एनबीएफसी- एनडी	एनबीएफसी-एनडी-एसआई						
	आईसीसी	आईसीसी	एनबीएफसी- एमएफआई	एनबीएफसी- फैक्टर	एनबीएफसी- आईसीसी	एनबीएफसी- आईएफसी	एनबीएफसी- एनओएफएचसी	एनबीएफसी-एनडी- एसआई कुल	
दिसं-19	1,52,652 (3)	873 (1)	36,101 (10)	-	5,23,024 (35)	29,945 (1)	27,440 (3)	6,16,510 (49)	7,70,034 (53)
मार्च-20	3,26,849 (6)	1,599 (2)	47,405 (11)	-	6,64,100 (48)	7,70,746 (3)	28,895 (3)	15,11,145 (65)	18,39,594 (73)
जून-20	3,28,090 (7)	2,808 (4)	44,631 (10)	-	6,56,740 (48)	8,05,097 (3)	31,219 (3)	15,37,687 (64)	18,68,585 (75)
सितं-20	4,09,992 (8)	2,403 (3)	44,155 (9)	-	7,16,281 (50)	8,27,570 (3)	32,468 (3)	16,20,474 (65)	20,32,869 (76)
दिसं-20	4,06,914 (6)	2,483 (3)	36,818 (6)	-	4,82,795 (36)	-	32,762 (3)	5,52,376 (45)	9,61,773 (54)
अवधि	गैर लाभार्थी एनबीएफसी								कुल
	एनबीएफसी-डी	एनबीएफसी- एनडी	एनबीएफसी-एनडी-एसआई						
	आईसीसी	आईसीसी	एनबीएफसी- एमएफआई	एनबीएफसी- फैक्टर	एनबीएफसी- आईसीसी	एनबीएफसी- आईएफसी	एनबीएफसी- एनओएफएचसी	एनबीएफसी-एनडी- एसआई कुल	
दिसं-19	40,221 (2)	227 (1)	7,630 (4)	1,298 (1)	3,13,335 (50)	5,690 (1)	2,722 (1)	3,30,676 (57)	3,71,123 (60)
मार्च-20	45,146 (4)	224 (1)	10,416 (6)	1,431 (1)	4,97,605 (74)	23,321 (3)	11,853 (2)	5,44,627 (86)	5,89,997 (91)
जून-20	44,377 (4)	22,286 (3)	10,203 (6)	1,201 (1)	4,64,337 (71)	76,783 (4)	12,108 (2)	5,64,632 (84)	6,31,295 (91)
सितं-20	46,528 (4)	22,995 (2)	9,585 (6)	1,320 (1)	5,26,639 (76)	72,864 (4)	14,916 (2)	6,25,323 (89)	6,94,846 (95)
दिसं-20	35,232 (2)	24,771 (3)	964 (1)	1,451 (1)	3,32,450 (49)	23,466 (3)	5,345 (1)	3,63,676 (55)	4,23,679 (60)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एनबीएफसी की संख्या हैं।

स्रोत: लेखक की गणना दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक के तिमाहियों के पर्यवेक्षी डेटा पर आधारित है।

⁵ आंकड़ों की उपलब्धता को देखते हुए यह विश्लेषण एचएफसी को छोड़कर एनबीएफसी तक सीमित रखा गया है।

निधीयन प्राप्त करने वाली एनबीएफसी बनाम जिन्होंने नहीं प्राप्त किया के स्वरूप को समझने के लिए, हम आकार (कुल आस्ति), सुदृढ़ता (पूंजीगत / कुल देनदारियों), चलनिधि के संबंध में हमारे लाभार्थी और गैर लाभार्थी समूहों के नमूने की विशेषताओं का पता लगाया है [(नकद और बैंक शेष + वर्तमान निवेश) / कुल आस्ति], लाभप्रदता (आस्ति पर वापसी, अर्थात, निवल लाभ / कुल आस्ति) और आस्ति की गुणवत्ता (अनर्जक आस्ति [एनपीए] अनुपात, यानी, सकल एनपीए / कुल आस्ति)⁶। सारणी 2 हमारे विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले इन प्रमुख चरों को सारांश देती है।

यह स्पष्ट है कि टीएलटीआरओ निधीयन के लाभार्थियों को यादृच्छिक रूप से नहीं चुना गया था, लेकिन कुछ एनबीएफसी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर बैंकों द्वारा चरी पिकिंग दर्शाता है। सबसे पहले, लाभार्थी एनबीएफसी आकार में बड़े हैं और मुख्य रूप से क्रेडिट मध्यस्थता के कारोबार करनेवाले हैं (चार्ट 7 और 8)।

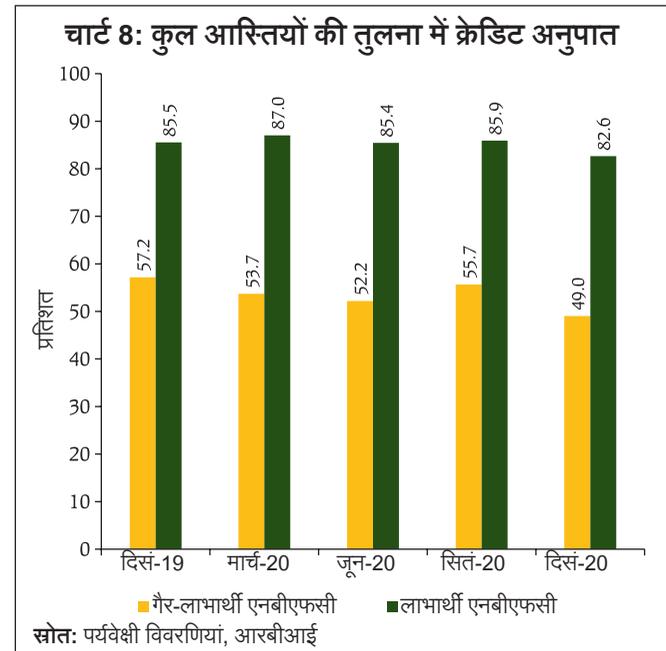
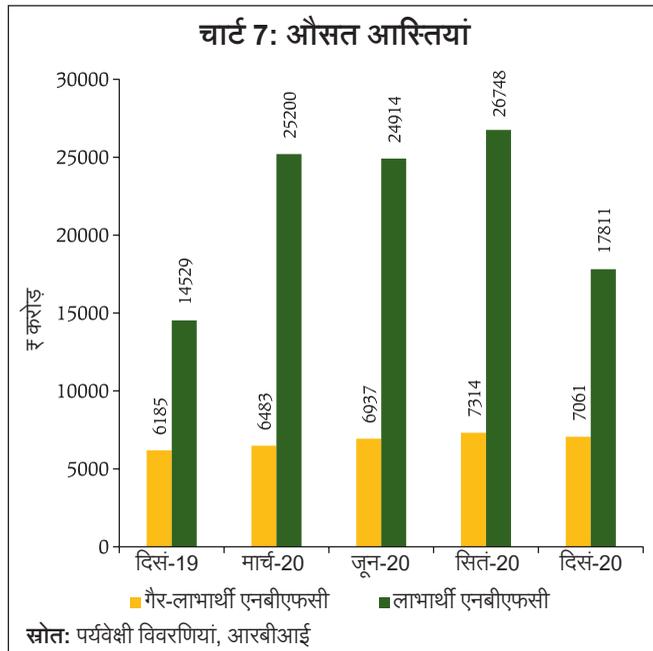
गैर लाभार्थी एनबीएफसी, आकार में तुलनात्मक रूप से छोटे होने के कारण, चुकता पूंजी और आरक्षित निधि और अधिशेष पर अधिक निर्भर होते हैं और बड़े लाभार्थी एनबीएफसी की तुलना में कम ऋण-भारित होते हैं, जिनके पास उधार के रूप में निधि के अतिरिक्त स्रोतों तक पहुंच है। यह पूर्व की उच्च पूंजी की तुलना में कुल देनदारियों के अनुपात को स्पष्ट करता है। इसी तरह, लाभार्थी

सारणी 2: प्रमुख चर के विस्तृत आंकड़े

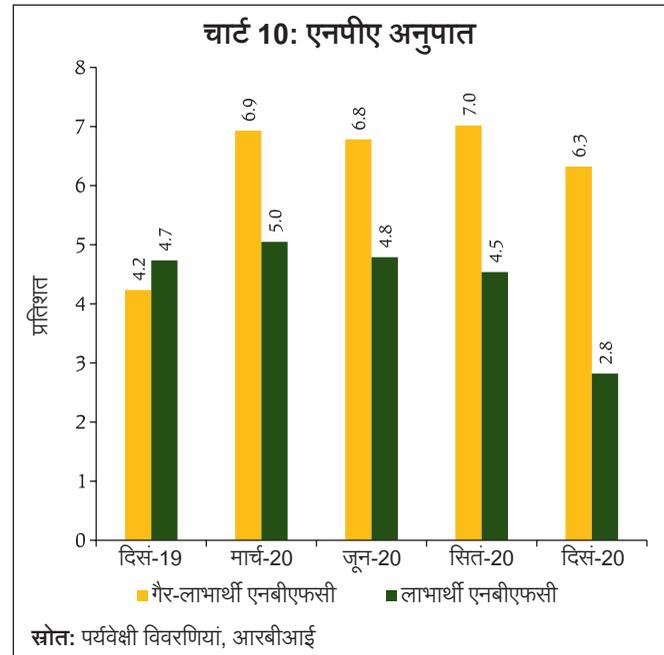
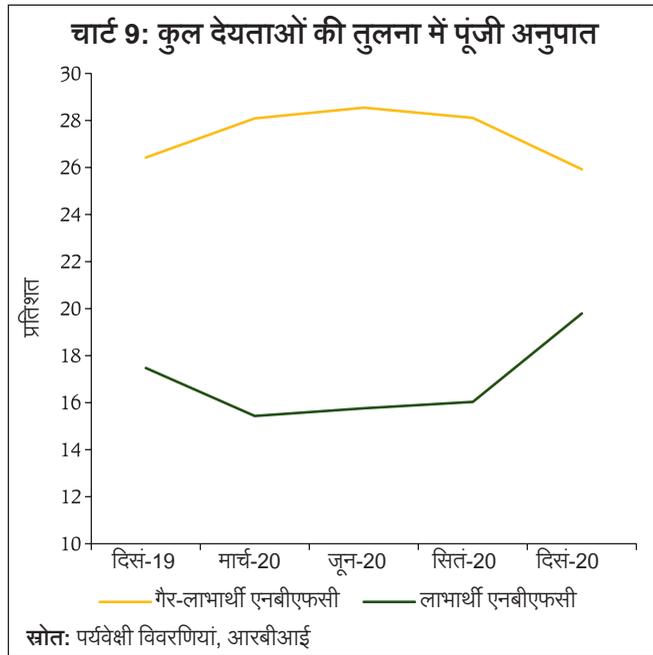
चर	समग्र				
	एन	माध्य	एस.डी	न्यूनतम	अधिकतम
कुल आस्ति	732	14,106	38,702	117.5	4,05,061
कुल देयताओं की तुलना में पूंजी अनुपात	732	34.4	23.0	10.5	93.2
चलनिधि अनुपात	732	13.0	14.2	0.5	58.5
आस्तियों पर प्रतिलाभ	732	1.2	1.5	-1.4	4.6
एनपीए अनुपात	719	3.0	4.1	0	17.1
क्रेडिट की तुलना में कुल आस्ति अनुपात	731	69.3	27.0	0	94.9
चर	लाभार्थी एनबीएफसी				
	एन	माध्य	एस.डी	न्यूनतम	अधिकतम
कुल आस्ति	332	22,955	55,396	117.5	4,05,061
कुल देयताओं की तुलना में पूंजी अनुपात	332	28.7	16.6	10.5	93.2
चलनिधि अनुपात	332	11.0	7.7	0.5	45.2
आस्तियों पर प्रतिलाभ	332	1.2	1.2	-1.3	4.5
एनपीए अनुपात	329	2.4	2.6	0	17.1
क्रेडिट की तुलना में कुल आस्ति अनुपात	332	80.4	10.6	44.6	94.9
चर	गैर लाभार्थी एनबीएफसी				
	एन	माध्य	एस.डी	न्यूनतम	अधिकतम
कुल आस्ति	400	6,760	8,891	223	53,367
कुल देयताओं की तुलना में पूंजी अनुपात	400	39.0	26.2	10.5	93.2
चलनिधि अनुपात	400	14.6	17.7	0.5	58.5
आस्तियों पर प्रतिलाभ	400	1.2	1.6	-1.4	4.6
एनपीए अनुपात	390	3.4	5.0	0	17.1
क्रेडिट की तुलना में कुल आस्ति अनुपात	399	60.1	32.5	0	94.9

टिप्पणी: एस.डी मानक विचलन है। कुल आस्ति जो स्क्रोड में है को छोड़कर प्रतिशत में

एनबीएफसी अपनी बही में कम चलनिधि रख सकते हैं क्योंकि वे आम तौर पर जब आवश्यकता होती है वे कम लागत वाले निधीयन



⁶ बाहरी डेटा बिंदु के प्रभाव को कम करने के लिए, चरों को 5 प्रतिशत और 95 प्रतिशत के स्तर पर निकाला गया।



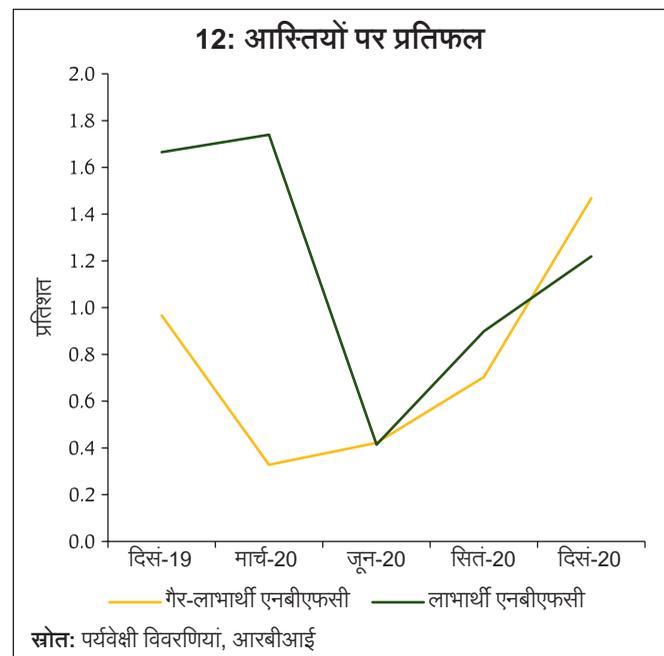
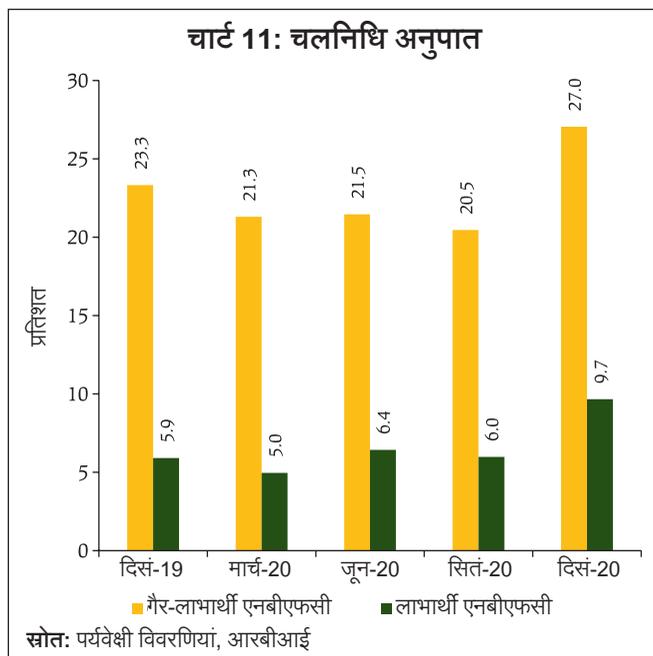
चैनलों में टैप कर सकते हैं जबकि गैर लाभार्थी एनबीएफसी को ऐसे निधीयन चैनल आसान नहीं हो सकते हैं (चार्ट 9 और 10)।

आम तौर पर, गैर लाभार्थी एनबीएफसी लाभार्थी एनबीएफसी की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त आस्ति रिपोर्ट करते हैं (चार्ट 11)। आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे फिर से शुरू होने से लाभार्थी और

गैर लाभार्थी एनबीएफसी की लाभप्रदता में सुधार हुआ है (चार्ट 12)।

IV.2 पहचान और अनुभवजन्य डिजाइन

चूंकि बैंकों द्वारा वित्त पोषण के लिए एनबीएफसी का चुनाव यादृच्छक नहीं था, इसलिए टीएलटीआरओ के प्रभाव को अलग



करने के लिए व्यक्तिगत एनबीएफसी विशेषताओं के लाभार्थी की स्थिति के सहसंबंध का मूल्यांकन करना आवश्यक है। लाभार्थी की स्थिति पर तुलन पत्र चर के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए दिसंबर 2019 की अवधि, टीएलटीआरओ के कार्यान्वयन से पहले की तिमाही के लिए निम्नलिखित रैखिक संभाव्यता मॉडल का अनुमान लगाया गया था:

$$Treated_i = \beta_1 SIZE_i + \beta_2 ROA_i + \beta_3 NPARATIO_i + \beta_4 CAPITAL_i + \beta_5 LIQUIDITY_i + v_i \dots (1)$$

जहां i एनबीएफसी को दर्शाता है और लाभार्थी i एक डमी वैरिएबल है जो उन एनबीएफसी के लिए एक मूल्य लेता है जिन्होंने निधीयन प्राप्त की और उन एनबीएफसी के लिए शून्य मूल्य लेता है जिन्होंने निधीयन प्राप्त नहीं किया है। ग्रोप और अन्य (2018) और जियासांटे और अन्य (2020) और पिछले भाग में चर्चा किए गए शोधपरक तथ्यों के आधार पर, स्वतंत्र चर में आकार⁷ जो एनबीएफसी की कुल आस्ति है, लाभप्रदता के लिए आरओए (निवल लाभ / कुल आस्ति), एनपीए अनुपात (सकल एनपीए / कुल आस्ति) के लिए चलनिधि की स्थिति के लिए आस्ति गुणवत्ता, (पूंजी/कुल देयता अनुपात) सुदृढ़ता और चलनिधि के लिए पूंजी [(नकद और बैंक शेष + वर्तमान निवेश)/कुल आस्ति] शामिल है। परिणाम बताते हैं कि आकार, एनपीए अनुपात और

चलनिधि टीएलटीआरओ के तहत निधि प्राप्त करने की संभावना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं (सारणी 3)। इन विशेषताओं को मुख्य डिफरेंस-इन-डिफरेंस अभ्यास में आधार बनाया जाएगा। डिफरेंस-इन-डिफरेंस विशेषताओं का निम्नलिखित आधार है:

$$Mismatch_{i,t} = \beta_i + \alpha_t + \delta(Treated_i * Post_t) + \theta X_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \dots (2)$$

जहां असंतुलन आश्रित चर है जिसे प्रत्येक परिपक्वता बकेट के प्रवाह और बहिर्वाह (स्करोड में) के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया है; β_i एनबीएफसी फिक्स्ड प्रभाव है; α_t समय निश्चित प्रभाव है; $Treated_i$ एक संकेतक चर है जो लाभार्थी एनबीएफसी के लिए एक और गैर लाभार्थी एनबीएफसी के लिए शून्य है; $Post_t$ हस्तक्षेप के बाद की अवधि को दर्शाता है जो 2020 जून के बाद से एक मूल्य दर्शाता है। $X_{i,t}$ में जैसे पहले उल्लेख किया गया है गैर लाभार्थी चर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दो अन्य तरलता बढ़ाने वाली नीति उपाय, अर्थात्, आंशिक ऋण गारंटी योजना (पीसीजीएस), जिसे वित्तीय रूप से मजबूत एनबीएफसी/एचएफसी और बी) विशेष चलनिधि योजना (एसएलएस) से पूल्ड आस्तियों की खरीद के लिए पीएसबी को सरकारी गारंटी प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में पेश किया गया था) जो सरकार द्वारा जुलाई 2020 में एक विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में एनबीएफसी/एचएफसी की चलनिधि स्थिति में सुधार करने के लिए घोषित किया गया था, को भी अनुमान के लिए आधार बनाया गया क्योंकि लाभार्थी एनबीएफसी की पहचान पर्यवेक्षी डेटासेट के माध्यम से उपलब्ध थी⁸। ब्याज का गुणांक, δ , नियंत्रण के अधीन नीति के कार्यान्वयन के बाद टीएलटीआरओ के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाली तथा लाभ प्राप्त न करनेवाली एनबीएफसी के बीच पहले की तुलना में मेल न खानेवाले अंतर को मापता है, और इसलिए, डिफरेंस-इन-डिफरेंस अनुमान के बराबर है। मॉडल के तीन विशिष्टताओं का अनुमान लगाया गया था। मॉडल 1 समय और एनबीएफसी निश्चित प्रभाव और नियंत्रण के साथ एक प्रतिगमन है। मॉडल 2 में नियंत्रण शामिल है और मॉडल 3 में संभावित एंडोजेनिटी समस्या को कम करने के लिए एनबीएफसी विशिष्ट स्वतंत्र चर से पिछड़ गया है, जिसे निम्नलिखित तरीके से व्यक्त किया गया है:

सारणी 3: रैखिक संभावना मॉडल (आश्रित चर - लाभार्थी डमी)

ट्रीटेड _i	गुणांक
आकार	0.234** (0.116)
आस्ति पर प्रतिलाभ	0.00934 (0.033)
एनपीए अनुपात	-0.0293** (0.014)
पूंजी	-0.00249 (0.002)
चलनिधि	-0.00908*** (0.003)
प्रेक्षण	110
समायोजित R ²	0.084

यहां, आकार एक डमी चर है जो दिसंबर 2019 तिमाही के आस्ति आकार संवितरण में एनबीएफसी की कुल आस्ति शीर्ष 25 प्रतिशत में होने पर 1 मान लेता है। कोष्ठक की मानक त्रुटियां

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

⁷ क्रेडिट और आस्तियों के बीच उच्च सहसंबंध के कारण, आस्तियों को स्वतंत्र चर के रूप में चुना गया था।

⁸ मार्च 2020 से लाभ प्राप्त करने वाली एनबीएफसी के लिए एक पीसीजीएस डमी बनाया गया था और दूसरों के लिए शून्य जबकि एसएलएस डमी ने उन एनबीएफसी के लिए एक का मूल्य लिया, जिन्होंने सितंबर 2020 से फंडिंग प्राप्त की और अन्य के लिए शून्य।

$$\begin{aligned}
 \text{Mismatch}_{i,t} = & \beta_i + \alpha_t + \delta(\text{Treated}_i * \text{Post}_t) + \\
 & \theta_1 \text{SIZE}_{i,t-1} + \theta_2 \text{ROA}_{i,t-1} + \\
 & \theta_3 \text{NPARATIO}_{i,t-1} + \theta_4 \text{CAPITAL}_{i,t-1} + \\
 & \theta_5 \text{LIQUIDITY}_{i,t-1} + \theta_6 \text{dummy PCGS}_i + \\
 & \theta_7 \text{dummy SLS}_i + \varepsilon_{i,t} \quad \dots (3)
 \end{aligned}$$

मानक त्रुटियों को एनबीएफसी स्तर पर एकत्रित किया गया है।

V. परिणाम

जैसा कि पहले सूचित किया गया है, मॉडल का अनुमान एएलएम के साथ आश्रित चर के रूप में लगाया गया था, जिसे प्रत्येक परिपक्वता बकेट के लिए अंतर्वाह और बहिर्वाह (₹ करोड़ में) के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। असंतुलन के लिए एक सकारात्मक मूल्य दिए गए बकेट के लिए बहिर्वाह की तुलना में अधिक अंतर्वाह को दर्शाता है और यह एक पर्याप्त चलनिधि स्थिति का संकेत है। असंतुलन में सुधार कारण या तो अंतर्वाह में वृद्धि या बहिर्वाह में कमी हो सकता है। लेखांकन के दृष्टिकोण से, एनबीएफसी द्वारा बाजार लिखतों को जारी करना और पुनर्भुगतान करने को संरचनात्मक चलनिधि रिटर्न के बहिर्वाह भाग में निपटाया जाता है। इसलिए, हमारे अध्ययन के संदर्भ में, ऐसा प्रतीत होता है कि जिन एनबीएफसी ने टीएलटीआरओ निधीयन प्राप्त की, उन्होंने उस पैसे का उपयोग उन परिपक्वता बकेट में मौजूदा देनदारियों का भुगतान करने के लिए किया, जो शीघ्र ही पुनर्भुगतान के लिए पात्र थे और जिसमें एनबीएफसी, चलनिधि की कमी का सामना कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप बहिर्वाह में गिरावट आ सकती है और बाद में उन बकेट के लिए एएलएम स्थिति में सुधार हो सकता है। हालांकि, टीएलटीआरओ के माध्यम से प्राप्त इस निधि को बाद की परिपक्वता बकेट में रखा जाना चाहिए, जब वे चुकौती के लिए देय होंगे। ऐसे मामलों में, लाभार्थी एनबीएफसी को गैर लाभार्थी फर्मों की तुलना में उपयुक्त दीर्घकालिक परिपक्वता बकेट में नकारात्मक और महत्वपूर्ण बहिर्वाह का सामना करना पड़ सकता है। एएलएम पर टीएलटीआरओ के प्रभाव का आकलन करने के लिए, हमने सबसे पहले एक साल से कम की आस्ति देयता मिसमैच बकेट को देखा।

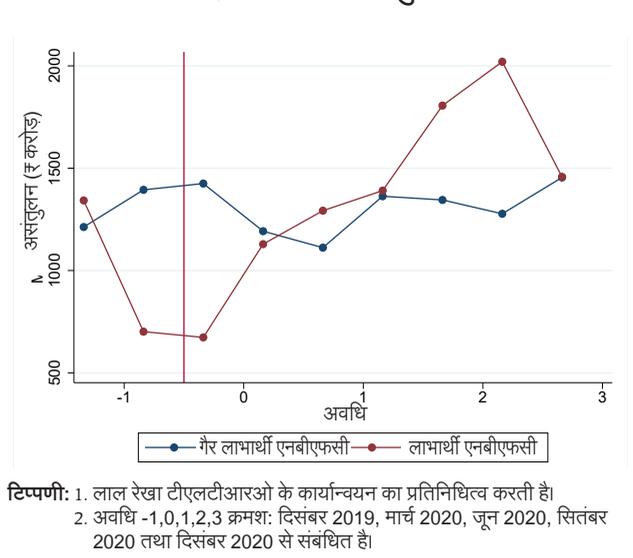
ए) एक वर्ष से कम-संयुक्त परिपक्वता बकेट

टीएलटीआरओ के कारण एएलएम प्रोफाइल में हुए परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, एनबीएफसी के लाभार्थी

और गैर लाभार्थी मिसमैच के बिनस्कैटर आरेख तैयार किए गए हैं⁹ (चार्ट 13)। यहां, '0' मार्च 2020 है, यानी वह अवधि जिसमें टीएलटीआरओ शुरू किया गया था और '-1' टीएलटीआरओ (दिसंबर 2019) की शुरुआत से पहले की अवधि है जबकि '1' टीएलटीआरओ की शुरुआत के बाद की अवधि है (जून 2020)। एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि में, लाभार्थी एनबीएफसी को पॉलिसी की शुरुआत से ठीक पहले तनाव का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद उनके लिए स्थिति में काफी सुधार हुआ, जो कि गैर लाभार्थी फर्मों के मामले में नहीं था (चार्ट 13)।

इसके अलावा, अनुमान के परिणाम बताते हैं कि यह सुधार टीएलटीआरओ के कारण है - लाभार्थी एनबीएफसी के पास ₹ 441 करोड़ - ₹ 751 करोड़ के दायरे में बेहतर चलनिधि की स्थिति थी (सारणी 4)। यह संभव है कि इस बकेट में देखा गया सुधार टीएलटीआरओ विंडो में प्राप्त राशि का उपयोग करके लाभार्थी एनबीएफसी की पुस्तकों में से उच्च लागत उधार (बहिर्वाह) का भुगतान करने के कारण है, जिससे एएलएम की स्थिति में सुधार हुआ है।

चार्ट 13: लाभार्थी और गैर लाभार्थी एनबीएफसी का बिनस्कैटर प्लॉट: एक वर्ष से कम संयुक्त परिपक्वता बकेट



⁹ चार्ट 13-18 में ये बिनस्कैटर प्लॉट एनबीएफसी के स्थिर प्रभाव के नियंत्रक हैं।

सारणी 4: 1 वर्ष से कम संयुक्त परिपक्वता बकेट पर टीएलटीआरओ का प्रभाव

आश्रित चर विचलन-असंतुलन (₹ करोड़)	(1)	(2)	(3)
ट्रीटेड, * पोस्ट	751.1** (302.0)	456.4** (226.6)	441.3** (217.7)
समायोजित R ²	0.896	0.920	0.962
प्रेक्षण	725	711	534
नियंत्रक	नहीं	हां	हां
एनबीएफसी एफई	हां	हां	हां
समय एफई	हां	हां	हां

कोष्ठक की ठोस मानक त्रुटियां
* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

इन परिणामों से प्रेरित होकर, निम्नलिखित उप भागों में एक वर्ष से कम समय सीमा में सभी परिपक्वता बकेट का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है।¹⁰

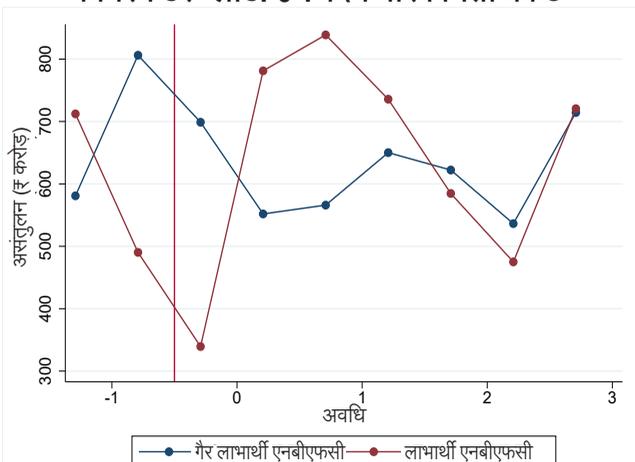
i) 0-7 दिन परिपक्वता बकेट

इस अल्ट्रा-शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी बकेट में लाभार्थी फर्मों ने कोविड-19 के बाद असंतुलन देखा गया। हालाँकि, इस बकेट ने कोविड के आने से पहले की अवधि में लाभार्थी और गैर लाभार्थी एनबीएफसी दोनों के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध थी और बाद में भारी गिरावट देखी गई। फिर भी, 27 मार्च, 2020 (टीएलटीआरओ 1.0) और 17 अप्रैल, 2020 (टीएलटीआरओ 2.0) को नीति की घोषणा के तत्काल बाद लाभार्थी फर्मों के लिए सुधार दिखाई दे रहा था, जो कि छोटी अवधि बकेट के अनुरूप है (चार्ट 14)।

सारणी 5 यह पुष्टि करती है कि ₹227 करोड़ - ₹444 करोड़ की सीमा में टीएलटीआरओ की शुरुआत के बाद लाभार्थी फर्मों के असंतुलन में सुधार हुआ (सारणी 5)।

¹⁰ केवल वे बकेट जिनके लिए ब्याज का गुणांक () सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है को यहां सूचित किया गया है

चार्ट 14: लाभार्थी और गैर लाभार्थी एनबीएफसी का बिनस्कैटर प्लॉट: 0-7 दिन परिपक्वता बकेट



टिप्पणी: 1. लाल रेखा टीएलटीआरओ के कार्यान्वयन का प्रतिनिधित्व करती है।
2. अवधि -1,0,1,2,3 क्रमशः दिसंबर 2019, मार्च 2020, जून 2020, सितंबर 2020 तथा दिसंबर 2020 से संबंधित है।

ii) एक महीने से अधिक और दो महीने तक की परिपक्वता बकेट

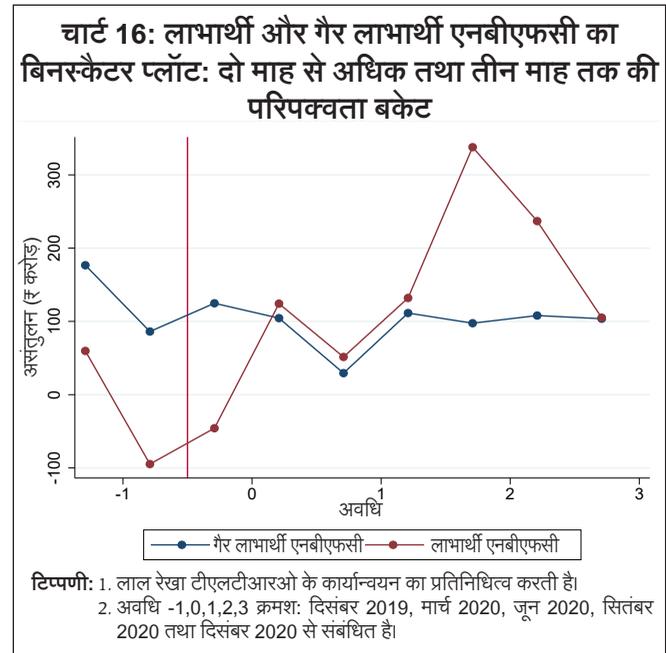
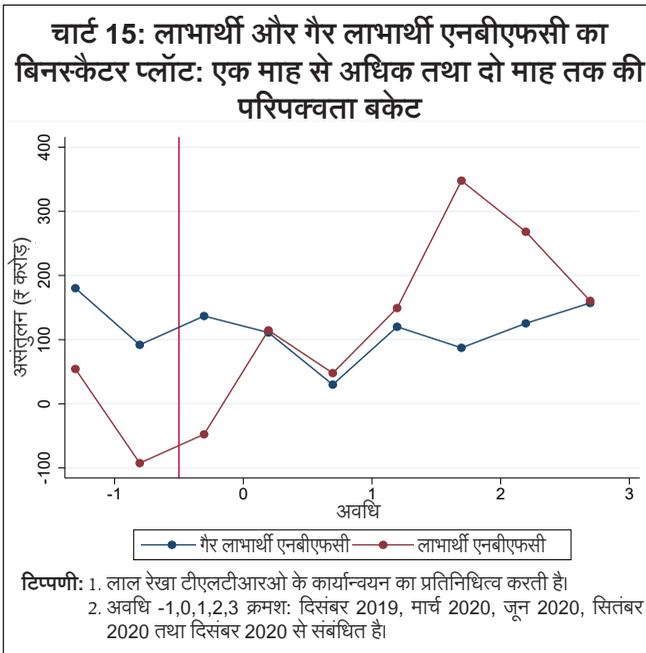
1-2 महीने की परिपक्वता बकेट में, लाभार्थी फर्मों को पूर्व-कोविड अवधि में चलनिधि के तनाव का सामना करना पड़ रहा था और नीति की शुरुआत के बाद सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जबकि गैर लाभार्थी फर्मों ने समान प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं की थी (चार्ट 15)।

नीति की शुरुआत के उपरांत, लाभार्थी और गैर लाभार्थी फर्मों के बीच असंतुलन अंतर औसतन ₹214 करोड़ और ₹281 करोड़ के बीच था (सारणी 6)।

सारणी 5: 0-7 दिन परिपक्वता बकेट पर टीएलटीआरओ का प्रभाव

आश्रित चर विचलन-असंतुलन (₹ करोड़)	(1)	(2)	(3)
ट्रीटेड, * पोस्ट	298.1** (119.1)	226.8** (114.6)	444.4*** (143.0)
समायोजित R ²	0.917	0.917	0.935
प्रेक्षण	742	727	550
नियंत्रक	नहीं	हां	हां
एनबीएफसी एफई	हां	हां	हां
समय एफई	हां	हां	हां

कोष्ठक की ठोस मानक त्रुटियां
* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$



iii) दो महीने से अधिक और तीन महीने तक की परिपक्वता बकेट

पिछली बकेट की तरह, लाभार्थी फर्मों ने मार्च 2020 में इस बकेट के लिए भी तनाव देखा, जो बाद में कम हो गया (चार्ट 16)। गैर लाभार्थी फर्मों ने इस तरह के सुधार की सूचना नहीं दी।

सारणी 7 इस बात की पुष्टि करती है कि इस बकेट में टीएलटीआरओ से चलनिधि की कमी को कम करने में लाभार्थी एनबीएफसी को लाभ हुआ। गैर लाभार्थी फर्मों

के सापेक्ष नीति के कारण लाभार्थी फर्मों को औसतन ₹ 220-235 करोड़ का लाभ हुआ। 0-7 दिन, 1-2 महीने और 2-3 महीने की उधारी कुछ ही समय में देय थी और कोविड-19 की वजह से अनिश्चितता और प्रतिकूल चलनिधि की स्थिति को देखते हुए एनबीएफसी जूझ रहे थे, निधि रोल ओवर करना मुश्किल था। ऐसे स्थिति में, एनबीएफसी ने टीएलटीआरओ निधि का उपयोग करके ऋण चुकाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विवेकपूर्ण उपाय किया होगा।

सारणी 6: एक माह से अधिक और दो माह तक की परिपक्वता बकेट पर टीएलटीआरओ का प्रभाव

आश्रित चर विचलन-असंतुलन (₹ करोड़)	(1)	(2)	(3)
ट्रीटेड _t * पोस्ट _t	244.6*** (88.55)	214.0*** (79.80)	281.1*** (104.9)
समायोजित R ²	0.691	0.697	0.761
प्रेक्षण	729	715	535
नियंत्रक	नहीं	हां	हां
एनबीएफसी एफई	हां	हां	हां
समय एफई	हां	हां	हां

कोष्ठक की ठोस मानक त्रुटियां

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

सारणी 7: दो माह से अधिक और तीन माह तक की परिपक्वता बकेट पर टीएलटीआरओ का प्रभाव

आश्रित चर विचलन-असंतुलन (₹ करोड़)	(1)	(2)	(3)
ट्रीटेड _t * पोस्ट _t	234.9** (91.64)	219.6*** (79.75)	234.0** (103.6)
समायोजित R ²	0.668	0.666	0.741
प्रेक्षण	742	727	550
नियंत्रक	नहीं	हां	हां
एनबीएफसी एफई	हां	हां	हां
समय एफई	हां	हां	हां

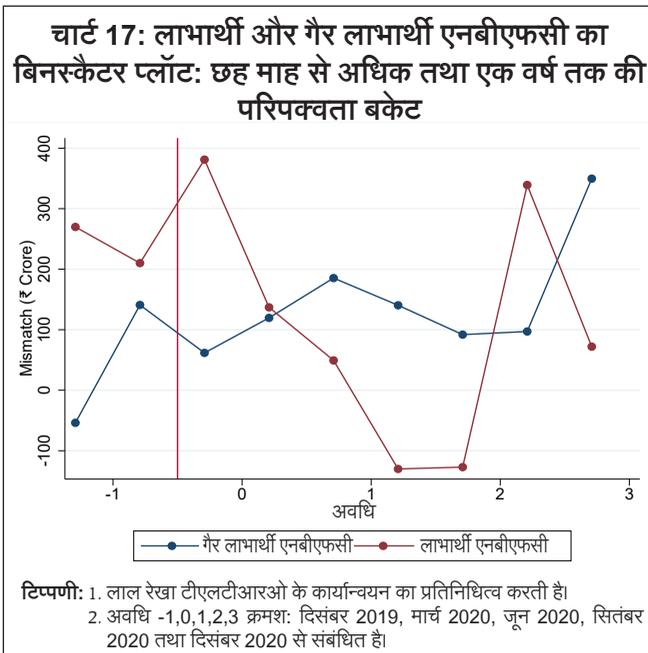
कोष्ठक की ठोस मानक त्रुटियां

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

iv) 6 महीने से अधिक और एक वर्ष तक की परिपक्वता बकेट

6 महीने से अधिक और एक वर्ष तक की दीर्घावधि परिपक्वता बकेट में, लाभार्थी फर्मों को कोविड-19 के तत्काल बाद में तनाव का सामना नहीं करना पड़ा और अन्य परिपक्वता विंडो के विपरीत, जून 2020 के बाद गिरावट देखी गई, हालांकि बाद में इसमें सुधार हुआ (चार्ट 17)।

परिणाम बताते हैं कि इस बकेट में लाभार्थी फर्मों के लिए असंतुलन बिगड़ गया। हालांकि, इसे चुकौती के समायोजन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बैंकों ने लाभार्थी फर्मों का ऋण खरीदा है जो इस परिपक्वता अवधि के तहत चुकौती के कारण थे और संभवतः प्रत्येक विनिर्देश के तहत नकारात्मक और महत्वपूर्ण गुणांक दर्शाते हैं (सारणी 8)। हालांकि, थोड़ा अधिक कार्यकाल होने के कारण, यह लाभार्थी एनबीएफसी को निधीयन की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना बनाने और संसाधन जुटाने के लिए पर्याप्त समय देता है।



सारणी 8: छह माह से अधिक और एक वर्ष तक की परिपक्वता बकेट पर टीएलटीआरओ का प्रभाव

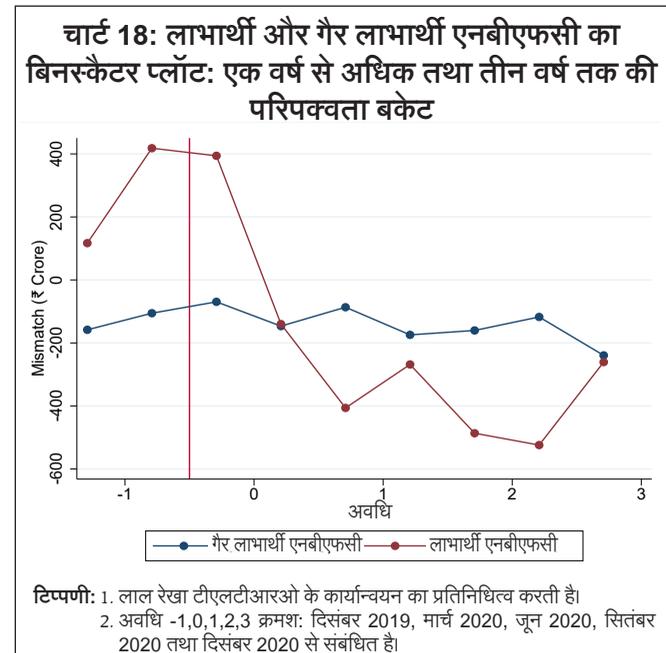
आश्रित चर विचलन-असंतुलन (₹ करोड़)	(1)	(2)	(3)
ट्रीटेड, * पोस्ट	-421.5* (234.0)	-361.1** (179.3)	-486.6** (226.2)
समायोजित R ²	0.754	0.753	0.816
प्रेक्षण	742	727	550
नियंत्रक	नहीं	हां	हां
एनबीएफसी एफई	हां	हां	हां
समय एफई	हां	हां	हां

कोष्ठक की तोस मानक त्रुटियां

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

बी) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक की परिपक्वता बकेट

लाभार्थी फर्मों ने टीएलटीआरओ की शुरुआत के बाद की अवधि में ठीक 6 महीने-1 वर्ष की परिपक्वता बकेट के समान एक-तीन साल की परिपक्वता बकेट में प्रवाह के सापेक्ष अधिक बहिर्वाह दर्ज किया (चार्ट 18)।



सारणी 9: एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक की परिपक्वता बकेट पर टीएलटीआरओ का प्रभाव

आश्रित चर विचलन- असंतुलन (₹ करोड़)	(1)	(2)	(3)
ट्रीटेड, * पोस्ट	-625.5** (257.2)	-380.1* (200.7)	-358.0** (172.9)
समायोजित R ²	0.801	0.847	0.919
प्रेक्षण	742	727	550
नियंत्रक	नहीं	हां	हां
एनबीएफसी एफई	हां	हां	हां
समय एफई	हां	हां	हां

कोष्ठक की ठोस मानक त्रुटियां

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

सारणी 9 पुष्टि करती है कि लाभार्थी एनबीएफसी को इस परिपक्वता बकेट में असंतुलन में गिरावट का सामना करना पड़ा। जैसा कि 6 महीने से अधिक-एक वर्ष की एएलएम विंडो के मामले में, यह संभावना है कि बैंकों ने एक-तीन साल के कार्यकाल के लाभार्थी एनबीएफसी के कागजात खरीदे और इसलिए, टीएलटीआरओ लाभ प्राप्त करने वाली एनबीएफसी ने अपने संरचनात्मक चलनिधि रिटर्न में इसके लिए उपयुक्त रूप से हिसाब लगाया। फिर भी, लाभार्थी एनबीएफसी, बड़े और अच्छे प्रदर्शन करने वाले होने के नाते, जरूरत पड़ने पर इस ऋण को चुकाने के लिए बाजार या बैंकों से संसाधन जुटा सकते हैं।

वृद्धिशील ऋण और वृद्धिशील तरल आस्तियों पर टीएलटीआरओ के प्रभाव की भी जांच की गई और उसे महत्वपूर्ण नहीं पाया गया।

सुदृढता जांच

सुदृढता जांच के रूप में, निम्नलिखित रूप में एक गतिशील विनिर्देश का अनुमान लगाया गया था कि टीएलटीआरओ के

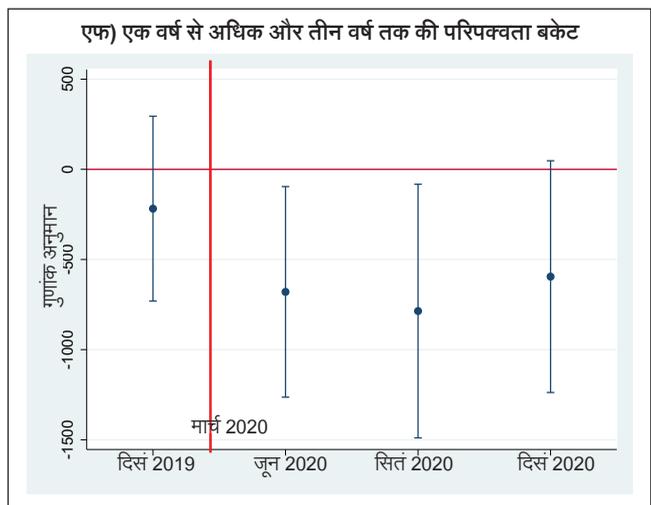
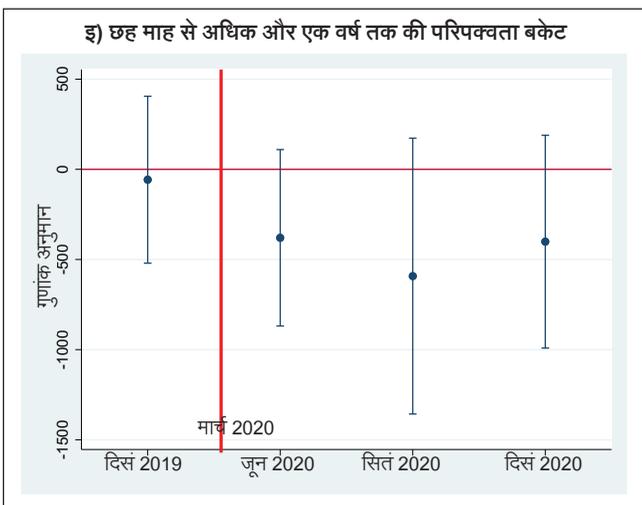
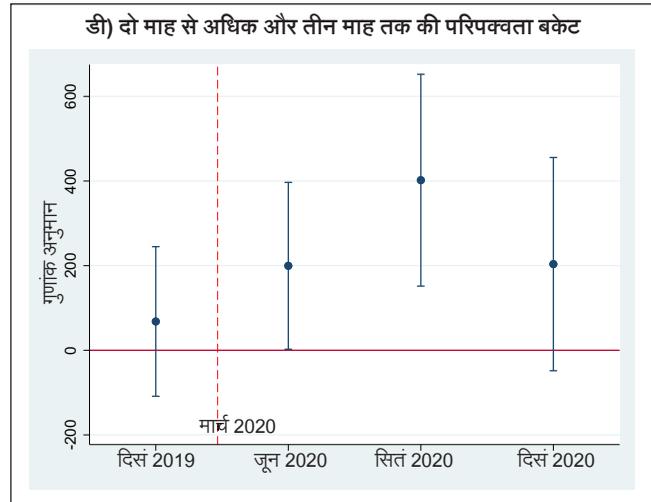
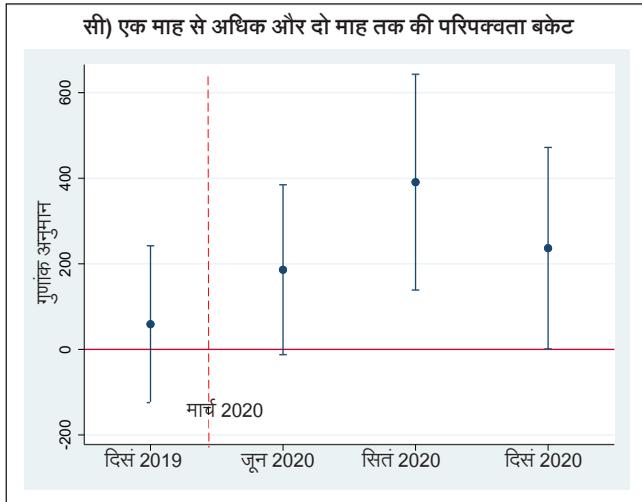
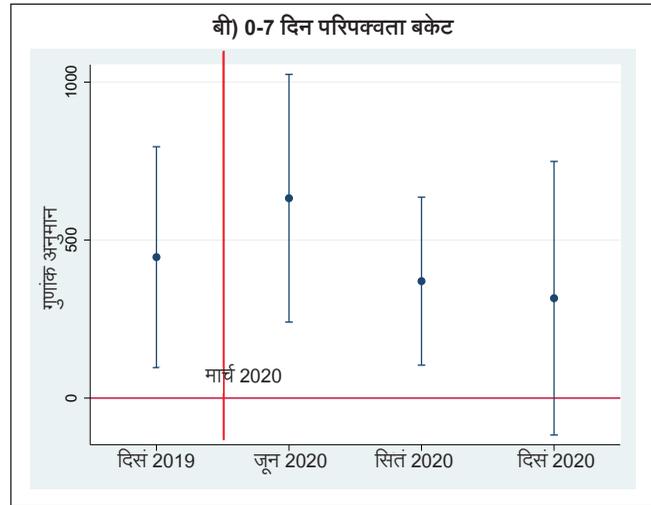
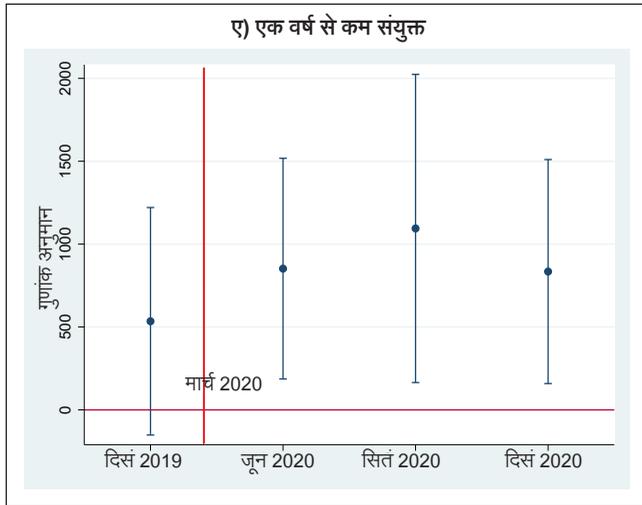
कार्यान्वयन के बाद लाभार्थी एनबीएफसी के एएलएम में सुधार हुआ है:

$$Mismatch_{i,t} = \beta_i + \alpha_t + \Sigma_t \delta_t (Treated_i * D_t) + \theta X_{i,t} + v_{i,t} \quad \dots (4)$$

जहां असंतुलन i,t अंतर्वाह और बहिर्वाह (₹ करोड़ में) के बीच का अंतर है, i एनबीएफसी निश्चित प्रभाव है, α_t समय निश्चित प्रभाव है, ट्रीटेड, एक संकेतक चर है जो लाभार्थी एनबीएफसी के लिए एक और गैर लाभार्थी फर्मों के लिए शून्य के बराबर है। दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 के बीच प्रत्येक समय अवधि के लिए एक संकेतक चर है (मार्च 2020 को छोड़कर जो संदर्भ अवधि के रूप में कार्य करता है)। गैर लाभार्थी का एक ही सेट यहां भी नियोजित किया गया है। ब्याज का गुणांक δ है, जो टीएलटीआरओ के माध्यम से निधि प्राप्त करने वाली एनबीएफसी और निधि प्राप्त न करनेवाली एनबीएफसी मार्च 2020 की तुलना में एक निश्चित अवधि में नियंत्रण के अधीन असंतुलन में अंतर को मापता है। इवेंट स्टडी प्लॉट के रूप में परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। यह देखा जा सकता है कि, तुलन पत्र विशेषताओं, समय-अपरिवर्तनीय कारकों (एनबीएफसी निश्चित प्रभाव) और समय निश्चित प्रभावों को नियंत्रित करने के बाद, मार्च 2020 की तुलना में लाभार्थी और गैर लाभार्थी समूहों के बीच असंतुलन अंतर पूर्व-टीएलटीआरओ अवधि (दिसंबर 2019) में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं था। जून के बाद से यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण होने लगा है, जो नीति के प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट 19)। ये परिणाम समानांतर प्रवृत्तियों की धारणा को भी सत्यापित करते हैं।¹¹

¹¹ मार्च 2020 में 0-7 दिनों की परिपक्वता बकेट को छोड़कर लाभार्थी एनबीएफसीयों को चलनिधि में तेज गिरावट का सामना करना पड़ा।

चार्ट 19: विविध एएलएम बकेट पर टीएलटीआरओ का प्रभाव



टिप्पणी: ग्राफ में समीकरण (4) से 95 प्रतिशत- विश्वास अंतराल के साथ गुणांक δ लिया गया है। लाल रेखा टीएलटीआरओ कार्यान्वयन को दर्शाती है।

VI. निष्कर्ष

एनबीएफसी आईएल एंड एफएस डिफॉल्ट के बाद अपने पैर जमा रहे थे, कोविड-19 महामारी ने प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू की जिसने उनकी चलनिधि की स्थिति बिगाड़ दी। रिजर्व बैंक और सरकार ने स्थिति को उबारने के लिए कई नीतिगत उपाय किए, जिनमें से एक टीएलटीआरओ योजना थी जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों और संस्थाओं को लक्षित चलनिधि प्रदान करना था जो चलनिधि की कमी और प्रतिबंधित बाजार पहुंच का सामना कर रहे थे। इस योजना के तहत, बैंकों को रेपो दर पर राशि उपलब्ध करायी गयी थी और एनबीएफसी सहित कॉर्पोरेट्स के निवेश ग्रेड पेपर में निवेश करने का निर्देश दिया गया था।

यह पेपर डिफरेंस-इन-डिफरेंस पद्धति का उपयोग करके एनबीएफसी के एएलएम पर टीएलटीआरओ के प्रभाव का विश्लेषण करता है। परिणाम बताते हैं कि यह नीति कोविड-19 के बाद की अवधि में लाभार्थी एनबीएफसी द्वारा सामना किए गए चलनिधि तनाव को कम करने में फायदेमंद थी, और उन्हें कठिन समय में नेविगेट करने में मदद मिली, खासकर जब से बाजार और बैंक दोनों ही उन्हें उधार देने में आगे नहीं आ रहे थे। इस योजना के माध्यम से निधि प्राप्त करने वाली एनबीएफसी को कोविड-19 के आघात के तुरंत बाद कुछ अल्पावधि एएलएम बकेट में तनाव का सामना करना पड़ा था और उन बकेट में नीति के लागू होने के बाद बेहतर प्रदर्शन देखा गया क्योंकि उन्होंने अपनी मौजूदा देनदारियों को चुका दिया। लंबी परिपक्वता वाली बकेट में, लाभार्थी एनबीएफसी के पास ऋणात्मक क्षेत्र में असंतुलन राशि थी, अर्थात्, अंतर्वाह की तुलना में अधिक बहिर्वाह, क्योंकि इस योजना के तहत बैंकों द्वारा खरीदा गया ऋण चुकौती के लिए था।

इसलिए, इस लेख में किए गए अनुभवजन्य अध्ययन से पता चलता है कि वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप एनबीएफसी क्षेत्र के लिए समय पर और प्रभावी साबित हुआ।

संदर्भ:

Bitra, Y., Meena, M., and A. Agarwal (2020), "Issues in Non-bank Financial Intermediation", *Reserve Bank of India Bulletin*, June 2020.

Giansante, S., Fatouh, M., and S. Ongena (2020), "Does quantitative easing boost bank lending to the real economy or cause other bank asset reallocation? The case of the UK", *Bank of England Working Paper No 883*, August.

Gropp, R., Mosk, T., Ongena, S., and W. Carlo (2018), "Bank Response to Higher Capital Requirements: Evidence from A-Quasi-Natural Experiment", *The Review of Financial Studies*, Vol 32, Issue 1, pp: 266–299.

Jayakumar, N., Neelima, K.M., and G. Prasad (2021), "Performance of NBFCs during the Pandemic: A Snapshot", *Reserve Bank of India Bulletin*, May 2021.

Reserve Bank of India (2020), *Report on Trend and Progress of Banking in India 2019-20*.

Reserve Bank of India (2021), *Annual Report 2020-21*.

Rituraj, Jagadeesh, M., Kumar, A., and A. Meena (2020), "Market Financing Conditions for NBFCs: Issues and Policy Options", *Reserve Bank of India Bulletin*, June 2020.

लघु वित्त बैंकों का प्रदर्शन - एक प्रारंभिक समीक्षा*

लघु वित्त बैंक (एसएफबी) विकास के प्रारंभिक चरण में हैं। ये ऐसे बैंकिंग संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यवहार्य व्यवसाय मॉडल विकसित करना है। इस अध्ययन में प्रारंभिक नीतिगत इनपुट के लिए लघु वित्त बैंकों के कार्य-निष्पादन का प्रारंभिक मूल्यांकन शामिल है। इस विश्लेषण से इन संस्थानों के कार्य-निष्पादन के सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में दक्षता, लीवरेज, चलनिधि और बैंकिंग व्यवसाय जैसे कारकों को दर्शाता है।

भूमिका

“कहीं भी गरीबी का व्याप्त होना समृद्धि के लिए संकट की स्थिति है।”¹ यह वक्तव्य संक्षेप में वैश्विक चुनौती के रूप में विषम विकास की कमियों को इंगित करता है। जबकि एक समावेशी और सतत विकास सदैव से भारत में अभिशासन का उद्देश्य रहा है, इस उद्देश्य को हाल के दिनों में वित्तीय समावेशन की नीति के माध्यम से एक नया प्रोत्साहन मिला है। अंतिम छोर पर व्यक्ति को जोड़ने के लिए एक बड़े कदम में, विशिष्ट क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभेदित बैंकों को बढ़ावा देने के लिए एक संरचना की घोषणा केंद्रीय बजट 2014-15 में की गई थी। इन विशिष्ट क्षेत्रों में किसान, कम आय वाले परिवार, लघु व्यवसाय, असंगठित क्षेत्र आदि सम्मिलित थे।

इस संरचना के हिस्से के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लाइसेंसकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए। एसएफबी के प्रारम्भ का प्राथमिक उद्देश्य जमाराशियों के प्रभावी विनियोजन और सूक्ष्म, लघु और असंगठित संस्थाएं को निम्न प्रसंस्करण लागत पर ऋण सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन में सुधार करना था (आरबीआई, 2014)। एसएफबी के दिशानिर्देशों का मसौदा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए विभेदित बैंकों के साथ पूर्व में किए गए प्रयोगों में हुई कमियों जैसे

* यह आलेख डीएसआईएम में सहायक परामर्शदाता श्री नितिन कुमार और डीईपीआर में प्रबंधक सुश्री सरिता शर्मा द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और यह आवश्यक नहीं है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

¹ फिलाडेल्फिया की आईएलओ घोषणा, 1944

कि संकीर्ण पूंजी आधार, प्रतिबंधात्मक भौगोलिक क्षेत्राधिकार, निधियों के स्रोत में विविधीकरण की कमी और संकेंद्रण जोखिम को सुधारते हुए बनाया गया था (गांधी, 2015)। लघु वित्त बैंकों में “लघु” शब्द समाज के अलग रखे गए तबके की सेवा के उद्देश्य को दिए गए महत्व को संदर्भित करता है, न कि बैंक का आकार को। उनके ऋण पोर्टफोलियो के कम-से-कम 50 प्रतिशत हिस्से में ₹25 लाख तक के ऋण शामिल होने चाहिए।

लघु या सामुदायिक बैंकिंग- उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं, दोनों में, समान रूप से लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की सेवा करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रचलित मॉडल है। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की तुलना में लघु बैंकों से जुड़े पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। एक तरफ, बड़े बैंकों के पास स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) और शाखाओं का बेहतर प्रसार है, वहीं लघु बैंक छोटे ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने में अधिक लचीले होने के लिए जाने जाते हैं (बर्जर और उडेल, 1995)। जबकि बड़े बैंक बड़े उद्यमियों को आस्तियों का उच्च अनुपात आबंटित करते हैं, तो स्थानीय बैंक पड़ोसी समुदाय की सेवा करते हैं (बर्जर और अन्य, 1995)। बड़े बैंक उधार देने के लिए आमतौर पर उधारकर्ताओं की साख, संपार्श्विक और लेखापरीक्षित विवरण जैसी ठोस जानकारी पर अधिक भरोसा करते हैं। लघु बैंक स्थानीय समुदाय के फीडबैक पर आधारित सुलभ जानकारी पर भरोसा करते हैं।

भारत में, एसएफबी की स्थापना का एक महत्वपूर्ण कारण एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को वित्त उपलब्ध कराना रहा है। योजित सकल मूल्य (जीवीए) में एमएसएमई की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक है, जिसने 2015-16 के दौरान 11 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न किया (भारत सरकार, 2020)। एमएसएमई को लाभदायक परियोजनाओं में निवेश करने के अवसरों की बाह्य वित्त की अनुपलब्धता के कारण कटौती की जा सकती है। एमएसएमई को ऋण संवितरण पर बैंकिंग प्रणाली के झटके भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं क्योंकि यह अतीत में बड़े एनपीए (अनर्जक आस्तियों) के कारण हुआ है। इसलिए, भारतीय संदर्भ में एमएसएमई की एक केंद्रित तरीके से आवश्यकता पूर्ति करने वाले समर्पित मध्यस्थ की आवश्यकता हो सकती है (हेकेन्स और अन्य, 2015; हसन और अन्य, 2017)।

इस आलेख में एसएफबी के परिचालन के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया है: ए. एसएफबी का अब तक का परिचालनगत कार्य-निष्पादन कैसा रहा है? बी. एसएफबी की लाभप्रदता के चालक कौन हैं? हम कुछ शोधपरक तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और लघु वित्त बैंकों के कार्य-निष्पादन के निकटस्थ निर्धारक तत्वों की भूमिका पर अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करते हैं। आलेख के खंड 2 में एसएफबी के परिचालन के लिए नीतिगत ढांचे को स्पष्ट करता है। डेटा और चर्चा की चर्चा खंड 3 में की गई है और उसके बाद खंड 4 में विश्लेषणात्मक कार्यनीति का वर्णन किया जाता है। निष्कर्षों की प्रस्तुति और चर्चा खंड 5 में और खंड 6 में विश्लेषण के सारांश होता है।

2. लघु वित्त बैंक: नीतिगत दृष्टिकोण

वंचित वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभेदित बैंकों को बढ़ावा देने के लिए एक संरचना की आवश्यकता के लिए केंद्रीय बजट 2014-15 में भारत सरकार की घोषणा से संकेत लेते हुए रिजर्व बैंक ने 2014-15 के दौरान लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए (आरबीआई, 2014)। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन के उद्देश्य निम्न रूप से को आगे बढ़ाना था: (i) मुख्य रूप से आबादी के वंचित और कम सेवा वाले वर्गों के लिए बचत वाहनों का प्रावधान। और (ii) उच्च प्रौद्योगिकी-कम लागत के परिचालन के माध्यम से लघु व्यवसाय इकाइयों; छोटे और सीमांत किसान; सूक्ष्म और लघु उद्योग; और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण की आपूर्ति। लघु वित्त बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं और समय-समय पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; आरबीआई अधिनियम, 1934 और अन्य प्रासंगिक कानून और निर्देशों द्वारा शासित हैं। तब से, रिजर्व बैंक द्वारा लघु वित्त बैंकों के “मांग पर” लाइसेंसिकरण के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए जाते हैं (आरबीआई, 2019)। वरिष्ठ स्तर पर बैंकिंग और वित्त में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले निवासी व्यक्ति/ पेशेवर (भारतीय नागरिक) एसएफबी स्थापित करने के लिए प्रवर्तक के रूप में पात्र हैं। “फिट एंड प्रापर” प्रवर्तकों / प्रवर्तक समूहों की जांच स्वस्थ प्रमाण, अखंडता, वित्तीय सुदृढ़ता और पेशेवर

अनुभव के सफल ट्रैक रिकॉर्ड के पिछले रिकॉर्ड के आधार पर की जानी चाहिए।

एसएफबी की स्थापना के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी आवश्यकता ₹200 करोड़ है जिसमें पूंजी पर्याप्तता अनुपात निरंतर आधार पर जोखिम भारित परिसंपत्तियों का 15 प्रतिशत है। मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई), और स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) भी दिशानिर्देशों के अधीन एसएफबी में परिवर्तन के लिए पात्र हैं। इससे पहले, 27 सितंबर 2018 को, रिजर्व बैंक ने श्री आर. गांधी की अध्यक्षता में शहरी सरकारी बैंकों (यूसीबी) पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप पात्र यूसीबी को लघु वित्त बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए एक योजना की घोषणा की। इस योजना के अनुसार, एसएफबी में परिवर्तन के इच्छुक यूसीबी को एसएफबी के इन “मांग पर” लाइसेंसिकरण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ऐसे लघु वित्त बैंकों की न्यूनतम निवल संपत्ति कारोबार शुरू होने की तारीख से ₹100 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा, उन्हें कारोबार शुरू होने की तारीख से पांच साल के भीतर अपनी न्यूनतम निवल संपत्ति ₹200 करोड़ तक बढ़ानी होगी।

3. डेटा

लघु वित्त बैंकों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए मार्च 2017 से मार्च 2020 तक एसएफबी के तिमाही आंकड़े पर्यवेक्षी रिटर्न के आधार पर संकलित किए जाते हैं। अध्ययन के समय भारत में कुल दस एसएफबी काम कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने अलग-अलग समय-बिंदुओं पर संचालन शुरू किया है। तदनुसार, हम विश्लेषण के लिए एक असंतुलित पैनल का निर्माण करते हैं। सभी चरों का विवरण नीचे दी गई सारणी 1 में दर्शाया गया है।

आश्रित चरों के लिए, साहित्य से संकेत लेते हुए हमने बैंक के कार्य-निष्पादन के लिए तीन प्रमुख संकेतक शामिल किए हैं, अर्थात्, लाभ मार्जिन, आरओई (इक्विटी पर प्रतिफल) और आरओए (आस्तियों पर प्रतिफल) (डीट्रिच और वानजेनरिड, 2014; पेट्रिया और अन्य, 2015: बर्जर और बाउमन, 2013)। व्याख्यात्मक चरों की ओर मुड़ते हुए, जीडीपी डिफ्लेटर द्वारा सामान्यीकृत आस्तियों के लघुगणक को आकार भिन्नता के लिए खाते में शामिल किया जाता है।

सारणी 1: चर की परिभाषा

चर	विवरण
आश्रित	
लाभ का अंतर	औसत बिक्री से निवल आय (प्रतिशत)
इक्विटी पर प्रतिफल	औसत इक्विटी से निवल आय (प्रतिशत)
आस्ति पर प्रतिफल	औसत आस्ति से निवल आय (प्रतिशत)
स्वतंत्र	
लॉग (आस्ति)	आस्तियों का लॉग
दक्षता	परिचालन आय की तुलना में परिचालन व्यय का प्रतिशत
लीवरेज	आस्तियों के लिए चुकता अंश पूंजी का प्रतिशत
चलनिधि	(चलनिधि*100)/ आस्तियां यहां, चलनिधि = नकद निधि+ बैंकों / एफआई / सीसीपी से देय + स्वीकृत प्रतिभूतियां
दबावग्रस्त_अग्रिम	सकल अग्रिमों की तुलना में (जीएनपीए + पुनर्चित मानक अग्रिम) का प्रतिशत
बैंकिंग_व्यवसाय	(क्रेडिट + जमाराशि)*100/ आस्ति
सीओएफ	निधियों की लागत
एलएलपी	ऋण हानि प्रावधान अर्थात सकल अग्रिमों के लिए एनपीए हेतु धारित प्रावधानों का प्रतिशत
प्रभावी_कर	कर पूर्व लाभ के लिए आयकर के प्रावधान का प्रतिशत
टीई	समय प्रभावों को अलग करने के लिए टाइम डमी

इसके अलावा, बैंकों में लागत आय अनुपात को दक्षता अंतर मापने के लिए सम्मिलित किया जाता है। लीवरेज को वित्तीय सुदृढ़ता और स्थिरता को प्रतिबिंबित करने वाला कारक माना गया है। इसी तरह, चलनिधि, दबावग्रस्त अग्रिमों और बैंकिंग व्यवसाय जैसे कारकों को एसएफबी के कार्य-निष्पादन पर उनके संभावित प्रभाव का आंकलन करने के लिए चुना जाता है।

निधियों की लागत (सीओएफ) लाभप्रदता का निर्धारण करने वाला एक महत्वपूर्ण चर है (राखे, 2010)। यह विभिन्न मध्यस्थता गतिविधियों के माध्यम से निधियाँ जुटाने में हुए व्यय को दर्शाता है। ऋण हानि प्रावधान (एलएलपी) एक अन्य प्रासंगिक चर है जिसका बैंक के कार्य-निष्पादन पर असर पड़ सकता है (डीट्रिच और वानजेनरिड, 2014)। यह एक बैंक के लिए ऋण की गुणवत्ता और उसके आबंटन को दर्शाता है। उच्च एलएलपी का तात्पर्य निम्न क्रेडिट गुणवत्ता से है जिसका बैंक की लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लाभप्रदता पर इसके प्रभाव को समझने के लिए प्रभावी कर दर को शामिल किया गया है। एक ओर, उच्च कर दर से कर-पश्चात लाभ कम हो सकता है (डेमिगुक-कुंट और हुइज़िंगा, 1999)। इसके विपरीत, बैंक अपने ग्राहकों पर कराधान का बोझ स्थानांतरित कर सकते हैं (अल्बर्टाज़ी और गैम्बाकोर्टा, 2009)।

साहित्य व्यावसायिक चक्रों या बाह्य कारकों के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करता है जिनका बैंक के कार्य-निष्पादन का

निर्धारण करने में भी असर हो सकता है, जैसे पेट्रिया और अन्य (2015), बर्जर और बाउमन (2013) और राखे (2010) के मामले में। इस संबंध में, हमने नमूने में सभी एसएफबी को प्रभावित करने वाले समय के अलग-अलग सभी कारकों को दर्शाने के लिए अपने विश्लेषण टाइम डमी की सूची में शामिल किया है।

4. कार्यप्रणाली

हमारे सूचना समूह की अनुदैर्घ्य प्रकृति के कारण, बैंक स्तर की विशेषताएं समय के साथ स्वतंत्र नहीं हो सकती हैं, जिससे सामान्य न्यूनतम स्ववायर तकनीक अनुपयुक्त हो जाती है, जो पक्षपाती अनुमान प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, एसएफबी की लाभप्रदता और अन्य नीतिगत निर्णय एक ही अवधि में विस्तारित हो सकते हैं जिससे दृढ़ता बनी रहती है। इसलिए, एक गतिशील ढांचा विनियोजित किया जाता है जिसमें पिछली अवधि की लाभप्रदता को एक स्वतंत्र चर के रूप में भी लिया जाता है। बड़ी संख्या में क्रॉस सेक्शन और छोटी समय अवधि वाले गतिशील पैनेल मॉडल में, जेनेरलाइस्ड मेथड ऑफ मोमेंट्स (जीएमएम) एस्टीमेटर कुशल अनुमान प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं (एरेलानो और बॉन्ड, 1991; एरेलानो और बोवर, 1995)। जीएमएम निम्न रूप में प्रतिपादित किया गया है:

$$y_{i,t} = \alpha y_{i,t-1} + \beta' X_{i,t} + \eta_i + \varepsilon_{i,t}; \text{ where } \varepsilon_{i,t} \sim N(0, \tau^{-1}) \quad \dots(1)$$

समीकरण (1) में, t^{th} अवधि में i^{th} एसएफबी के आश्रित चर को दर्शाता है। पश्चायित अंतर्जात चर को $Y_{i,t-1}$ द्वारा दर्शाया जाता है। मैट्रिक्स $X_{i,t}$ व्याख्यात्मक चर के मूल्यों को दर्शाता है। अनदेखा एसएफबी प्रभाव है और विशेष प्रकृति के सामान्य स्वभाव के झटके हैं। सभी विशिष्टताओं का अनुमान जीएमएम फ़र्स्ट डिफ़्रेंस स्पेसिफिकेशन का उपयोग करके लगाया जाता है ताकि एसएफबी के विशिष्ट प्रभाव हटा दिए जाएं। इसलिए, समीकरण (1) को निम्नानुसार पुनः प्रतिपादित किया जा सकता है।

$$y_{i,t} - y_{i,t-1} = \alpha(y_{i,t-1} - y_{i,t-2}) + \beta'(X_{i,t} - X_{i,t-1}) + (\varepsilon_{i,t} - \varepsilon_{i,t-1})$$

निम्न मान्यताओं के तहत: (ए) एरर शब्द क्रमिक रूप से सहसंबद्ध नहीं है, (बी) व्याख्यात्मक चर भविष्य में एरर अवधि की प्राप्ति के साथ सहसंबद्ध नहीं हैं, जीएमएम गतिशील पैनेल अनुमानक निम्नलिखित स्थितियों को नियोजित करता है।

$$E[y_{i,t-s} \cdot (\varepsilon_{i,t} - \varepsilon_{i,t-1})] = 0 \text{ for } s \geq 2; t = 3, \dots, T$$

$$E[X_{i,t-s} \cdot (\varepsilon_{i,t} - \varepsilon_{i,t-1})] = 0 \text{ for } s \geq 2; t = 3, \dots, T$$

जीएमएम अंतर अनुमान में उपकरणों का अनुप्रयोग न केवल अंतर्जात के मुद्दे को प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है बल्कि $(Y_{i,t} - Y_{i,t-2})$ के साथ $(E_{i,t} - E_{i,t-1})$ के सहसंबंध को भी प्रबंधित करता है। इसके अतिरिक्त, जीएमएम अंतर उपकरणों की संख्या के मुद्दे को भी दरकिनार कर देता है, जो कि सिस्टम जीएमएम के सरगन टेस्ट के कमजोर होने के मामले में अन्यथा बड़ा हो सकता है।

समीकरण (1) का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

$$\begin{aligned} Dep_{i,t} = & \beta_1 Dep_{i,t-1} + \beta_2 Log(Assets)_{i,t} + \beta_3 Efficiency_{i,t} + \\ & \beta_4 Leverage_{i,t} + \beta_5 Liquidity_{i,t} + \beta_6 Stressed_Advances_{i,t} + \\ & \beta_7 Banking_Business_{i,t} + \beta_8 COF_{i,t} + \beta_9 LLP_{i,t} + \\ & \beta_{10} (Effective_Tax)_{i,t} + TE + \eta_i + \varepsilon_{i,t} \end{aligned} \quad \dots(2)$$

जैसा कि देखा गया है, डीईपी हमारा आश्रित चर है जिसे लाभ मार्जिन, आरओई और आरओए के रूप में अलग-अलग स्वतंत्र चरों के सामान्य सेट के साथ जैसा कि समीकरण (2) के दाईं ओर दिखाया गया है, लिया जाता है। टीई नमूने में एसएफबी को प्रभावित करने वाले सभी समय के अलग-अलग कारकों को दर्शाने वाले समय को दर्शाता है।

5. विश्लेषण और परिणाम

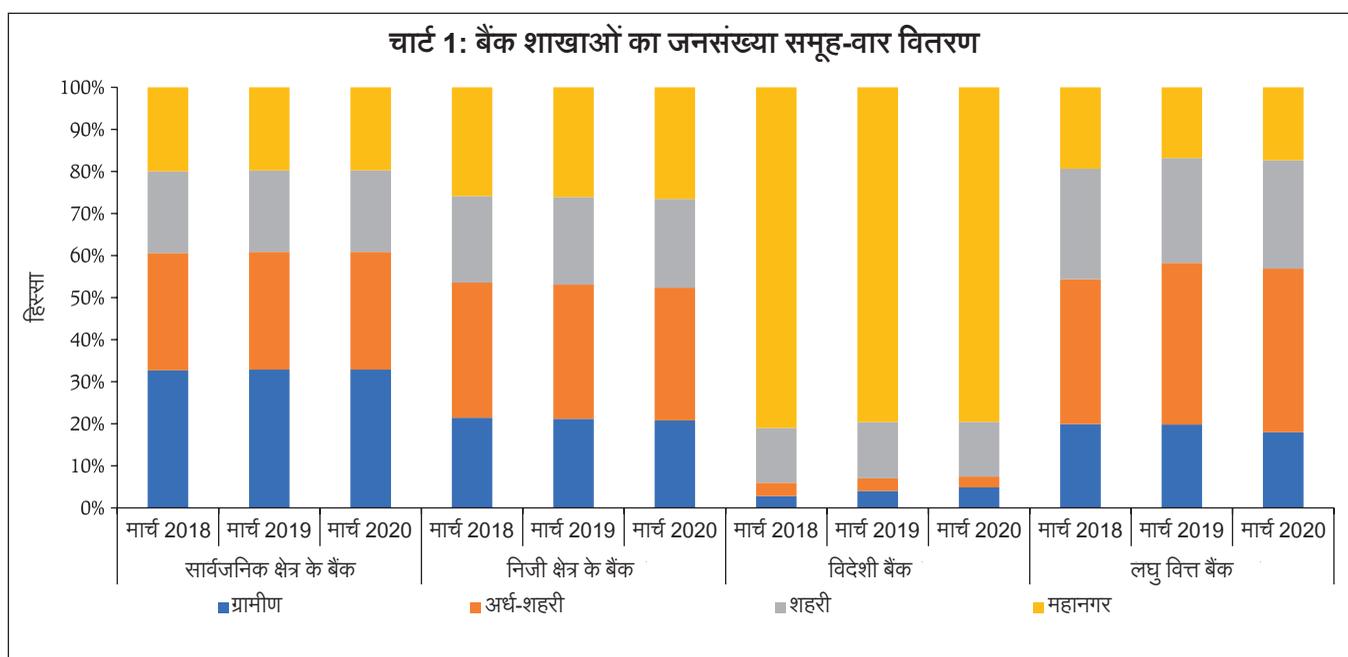
एसएफबी के स्थानिक और प्रवृत्ति मूल्यांकन के एक सिंहावलोकन पर अगले उप-भाग में चर्चा की गई है। इसके बाद

लाभप्रदता के निर्धारकों के प्रतिगमन विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षों की प्रस्तुति है।

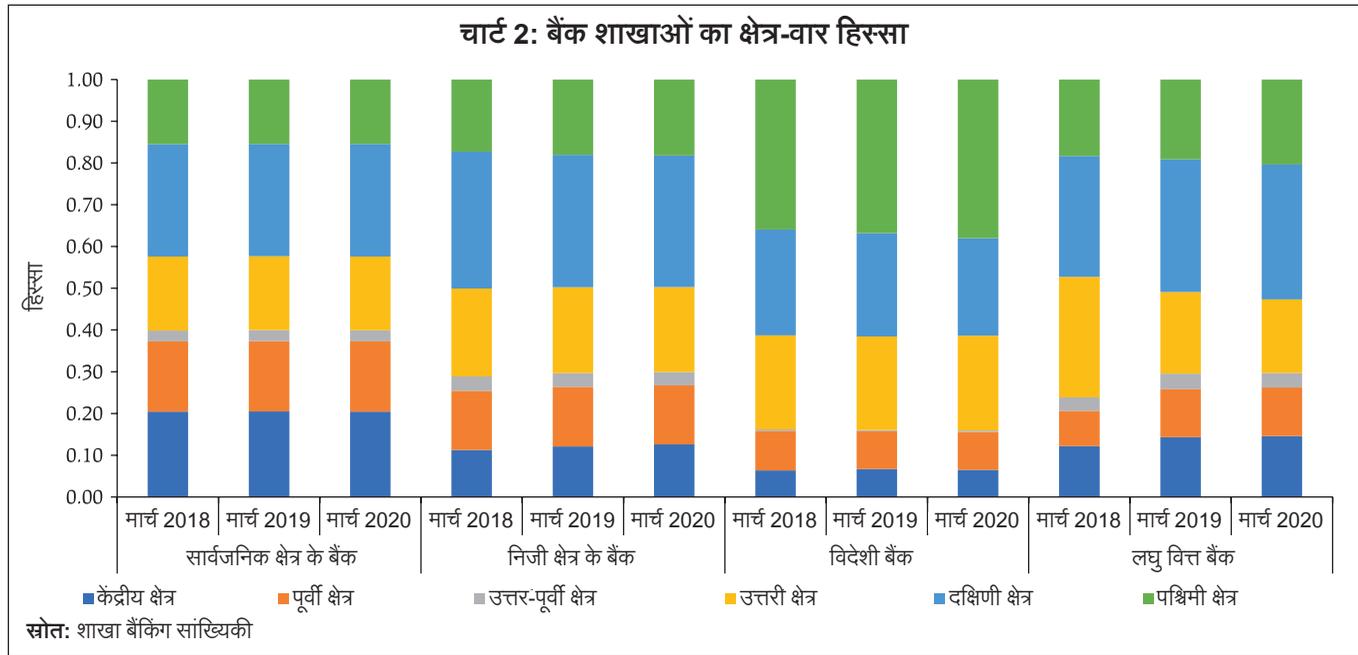
5.1 शोधपरक तथ्य

अन्य बैंक समूहों के साथ एसएफबी के प्रमुख अनुपातों और दरों की तुलना सारणी 2 (अनुबंध) में प्रस्तुत की गई है। अन्य बैंक समूहों की तुलना में एसएफबी के लिए उच्च ऋण जमा (सीडी) अनुपात देखा गया है, जो उपलब्ध निधि की उधार गतिविधि में उच्च रूपांतरण दर को दर्शाता है। एसएफबी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करना था। यह वास्तव में एसएफबी के प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के हिस्से के साथ अन्य पारंपरिक बैंकिंग समूहों² की तुलना में काफी अधिक पाया गया है। एसएफबी की जमाराशियों की वृद्धि दर और ऋण दोनों ही सामान्य रूप से लघु आधार के कारण अधिक होते हैं। अन्य बैंक समूहों की तुलना में एसएफबी के लिए लाभप्रदता और आस्तियों की गुणवत्ता के आंकड़े भी बेहतर हैं। इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समूह के लिए लाभप्रदता उपाय न के बराबर हैं।

बैंक शाखाओं के जनसंख्या समूह-वार वितरण पर चार्ट 1 से पता चलता है कि बैंक शाखाओं की कुल संख्या में से,



² प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के संबंध में शर्तें एनबीसी (समायोजित निवल बैंक ऋण) के प्रतिशत के रूप में अंतिम तुलन पत्र की तारीख पर हैं। सभी लघु वित्त बैंकों ने 75 प्रतिशत एनबीसी के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।



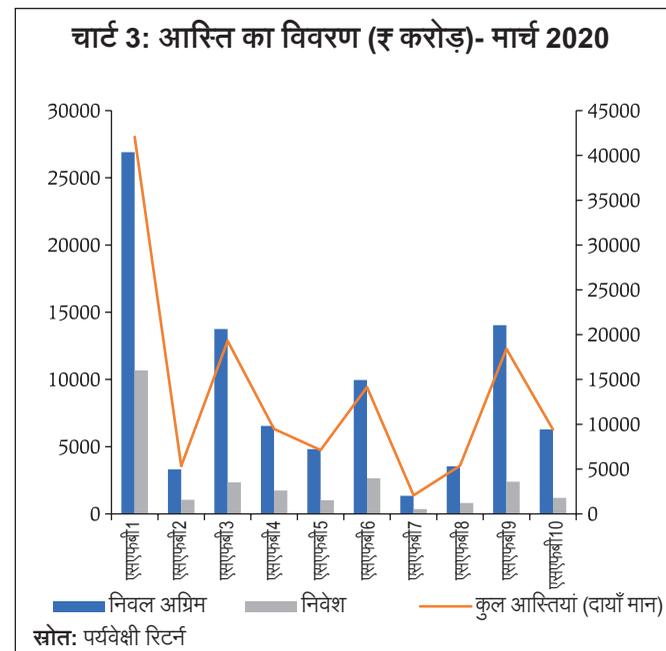
एसएफबी³ की अर्ध-शहरी शाखाओं का हिस्सा सबसे अधिक है जो कि मार्च 2020 में शाखाओं की संख्या लगभग 39 प्रतिशत है (सराफ और चव्हाण, 2021)। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र, जो वित्तीय समावेशन अभियान के लिए नीति निर्माताओं का विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं, मार्च 2020 में इन क्षेत्रों की कुल मिलाकर 57 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। हालांकि, यह हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 61 प्रतिशत की तुलना में कम है, जिनका ग्रामीण वर्गों में बेहतर कवरेज है। मार्च 2018 के बाद से जनसंख्या समूहों में शाखाओं की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत समान रही है। चार्ट 2 के अनुसार, यह देखा गया है कि एसएफबी की कुल शाखाओं का लगभग 30 प्रतिशत शाखाएं दक्षिणी भारत में स्थित है, इसके बाद उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में प्रत्येक में लगभग 20 प्रतिशत है। यह इंगित करता है कि दक्षिणी क्षेत्रों में एसएफबी की अधिक प्रमुखता है, जो कई एसएफबी के दक्षिण भारत में सक्रिय होने के कारण आश्चर्यजनक नहीं है।

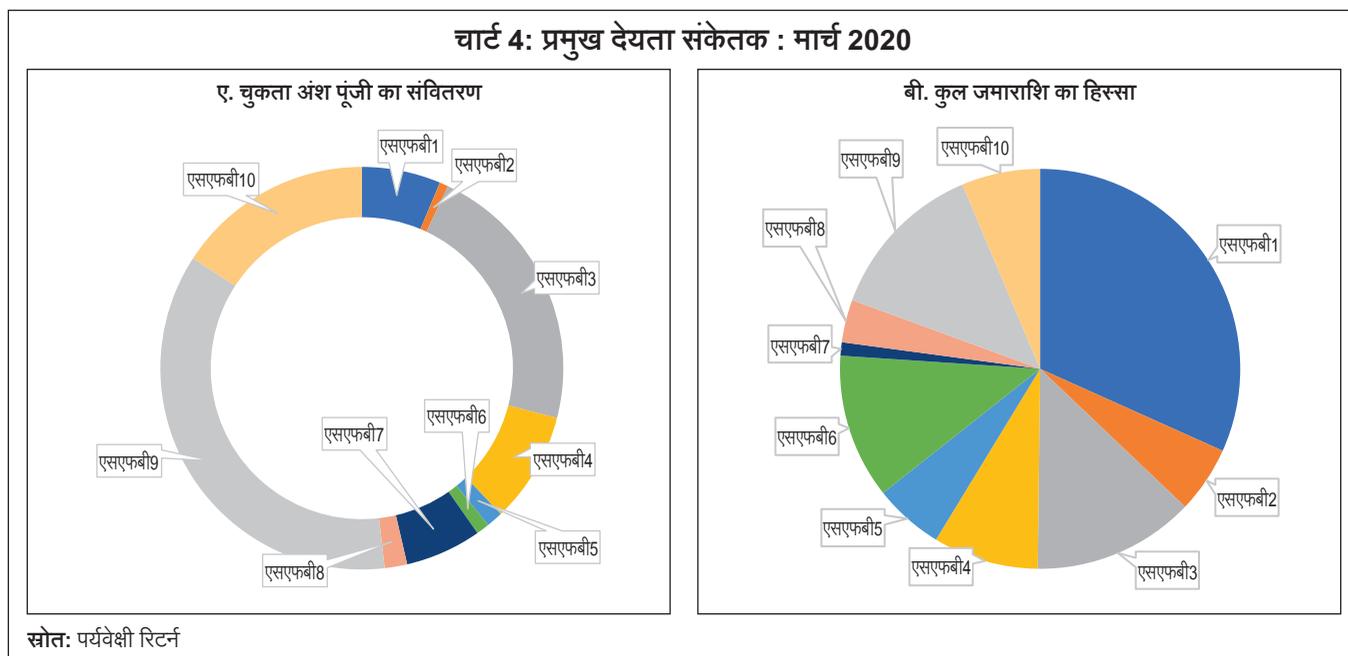
इसके बाद, एसएफबी में संतुलन पत्र की मदों की तुलना की जाती है। आस्ति के आकार के मामले में मार्च 2020 में सबसे बड़ा

³ एसएफबी ने बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) में 25 प्रतिशत बैंकिंग आउटलेट होने की शर्त पूरी कर ली है, क्योंकि 18 मई, 2017 की शाखा प्राधिकरण नीति पर युक्तिकरण पर परिपत्र के अनुसार यूआरसी की परिभाषा में अधिक मानदंड शामिल हैं। इसलिए, यूआरसी में ग्रामीण शाखाएं और बैंकिंग आउटलेट समान नहीं हो सकते हैं।

⁴ इसके बाद से दस लघु वित्त बैंकों को लगातार एसएफबी1, एसएफबी2, ..., एसएफबी10 के रूप में कूट बद्ध किया गया है।

बैंक एसएफबी1⁴ ₹42,064 करोड़ पर है, उसके बाद एसएफबी3 ₹19.315 करोड़ पर है। अकेले एसएफबी1 में कुल आस्ति के मामले में सभी एसएफबी की तुलना में लगभग 32 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। दूसरी ओर, एसएफबी7, एसएफबी2, एसएफबी8 सबसे छोटे एसएफबी हैं जिनकी कुल संपत्ति ₹6,000 करोड़ से कम है। एसएफबी की आस्तियों के आस्ति पोर्टफोलियो का प्रमुख हिस्सा अग्रिम होता है और उसके बाद निवेश दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है (चार्ट 3)।





लघु वित्त बैंकों के देयता पक्ष में, मार्च 2020 में सकल पूंजी में एसएफबी9 की सबसे अधिक 36 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसके बाद एसएफबी3 लघु वित्त बैंकों की सकल पूंजी का 22 प्रतिशत है। जबकि जमा पक्ष में, एसएफबी1 32 प्रतिशत के साथ सबसे बड़े खंड पर कब्जा करता है, उसके बाद इसी अवधि के लिए एसएफबी3 और एसएफबी9, प्रत्येक में 13 प्रतिशत हिस्सेदारी है (चार्ट 4)।

5.2 अनुभवजन्य परिणाम

सारणी 3 (अनुलग्नक) प्रमुख चरों के वर्णनात्मक आंकड़ों को सारणीबद्ध करती है। सभी लाभप्रदता अनुपात जैसे, लाभ मार्जिन, आरओई और आरओए केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य माप के अनुसार सुधार प्रदर्शित करते हैं। लेकिन, सितंबर 2018 में एक बढ़े हुए मानक विचलन⁵ के साथ लाभप्रदता अनुपात का औसत तेजी से गिरा है। इसके अलावा, मार्च 2017 में केवल पांच एसएफबी क्रियाशील थे जो सितंबर 2018 में बढ़कर 10 हो गए, जिससे उच्च विस्तार में योगदान हुआ। कुल आस्तियों द्वारा मापे गए कुल आकार में औसत और माध्य दोनों के संदर्भ में बहुत कम वृद्धि हुई है। औसत दक्षता मार्च 2017 में 75 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2020 में 66 प्रतिशत हो गई है। मोटे तौर पर, चलनिधि और

बैंकिंग व्यवसाय, दोनों में, सितंबर 2018 से मार्च 2020 तक कम परिवर्तनशीलता के साथ माध्य और माध्यिका दोनों के संदर्भ में वृद्धि हुई है।

प्रतिगमन परिणाम बाहरी प्रेक्षण(णों) के अस्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं, जो समग्र परिणाम को दूषित कर सकते हैं। इस संबंध में, डीएफआईटीएस⁶ उपाय व्यापक रूप से आउटलाइर्स (माध्य से अत्यधिक विचलन) की पहचान करने के लिए नियोजित है (वेल्ल और कुह, 1977)। डीएफआईटीएस परीक्षण के आवेदन के बाद अनुभवजन्य जांच के लिए प्रेक्षणों की संख्या 109 थी। प्रतिगमन विश्लेषण करने से पहले, चर की स्थिरता स्थापित करना उचित है। गैर-स्थिर चरों को शामिल करने वाले प्रतिगमन अप्रामाणिक परिणाम दर्शाते हैं। इस संदर्भ में, पैनेल यूनिट रूट परीक्षण किए गए जो यूनिट रूट की अमान्य परिकल्पना को अस्वीकार करने का सुझाव देते हैं (अनुलग्नक सारणी 4)। तदनुसार, हमने स्तर पर सभी चर शामिल किए हैं।

लाभप्रदता के निर्धारकों का जीएमएम अनुमान परिणाम सारणी 5 (अनुलग्नक) में दर्शाया गया है। केस 1, 2, 3 में आश्रित चर क्रमशः लाभ मार्जिन, आरओई और आरओए हैं। मोटे तौर पर,

⁵ यह एक एसएफबी के कारण हुआ है जो मार्च 2018 से क्रियाशील हुआ था। अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण, इसने 2018 के दौरान एसएफबी के औसत स्कोर को नीचे गिरा दिया है।

⁶ डीएफआईटीएस एक नैदानिक उपाय है जिसका उपयोग प्रतिगमन में बाहरी टिप्पणियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। डीएफआईटीएस i^{th} मामले के लिए अनुमानित मूल्यों के बीच एक छोटा अंतर है जब प्रतिगमन i^{th} अवलोकन के साथ और उसके बिना फिट होता है। डीएफआईटीएस का उच्च मूल्य जांच के योग्य है।

गुणांक के अनुमानों के संकेत और महत्व के परिणाम की मजबूती का संकेत देने वाले सभी तीन प्रतिगमनों में समान हैं। सबसे आगे, यह देखा गया है कि दक्षता तीनों मॉडलों के लिए लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। राखे (2010), डीट्रिच और वानजेनरिड (2014) से एसएफबी को भी निष्कर्षों का विस्तार करने वाले एसएफबी के मामले में सभी तीन मॉडलों के लिए उपार्जन की तुलना में उच्च परिचालन लागत स्पष्ट रूप से लाभप्रदता संकेतकों पर हानिकारक प्रभाव डाल रही है। उसके बाद, लीवरेज का गुणांक सभी मॉडल वेरिएंट में सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया है। परिणाम एसएफबी के कार्य-निष्पादन को बढ़ाने पर पूंजी के उचित स्तर के मूल्यवान योगदान की ओर इंगित करता है। परिणाम अन्य अध्ययनों के संबंध में संगतपूर्ण है, जो पूंजी अनुपात के साथ समान निष्कर्ष प्राप्त करते हैं (डीट्रिच और वानजेनरिड, 2014; पेट्रिया और अन्य, 2015)। चलनिधि का अनुमान सकारात्मक है और लाभ मार्जिन और इक्विटी पर प्रतिफल के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग व्यवसाय लाभप्रदता के सभी उपायों के लिए लाभकारी प्रभाव उत्पन्न कर रहा है।

इसी कड़ी में, सभी मॉडलों के लिए वाल्ड आँकड़ा सहसंयोजकों के महत्व को इंगित करने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अवशिष्ट सहसंबंध की अनुपस्थिति का संकेत देने वाले सभी मामलों के लिए पहले और दूसरे क्रम-दोनों का क्रमिक सहसंबंध महत्वहीन है। अधिक पहचान प्रतिबंधों के सरगन आंकड़े सारणीबद्ध हैं जो कि उपकरणों की वैधता स्थापित करते हैं। कुल मिलाकर, ये परिणाम लाभप्रद परिचालन के लिए बैंकों के आंतरिक कारकों जैसे दक्षता, लीवरेज, चलनिधि और बैंकिंग व्यवसाय के सापेक्ष महत्व को दर्शाते हैं।

6. निष्कर्ष

एसएफबी को समाज के वंचित और सीमांत वर्गों की सेवा करने के उद्देश्य से लाइसेंस प्रदान किया गया है। समय के साथ, रिज़र्व बैंक लघु वित्त बैंकों की अधिक प्रभावशीलता के लिए दिशानिर्देशों को अद्यतन करता रहा है। इस अध्ययन के समय एसएफबी तीन साल से अधिक समय से परिचालन में हैं। इस संबंध में, अध्ययन लघु वित्त बैंकों के परिचालनगत कार्य-निष्पादन का आंकलन करने का प्रयास करता है। प्रारंभिक विश्लेषण से पता

चलता है कि एसएफबी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की सेवा करने में अग्रणी हैं। अधिकांश एसएफबी हाल की तिमाहियों में और सुधार के साथ स्वस्थ प्रदर्शन कर रहे हैं।

अनुभवजन्य परिणाम दर्शाते हैं कि दक्षता, लीवरेज, चलनिधि और बैंकिंग व्यवसाय जैसे सूक्ष्म कारक परिचालन की इस प्रारंभिक अवधि के दौरान लघु वित्त बैंकों की लाभप्रदता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि एसएफबी विशुद्ध रूप से लाभ कमाने वाले मध्यस्थ के बजाय कम-विशेषाधिकार प्राप्त आबादी के आला वर्ग की सेवा के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। सीमित समयावधि उपलब्ध होने के कारण, विश्लेषण के परिणाम को इस स्तर पर सांकेतिक माना जा सकता है और आगे चलकर अधिक-से-अधिक डेटा के साथ इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

संदर्भ

- Albertazzi, U., and Gambacorta, L. (2009), "Bank profitability and the business cycle", *Journal of Financial Stability*, 5(4), 393-409.
- Arellano, M., and Bond, S. (1991), "Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations", *The Review of Economic Studies*, 58(2), 277-297.
- Arellano, M., and Bover, O. (1995), "Another look at the instrumental variable estimation of error-components models", *Journal of Econometrics*, 68(1), 29-51.
- Berger, A. N., and Bouwman, C. H. (2013), "How does capital affect bank performance during financial crises?" *Journal of Financial Economics*, 109(1), 146-176.
- Berger, A. N., Kashyap, A. K., Scalise, J. M., Gertler, M., and Friedman, B. M. (1995), "The transformation of the US banking industry: What a long, strange trip it's been", *Brookings papers on economic activity*, 1995(2), 55-218. 2017-18.
- Berger, A. N., and Udell, G. F. (1995), "Relationship lending and lines of credit in small firm finance", *Journal of Business*, 351-381.

- Demirguc-Kunt, A., and Huizinga, H. (1999), "Determinants of commercial bank interest margins and profitability: Some international evidence", *World Bank Economic Review*, 13(2), 379-408.
- Dietrich, A., and Wanzenried, G. (2014), "The determinants of commercial banking profitability in low-, middle-, and high-income countries", *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 54(3), 337-354.
- Gandhi, R. (2015), "Disruptive Innovation and Inclusive Growth – Some Random Thoughts", Speech delivered at FIBAC 2015, Mumbai, August 25, 2015.
- Government of India (2020), "Annual Report 2019-20", Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.
- Hakenes, H., Hasan, I., Molyneux, P., and Xie, R. (2015). Small banks and local economic development. *Review of Finance*, 19(2), 653-683.
- Hasan, I., Jackowicz, K., Kowalewski, O., and Kozłowski, L. (2017). Do local banking market structures matter for SME financing and performance? New evidence from an emerging economy. *Journal of Banking and Finance*, 79, 142-158.
- Petria, N., Capraru, B., and Ihnatov, I. (2015), "Determinants of banks' profitability: evidence from EU 27 banking systems", *Procedia Economics and Finance*, 20(15), 518-524.
- Rakhe, P. B. (2010), "Profitability of foreign banks vis-à-vis other bank groups in India—a panel data analysis", *Reserve Bank of India Occasional Papers*, 31(2), 49-67.
- Reserve Bank of India (2014), "RBI releases Guidelines for Licensing of Small Finance Banks in the Private Sector". Department of Communications (November 27, 2014), Mumbai.
- Reserve Bank of India (2019), Draft Guidelines for "on tap" Licensing of Small Finance Banks in the Private Sector, Reserve Bank of India (September 13, 2019).
- Saraf, R., Chavan, P. (2021), "Small Finance Banks: Balancing Financial Inclusion and Viability", *RBI Bulletin*, January 2021, pp. 49-60.
- Welsch, R. E., and Kuh, E. (1977), "Linear regression diagnostics", (No. w0173), National Bureau of Economic Research.

अनुबंध

सारणी 2: बैंक समूह-वार प्रमुख संकेतक

(प्रतिशत)

अवधि	अनुपात	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	लघु वित्त बैंक
2018-19	सीडी अनुपात	69.44	88.26	68.26	120.91
	कुल जमाराशि की तुलना में मांग और बचत जमा	39.5	41.46	39.81	18.71
	जमा वृद्धि	2.71	25.1	17.45	112.95
	कुल अग्रिम में से प्राथमिकता क्षेत्र के लिए	32.7	30.21	27.08	68.32
	अग्रिम वृद्धि	3.43	24.96	13.02	70.48
	आस्ति पर प्रतिफल	-0.65	0.63	1.56	1.59
	इक्विटी पर प्रतिफल	-11.44	5.45	8.77	12.59
	जीएनपीए अनुपात	11.59	5.25	2.99	1.83
2019-20	सीडी अनुपात	68.06	87.16	62.56	109.81
	कुल जमाराशि की तुलना में मांग और बचत जमा	39.93	41.36	42.07	15.35
	जमा वृद्धि	6.62	10.32	17.73	67.73
	कुल अग्रिम में से प्राथमिकता क्षेत्र के लिए	31.87	30.92	27.08	71.79
	अग्रिम वृद्धि	4.5	8.95	7.9	52.33
	आस्ति पर प्रतिफल	-0.23	0.51	1.55	1.7
	इक्विटी पर प्रतिफल	-4.16	3.3	8.76	15
	जीएनपीए अनुपात	10.25	5.45	2.34	1.87

स्रोत: भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां, मार्च 2020

सारणी 3: वर्णनात्मक सांख्यिकी

चर	मार्च 2017			सितंबर 2018			मार्च 2020		
	माध्यिका	माध्य	मानक विचलन	माध्यिका	माध्य	मानक विचलन	माध्यिका	माध्य	मानक विचलन
लाभ का अंतर	5.36	4.34	3.49	10.44	-6.42	67.37	11.68	9.40	4.48
इक्विटी पर प्रतिफल	1.59	3.31	4.04	11.72	-14.91	101.34	13.08	12.72	6.50
आस्ति पर प्रतिफल	0.18	0.39	0.50	1.72	-0.56	10.59	2.04	1.67	0.90
इन (एसेट्स)	12.35	12.75	0.64	12.91	12.98	0.81	13.42	13.46	0.84
दक्षता	75.27	78.08	9.91	64.52	73.51	55.59	65.64	63.90	10.28
लीवरेज	10.87	10.08	5.77	4.56	6.75	6.66	3.07	4.58	4.70
चलनिधि	34.43	35.51	7.63	24.44	24.69	6.02	27.28	27.42	3.89
दबावग्रस्त अग्रिम	0.53	1.08	1.44	2.20	5.45	10.48	1.72	1.88	0.88
बैंकिंग व्यवसाय	71.09	78.74	27.32	104.91	102.36	14.99	108.94	111.93	12.22
सीओएफ	1.92	3.50	2.92	9.21	9.07	1.48	8.69	8.56	0.89
एलएलपी	0.29	0.52	0.70	1.21	3.65	7.48	0.83	0.89	0.41
प्रभावी कर	45.03	54.52	26.72	26.69	11.28	37.39	24.97	20.53	10.26

टिप्पणी: (आस्ति) को छोड़कर सभी चर का प्रतिशत

स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न

सारणी 4: पैनल यूनिट रूट टेस्ट के परिणाम

चर	प्रतिलोम काई-वर्ग (ची-स्क्वायर) आंकड़े	संशोधित काई-वर्ग (ची-स्क्वायर) आंकड़े
लाभ का अंतर	53.32***	5.27***
इक्विटी पर प्रतिफल	32.7**	2.01**
आस्ति पर प्रतिफल	32.12**	1.92**
इन (एसेट्स)	88.02***	10.75***
दक्षता	63.43***	6.87***
लीवरेज	28.67*	1.37*
चलनिधि	67.64***	7.53***
दबावग्रस्त अग्रिम	163.94***	22.76***
बैंकिंग व्यवसाय	72.6***	8.32***
सीओएफ	469.89***	71.13***
एलएलपी	173.55***	24.28***
प्रभावी कर	167.16***	23.27***

टिप्पणी: असंतुलित पैनल डेटा के लिए प्रवृत्ति सहित फिलिप्स-पेरॉन यूनिट रूट टेस्ट लागू किया गया है। परीक्षण की जा रही अशक्त परिकल्पना यह है कि सभी पैनलों में एक यूनिट रूट होती है। *, **, *** क्रमशः 10, 5 और 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्व दर्शाते हैं।

स्रोत: लेखकों की गणना।

सारणी 5: एसएफबी के प्रदर्शन का अनुमान परिणाम

चर	लाभ का अंतर	इक्विटी पर प्रतिफल	आस्ति पर प्रतिफल
	(1)	(2)	(3)
एल1. डीईपी	0.138 (0.286)	-0.003 (0.149)	0.152 (0.308)
इन (एसेट्स)	9.492 (8.54)	20.491 (12.556)	1.764 (1.672)
दक्षता	-0.635*** (0.124)	-0.602*** (0.089)	-0.113*** (0.019)
लीवरेज	2.14*** (0.605)	3.961*** (0.698)	0.307*** (0.101)
चलनिधि	0.631** (0.293)	0.877*** (0.319)	0.09 (0.058)
दबावग्रस्त अग्रिम	2.348 (1.531)	1.084 (1.523)	0.368 (0.26)
बैंकिंग व्यवसाय	0.566*** (0.133)	0.831*** (0.155)	0.09*** (0.024)
सीओएफ	-1.268 (1.496)	1.579 (0.997)	0.109 (0.201)
एलएलपी	-2.447 (2.13)	-1.377 (2.464)	-0.441 (0.375)
प्रभावी कर	0.003 (0.013)	0.02 (0.016)	2.3E-04 (0.002)
<i>मॉडल निदान</i>			
वालड आंकड़े	415.39***	803.98***	666.60***
एआर-1	-0.33	0.09	-0.25
एआर-2	0.72	0.47	0.70
सरगन आँकड़े	0.01	1.16	0.03

सभी मॉडलों का अनुमान जीएमएम फ़र्स्ट-डिफ़ेंस स्पेसीफिकेशन का उपयोग करके लगाया गया है। *, **, *** क्रमशः 10, 5 और 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्व को दर्शाते हैं। सारणी को उदार रखने के लिए टीई के अनुमानों को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। एल1. डीईपी आश्रित चर के पहले अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है। कोष्ठक में दिए गए अंक मानक त्रुटि को दर्शाते हैं।

स्रोत: लेखकों की गणना।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी लेखा और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक शृंखला

विषय -वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	107
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	108
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	109
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय/विक्रय	110
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	111
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	111
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	112
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	113
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	114
9	कुल चलनिधि राशियां	114
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	115
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	115
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	116
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	116
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	117
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	118
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	119
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	120
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	121
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	121
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	121
21	थोक मूल्य सूचकांक	122
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	126
	सरकारी खाते और खजाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	126
24	खजाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	127
25	खजाना बिलों की नीलामी	127
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	128
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	129
28	वाणिज्यिक पत्र	129
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	129
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	130

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	131
32	विदेशी मुद्रा भंडार	131
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	131
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	132
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	132
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	133
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	133
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	134
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	135
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	136
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	137
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	138
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	139
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	141
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	142
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	143
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	144
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	145
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	146

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।

— = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2020-21	2019-20		2020-21	
		ति3	ति4	ति3	ति4
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	-6.2	3.4	3.7	1.0	3.7
1.1.1 कृषि	3.6	3.4	6.8	4.5	3.1
1.1.2 उद्योग	-6.4	-3.0	-3.2	1.6	5.5
1.1.3 सेवाएं	-8.4	5.8	5.6	-0.2	3.2
1.1क अंतिम खपत व्यय	-7.3	6.8	3.3	-2.6	6.4
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	-10.8	2.4	2.5	2.6	10.9
	2020-21	2020		2021	
	1	मई	जून	मई	जून
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-8.4	-33.4	-16.6	29.3	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	11.4	10.5	9.6	9.5	9.8
2.1.2 ऋण	5.6	5.5	5.6	5.9	6.1
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	5.5	5.5	5.4	5.8	6.1
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	19.3	16.7	18.9	11.7	10.4
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	18.8	11.8	11.8	18.3	16.9
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	12.2	11.7	12.3	10.3	10.7
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	3.50	3.00	3.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.2	3.8	3.7	4.8	4.7
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.4	73.3	73.6	70.9	71.1
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	37.4	-38.7	-37.6	-84.4	-55.7
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5	29.3	29.9	29.9	30.1
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	46.8	91.4	122.8	65.0	87.1
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
4.4 बैंक दर	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
4.5 आधार दर	7.40/8.80	8.15/9.40	7.40/9.00	7.40/8.80	7.40/8.80
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	6.55/7.05	6.95/7.50	6.70/7.45	6.55/7.05	6.55/7.05
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	4.90/5.50	5.10/5.90	5.10/5.65	4.90/5.50	4.90/5.50
4.8 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.75/3.50	2.70/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	3.25	3.62	3.54	3.18	3.15
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.32	3.19	3.19	3.40	3.44
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.47	3.40	3.42	3.60	3.72
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.83	3.41	3.54	3.73	3.89
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.34	5.79	5.90	6.28	6.36
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमरीकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	72.40	75.64	75.48	72.48	74.18
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	85.31	83.91	84.63	88.23	88.57
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरीकी डॉलर					
1-माह (%)	6.80	3.49	3.66	5.46	3.80
3-माह (%)	5.64	3.60	3.66	5.63	3.99
6-माह (%)	5.47	3.73	3.82	5.49	4.13
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	6.18	6.3	6.2	6.3	6.3
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.03	5.1	5.1	5.3	5.6
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.29	-3.4	-1.8	12.9	12.1
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	1.71	-2.1	-0.1	9.6	7.7
6.3.2 ईंधन और पावर	-7.99	-23.1	-16.2	37.6	32.8
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	2.75	-0.3	0.1	10.8	10.9
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-17.08	-51.0	-48.5	68.7	98.3
7.2 निर्यात	-7.08	-35.7	-12.5	68.1	48.3

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2020-21	2020	2021				जुला. 30
			जुला.	जुला. 2	जुला. 9	जुला. 16	
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2831727	2646131	2946228	2958354	2950407	2941015	2919525
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	13	19	17	13	12	15
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2831738	2646144	2946247	2958371	2950420	2941027	2919541
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	106555	123866	112620	114114	115101	113295	115119
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2724437	2521510	2832990	2843636	2834709	2826934	2803636
1.2.3 रुपया सिक्का	746	768	637	621	610	798	786
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमा राशियां	1504697	1281734	1823443	1846466	1857912	1877568	1959069
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	100	100	100	100	101	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	542693	435414	657894	621651	660018	626624	674997
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6529	5443	6904	6939	6992	6903	7455
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3204	2536	3666	3606	3581	3489	3582
2.1.1.7 अन्य बैंक	31820	25694	36023	36840	35686	36972	37177
2.1.1.8 अन्य	895440	805280	1094822	1150570	1124848	1177362	1209139
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	24868	7225	23991	26718	26644	26074	26576
2.1.2 अन्य देयताएं	1343670	1544130	1383095	1387384	1384342	1368490	1383256
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	2848367	2825864	3206538	3233851	3242254	3246058	3342325
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	13	19	17	13	12	15
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1204135	1180774	1433173	1426145	1437559	1426747	1511979
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1674	4857	11251	14104	5827	1181	836
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	90275	258425	90973	90853	91602	91559	91796
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	26422	25013	11554	11554	11554	11731	16731
2.2.3.7 एक्विजिमेंट बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	6678	9649	7678	7678	7669	6769	6609
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	24858	7226	17086	23499	23474	22952	26670
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1331671	1180831	1471601	1494053	1496935	1519495	1518026
2.2.6 अन्य आस्तियां	162643	159076	163203	165947	167621	165611	169662
2.2.6.1 सोना	146572	157597	159230	161706	163472	161269	164967

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घावधि रिपो परिचालन&	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन#	लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घावधि रिपो परिचालन	एनबीफसी/एचएफसीएस के लिए विशेष चलनिधि योजना ₹	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12-2-4-7-8-13)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय					
जून 1, 2021	-	402563	-	-	0	-	-	-	500	-	-	-	-	-402063
जून 2, 2021	-	404497	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-404497
जून 3, 2021	-	406786	-	-	209	-	-	-	290	-	-	-	-	-406287
जून 4, 2021	-	358822	-	200029	0	-	-	-	620	-	-	-	150	-558381
जून 5, 2021	-	35574	-	-	1021	-	-	-	-	-	-	-	-	-34553
जून 6, 2021	-	999	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-961
जून 7, 2021	-	398908	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-398856
जून 8, 2021	-	383929	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-383929
जून 9, 2021	-	378913	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-378913
जून 10, 2021	-	367572	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-367572
जून 11, 2021	-	362304	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-362277
जून 12, 2021	-	2304	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-2293
जून 13, 2021	-	1699	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-1588
जून 14, 2021	-	361592	-	-	0	-	-	-	-	-	320	-	-	-361272
जून 15, 2021	-	374505	-	-	0	3916	-	-	-	-	-	490	-	-370099
जून 16, 2021	-	313654	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-313654
जून 17, 2021	-	317491	-	-	29	-	-	-	390	-	-	-	-	-317072
जून 18, 2021	-	304546	-	200009	59	-	-	-	40160	-	-	-	1000	-465336
जून 19, 2021	-	44220	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-44218
जून 20, 2021	-	2438	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-2334
जून 21, 2021	-	314349	-	-	0	-	-	-	100	-	-	-	-	-314249
जून 22, 2021	-	345816	-	-	0	10199	-	-	160	-	-	-	-	-335457
जून 23, 2021	-	349005	-	-	0	-	-	-	200	-	-	-	-	-348805
जून 24, 2021	-	345721	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-345721
जून 25, 2021	-	354255	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-354253
जून 26, 2021	-	2541	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-2450
जून 27, 2021	-	6001	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-5942
जून 28, 2021	-	375834	-	-	0	-	-	-	160	-	-	-	-	-375674
जून 29, 2021	-	401344	-	-	130	1537	-	-	-	-	-	-	-	-399677
जून 30, 2021	-	484819	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-484804

टिप्पणी: # लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ), लक्षित दीर्घावधि रिपोपरिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) और मांग के अनुसार लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन। ऋणात्मक(-) चिन्ह बैंकों द्वारा लिए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है। & ऋणात्मक (-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतानकोदर्शाता है।

₹ 7 मई, 2021 के प्रेस विज्ञप्ति 2021-2022/177 के अनुसार, अतिरिक्तप्रोत्साहनके रूप में बैंक अपनी अधिशेष तरलता कोCOVID ऋण पुस्तिका के आकार के तहत पार्ककरने के लिए पात्रहैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग शुक्रवार कोएक विशेष 14-दिवसीय रिवर्सरिपोविडोका संचालनउस दर पर किया जाएगा जोरेपोदर से 25 बीपीएस कम है।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2020-21	2020	2021	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	68315	9814	5842	18633
1.1 क्रय (+)	162479	14847	7142	21923
1.2 विक्रय (-)	94164	5033	1300	3290
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	510516	73847	43956	138217
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	68315	13035	10054	28687
(करोड़ ₹)	510516	97982	75735	213952
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	72751	2459	59852	49573

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2020-21	2020	2021	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	12118	0	0	550
1.2 विक्रय (-)	12118	0	0	550
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	690	0	550	0

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	30 जून 2021 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	8668	1185	7483
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	14922	900	14022
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	42548	14480	28068
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
कुल (1+2+3+4)	66138	16565	49573

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2020-21	2020	2021					
		जुला. 31	फर. 26	मार्च 26	अप्रै. 23	मई 21	जून 18	जुला. 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	182	80	58	182	149	494	59	254
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	0	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	0	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	-	30	0	0	0	0	0	0
4. अन्य								
4.1 सीमा	75000	65000	75000	75000	75000	60000	76000	76000
4.2 बकाया	32387	34376	32842	32387	27122	1662	5578	23296
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	32569	34486	32900	32569	27271	2156	5637	23550

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा अर्थात एक्जिम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू/एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2020-21	2020	2021		
		जून 19	मई 21	जून 4	जून 18
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2751828	2567080	2861367	2877189	2886087
1.1 संचलन में नोट	2826851	2634218	2937217	2949472	2961524
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	26170	25644	26230	26252	26252
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	101935	93525	102822	99278	102432
2 जनता की जमाराशियां	2042487	1611690	1879245	1916077	1937613
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1995136	1572974	1830794	1866196	1887418
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	38716	48451	49881	50194
3 एम₁ (1 + 2)	4794315	4178770	4740612	4793266	4823700
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	150963	150963	150963	150963	150963
5 एम₂ (3 + 4)	4945278	4329733	4891575	4944229	4974663
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	14050278	13140721	14270307	14379960	14343807
7 एम₃ (3 + 6)	18844594	17319491	19010920	19173225	19167506
8 कुल डाकघर जमाराशियां	433441	433441	433441	433441	433441
9 एम₄ (7 + 8)	19278035	17752932	19444361	19606666	19600947

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
			जून 19	मई 21	जून 4
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	5850374	5499987	5862533	6024534	5919172
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1099686	1123896	1025199	1108321	1049521
1.1.1 सरकार पर दावे	1337300	1180189	1441680	1448299	1487439
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1333917	1175526	1439024	1437064	1475641
1.1.1.2 राज्य सरकारें	3383	4663	2656	11235	11799
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाशियां	237615	56293	416481	339978	437918
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	237572	56251	416439	339936	437875
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	4750689	4376091	4837335	4916213	4869650
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11668469	10902373	11542997	11552694	11552418
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	8709	7187	1435	1964	5749
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11659760	10895186	11541562	11550730	11546669
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	10949512	10247763	10831221	10843425	10841755
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	694758	637516	693112	689798	687525
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	15490	9908	17229	17508	17389
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	4578846	4075368	4678189	4776584	4813999
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4199400	3830714	4298743	4397138	4434553
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4199637	3830951	4298979	4397374	4434789
3.1.2 विदेशी देयताएं	237	237	237	237	237
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	379446	244655	379446	379446	379446
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26387	26973	26995	26995
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	3280008	3184625	3099772	3207582	3145077
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1356660	1515001	1332483	1328980	1349809
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1923349	1669624	1767289	1878602	1795268
एम₃ (1+2+3+4-5)	18844594	17319491	19010920	19173225	19167506

डेटा 26 मार्च, 2021 से संबंधित है

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020		2021	
		जून 19	मई 21	जून 4	जून 18
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	4794315	4178770	4740612	4793266	4823700
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	11048293	10013204	11094849	11196929	11209810
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	18936067	17431047	19105836	19266103	19264136
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2751828	2567080	2861367	2877189	2886087
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	15892863	14538382	15951321	16096558	16078774
1.2.1 मांग जमाराशियां	1995136	1572974	1830794	1866196	1887418
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	13897727	12965408	14120527	14230362	14191356
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6253977	5834434	6354237	6403663	6386110
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	123414	91409	79058	68603
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7643750	7130974	7766290	7826699	7805246
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	38716	48451	49881	50194
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	244025	286869	244696	242475	249080
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	18509289	17426552	18372152	18550847	18444049
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	5850374	5499987	5862533	6024534	5919172
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1099686	1123896	1025199	1108321	1049521
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	4750689	4376091	4837335	4916213	4869650
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	12658915	11926565	12509619	12526313	12524877
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	34134	29238	3113	3648	7433
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	12624780	11897327	12506505	12522665	12517444
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	951313	989760	949168	958906	954872
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26387	26973	26995	26995
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4438202	3852370	4620976	4630984	4691693
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	3830714	4298743	4397138	4434553
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	238802	21656	322233	233847	257140
2.4 पूंजी खाता	2775245	2821178	2911846	2936630	2972837
2.5 अन्य मदें (निवल)	1263091	1053084	1002419	1006094	925764

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2020-21	2020		2021	
		जून	अप्रै.	मई	जून
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	18936067	17431047	19000006	19105836	19264136
2 डाकघर जमाराशियां	433441	433441	433441	433441	433441
3 एल₁ (1 + 2)	19369508	17864488	19433447	19539277	19697577
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	33179	53474	28937	28932	30104
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2645	10666	3563	3563	3563
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	25550	39450	20275	20275	21525
4.3 सावधि जमाराशियां	4984	3358	5099	5094	5016
5 एल₂ (3 + 4)	19402687	17917962	19462384	19568208	19727681
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	31905	31905
7 एल₃ (5 + 6)	19434592	17949867	19759586

टिप्पणी : संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020		2021	
		जून 19	मई 21	जून 4	जून 18
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2853763	2660605	2964190	2976467	2988519
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	698867	484463	649717	711790	715442
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	651748	451363	603344	665049	669032
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	38716	48451	49881	50194
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3599981	3183784	3662358	3738138	3754155
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	730328	841684	669125	642985	642416
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	1099686	1123896	1025199	1108321	1049521
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1096345	1119275	1022585	1097128	1037765
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1333174	1174736	1438339	1436388	1474980
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1333174	1174736	1438339	1436388	1474980
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	743	790	685	676	661
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	237572	56251	416439	339936	437875
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	3340	4621	2614	11193	11756
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-403492	-311450	-359187	-468984	-414538
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-378066	-289399	-357508	-467300	-412854
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	34134	29238	3113	3648	7433
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	1	326	1	1	1
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	25426	22051	1679	1684	1684
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26387	26973	26995	26995
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	3830714	4298743	4397138	4434553
2.3.1 सोना	247723	250028	275640	274540	265576
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3951694	3580703	4023120	4122615	4168994
2.4 पूंजी खाता	1173033	1259409	1233571	1229806	1250419
2.5 अन्य मदें (निवल)	183626	255592	98912	99175	99390

सं. 11: रिज़र्व बैंक - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2020		2021			
		जून 26	मई 28	जून 4	जून 11	जून 18	जून 25
		1	2	3	4	5	6
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	3599981	3163675	3705431	3738138	3704603	3754155	3698987
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	2853763	2660478	2963060	2976467	2990952	2988519	2980029
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	698867	463901	692723	711790	663649	715442	668838
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	39296	49649	49881	50003	50194	50120
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1099686	1134432	1069925	1108321	1080546	1049521	1017177
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-378066	-322330	-404069	-467300	-470693	-412854	-452721
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	8709	9203	1963	1964	1902	5749	6048
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	3811722	4313624	4397138	4418495	4434553	4467940
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26411	26995	26995	26995	26995	27053
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1356660	1495763	1303006	1328980	1352642	1349809	1366509

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों/ माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		जून 19	मई 21	जून 4	जून 18
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	14960977	13691815	15017382	15163555	15146093
1.1.1 मांग जमाराशियां	1861209	1452440	1695059	1730276	1751739
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	13099768	12239375	13322323	13433279	13394354
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5894896	5507719	5995045	6044976	6027459
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	123414	91409	79058	68603
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7204873	6731656	7327278	7388304	7366895
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	244025	286869	244696	242475	249080
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	16368358	15383601	16323001	16434933	16385814
2.1.1 सरकार को ऋण	4461632	4141325	4534285	4626857	4580580
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11906727	11242276	11788715	11808076	11805233
2.1.2.1 बैंक ऋण	10949512	10247763	10831221	10843425	10841755
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10888258	10158474	10740559	10753449	10754843
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	13970	12643	16039	13291	16166
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	894	1072	1250	1416	1402
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	942351	980798	940205	949944	945909
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	238802	21656	322233	233847	257140
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	454866	289675	531282	442798	470587
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	152552	175313	149780	149597	152451
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	63512	92706	59269	59354	60996
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	1010202	823903	1052544	1220586	1173216
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	542693	451363	603344	665049	669032
2.3.2 उपलब्ध नकदी	90748	83141	91692	88237	91330
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-376761	-289399	-357508	-467300	-412854
2.4 पूंजी खाता	1578041	1537598	1654104	1682653	1698248
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	834319	712879	781596	800683	722749
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	593102	426797	511502	530556	514490
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	70853	75819	56308	58321	66063

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	26 मार्च 2021 की स्थिति	2020	2021		
		जून 19	मई 21	जून 4	जून 18
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	4462526	4142392	4535489	4628273	4581982
2 वाणिज्यिक पत्र	82584	110140	78342	80602	81474
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	9840	11800	9587	9663	10566
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	64035	70645	65536	65563	68918
3.3 अन्य	5210	5208	5136	5134	5125
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	121008	131832	118763	118402	113821
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	308904	303538	305422	312699	321962
4.3 अन्य	149325	156851	152802	153610	153305
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	31142	68484	40436	38993	39269
5.2 वित्तीय संस्थाएं	167130	122359	164148	165276	151470

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2020-21	2020	2021		2020-21	2020	2021	
		जून	मई	जून		जून	मई	जून
1	2	3	4	5	6	7	8	
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	209	210	209	210	133	134	133	134
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	259530	327590	245040	240574	254589	322308	240110	235512
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	200585	250049	181875	181709	195866	244929	177405	177399
1.2 बैंकों से उधार राशि	40886	61160	44689	39952	40880	61160	44471	39456
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	18059	16382	18477	18912	17843	16219	18234	18656
2 अन्य के प्रति देयताएं	16457782	15178146	16527824	16516961	16014145	14743862	16089154	16078860
2.1 कुल जमाराशियां	15540152	14331884	15682311	15692010	15113512	13915114	15261152	15272352
2.1.1 मांग	1899343	1521699	1802866	1788424	1861193	1486775	1763217	1748636
2.1.2 मीयादी	13640809	12810184	13879446	13903586	13252320	12428339	13497935	13523716
2.2 उधार	248271	293300	248315	257480	244025	289039	242718	252064
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	669359	552962	597198	567470	656607	539709	585284	554444
3 रिजर्व बैंक से उधार	90275	290512	90093	90829	90275	290512	90093	90829
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	90275	290512	90093	90829	90275	290512	90093	90829
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	650745	533008	757622	732253	633440	517852	738455	713780
4.1 उपलब्ध नकदी	92793	90080	94785	93473	90748	87658	92728	91424
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	557951	442928	662837	638780	542693	430194	645726	622356
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	265729	330943	247367	245113	197541	260839	191072	188930
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	179430	213816	171280	169301	143294	177476	138317	134552
5.1.1 चालू खाते में	16796	21933	18640	16551	14226	19719	16107	14204
5.1.2 अन्य खातों में	162634	191883	152640	152750	129068	157758	122209	120347
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	36716	41153	27532	26459	10654	15245	8874	9180
5.3 बैंकों को अग्रिम	19908	24293	18069	21523	16764	23152	16028	19910
5.4 अन्य आस्तियां	29675	51681	30487	27831	26829	44966	27853	25288
6 निवेश	4598924	4289272	4695860	4739431	4462526	4166414	4558998	4601130
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4591896	4281592	4688752	4732509	4461632	4165558	4557647	4599956
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7029	7679	7108	6922	894	856	1352	1175
7 बैंक ऋण	11297014	10571882	11161004	11198423	10949509	10240256	10824944	10861025
7क खाद्यान्न ऋण	91653	115026	125083	121177	61254	84620	89265	85359
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	11081668	10381645	10958298	10997642	10736491	10051973	10624467	10662355
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	30896	21661	29136	29579	30531	21406	29108	29544
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	128831	126950	121059	116143	127883	125980	119655	114793
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	20762	16203	17904	20271	20394	15978	17642	20057
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	34857	25422	34607	34789	34210	24919	34071	34277

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मई 26, 2021	2020	2021		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			जून 19	मई 21		
	1	2	3	4	%	%
I. सकल बैंक ऋण (II+III)	10949509	10245677	10833589	10841866	-1.0	5.8
II. खाद्यान्न ऋण	61254	89289	90663	86912	41.9	-2.7
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	10888255	10156388	10742926	10754953	-1.2	5.9
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1299914	1152935	1284756	1284399	-1.2	11.4
2. उद्योग	2918028	2875210	2883797	2867304	-1.7	-0.3
2.1 सूक्ष्म और लघु ¹	383854	352696	370718	375116	-2.3	6.4
2.2 मझौले	136054	95671	145549	147875	8.7	54.6
2.3 बड़े	2398121	2426844	2367530	2344313	-2.2	-3.4
3. सेवाएं	2630566	2528492	2571093	2600627	-1.1	2.9
3.1 परिवहन परिचालक	145195	140190	142300	141169	-2.8	0.7
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	21043	20592	20155	21006	-0.2	2.0
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	49590	46253	49513	49640	0.1	7.3
3.4 शिपिंग	7172	5155	5244	6804	-5.1	32.0
3.5 नौवहन	25624	24612	26144	26440	3.2	7.4
3.6 पेशेवर सेवाएं	119488	118781	113092	112123	-6.2	-5.6
3.7 व्यापार	617627	552855	614482	614336	-0.5	11.1
3.7.1 थोक व्यापार	319197	269162	315911	315376	-1.2	17.2
3.7.2 खुदरा व्यापार	298430	283693	298570	298960	0.2	5.4
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	235547	229263	233695	232292	-1.4	1.3
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) ² जिसमें से	945061	903594	899502	883851	-6.5	-2.2
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	187324	188923	168213	166199	-11.3	-12.0
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	78441	32148	74262	77528	-1.2	141.2
3.10 अन्य सेवाएं ³	464219	487198	466967	512966	10.5	5.3
4. व्यक्तिगत ऋण	2813713	2490377	2787265	2786519	-1.0	11.9
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	7307	8847	7049	7093	-2.9	-19.8
4.2 आवास	1459066	1334900	1462029	1464645	0.4	9.7
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	71544	61457	66510	65891	-7.9	7.2
4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	4570	5803	4401	4430	-3.1	-23.7
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	116537	97586	104475	102757	-11.8	5.3
4.6 शिक्षा	63805	65017	62965	62720	-1.7	-3.5
4.7 वाहन ऋण	241657	214602	240170	238214	-1.4	11.0
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	60726	34267	62101	62221	2.5	81.6
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	788503	667898	777567	778548	-1.3	16.6
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
5.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां ⁴	1264151	1143831	1258377	1253199	-0.9	9.6
5.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम ⁵	1107236	1074132	1027910	1036420	-6.4	-3.5
5.3 मध्यम उद्यम ⁶	206122	115379	183639	188251	-8.7	63.2
5.4 आवास	469863	463684	472326	470908	0.2	1.6
5.5 शिक्षा ऋण	48201	52042	47526	47127	-2.2	-9.4
5.6 नवीकरणीय ऊर्जा	1171	786	1144	1321	12.9	68.1
5.7 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2352	913	2424	2467	4.9	170.1
5.8 निर्यात ऋण ⁷	19028	16785	15649	19852	4.3	18.3
5.9 अन्य	19062	10191	22417	23860	25.2	134.1
5.10 नेट पीएसएलसी- एसएफ/एमएफ सहित कमजोर वर्ग	813263	732581	813511	832421	2.4	13.6

टिप्पणी 1: डाटा अनंतिम हैं। सकल बैंक ऋण और गैर-खाद्य ऋण का डाटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (एससीबी) शामिल किया गया है, जब कि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डाटा क्षेत्र-वार पर और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल गैर खाद्य ऋण के लगभग 90 प्रतिशत के चुनिंदा बैंकों को समाविष्ट किया गया है। टिप्पणी 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

1. सूक्ष्म और लघु में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण और पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।
7. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत निर्यात ऋण विदेशी बैंकों से संबंधित हैं।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	26 मार्च, 2021	2020	2021		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जून 19	मई 21	जून 18		
	1	2	3	4	2021-22	2021
				%	%	
1 उद्योग (2.1 से 2.19)	2918028	2875210	2883797	2867304	-1.7	-0.3
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	46094	42890	44637	46544	1.0	8.5
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	165669	157937	165331	164730	-0.6	4.3
1.2.1 चीनी	25552	25491	24346	23210	-9.2	-9.0
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	20547	17589	19812	19807	-3.6	12.6
1.2.3 चाय	5512	5108	5467	5692	3.3	11.4
1.2.4 अन्य	114058	109749	115705	116021	1.7	5.7
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	15663	15025	15496	15153	-3.3	0.8
1.4 वस्त्र	201250	189236	204709	202771	0.8	7.2
1.4.1 सूती वस्त्र	91567	86401	90244	88557	-3.3	2.5
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2713	2046	2639	2624	-3.3	28.3
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	30674	26835	31667	31216	1.8	16.3
1.4.4 अन्य वस्त्र	76295	73954	80158	80374	5.3	8.7
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11299	10937	11479	11450	1.3	4.7
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	13296	12590	13523	13543	1.9	7.6
1.7 कागज और कागज से बने उत्पाद	35540	31676	36005	36339	2.3	14.7
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आणविक इंधन	72323	73324	70454	73299	1.3	0.0
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	186911	180006	181091	179134	-4.2	-0.5
1.9.1 उर्वरक	32212	34486	31400	31748	-1.4	-7.9
1.9.2 औषधि और दवाइयाँ	51138	52040	50339	49653	-2.9	-4.6
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	45767	39455	42607	40172	-12.2	1.8
1.9.4 अन्य	57794	54025	56745	57561	-0.4	6.5
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	53494	48402	54521	54578	2.0	12.8
1.11 कांच और कांच के सामान	9124	8133	9028	9234	1.2	13.5
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	52196	57162	50569	50255	-3.7	-12.1
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	328663	350359	307723	299116	-9.0	-14.6
1.13.1 लोहा और स्टील	232849	266465	213800	206361	-11.4	-22.6
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	95814	83894	93923	92755	-3.2	10.6
1.14 सभी अभियांत्रिकी	147312	147283	148011	145635	-1.1	-1.1
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	32433	29742	33647	32351	-0.3	8.8
1.14.2 अन्य	114879	117541	114364	113284	-1.4	-3.6
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	83559	85374	83094	84258	0.8	-1.3
1.16 रत्न और आभूषण	62714	55686	57992	60158	-4.1	8.0
1.17 निर्माण	95511	102607	98223	97632	2.2	-4.8
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1091624	1069114	1084963	1092381	0.1	2.2
1.18.1 पावर	566455	568950	559500	564092	-0.4	-0.9
1.18.2 दूरसंचार	113080	146155	113926	116239	2.8	-20.5
1.18.3 सड़क	236947	182007	232489	233219	-1.6	28.1
1.18.4 हवाई अड्डा	7327	4546	9464	9467	29.2	108.2
1.18.5 बंदरगाह	7363	11104	8474	7700	4.6	-30.7
1.18.6 रेलवे	11021	11996	12322	12346	12.0	2.9
1.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	149432	144356	148789	149318	-0.1	3.4
1.19 अन्य उद्योग	245786	237470	246949	231094	-6.0	-2.7

टिप्पणी : जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2020-21	2020		2021					
		मई 29	मार्च 26	अप्रै. 09	अप्रै. 23	अप्रै. 30	मई 07	मई 21	मई 28
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	32	31	30	31	32	32	32
1 कुल जमा राशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	125859.6	125730.0	125859.6	127075.5	125866.2	125959.1	125179.6	124966.0	123810.8
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	23736.9	25020.8	23736.9	23837.8	22965.2	23839.0	25490.5	25400.2	26861.5
2.1.1 जमा राशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	4896.9	5276.6	4896.9	4685.8	4281.2	5197.4	5245.1	4581.6	5137.8
2.1.1.2 अन्य	13,899.4	13939.5	13899.4	14395.6	13845.8	13808.0	15047.4	15721.6	15490.8
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	10.0	184.9	484.9	829.8
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	4940.6	5779.7	4940.6	4756.4	4838.2	4823.6	5013.1	4612.2	5403.1
2.2 मीयादी देयताएं	179957.5	177995.6	179957.5	182880.1	181469.1	178836.8	173773.6	172843.1	169786.4
2.2.1 जमा राशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	65333.7	64012.5	65333.7	67268.5	66572.3	64191.2	61126.2	61084.0	59567.6
2.2.1.2 अन्य	111960.2	111790.5	111960.2	112679.8	112020.4	112151.0	110132.2	109244.4	108320.0
2.2.2 बैंकों से उधार	630.0	755.9	630.0	899.9	899.9	899.9	909.0	909.0	1118.9
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	2033.7	1436.6	2033.7	2031.8	1976.4	1594.6	1606.3	1605.7	779.9
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	63559.8	56438.5	63559.8	61519.5	58641.5	58682.0	49148.8	47868.8	49695.4
4.1 मांग	15691.8	13701.3	15691.8	14912.6	12625.5	11930.6	10425.1	10059.3	11059.3
4.2 मीयादी	47868.0	42737.1	47868.0	46606.8	46016.0	46751.4	38723.7	37809.4	38636.1
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	8151.1	7535.9	8151.1	7511.5	8340.2	8308.0	8053.6	8964.2	9254.1
5.1 उपलब्ध नकदी	570.3	720.7	570.3	599.4	579.1	584.9	588.7	672.4	662.8
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	7580.8	6815.2	7580.8	6912.1	7761.2	7723.1	7465.0	8291.8	8591.3
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1148.1	1403.1	1148.1	831.3	827.4	898.8	1074.3	1120.4	1208.9
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	64455.2	53179.8	64455.2	67901.4	66257.2	65337.4	65921.0	66037.9	67366.8
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	28835.7	30659.9	28835.7	27900.9	24989.0	24508.8	18568.5	21056.5	21739.2
9 बैंक ऋण (10.1+11)	114631.6	111318.8	114631.6	117342.6	116773.9	117735.8	112796.8	125981.9	107780.5
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	114612.1	111315.6	114612.1	117326.7	116758.0	117719.9	112780.9	125966.5	107765.1
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	89429.1	79337.2	89429.1	88609.3	87632.4	86692.3	81383.2	79921.7	84144.9
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	19.5	3.2	19.5	15.9	15.9	15.9	15.9	15.4	15.4

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2020-21			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	जून '20	मई '21	जून '21(अ)	जून '20	मई '21	जून '21(अ)	जून '20	मई '21	जून '21(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	156.7	161.1	158.3	152.3	158.7	160.5	157.0	164.2	166.2	154.0	160.7	162.6
1.1 अनाज और उत्पाद	145.4	149.9	146.8	148.2	145.1	145.6	152.7	148.8	149.2	149.6	146.3	146.7
1.2 मांस और मछली	185.2	192.4	187.7	190.3	198.5	200.1	197.0	204.3	205.6	192.7	200.5	202.0
1.3 अंडा	160.3	164.8	162.0	149.4	168.6	179.3	154.6	173.0	182.8	151.4	170.3	180.7
1.4 दूध और उत्पाद	154.1	154.4	154.2	153.3	155.8	156.1	153.4	156.5	156.4	153.3	156.1	156.2
1.5 तेल और चर्बी	148.2	139.9	145.2	138.2	184.4	190.4	132.9	168.8	172.1	136.3	178.7	183.7
1.6 फल	146.9	153.4	149.9	143.2	162.3	158.6	151.8	172.5	171.5	147.2	167.1	164.6
1.7 सब्जी	174.2	196.2	181.7	148.9	138.4	144.7	171.2	166.5	176.2	156.5	147.9	155.4
1.8 दाल और उत्पाद	154.4	156.0	154.9	150.3	165.1	165.5	152.0	165.9	166.9	150.9	165.4	166.0
1.9 चीनी और उत्पाद	114.4	117.0	115.3	113.2	114.3	114.6	116.3	115.9	116.1	114.2	114.8	115.1
1.10 मसाले	161.9	160.4	161.4	159.8	169.7	170.0	158.8	165.2	165.5	159.5	168.2	168.5
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	149.8	141.3	146.3	142.1	164.6	165.5	135.6	152.0	152.2	139.4	159.3	159.9
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	163.2	165.5	164.3	161.8	169.8	171.7	161.7	171.1	173.3	161.8	170.4	172.4
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	181.8	188.7	183.6	182.4	189.6	189.1	186.7	198.2	195.3	183.5	191.9	190.8
3 कपड़ा और जूते	155.6	149.7	153.3	154.1	164.5	164.6	147.2	154.1	154.9	151.4	160.4	160.8
3.1 कपड़ा	156.4	152.0	154.7	154.7	165.3	165.4	149.1	156.5	157.5	152.5	161.8	162.3
3.2 जूते	151.1	137.2	145.3	150.0	160.6	159.9	136.6	140.2	140.6	144.4	152.1	151.9
4 आवास	--	157.2	157.2	--	--	--	154.7	161.6	160.5	154.7	161.6	160.5
5 ईंधन और लाइट	149.1	140.9	146.0	144.9	161.7	162.1	137.1	155.5	156.2	141.9	159.4	159.9
6 विविध	153.9	146.1	150.2	151.7	161.1	161.5	142.0	152.3	153.6	147.0	156.8	157.7
6.1 घरेलू सामान और सेवा	152.9	145.2	149.3	151.7	158.8	159.2	140.4	150.1	150.0	146.4	154.7	154.9
6.2 स्वास्थ्य	160.3	151.3	156.9	158.2	169.1	169.7	148.1	160.4	160.8	154.4	165.8	166.3
6.3 परिवहन और संचार	144.9	135.0	139.7	141.4	153.2	154.0	129.3	145.0	147.6	135.0	148.9	150.6
6.4 मनोरंजन	154.0	144.3	148.5	153.2	160.0	161.0	144.5	152.6	151.6	148.3	155.8	155.7
6.5 शिक्षा	162.5	156.2	158.9	161.8	167.6	166.7	152.5	156.6	158.4	156.4	161.2	161.8
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	153.7	155.8	154.5	151.2	159.3	159.5	152.2	157.5	158.0	151.6	158.6	158.9
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	156.1	154.4	155.3	152.7	161.1	162.1	150.8	159.5	160.4	151.8	160.4	161.3

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2020-21	2020		2021	
				जून	मई	जून	जून
	1	2	3	4	5	6	
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	--	--	120.6	121.7	
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1034	1018	1049	1057	
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	--	1040	1024	1057	1065	

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2020-21	2020		2021	
		जून	मई	जून	जून
	1	2	3	4	
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	48723	47315	47860	47891	
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	59283	48213	70833	69960	

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
				जून	अप्रै.	मई (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	123.4	119.3	132.0	132.7	133.7
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	145.7	140.9	151.5	150.5	151.8
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	160.7	155.4	161.6	159.7	160.2
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	159.3	161.6	161.0	162.3	161.4
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	179.2	159.3	170.1	159.5	162.5
1.1.1.3 दूध	4.440	153.4	151.9	154.7	155.2	154.4
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	151.2	152.5	162.1	163.1	165.6
1.1.1.5 मसाले	0.529	149.5	145.6	151.6	149.8	151.1
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	162.0	147.9	169.7	168.7	166.2
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	130.5	125.1	143.2	145.0	148.7
1.1.2.1 फाइबर	0.839	119.8	116.9	133.1	135.1	142.5
1.1.2.2 तिलहन	1.115	161.7	154.8	195.7	208.8	212.9
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	109.0	103.8	115.5	115.5	115.9
1.1.2.4 फूल	0.204	210.0	200.5	163.0	119.5	138.7
1.1.3 खनिज	0.833	164.9	166.3	185.9	184.3	186.1
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	159.8	162.5	182.9	183.8	182.9
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.1	179.7	196.5	186.2	197.1
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	70.4	67.7	90.2	90.2	92.3
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	94.0	85.6	108.9	110.5	113.7
1.2.1 कोल	2.138	126.6	126.4	127.3	127.3	127.3
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	141.8	141.6	141.9	141.9	141.9
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.3	119.0	119.8	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	130.9	131.1	138.1	138.1	138.1
1.2.2 खनिज तेल	7.950	79.2	68.6	103.1	105.8	111.0
1.2.3 बिजली	3.064	109.6	101.0	111.1	111.1	111.1
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	121.5	118.6	129.9	131.0	131.5
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	141.4	137.5	154.2	156.8	155.9
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.2	134.8	143.4	144.2	144.3
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	139.0	139.3	143.2	139.6	139.8
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	120.2	119.3	121.5	121.6	122.1
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	143.5	128.5	182.7	190.7	185.4
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	146.9	148.7	148.9	148.2	147.7
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	143.5	145.1	142.7	142.3	144.3
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	115.9	117.2	121.5	123.5	123.4
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	138.1	137.5	140.9	141.4	141.9
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	118.4	119.2	118.4	119.1	118.6
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	128.0	127.9	128.2	128.4	127.8
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	132.3	133.8	131.5	130.5	133.5
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	166.5	163.8	171.4	178.8	178.3
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	147.0	143.8	152.8	150.3	149.9
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	132.2	129.7	137.9	136.0	137.6
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	142.9	147.0	142.4	143.9	147.5
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	170.5	167.7	187.9	192.1	196.3
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	124.5	125.5	125.7	126.1	126.0
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	120.2	121.0	121.7	122.2	123.5
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	126.5	127.5	128.4	128.0	127.3
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	129.4	130.5	129.5	130.2	128.6
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	157.2	158.6	160.3	159.3	157.7
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	157.2	158.6	160.3	159.3	157.7

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
				जून	अप्रै.	मई (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.6	113.6	128.7	128.3	129.4
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	106.6	100.6	121.0	120.3	120.9
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	131.7	129.1	140.1	139.7	142.0
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	115.2	117.0	121.9	122.1	122.0
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	132.3	131.5	134.6	134.0	134.9
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	155.6	149.4	170.6	172.5	171.0
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	116.3	118.3	119.5	121.0	121.6
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.6	137.3	140.3	140.0	139.9
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	138.1	137.7	139.2	139.7	139.9
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	139.8	136.3	143.5	140.9	140.2
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	117.9	117.6	118.2	118.8	118.9
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	101.1	102.2	97.7	98.9	99.6
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	138.6	138.5	139.8	140.2	140.5
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	120.6	119.6	122.2	122.7	122.4
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	134.6	134.1	138.4	137.4	138.7
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	120.7	121.1	124.2	121.7	124.3
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	136.6	136.4	140.6	139.9	140.4
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	185.8	179.8	191.3	191.3	194.5
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	125.7	124.5	127.9	127.2	130.0
1.3.8 कागज और कागज के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	121.7	120.4	132.8	133.7	132.8
1.3.8.1 लुगदी, कागज और कागज बोर्ड	0.493	124.1	122.6	138.5	137.8	136.3
1.3.8.2 लहरदार कागज और पेपर बोर्ड और कागज के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	122.2	119.0	130.9	135.5	134.6
1.3.8.3 कागज की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	117.4	118.2	125.7	125.4	125.3
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	153.8	150.8	153.8	153.1	154.0
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	153.8	150.8	153.8	153.1	154.0
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	118.2	115.7	128.0	127.8	128.1
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	118.6	114.9	133.5	134.2	135.5
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	123.6	123.4	126.5	127.4	126.7
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	116.7	109.1	140.2	135.7	133.8
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	124.4	123.2	126.7	127.9	127.4
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	114.9	113.5	121.4	121.7	123.5
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	120.6	120.1	123.4	124.0	125.4
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	115.1	113.6	122.9	122.3	124.5
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	93.7	91.3	102.4	102.0	101.9
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	130.9	129.3	134.7	134.8	136.9
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	130.9	129.3	134.7	134.8	136.9
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	111.3	107.7	122.2	121.4	121.0
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.3	98.4	102.3	102.0	102.3
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	93.3	92.7	98.1	97.8	98.7
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	120.3	114.7	135.3	134.3	133.4
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	117.6	118.3	121.2	120.5	121.6
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	127.2	127.5	132.5	135.1	136.4
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	109.5	109.1	111.8	113.5	112.7
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	109.3	110.8	114.1	94.9	112.5
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	109.5	109.1	114.4	107.7	110.4
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	120.9	121.9	124.7	125.1	124.9

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
				जून	अप्रै.	मई (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेंट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	125.3	127.1	128.2	128.4	129.0
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	121.1	120.9	122.9	122.5	123.4
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	78.9	77.6	78.9	78.9	81.5
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	111.4	103.8	128.6	131.8	133.8
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	109.2	97.0	133.6	138.0	137.7
1.3.14.2 मेटेलिक आयसन	0.653	113.3	101.3	135.5	136.6	137.5
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.8	94.4	113.0	116.7	116.7
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	112.0	104.8	127.6	129.2	131.2
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	117.2	106.5	142.8	154.1	154.8
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	108.3	102.3	127.7	128.0	127.6
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	108.7	101.3	131.0	126.8	135.5
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	127.9	120.9	140.4	141.8	150.0
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.3	105.1	125.9	130.8	131.9
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.1	107.6	113.3	115.2	118.0
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	145.7	147.5	155.3	148.8	155.6
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.9	113.8	122.6	124.7	126.3
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	114.1	112.0	120.6	121.5	122.7
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	127.8	123.3	139.4	145.6	147.7
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	98.9	99.0	96.8	96.8	96.8
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.7	96.1	100.9	101.6	105.6
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	102.9	100.8	106.7	106.9	106.4
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	125.0	123.6	131.3	132.9	134.3
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	109.8	109.9	111.6	112.1	112.1
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	99.1	96.7	102.2	102.9	100.8
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.8	135.1	134.6	134.8	135.5
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	114.9	115.4	116.3	116.6	120.7
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	98.5	99.5	101.8	102.6	101.4
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	107.7	109.2	107.0	107.0	107.0
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	141.8	142.0	142.8	141.9	142.4
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	102.8	102.0	103.5	103.5	106.5
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	102.7	112.1	95.8	95.8	98.6
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	113.6	112.0	118.6	119.4	119.3
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	113.2	112.2	117.6	118.5	116.9
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.1	118.1	116.5	117.2	117.3
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	98.1	96.9	102.2	102.3	101.1
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	115.9	109.5	130.4	132.8	134.9
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	111.1	110.4	112.4	112.8	113.2
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.7	117.8	124.6	124.3	125.3
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	109.5	109.9	110.2	109.9	113.6
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	114.0	112.7	116.7	117.0	117.7
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	106.3	104.0	112.7	113.7	115.5
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	119.4	117.0	120.3	120.3	120.5
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	111.6	111.1	114.2	114.4	113.7
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गैयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.8	110.3	114.4	114.0	115.4
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	80.2	81.3	72.1	72.3	72.3
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने-उतारने वाले उपकरण	0.285	113.4	110.9	115.2	116.4	116.4

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
				जून	अप्रै.	मई (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	128.7	127.9	131.1	131.0	131.8
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	121.6	120.6	122.9	123.4	124.6
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	108.4	108.2	109.7	109.4	110.1
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	75.1	76.8	76.6	76.7
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	128.0	125.6	128.3	128.4	130.1
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	121.9	122.7	126.0	125.9	124.8
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	128.7	126.1	132.5	133.5	134.0
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	65.2	64.6	66.4	66.5	66.2
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	117.8	117.0	119.1	120.5	119.6
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	119.4	117.9	119.8	121.7	119.6
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	116.1	116.0	118.4	119.1	119.7
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	126.2	124.5	128.8	129.9	129.9
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.9	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	105.0	106.3	104.1	104.1	103.8
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	124.7	122.6	127.5	129.0	128.9
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	130.3	128.5	135.2	135.3	136.3
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	128.5	127.2	132.7	133.5	132.4
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	133.2	128.3	145.8	146.9	147.5
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	133.2	128.3	145.8	146.9	147.5
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	132.4	127.8	133.9	138.4	138.4
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	130.5	125.7	131.9	136.7	136.7
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	173.7	172.7	196.9	200.4	195.3
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	132.0	130.9	135.9	135.9	136.9
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	142.4	141.2	146.6	147.6	146.8
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	167.4	167.2	169.8	170.7	170.7
2 खाद्य सूचकांक	24.378	153.4	148.7	158.8	158.6	158.6

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारत	2019-20	2020-21	अप्रैल- मई		मई	
				2020-21	2021-22	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	129.0	118.1	72.1	121.7	90.2	116.6
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	109.6	101.0	83.2	107.7	87.6	108.0
1.2 विनिर्माण	77.63	129.6	117.2	63.3	119.5	84.4	113.5
1.3 बिजली	7.99	158.4	157.6	138.1	168.0	150.6	161.9
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	127.0	118.1	99.2	124.6	106.0	122.7
2.2 पूंजीगत माल	8.22	93.3	75.7	21.2	72.8	35.4	65.6
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	137.7	124.7	64.2	134.6	83.7	129.9
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	136.6	124.7	54.4	135.6	88.4	129.8
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	119.0	100.9	22.6	93.8	39.7	78.7
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.3	142.4	104.0	139.1	135.3	136.4

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - जून			
	2021-22 (बजट आकलन)	2021-22 (वास्तविक)	2020-21 (वास्तविक)	बजट आकलनों का प्रतिशत	
				2021-22	2020-21
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	1788424	539997	150008	30.2	7.4
1.1 कर राजस्व (निवल)	1545396	412680	134822	26.7	8.2
1.2 करेतर राजस्व	243028	127317	15186	52.4	3.9
2 गैरेतर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	188000	7402	3573	3.9	1.6
2.1 ऋण की वसूली	13000	3406	3573	26.2	23.9
2.2 अन्य प्राप्तियां	175000	3996	0	2.3	0.0
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	1976424	547399	153581	27.7	6.8
4 राजस्व व्यय	2929000	710148	727671	24.2	27.7
4.1 ब्याज भुगतान	809701	184295	160493	22.8	22.7
5 पूंजी व्यय	554236	111496	88273	20.1	21.4
6 कुल व्यय (4+5)	3483236	821644	815944	23.6	26.8
7 राजस्व घाटा (4-1)	1140576	170151	577663	14.9	94.8
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	1506812	274245	662363	18.2	83.2
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	697111	89950	501870	12.9	569.4

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	2020		2021				
		जून 26	मई 21	मई 28	जून 4	जून 11	जून 18	जून 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	5676	37408	8232	8922	8688	9451	10621	10543
1.2 प्राथमिक व्यापारी	16740	15861	28086	32090	32454	33516	31659	34544
1.3 राज्य सरकारें	13347	13097	32220	34870	35800	39050	38982	41982
1.4 अन्य	52802	138769	114276	121465	131929	140761	152759	160981
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	67473	127626	111574	116696	120899	123567	126805	127372
2.2 प्राथमिक व्यापारी	30966	50405	48301	48862	51679	52864	57658	58473
2.3 राज्य सरकारें	9436	12805	9839	9839	11839	11839	11839	11839
2.4 अन्य	31800	97950	64548	71404	75993	85005	88710	99532
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	119024	102736	132490	136542	135805	135466	138673	134123
3.2 प्राथमिक व्यापारी	154197	71661	152922	152729	148537	140143	134335	135126
3.3 राज्य सरकारें	18510	12395	18875	18725	17973	17973	17983	17983
3.4 अन्य	174501	131078	121458	109770	106965	107655	102239	97843
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	220351	153167	156220	158373	106109	76668	84391	124998
4.4 अन्य	747	440	1218	657	1064	2063	1114	685
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	694471	811790	842820	861914	878561	897290	912261	930341

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ		स्वीकृत बोलियाँ		कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)		
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या				कुल अंकित मूल्य	
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2021-22										
जून 2	15000	98	35214	5761	58	14994	5761	20755	99.16	3.4125
जून 9	15000	106	44462	4252	42	14998	4252	19250	99.16	3.4035
जून 16	15000	83	33213	5502	57	14998	5502	20500	99.14	3.4692
जून 23	15000	130	42296	4514	60	14986	4514	19500	99.14	3.4679
जून 30	15000	110	51656	2001	41	14999	2001	17000	99.15	3.4443
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2021-22										
जून 2	15000	106	29313	2008	83	14992	2008	17000	98.21	3.6488
जून 9	15000	163	41325	3	72	14997	3	15000	98.22	3.6399
जून 16	15000	129	41468	10	78	14990	10	15000	98.19	3.6969
जून 23	15000	173	47596	3	77	14997	3	15000	98.18	3.7189
जून 30	15000	182	44896	894	70	14993	894	15888	98.18	3.7200
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2021-22										
जून 2	6000	72	20950	73	29	6000	73	6073	96.40	3.7426
जून 9	6000	75	20735	1	35	5999	1	6000	96.39	3.7595
जून 16	6000	73	14652	0	52	6000	0	6000	96.30	3.8526
जून 23	6000	122	23026	0	31	6000	0	6000	96.27	3.8851
जून 30	6000	98	25631	0	28	6000	0	6000	96.27	3.8898

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1		2
जून	1, 2021	1.90-3.50	3.12
जून	2, 2021	1.90-3.45	3.12
जून	3, 2021	1.90-3.40	3.08
जून	4, 2021	1.90-3.65	3.13
जून	5, 2021	2.60-3.70	3.06
जून	7, 2021	1.90-3.40	3.14
जून	8, 2021	1.90-3.40	3.09
जून	9, 2021	1.90-3.40	3.13
जून	10, 2021	1.90-3.40	3.08
जून	11, 2021	1.90-3.40	3.09
जून	14, 2021	1.90-3.40	3.13
जून	15, 2021	1.90-3.45	3.14
जून	16, 2021	1.90-3.45	3.20
जून	17, 2021	1.90-3.45	3.15
जून	18, 2021	1.90-3.45	3.17
जून	19, 2021	2.60-3.35	2.87
जून	21, 2021	1.90-3.45	3.17
जून	22, 2021	1.90-3.45	3.13
जून	23, 2021	1.90-3.50	3.17
जून	24, 2021	1.90-3.45	3.16
जून	25, 2021	1.90-3.47	3.16
जून	28, 2021	1.90-3.40	3.14
जून	29, 2021	1.90-3.40	3.14
जून	30, 2021	1.90-3.50	3.15
जुला.	1, 2021	1.90-3.40	3.12
जुला.	2, 2021	1.90-3.40	3.11
जुला.	3, 2021	2.70-3.30	2.90
जुला.	5, 2021	1.90-3.40	3.15
जुला.	6, 2021	1.90-3.40	3.11
जुला.	7, 2021	1.90-3.40	3.13
जुला.	8, 2021	1.90-3.40	3.17
जुला.	9, 2021	1.90-3.40	3.17
जुला.	12, 2021	1.90-3.40	3.20
जुला.	13, 2021	1.90-3.40	3.18
जुला.	14, 2021	1.90-3.40	3.21
जुला.	15, 2021	1.90-3.40	3.19

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2020	2021			
	जून 19	मई 7	मई 21	जून 4	जून 18
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	121465.00	87177.58	90349.28	78308.17	68209.42
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	5500.59	5276.72	5836.60	7547.33	6209.13
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.92-5.08	3.57-4.21	3.43-4.01	3.47-4.69	3.44-4.11

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2020	2021			
	जून 30	मई 15	मई 31	जून 15	जून 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	391482.30	404445.55	388707.25	404804.90	376117.85
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	56270.85	66560.60	61593.90	73440.40	97928.00
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.18-13.35	3.19-11.69	3.36-12.87	3.36-11.32	3.43-13.03

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	2020	2021					
		जून 26	मई 21	मई 28	जून 4	जून 11	जून 18	जून 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17461	18541	17255	16285	12369	12680	13526	13148
2 नोटिस मुद्रा	2604	478	669	5913	3431	681	4513	1009
3 मीयादी मुद्रा	757	690	731	807	571	611	708	568
4 त्रिपक्षीय रिपो	421118	379722	450852	526894	432505	425896	491460	476714
5 बाजार रिपो	337341	301952	371296	458253	379151	360174	433580	329177
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	2990	1764	9574	12063	13358	5616	7078	8737
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	56068	61322	88420	73563	59838	63446	73797
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	62490	60318	45821	52981	39397	58194	48523	43103
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5080	7861	7189	4165	7411	4507	7912	6446
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	4970	7991	6547	8193	6826	7104	8658	8852
10.2 182-दिवसीय	4870	3242	2683	4315	3610	2004	3490	3881
10.3 364-दिवसीय	4010	2589	2994	2314	4088	3439	3877	2396
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1490	1375						
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	82910	83375	65235	71968	61333	75248	72459	64678
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	-	371	7037	1014	610	175	8120	145

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2020-21		2019-20 (अप्रै-जून)		2020-21 (अप्रै-जून)*		जून 2020		जून 2021*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	74	102062	5	53141	22	12864	2	53127	10	9550
1ए प्रीमियम	73	97648	5	52710	21	12449	2	52703	10	9223
1.1 पब्लिक	53	38004	4	16	16	12179	1	2	8	9146
1.1.1 प्रीमियम	53	34848	4	9	16	11844	1	2	8	8881
1.2 राइट्स	21	64059	1	53124	6	685	1	53124	2	404
1.2.1 प्रीमियम	20	62800	1	52702	5	605	1	52702	2	342
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बांड और डिबेंचर	16	5806	4	722	6	3450	2	322	–	–
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	16	5806	4	722	6	3450	2	322	–	–
3.1.1 पब्लिक	16	5806	4	722	6	3450	2	322	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	90	107868	9	53862	28	16314	4	53449	10	9550
4.1 पब्लिक	69	43809	8	738	22	15629	3	325	8	9146
4.2 राइट्स	21	64059	1	53124	6	685	1	53124	2	404

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकड़े कुल में नहीं जुड़ सकते।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2020-21	2020	2021				
		1	जून	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून
			2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	2154339	165899	200883	252670	228491	236426	239047
	मिलियन अमरीकी डॉलर	291164	21908	27610	34711	30681	32269	32498
1.1 तेल	करोड ₹	190749	14143	17933	26199	26996	39058	29588
	मिलियन अमरीकी डॉलर	25784	1868	2465	3599	3625	5331	4022
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	1963591	151756	182950	226471	201495	197368	209459
	मिलियन अमरीकी डॉलर	265379	20040	25145	31112	27056	26938	28475
2 आयात	करोड ₹	2909937	159892	295004	352365	340499	282454	308002
	मिलियन अमरीकी डॉलर	393611	21114	40547	48407	45722	38551	41872
2.1 तेल	करोड ₹	611353	37342	65710	74768	80961	69255	78532
	मिलियन अमरीकी डॉलर	82684	4931	9031	10271	10871	9452	10676
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	2298584	122551	229295	277597	259538	213198	229470
	मिलियन अमरीकी डॉलर	310927	16183	31515	38135	34850	29099	31196
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-755597	6006	-94121	-99695	-112008	-46027	-68955
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-102447	793	-12936	-13696	-15040	-6282	-9374
3.1 तेल	करोड ₹	-420605	-23199	-47776	-48569	-53965	-30197	-48944
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-56900	-3063	-6567	-6672	-7246	-4121	-6654
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-334993	29205	-46345	-51126	-58043	-15830	-20011
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-45547	3857	-6370	-7024	-7794	-2161	-2720

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2020	2021						
		1	जुला. 24	जून 18	जून 25	जुला. 2	जुला. 9	जुला. 16	जुला. 23
			2	3	4	5	6	7	
1 कुल भंडार	करोड ₹	3910859	4464016	4519253	4559356	4566920	4572099	4549373	
	मिलियन अमरीकी डॉलर	522630	603933	608999	610012	611895	612730	611149	
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	3595444	4150552	4201958	4237769	4241429	4243914	4225412	
	मिलियन अमरीकी डॉलर	480482	561540	566240	566988	568285	568748	567628	
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	270134	265576	269344	271850	275820	278573	274565	
	मिलियन अमरीकी डॉलर	36100	35931	36296	36372	36956	37333	36884	
	मात्रा (मैट्रिक टन)	664.21	698.11	702.78	705.58	706.51	707.44	708.38	
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1048	1049	1049	1087	1087	1087	1087	
	करोड ₹	10953	11078	11119	11568	11550	11554	11506	
	मिलियन अमरीकी डॉलर	1464	1499	1498	1548	1547	1548	1546	
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	34328	36809	36832	38169	38122	38058	37891	
	मिलियन अमरीकी डॉलर	4585	4965	4965	5105	5107	5100	5091	

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से हैं।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2020-21	2020	2021		2020-21	2021-22
		1	जून	मई	जून	अप्रै.-जून
	2	3	4	5	6	
1 एनआरआई जमाराशियां	141895	132719	144288	141160	3000	3138
1.1 एफसीएनआर (बी)	20473	22458	19876	19623	-1786	-850
1.2 एनआर (ई) आरए	102579	94079	105245	102643	4442	3333
1.3 एनआरओ	18842	16182	19166	18894	344	655

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2020-21	2020-21	2021-22	2020	2021	
		अप्रै.-जून	अप्रै.-जून	जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	43955	-528	11362	-914	9040	-513
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	54927	2105	16617	64	10547	1398
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	81973	11840	22525	3309	12128	4173
1.1.1.1.1 इक्विटी	61088	6897	17902	1661	10574	2777
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	948	97	110	4	69	39
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	51597	5661	10610	1408	4318	2088
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7091	804	6847	138	6076	538
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1452	335	335	112	112	112
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	16935	3908	3908	1303	1303	1303
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3950	1035	715	345	252	93
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	27046	9735	5908	3245	1582	2775
1.1.1.2.1 इक्विटी	26983	9725	5816	3242	1540	2739
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	63	10	92	3	41	35
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	10972	2633	5255	979	1506	1911
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	5583	1235	2310	529	1132	570
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3013	753	753	251	251	251
1.1.2.3 अन्य पूंजी	6688	789	2675	246	240	1280
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	4313	144	483	48	117	190
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	36137	642	-1067	3174	447	465
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	38725	1098	159	3326	904	995
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	2589	456	1226	152	458	530
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	80092	114	10295	2260	9487	-48

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2020-21	2020	2021		
		जून	अप्रै.	मई	जून
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	12684.40	780.67	1188.18	1250.24	1232.22
1.1 जमाराशियां	680.37	44.53	75.78	68.20	64.32
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	62.75	3.64	9.19	7.85	10.02
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	471.80	34.16	51.78	52.19	66.91
1.4 उपहार	1586.24	108.81	161.56	149.38	178.21
1.5 दान	12.59	0.82	0.72	1.95	1.59
1.6 यात्रा	3239.67	195.11	284.76	294.02	277.65
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2680.10	185.33	240.74	237.27	241.57
1.8 चिकित्सा उपचार	29.75	3.07	2.16	2.57	2.52
1.9 विदेश में शिक्षा	3836.12	198.82	353.49	429.73	380.23
1.10 अन्य	85.03	6.38	8.00	7.07	9.20

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2019-20	2020-21	2020	2021	
			जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा बास्केट (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	98.00	93.92	93.68	93.61	93.21
1.2 रीर	103.20	103.46	103.17	104.36	104.30
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	97.38	93.59	93.29	93.20	92.76
2.2 रीर	102.88	102.96	102.54	103.61	103.62
6- मुद्रा बास्केट (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	94.92	88.47	89.00	87.03	86.62
1.2 रीर	103.60	101.78	102.16	101.78	102.09
2 आधार : 2018-19 =100					
2.1 नीर	100.78	93.93	94.49	92.40	91.97
2.2 रीर	103.30	101.49	101.87	101.49	101.80

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरीकी मिलियन डॉलर में)

मद	2020-21	2020	2021	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1063	105	60	87
1.2 राशि	26799	852	738	1485
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	13	1	-	-
2.2 राशि	8456	170	-	-
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1076	106	60	87
3.2 राशि	35255	1022	738	1485
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.03	5.11	6.41	5.12
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.93	2.44	1.86	1.75
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-13.00	0.00-10.00	0.00-8.80	0.00-10.25

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	जन.-मार्च 2020			जन.-मार्च 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	334313	315519	18794	336072	332683	3389
1 चालू खाता (1.1+1.2)	157116	156558	558	173382	181543	-8161
1.1 पण्य	76527	111569	-35042	91281	133025	-41745
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	80590	44990	35600	82101	48518	33583
1.2.1 सेवाएं	53060	31033	22027	56004	32520	23485
1.2.1.1 यात्रा	6860	4208	2652	2308	3141	-834
1.2.1.2 परिवहन	5016	5761	-745	6080	5633	446
1.2.1.3 बीमा	623	426	198	647	566	82
1.2.1.4 जीएनआईई	182	284	-102	159	241	-82
1.2.1.5 विविध	40378	20354	20024	46811	22938	23873
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	23285	2159	21125	26802	3327	23475
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	11474	11928	-454	13324	12847	478
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1024	1256	-232	1258	1402	-145
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	631	350	281	696	399	297
1.2.2 अंतरण	20579	2179	18400	20927	2085	18842
1.2.2.1 आधिकारिक	26	299	-273	18	285	-267
1.2.2.2 निजी	20553	1880	18673	20909	1801	19108
1.2.3 आय	6950	11778	-4827	5170	13913	-8743
1.2.3.1 निवेश आय	5523	11079	-5557	3517	13192	-9675
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1428	698	729	1653	721	932
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	176311	158960	17350	162690	150429	12261
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	99638	101420	-1782	108195	98236	9959
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	20871	8908	11963	15393	12714	2679
2.1.1.1 भारत में	19255	4070	15185	13679	7928	5750
2.1.1.1.1 इक्विटी	13923	4062	9861	8553	7894	659
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3772		3772	4519		4519
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1560	8	1552	607	34	573
2.1.1.2 विदेश में	1616	4838	-3222	1714	4786	-3072
2.1.1.2.1 इक्विटी	1616	2107	-491	1714	1197	517
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	788	-788	0	753	-753
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1943	-1943	0	2835	-2835
2.1.2 संविभाग निवेश	78767	92511	-13745	92802	85522	7280
2.1.2.1 भारत में	76983	91726	-14743	92500	84310	8190
2.1.2.1.1 एफआईआई	76983	91726	-14743	92500	84310	8190
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	60171	66381	-6209	81440	73679	7761
2.1.2.1.1.2 ऋण	16812	25345	-8534	11059	10631	428
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0		0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1783	785	998	303	1212	-909
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	27444	17526	9918	26446	18725	7721
2.2.1 बाह्य सहायता	2000	1420	580	5380	1387	3993
2.2.1.1 भारत द्वारा	2	28	-26	10	21	-11
2.2.1.2 भारत को	1998	1392	606	5370	1366	4004
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	16368	6030	10338	11834	5759	6075
2.2.2.1 भारत द्वारा	1983	1053	930	683	745	-63
2.2.2.2 भारत को	14385	4977	9408	11152	5014	6138
2.2.3 भारत को अल्पावधि	9077	10076	-1000	9232	11578	-2346
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	9077	9725	-649	8067	11578	-3511
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	351	-351	1165	0	1165
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	22109	26716	-4606	16733	21158	-4425
2.3.1 वाणिज्य बैंक	21996	26716	-4719	16518	21158	-4640
2.3.1.1 आस्तियां	4813	10222	-5409	4141	7973	-3832
2.3.1.2 देयताएं	17183	16493	690	12377	13185	-808
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	16844	14079	2765	11350	11889	-539
2.3.2 अन्य	113	0	113	215	0	215
2.4 रुपया ऋण चुकौती		7	-7		7	-7
2.5 अन्य पूंजी	27119	13292	13827	11315	12302	-987
3 भूल-चूक	886		886		711	-711
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	18794	-18794	0	3389	-3389
4.1 आईएमएफ				0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	18794	-18794	0	3389	-3389

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	जन.-मार्च 2020			जन.-मार्च 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2419902	2283860	136042	2449502	2424800	24702
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1137275	1133238	4037	1263718	1323202	-59484
1.1 पण्य	553933	807581	-253649	665312	969572	-304260
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	583342	325657	257686	598406	353629	244776
1.2.1 सेवाएं	384069	224629	159441	408194	237025	171170
1.2.1.1 यात्रा	49657	30461	19197	16819	22896	-6077
1.2.1.2 परिवहन	36311	41701	-5390	44312	41058	3254
1.2.1.3 बीमा	4512	3081	1430	4719	4125	594
1.2.1.4 जीएनआईई	1316	2057	-741	1158	1759	-601
1.2.1.5 विविध	292273	147329	144944	341186	167187	173999
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	168546	15631	152914	195350	24250	171099
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	83051	86341	-3290	97117	93634	3484
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	7410	9092	-1682	9166	10220	-1054
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4567	2532	2035	5073	2905	2168
1.2.2 अंतरण	148962	15774	133188	152529	15199	137330
1.2.2.1 आधिकारिक	189	2167	-1978	129	2074	-1945
1.2.2.2 निजी	148773	13607	135166	152400	13125	139275
1.2.3 आय	50311	85253	-34942	37682	101406	-63724
1.2.3.1 निवेश आय	39977	80198	-40221	25637	96153	-70517
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10333	5055	5278	12045	5252	6793
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1276212	1150622	125590	1185784	1096418	89366
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	721222	734119	-12897	788594	716008	72586
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	151075	64481	86594	112193	92670	19523
2.1.1.1 भारत में	139378	29459	109919	99699	57788	41911
2.1.1.1.1 इक्विटी	100781	29401	71380	62338	57537	4801
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	27305	0	27305	32935	0	32935
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	11292	58	11234	4427	251	4176
2.1.1.2 विदेश में	11697	35022	-23324	12493	34882	-22389
2.1.1.2.1 इक्विटी	11697	15253	-3556	12493	8726	3767
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5702	-5702	0	5490	-5490
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	14067	-14067	0	20666	-20666
2.1.2 संविभाग निवेश	570147	669638	-99491	676402	623338	53063
2.1.2.1 भारत में	557238	663952	-106714	674196	614505	59691
2.1.2.1.1 एफआईआई	557238	663952	-106714	674196	614505	59691
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	435547	480491	-44945	593588	537019	56569
2.1.2.1.1.2 ऋण	121691	183461	-61770	80608	77487	3122
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	12909	5686	7223	2206	8833	-6628
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	198653	126862	71791	192758	136479	56279
2.2.1 बाह्य सहायता	14475	10277	4198	39212	10111	29101
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	201	-187	71	153	-82
2.2.1.2 भारत को	14461	10076	4385	39141	9958	29183
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	118476	43648	74828	86255	41978	44276
2.2.2.1 भारत द्वारा	14351	7622	6729	4975	5433	-459
2.2.2.2 भारत को	104125	36026	68099	81280	36545	44735
2.2.3 भारत को अल्पावधि	65702	72938	-7236	67291	84390	-17099
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	65702	70397	-4695	58799	84390	-25591
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	2541	-2541	8492	0	8492
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	160037	193379	-33343	121962	154215	-32253
2.3.1 वाणिज्य बैंक	159220	193379	-34160	120397	154215	-33818
2.3.1.1 आस्तियां	34842	73992	-39151	30186	58112	-27927
2.3.1.2 देयताएं	124378	119387	4991	90211	96103	-5892
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	121926	101911	20016	82726	86651	-3925
2.3.2 अन्य	817	0	817	1565	0	1565
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	50	-50	0	50	-50
2.5 अन्य पूंजी	196301	96212	100089	82471	89666	-7196
3 भूल-चूक	6415	0	6415	0	5180	-5180
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	136042	-136042	0	24702	-24702
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	136042	-136042	0	24702	-24702

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	जन.-मार्च 2020			जन.-मार्च 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	157116	156531	584	173382	181517	-8135
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क. + 1.अ.ख.)	129586	142601	-13015	147285	165545	-18260
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	76527	111569	-35042	91281	133025	-41745
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	75738	106394	-30656	89691	115206	-25515
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	789	0	789	1590	0	1590
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	5175	-5175	0	17819	-17819
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	53060	31033	22027	56004	32520	23485
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	66	8	58	102	6	96
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	41	309	-269	54	211	-157
1.अ.ख.3 परिवहन	5016	5761	-745	6080	5633	446
1.अ.ख.4 यात्रा	6860	4208	2652	2308	3141	-834
1.अ.ख.5 निर्माण	931	708	223	752	713	39
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	623	426	198	647	566	82
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1024	1256	-232	1258	1402	-145
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	182	1641	-1459	238	2107	-1868
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	23967	2638	21329	27574	3909	23665
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	11474	11928	-454	13324	12847	478
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	588	819	-231	727	878	-150
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	182	284	-102	159	241	-82
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	2105	1046	1059	2781	865	1916
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	6950	11778	-4827	5170	13913	-8743
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1428	698	729	1653	721	932
1.आ.2 निवेश आय	4487	10921	-6434	2621	12952	-10331
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	2163	4654	-2491	1363	7837	-6474
1.आ.2.2 सविभाग निवेश	88	2346	-2259	28	1633	-1605
1.आ.2.3 अन्य निवेश	457	3910	-3452	122	3481	-3359
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1778	10	1768	1109	1	1107
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1036	159	878	896	240	656
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	20579	2152	18427	20927	2058	18868
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	20553	1880	18673	20909	1801	19108
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	20102	1358	18745	20224	1303	18920
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	451	522	-71	686	497	188
1.इ.2 सामान्य सरकार	26	272	-247	17	258	-240
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	142	161	-19	191	230	-38
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	9	40	-31	87	38	49
2.2 पूंजी अंतरण	133	121	12	104	191	-88
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	176169	177620	-1451	162499	153615	8884
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	20871	8908	11963	15393	12714	2679
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	19255	4070	15185	13679	7928	5750
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	17695	4062	13633	13071	7894	5177
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	13923	4062	9861	8553	7894	659
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3772	0	3772	4519	0	4519
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1560	8	1552	607	34	573
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1560	8	1552	607	34	573
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1616	4838	-3222	1714	4786	-3072
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1616	2895	-1279	1714	1950	-236
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1616	2107	-491	1714	1197	517
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	788	-788	0	753	-753
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1943	-1943	0	2835	-2835
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	1943	-1943	0	2835	-2835
3.2 सविभाग निवेश	78767	92511	-13745	92802	85522	7280
3.2अ भारत में सविभाग निवेश	76983	91726	-14743	92500	84310	8190
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	60171	66381	-6209	81440	73679	7761
3.2.2 ऋण प्रतिभितियां	16812	25345	-8534	11059	10631	428
3.2आ. भारत द्वारा सविभाग निवेश	1783	785	998	303	1212	-909
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	11473	9287	2186	2662	4929	-2267
3.4 अन्य निवेश	65058	48119	16939	51642	47061	4581
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	16957	14079	2878	11565	11889	-324
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	113	0	113	215	0	215
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	16844	14079	2765	11350	11889	-539
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	23520	20086	3433	22382	16416	5966
3.4.3अ भारत को ऋण	21535	19006	2529	21690	15650	6040
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	1985	1081	904	692	766	-74
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	37	45	-8	27	43	-16
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	9077	10076	-1000	9232	11578	-2346
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	15468	3832	11635	8435	7134	1301
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	18794	-18794	0	3389	-3389
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए.	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए.	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	18794	-18794	0	3389	-3389
4. कुल आस्तियां / देयताएं	176169	177620	-1451	162499	153615	8884
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	92776	83455	9321	99217	89707	9510
4.2 ऋण लिखत	67925	71539	-3613	54846	53384	1462
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	15468	22627	-7159	8435	10524	-2088
5. निवल भूल-चूक	886	0	886	711	-711	0

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(कोड़ ₹)

मद	जन.-मार्च 2020			जन.-मार्च 2021 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	1137271	1133041	4230	1263714	1323006	-59291
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	938002	1032210	-94208	1073506	1206597	-133090
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	553933	807581	-253649	665312	969572	-304260
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	548221	770126	-221905	653724	839694	-185970
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	5712	0	5712	11588	0	11588
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	37456	-37456	0	129878	-129878
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	384069	224629	159441	408194	237025	171170
1.अ.ख.1 अन्य के स्वाभिवल वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	475	57	418	741	44	697
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	295	2240	-1944	393	1536	-1143
1.अ.ख.3 परिवहन	36311	41701	-5390	44312	41058	3254
1.अ.ख.4 यात्रा	49657	30461	19197	16819	22896	-6077
1.अ.ख.5 निर्माण	6740	5124	1616	5482	5199	283
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4512	3081	1430	4719	4125	594
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	7410	9092	-1682	9166	10220	-1054
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1319	11876	-10557	1737	15356	-13619
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	173487	19096	154390	200979	28494	172485
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	83051	86341	-3290	97117	93634	3484
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	4259	5927	-1669	5300	6397	-1096
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1316	2057	-741	1158	1759	-601
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	15237	7575	7662	20269	6308	13962
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	50311	85253	-34942	37682	101406	-63724
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10333	5055	5278	12045	5252	6793
1.आ.2 निवेश आय	32476	79049	-46573	19106	94405	-75299
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	15659	33689	-18030	9937	57123	-47186
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	634	16984	-16351	203	11901	-11699
1.आ.2.3 अन्य निवेश	3311	28299	-24989	886	25372	-24486
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	12873	76	12797	8080	10	8071
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	7502	1149	6352	6530	1748	4782
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	148958	15577	133381	152526	15003	137523
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	148773	13607	135166	152400	13125	139275
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	145508	9826	135681	147403	9500	137903
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	3265	3781	-516	4997	3625	1372
1.इ.2 सामान्य सरकार	185	1970	-1785	126	1878	-1752
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	1027	1167	-140	1393	1673	-280
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नाम) / निस्तारण (जमा)	67	293	-226	636	278	358
2.2 पूँजी अंतरण	960	874	85	757	1395	-638
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	1275189	1285693	-10505	1184395	1119643	64752
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1.अ+3.1.आ)	151075	64481	86594	112193	92670	19523
3.1.अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	139378	29459	109919	99699	57788	41911
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	128086	29401	98685	95272	57537	37735
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	100781	29401	71380	62338	57537	4801
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	27305	0	27305	32935	0	32935
3.1.अ.2 ऋण लिखत	11292	58	11234	4427	251	4176
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	11292	58	11234	4427	251	4176
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	11697	35022	-23324	12493	34882	-22389
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	11697	20955	-9257	12493	14216	-1723
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	11697	15253	-3556	12493	8726	3767
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5702	-5702	0	5490	-5490
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	14067	-14067	0	20666	-20666
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	14067	-14067	0	20666	-20666
3.2 संविभाग निवेश	570147	669638	-99491	676402	623338	53063
3.2.अ भारत में संविभाग निवेश	557238	663952	-106714	674196	614505	59691
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	435547	480491	-44945	593588	537019	56569
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	121691	183461	-61770	80608	77487	3122
3.2.आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	12909	5686	7223	2206	8833	-6628
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	83046	67224	15822	19402	35925	-16523
3.4 अन्य निवेश	470921	348309	122612	376398	343008	33391
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	122743	101911	20832	84291	86651	-2360
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	817	0	817	1565	0	1565
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	121926	101911	20016	82726	86651	-3925
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईपीबी और बैंकिंग पूँजी)	170245	145393	24852	163138	119653	43484
3.4.3.अ भारत को ऋण	155879	137570	18309	158092	114067	44025
3.4.3.आ भारत द्वारा ऋण	14365	7823	6542	5045	5586	-540
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	270	328	-58	198	313	-116
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	65702	72938	-7236	67291	84390	-17099
3.4.6 अन्य खाते प्राच्य/देय-अन्य	111962	27740	84222	61481	52000	9481
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	136042	-136042	0	24702	-24702
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	136042	-136042	0	24702	-24702
4. कुल आस्तियां / देयताएं	1275189	1285693	-10505	1184395	1119643	64752
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	671555	604085	67470	723159	653844	69315
4.2 ऋण लिखत	491672	517827	-26155	399754	389097	10657
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	111962	163782	-51820	61481	76702	-15221
5. निवल भूल-चूक	6415	0	6415	0	5180	-5180

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2020-21		2020				2021	
			मार्च		दिसं.		मार्च	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	193929	482208	182957	418234	190857	480190	193929	482208
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	122726	456947	118442	395426	122489	454603	122726	456947
1.2 अन्य पूंजी	71203	25261	64515	22809	68368	25587	71203	25261
2 संविभाग निवेश	6436	281842	3847	246700	5527	274032	6436	281842
2.1 इक्विटी	840	177278	602	134778	1732	170630	840	177278
2.2 ऋण	5596	104563	3246	111922	3795	103402	5596	104563
3 अन्य निवेश	80897	446867	52412	427500	69382	438780	80897	446867
3.1 व्यापार ऋण	5644	100342	1460	104271	3196	102598	5644	100342
3.2 ऋण	13335	190382	6731	179834	10610	183983	13335	190382
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	42436	142069	26011	130761	37343	140683	42436	142069
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	19482	14074	18210	12634	18234	11516	19482	14074
4 रिज़र्व्स	576984		477807		585771		576984	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	858246	1210917	717023	1092434	851536	1193002	858246	1210917
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-352671		-375411		-341466		-352671

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2020-21	2020	2021		वि. व. 2020-21	2020	2021	
			जून	मई			जून	जून
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	255451.57	16188.00	29734.31	32126.98	9179707	599381	898224	1033422
1.1 इंटर-बैंक \$	25220.35	1423.94	2528.93	2829.58	1871236	118965	174307	196264
1.2 इंटर-बैंक \$	230231.22	14764.06	27205.39	29297.41	7308472	480416	723917	837159
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	32493.63	2431.49	2336.06	2703.44	41581497	3123215	2953188	3468711
2.1 इंटर-बैंक @	6886.15	533.60	492.39	545.84	20601554	1529247	1290828	1501184
2.2 इंटर-बैंक @	25607.48	1897.89	1843.67	2157.60	20979943	1593967	1662360	1967527
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	60905.81	4716.58	4169.98	4761.61	2889826	229517	202854	229633
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	51.41	3.23	3.65	4.31	2560	163	187	219
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	60602.23	4698.45	4142.63	4735.38	2878025	228734	201978	228681
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	252.17	14.91	23.69	21.91	9240	620	690	734
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	394.60	29.42	20.81	7.87	1532	116	122	59
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	353.33	27.82	18.08	7.03	1483	114	102	44
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	41.27	1.60	2.73	0.84	49	3	19	15
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	9460.43	990.75	824.36	856.89	225420	19749	24138	24187
5.1 एईपीएस @	9460.43	990.75	824.36	856.89	225420	19749	24138	24187

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2021 तक	2020	2021	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	9602.51	9027.03	9647.02	9688.24
1.1 क्रेडिट कार्ड	620.49	572.89	623.93	628.15
1.2 डेबिट कार्ड	8982.02	8454.14	9023.09	9060.08
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	21952.60	19008.07	22609.29	22947.96
2.1 वॉलेट @	20052.10	17553.64	20542.99	20864.68
2.2 कार्ड @	1900.51	1454.43	2066.30	2083.28
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.39	2.34	2.40	2.40
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.14	2.10	2.15	2.14
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.25	0.24	0.26	0.26
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	4.04	2.96	4.25	4.54
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	47.20	43.26	45.20	45.93
6 भारत क्यूआर @	35.70	21.51	48.63	49.33
7 यूपीआई क्यूआर *	925.22	-	981.82	1018.26

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2019-20	2019	2020		
			अग.	जून	जुला.	अग.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	159573	11199	16063	14659	12164
	बकाया	1078535	975153	1113107	1127727	1139857
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	116389	7932	12968	11821	9385
	बकाया	734807	665357	763577	775398	784783
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	25893	1460	3933	2840	1548
	बकाया	166140	153077	177232	180072	181620
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	36	-10	-13	-13	-16
	बकाया	3143	2966	3122	3109	3093
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	-1	-2	1	-3	-2
	बकाया	9	-7	8	5	3
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	16510	1133	1096	1440	1110
	बकाया	209168	197791	210984	212424	213534
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	20334	1459	2024	2118	1807
	बकाया	76042	62759	79523	81641	83448
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	41795	2933	3836	4281	3430
	बकाया	166087	138866	172804	177085	180515
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	92618	79433	95703	97723	99212
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7097	6359	7121	7182	7206
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7536	7104	7506	7490	7465
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	58836	45970	62474	64690	66632
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	11821	959	2091	1158	1508
	बकाया	114222	109909	119908	121066	122574
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	1	0	0	0	0
	बकाया	-25	-25	-25	-25	-25
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	30170	2965	2739	2426	2480
	बकाया	252190	230478	257316	259703	262149
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	19495	2103	1325	1446	1278
	बकाया	117987	103852	120403	121849	123127
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-101	-74	0	0	0
	बकाया	162	-235	162	162	162
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18168	-1344	-691	-1947	-877
	बकाया	1135	10800	357	-1590	-2467
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	28972	2280	2105	2927	2079
	बकाया	122602	105623	126197	129124	131203
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	-4	0	0	0	0
	बकाया	-155	-173	-155	-155	-155
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-24	0	0	0	0
	बकाया	-106	-82	-106	-106	-106
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	10565	10693	10458	10419	10385
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	13014	302	356	412	299
	बकाया	91538	79318	92214	92626	92925

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियों हैं अर्थात् सकल प्राप्तियों माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2020				2021
	मार्च	जून	सितं	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	6486585	6704983	7137069	7357111	7635902
1. वाणिज्य बैंक	40.41	38.98	38.55	37.81	37.77
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.39	0.36	0.34	0.25	0.27
3. बीमाकृत कंपनियां	25.09	26.24	25.33	25.64	25.30
4. म्यूच्युअल फंड	1.43	2.02	2.42	2.62	2.94
5. सहकारी बैंक	1.90	1.86	1.86	1.83	1.82
6. वित्तीय संस्थाएं	0.53	1.19	1.42	1.00	1.00
7. कॉरपोरेट	0.81	0.78	0.94	1.05	1.06
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	2.44	1.79	2.05	2.10	1.87
9. भविष्य निधियां	4.72	4.96	4.77	4.61	4.44
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	15.13	14.70	15.00	15.71	16.20
11. अन्य	7.17	7.11	7.32	7.37	7.33
11.1 राज्य सरकार	2.05	1.99	1.86	1.76	1.69

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2020				2021
	मार्च	जून	सितं.	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	3265990	3393099	3564979	3721573	3879982
1. वाणिज्य बैंक	34.99	33.54	34.60	34.19	33.69
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.76	0.74	0.54	0.36	0.48
3. बीमाकृत कंपनियां	31.63	30.85	30.26	30.25	30.04
4. म्यूच्युअल फंड	1.14	1.74	1.96	1.92	1.82
5. सहकारी बैंक	4.12	4.38	4.19	4.11	4.05
6. वित्तीय संस्थाएं	0.11	1.96	1.92	1.88	1.86
7. कॉरपोरेट	0.30	0.31	0.39	0.45	0.49
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	22.22	21.70	21.31	21.20	22.00
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.81	0.77
11. अन्य	4.71	4.78	4.80	4.82	4.77
11.1 राज्य सरकार	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18

खजाना बिल					
श्रेणी	2020				2021
	मार्च	जून	सितं	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	538409	881362	982286	839729	690646
1. वाणिज्य बैंक	61.06	46.11	53.50	54.75	55.54
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	2.26	1.48	2.16	1.65	2.82
3. बीमाकृत कंपनियां	7.45	4.64	4.06	4.50	5.61
4. म्यूच्युअल फंड	13.24	23.45	19.90	18.98	17.80
5. सहकारी बैंक	2.55	1.95	1.63	1.61	2.43
6. वित्तीय संस्थाएं	0.58	1.67	1.34	1.11	1.24
7. कॉरपोरेट	1.89	1.43	1.63	2.01	3.16
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.02	0.05	0.00	0.09	0.22
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	11.27	4.80	0.68	0.49
11. अन्य	10.95	7.95	10.99	14.63	10.70
11.1 राज्य सरकार	6.22	4.35	7.76	13.27	5.98

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (सं.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	3760611	4265969	4515946	5040747	5875914	6470254
1.1 गतिविधियां	2201287	2537905	2635110	2882758	3486519	3818358
1.1.1 राजस्व	1668250	1878417	2029044	2224367	2708218	2920507
1.1.2 पूंजी	412069	501213	519356	596774	694262	794599
1.1.3 ऋण	120968	158275	86710	61617	84038	103252
1.2 गैर गतिविधियां	1510810	1672646	1812455	2078276	2295105	2556504
1.2.1 राजस्व	1379727	1555239	1741432	1965907	2171963	2421566
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	648091	724448	814757	894520	969344	1091617
1.2.2 पूंजी	127306	115775	69370	111029	121159	132961
1.2.3 ऋण	3777	1632	1654	1340	1984	1977
1.3 अन्य	48514	55417	68381	79713	94290	95393
2. कुल प्राप्तियां	3778049	4288432	4528422	5023352	5779396	6524526
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2748374	3132201	3376416	3797731	4338225	4828088
2.1.1 कर प्राप्तियां	2297101	2622145	2978134	3278947	3547958	3951657
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1440952	1652377	1853859	2030050	2157126	2436871
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	852271	965622	1121189	1246083	1386652	1510287
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3878	4146	3086	2814	4180	4500
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	451272	510056	398282	518783	790267	876430
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	35779	33220	34224	36273	33272	30911
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	59827	69063	142433	140287	129507	232172
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	16561	20942	42213	44667	62499	18302
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	43266	48122	100219	95621	67008	213870
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	952410	1064704	997097	1102729	1408183	1409995
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	231090	617123	144792	387091	518093	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	60472	195816	-144847	325987	190241	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	708572	429585	844375	710119	885156	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	673298	689821	794856	795845	962386	1105573
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	80015	35038	71222	88961	213430	213430
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	35261	45688	42351	51004	42900	42529
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-3322	-6436	18423	-18298	-241	2978
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	13470	17792	25138	66289	32949	35987
3ख.1.6 नकद शेष	-17438	-22463	-12476	17395	96518	-54272
3ख.1.7 अन्य	158378	287268	49653	96014	55309	59147
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	27.3	27.7	26.4	26.6	28.9	28.8
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	27.4	27.9	26.5	26.5	28.4	29.0
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	20.0	20.3	19.7	20.0	21.3	21.5
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.7	17.0	17.4	17.3	17.4	17.6
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.9	6.9	5.8	5.8	6.9	6.3

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जून 2021 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	718	29	1831	29	1670	15
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	518	12	-	-	-	-
6	गोवा	54	12	62	6	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	61	1	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	1193	23	642	18
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	153	29	1572	29	262	12
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	232	27	139	12
17	मेघालय	40	2	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	98	14	-	-
19	नगालैंड	84	15	30	6	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	87	3	-	-	-	-
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	725	29	1596	29	900	24
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	जून 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8788	864	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1768	3	--	-
3	असम	4045	58	--	-
4	बिहार	5935	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4971	--	1	4550
6	गोवा	650	328	--	-
7	गुजरात	5198	508	--	-
8	हरियाणा	824	1282	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	292	--	--	-
12	कर्नाटक	6129	--	--	15000
13	केरल	2271	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	973	--	-
15	महाराष्ट्र	44662	672	--	11500
16	मणिपुर	163	106	--	-
17	मेघालय	768	44	9	-
18	मिज़ोरम	372	48	--	-
19	नगालैंड	1745	35	--	-
20	उड़ीसा	11891	1542	89	19933
21	पुदुचेरी	325	--	--	807
22	पंजाब	1427	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	2000
24	तमिलनाडु	7049	--	40	17414
25	तेलंगाना	6015	1307	--	-
26	त्रिपुरा	396	10	--	600
27	उत्तराखंड	986	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3459	135	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9445	615	214	-
	कुल	129571	8530	670	71804

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22						2021-22 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	अप्रैल		मई		जून		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	42415	33444	50896	41915	2000	1300	6000	5417	6000	5420	14000	12137
2	अरुणाचल प्रदेश	1366	1287	767	767	400	400	-	-	-	-	400	400
3	असम	12906	10996	15030	14230	-	-	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	25601	22601	27285	24685	-	-	2000	2000	2000	2000	4000	4000
5	छत्तीसगढ़	11680	10980	13000	10500	-	-	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	2600	2000	3354	3054	-	-	-	-	300	300	300	300
7	गुजरात	38900	28600	44780	33280	-	-	-	-1000	4500	3500	4500	2500
8	हरियाणा	24677	20677	30000	25550	-	-1800	5000	4000	5000	5000	10000	7200
9	हिमाचल प्रदेश	6580	4460	6000	3755	-	-	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	7869	6760	9328	6020	500	500	400	400	1700	1000	2600	1900
11	झारखंड	7500	5656	9400	8900	-	-	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	48500	42500	69000	61900	-	-	-	-	-	-	-	-
13	केरल	18073	12617	28566	23066	-	-	1500	1500	7500	7500	9000	9000
14	मध्य प्रदेश	22371	16550	45573	38773	-	-	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	48498	32998	69000	50022	-	-	13500	13500	10500	10500	24000	24000
16	मणिपुर	1757	1254	1302	1044	200	200	-	-	200	200	400	400
17	मेघालय	1344	1070	1777	1587	200	200	-	-100	200	200	400	300
18	मिज़ोरम	900	745	944	677	-	-150	150	150	-	-	150	-
19	नगालैंड	1000	423	1721	1366	350	350	-	-	250	150	600	500
20	उड़ीसा	7500	6500	3000	500	-	-500	-	-	-	-	-	-500
21	पुदुचेरी	970	470	1390	790	-	-	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	27355	18470	32995	23467	-	-1600	-	-800	3500	1850	3500	-550
23	राजस्थान	39092	24686	57359	44273	4000	4000	4000	3500	8500	7500	16500	15000
24	सिक्किम	809	481	1292	1292	-	-	500	500	-	-	500	500
25	तमिलनाडु	62425	49826	87977	76796	-	-	12000	11000	12000	10500	24000	21500
26	तेलंगाना	37109	30697	43784	37365	1500	1000	3500	3083	8500	8080	13500	12163
27	त्रिपुरा	2928	2578	1916	1631	-	-	-	-100	-	-50	-	-150
28	उत्तराखंड	69703	52744	75500	59185	-	-	-	-2500	5000	4000	5000	1500
29	उत्तरप्रदेश	5100	4500	6200	5208	-	-500	-	-	700	700	700	200
30	पश्चिम बंगाल	56992	40882	59680	50180	-	-3173	2000	-	8500	5500	10500	2327
	कुल	634521	487454	798816	651777	9150	227	50550	40550	84850	73850	144550	114627

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम₂ और एनएम₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
 एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
 जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाए गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओ/शाखाओ के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का सकेंतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2018-19 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

o बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल हैं।

o जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2020-21 से लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

:- नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2021	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,520 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2019-20	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2019-20	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2020-21 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 2, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 1, 2020	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 - टाइम सीरीज डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdepr@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001। एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रताशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdepr@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।